राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

हितों के टकराव को लेकर गांगुली पर सख्त लोकपाल

>> 14

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 96

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, शनिवार, 14 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

भगवान और महापुरुषों के नाम पर रख दिए पेड़ों के नाम

जमशेदपुर : झारखंड के जमशेदपुर जिले के गोलमुरी क्षेत्र में सड़क किनारे तार की जाली से घिरे बाड़े पर भगवान और महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। राम, कृष्ण, रहीम, गुरुनानक देव, गुरुगोविंद सिंह और रविदास के रूप ये पेड़-पौधे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। (पेज-6)

जागरण विशेष

झारखंड में अब किसानों की दोस्त बनेगी जलकुंभी

पाकुड़ : जलीय जीवों को नष्ट कर देने वाली जलकुंभी स्वभाव अब बदलने वाला है। अब यह किसानों की दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में जानी जाएगी। दरअसल, इससे हरी खाद बनाने की विधि ईजाद की गई है। (पेज-15)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

दो को छोड़ काली सूची से सभी सिख हुए बाहर

नई दिल्ली : गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के ठीक पहले मोदी सरकार ने सालों से काली सूची में शामिल विदेश में रह रहे सिखों को बड़ी राहत दी है। काली सूची में शामिल 314 में से 312 सिखों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। अब इन सिखों और उनके परिवार के सदस्यों का भारत आना संभव हो सकेगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

पुलिस निगरानी में चिन्मयानंद, सील किया गया आवास

शाहजहांपुर : दुष्कर्म के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एसआइटी का शिकंजा कसने लगा है। चिन्मयानंद की निगरानी के लिए पुलिस तैनात की गई है। साथ ही एक कमरे को छोड़कर उनका बाकी आवास सील कर दिया गया। बता दें आश्रम परिसर में ही चिन्मयानंद डिग्री कॉलेज और लॉ कॉलेज संचालित होते हैं।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

आठ अक्टूबर से नेमलेस और फेसलेस आइटी असेसमेंट

नई दिल्ली : सरकार करदाताओं के लिए ऑनलाइन असेसमेंट स्कीम लेकर आई है। इसे बिना चेहरे और बिना नाम वाला असेसमेंट (मूल्यांकन) का नाम दिया गया है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्कीम विजयादशमी यानी आठ अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

अमेरिका में ओपॉयड दवाएं बेचने में आठ भारतवंशी बंदी

न्यूयॉर्क : अमेरिका में ओपॉयड (नशीली दर्द निवारक) दवाएं बेचने के आरोप में भारतीय मूल के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए भारतवंशियों पर आरोप है कि वे भारत से करोड़ों डॉलर की बिना ब्रांड वाली नशीली दर्द निवारक दवाएं मंगवाकर अमेरिका में बेचते थे। इन ओपॉयड दवाओं को अमेरिकी डाक या कूरियर के जरिये ग्राहकों को भेजा जाता था।

दिल्ली में फिर ऑड-इवेन का एलान, गडकरी ने कहा-जरूरत नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली के लोगों को सर्दियों में प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार फिर से ऑड-इवेन (विषम-सम) योजना शुरू होगी। सरकार ने चार से 15 नवंबर तक चौपहिया वाहनों के लिए ऑड-इवेन व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। 9 और 10 नवंबर को शनिवार व रविवार होने की वजह से नियम में छूट मिलेगी। प्रेटू के अनुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा,इस कदम की कोई जरूरत नहीं है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सात बिंदुओं पर कार्य योजना बनी है। ऑड-इवेन योजना उसी का हिस्सा है। सीएम ने कहा, अक्टूबर व नवंबर में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से और सर्दियों में होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए यह कवायद शुरू की गई है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार से भी इस संबंध में बात करेगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, विभिन्न स्तर पर चर्चा में 1200 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्हीं के आधार पर सात बिंदुओं पर केंद्रित कार्ययोजना बनाई गई है।

नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा, 'अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने जो नई रिंग रोड बनवाई है, उससे दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है। इसके अलावा मेरा मंत्रालय करीब 50,000 करोड़ रुपये सड़क निर्माण पर खर्च कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगले दो वर्षों में दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी।

- चार से 15 नवंबर तक चौपहिया वाहनों पर लागू रहेगी योजना

दिल्ली सचिवालय मे पत्रकार वार्ता को संबोधित करते सीएम अरविंद केजरीवाल।

कार्ययोजना की खास बातें

- वार रूम बनाया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण से संबंधित शिकायतें दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी
- स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम से लोगों से प्रदूषण घटाने में सहयोग मांगा जाएगा
- 15 नवंबर के बाद ऑड-इवेन और दिवाली पर लेजर-शो को छोड़ बाकी बिंदु पर बनी कार्ययोजना लागू रहेगी

क्या होती है योजना

बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते सड़कों से वाहनों की संख्या कम करने के लिए इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं। इसके तहत सड़कों पर वाहनों को उसके सम-विषम नंबरों के आधार पर चलने की अनुमति होती है। एक दिन सम संख्या वाले यानी ऐसे वाहन जिनके नंबर की आखिरी संख्या 0, 2, 4, 6, 8 पर खत्म होती है, उन्हें चलाया जाता है। दूसरे दिन सड़कों पर विषम संख्या (1,3,5,7 और 9) पर खत्म होने वाले नंबरों की गाड़ियां चलती हैं।

क्यों है जरूरत

2018 तक दिल्ली की सड़कों पर 31 लाख पंजीकृत वाहन दौड़ते थे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली पिछले कई साल से शामिल है। सर्वाधिक प्रदूषण की स्थिति में यहां पीएम 10 की स्थिति 800 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच जाती है, जो तय मानक से आठ गुना अधिक है। सर्वाधिक घातक सूक्ष्म कणों पीएम 2 .5 प्रति घनमीटर 400 माइक्रोग्राम तक पहुंच जाता है, जबकि इसकी सीमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है।

अन्य देशों में नियम

चीन के बीजिंग में 2008 के ओलंपिक के दौरान इस नियम को लागू किया गया। इससे प्रदूषण में 40 फीसद की कमी आई। ब्राजील की राजधानी साओ पाउलो में गत एक दशक से इस नियम को अपनाया जा रहा है। नार्वे की राजधानी ओस्लो में भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया जाता है। 2012 के ओलंपिक के दौरान लंदन में इसे लागू किया गया। कुछ अन्य देशों ने भी इस तरह की योजना पर काम करने की कोशिश की है।

कम हुआ था 10 से 12 फीसद प्रदूषण

दिल्ली सरकार ने 2016 में दो बार ऑड-इवेन योजना लागू की थी। एक जनवरी से 15 जनवरी और 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इसे लागू किया था। दावा है कि उस समय 10 से 12 फीसद तक प्रदूषण कम हुआ था। अब एक बार फिर इसी तरह की कोशिश की जा रही है ताकि दिल्ली को प्रदूषण की बड़ी समस्या से राहत देने की कोशिश की जा सके।

बहुत असरकारी नहीं

2017 में आइआइटी और आइआइएम के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से शोध किया, जिसमें पाया गया कि ऑड-ईवन स्कीम के पहले चरण में दिल्ली के प्रदूषण में सिर्फ 2 से 3 फीसद गिरावट आई।

सुधार जारी : पिछले तीन साल के दौरान दिल्ली के प्रदूषण में 25 फीसद की कमी आई है। स्वच्छ हवा के लक्ष्य को पाने के लिए इस प्रदूषण में 65 फीसद और कटौती की दरकार होगी।

अहम मामला ▶ शीर्ष अदालत ने फेसबुक की याचिका पर सुनवाई के केंद्र को दिया निर्देश

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने पर जल्द फैसला करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने की जरूरत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और वाट्सएप की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने केंद्र से सवाल किया कि क्या वह सोशल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति बनाने और सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार से जोड़ने पर विचार कर रही है।

याचिका में फेसबुक ने मद्रास, बांबे और मध्य प्रदेश हाई कोर्टों में इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें हाई कोर्टों से याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। वह केंद्र सरकार से इस पर निर्देश प्राप्त करेंगे। इसके बाद पीठ ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 24 सितंबर तक का समय दे दिया।

याचिका में फेसबुक ने कहा है कि याचिकाओं का ट्रांसफर न्याय के हित में है क्योंकि इससे हाई कोर्टों के विरोधाभासी फैसलों से बचा जा सकेगा। उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दो याचिकाएं मद्रास हाई कोर्ट में और एक-एक याचिका बांबे व मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दायर की गई थीं। उसने इन हाई कोर्टों में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग भी की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में जारी सुनवाई पर रोक तो नहीं लगाई थी, लेकिन उन्हें अंतिम आदेश जारी करने से रोक दिया था। हाई कोर्टों में याचिकाओं में मांग की गई है कि आधार अथवा किसी भी पहचान पत्र को सोशल मीडिया अकाउंट्स के सत्यापन के लिए अनिवार्य बनाया जाए। फेसबुक ने कहा है कि सभी याचिकाओं में एक जैसी मांग की गई है। चूंकि इस मामले में किसी भी फैसले का दूरगामी प्रभाव होगा, लिहाजा फैसले में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए।

एससी-एसटी एक्ट बड़ी पीठ के हवाले पेज>>3

क्या है मामला

तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया कंपनियां भारतीय कानूनों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे अपराधियों को पकड़ने में देरी और अपराध नियंत्रण में मुश्किल होती है।

क्यों अहम है मसला

आतंकवाद को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल हुआ है, हो रहा है। इसे खत्म करने के लिए सरकार सोशल मीडिया से जुड़े कानून कड़े करने की कोशिशों में जुटी हैं। फर्जी खबरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से फैलती हैं, जिन्हें रोकना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है

कुछ बड़े सवाल हैं सामने....

अगर फेसबुक, वाट्सएप समेत अन्य कंपनियों के पास करोड़ों भारतीयों के आधार कार्ड रिकॉर्ड पहुंच गए तो सूचनाओं के दुरूपयोग का प्रश्न आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की जानकारी को अब तक निजता से जोड़कर रखा हुआ है। कोर्ट ने स्वयं कंपनियों द्वारा आधार की जानकारी लेना वैकल्पिक कर दिया है।

इससे पहले...

- **20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से कहा था कि वह सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक करने के मामले में सुनवाई जारी रखे, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाए।**
- **तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट इस मामले के विशिष्ट चरण में पहुंच गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते फैसला नहीं ले पा रहा है।**
- **फेसबुक की दलील थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं की जानकारी अपराध नियंत्रण प्राधिकारों को दें या नहीं दें, इस बारे में सबसे बड़ी अदालत को ही फैसला करना चाहिए क्योंकि इसके वैश्विक परिणाम होंगे**

अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ देना बड़ी गलती

इस्लामाबाद, एएनआइ

हर मोर्चे पर मिल रही विफलता से निराश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब आत्म अवलोकन की मुद्रा में हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ देने को पाकिस्तान की बड़ी गलती माना। इमरान के अनुसार, पाक को तटस्थ रवैया अपनाना चाहिए था। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना दो दशक से तालिबान के खिलाफ लड़ाई छेड़े हुए है।

रसिया टूडे को दिए साक्षात्कार में इमरान ने कहा, शिद्दत से महसूस करता हूं कि पाकिस्तान को इस लड़ाई से अलग रहना चाहिए था, क्योंकि इसमें शामिल होना उसके खिलाफ गया। हमारे 70 हजार लोगों की जानें गईं और 100 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। इसके बाद अमेरिका के अफगानिस्तान में न जीतने का दोष हमें दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा, कि यह पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं हो रहा। इमरान का यह वक्तव्य अक्टूबर में होने वाली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की बैठक से पूर्व दुनिया को दी जा रही सफाई माना जा रहा है। आतंकी संगठनों को मिलने वाले धन पर रोक लगाने में विफल रहे पाक को एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है। एफएटीएफ की कार्रवाई से पाक को अंतरराष्ट्रीय सहायता मिलनी मुश्किल हो जाएगी।

इमरान ने स्वीकारा आतंकी पाकिस्तान में पैदा हुए, गृह मंत्री के बाद पीएम का इकरारनामा

साक्षात्कार में इमरान ने माना कि पाक में पैदा हुए आतंकी संगठनों ने अमेरिका से धन लेकर अफगानस्तान में सोवियत रूस की सेना से लड़ाई लड़ी। अब वही संगठन पाक पर भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका की आतंकवाद निरोधी लड़ाई में शामिल होकर पाकिस्तान ने अपने लोगों को खोया और अर्थव्यवस्था बर्बाद कर ली। नतीजा यह हुआ कि पाक नकद धनराशि के लिए मोहताज हो गया। अब कई देशों व अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन लेकर काम चल रहा है। बुधवार को कुछ ऐसा ही बयान गृह मंत्री एजाज अहमद शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि पाक ने आतंकी संगठनों को पालने में अरबों रुपये खर्च किए। अब यही संगठन मुसीबत बन गए हैं। इसी के चलते दुनिया का कोई भी देश पाक के साथ नहीं खड़ा है। उन्होंने यह बात हाल में जम्मू-कश्मीर मसले पर पाक के छेड़े अभियान को समर्थन न मिलने पर कही। उन्होंने इसके लिए इमरान समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया।

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान ने फिर उगला जहर पेज>>13

गौतम नवलखा के खिलाफ मामला निराधार नहीं, गहन जांच जरूरी : बांबे हाई कोर्ट

मुंबई, प्रेट्र : बांबे हाई कोर्ट ने कहा है कि नक्सली विचारक गौतम नवलखा के खिलाफ मामला निराधार नहीं है। इस मामले में प्रथम दृष्टया सुबूत हैं, जिनकी और गहन जांच की जरूरत है। नवलखा ने अपने खिलाफ पुणे पुलिस द्वारा दर्ज एफआइआर रद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसके खिलाफ पुलिस के पास कोई सुबूत नहीं हैं उसे इस मामले में गलत ढंग से घसीटा गया है।

पुणे पुलिस ने नवलखा एवं अन्य के खिलाफ नक्सलियों से संपर्क रखने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। नक्सली विचारक के खिलाफ कोरेगांव-भीमा हिंसा से जुड़े होने का भी आरोप है। न्यायाधीश रंजीत मोरे और भारती डांगरे की पीठ ने शुक्रवार को नवलखा की याचिका खारिज करते हुए कहा, मामले में प्रथम दृष्टया सुबूत हैं।

गौतम नवलखा एवं चार अन्य 31 दिसंबर, 2017 को एल्गार परिषद के सम्मेलन के अगले दिन कोरेगांव-भीमा में भड़की हिंसा के मामले में आरोपित हैं। सभी पर माओवादियों से संपर्क रखने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ गैरकानूनी गतविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। शीर्ष कोर्ट ने सभी को अपने घर में ही नजरबंद रखने का आदेश दिया था। बाद में पुणे पुलिस को आगे की जांच जारी रखने की हरी झंडी दे दी थी।

- **बांबे हाई कोर्ट ने नक्सली विचारक की एफआइआर रद करने की याचिका को किया खारिज**

> मामले के महत्व पर विचार करने के बाद हम महसूस करते हैं कि गहन जांच की जरूरत है। मामला निराधार नहीं है और तथ्यों का अभाव भी नहीं है। -बांबे हाई कोर्ट

गौतम नवलखा फाइल फोटो

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, सीबीआइ ने किया तलब

जागरण संवाददाता, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त एवं वर्तमान एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक शुक्रवार को हटा दी। इससे राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआइ ने उनके आवास पर शुक्रवार को ही नोटिस चस्पा कर दिया है। उनको शनिवार को तलब किया गया है।

राजीव कुमार पर सारधा घोटाले के सुबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं। सारधा घोटाले की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल (एसआइटी) का गठन किया गया था, वह उसके प्रमुख थे। सीबीआइ का कहना है कि उन्होंने सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन की लाल रंग की एक डायरी व पेन ड्राइव को छिपाकर रखा है। वहीं, राजीव कुमार का कहना है कि उनके पास इस तरह की कोई डायरी नहीं है। यही वजह है कि सीबीआइ राजीव को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट में शुक्रवार को लंबी सुनवाई के दौरान सीबीआइ के अधिवक्ता ने राजीव कुमार के खिलाफ बेहद मजबूत दलीलें पेश कीं। राजीव के अधिवक्ता ने भी बचाव करने का पूरा प्रयास किया। अलबत्ता, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मधुमिता मित्रा की पीठ ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक हटा दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआइ के अधिकारियों ने बैठक कीं। इसके बाद दो अधिकारी शाम करीब 4.55 बजे राजीव कुमार के आवास पर पहुंचे। राजीव कुमार घर पर नहीं थे। इसके बाद सीबीआइ अधिकारियों ने उनके आवास की दीवार पर नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में शनिवार सुबह 10 बजे तक राजीव कुमार को सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने का जिक्र है।

- **हाई कोर्ट ने हटाई राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक**
- **जांच एजेंसी ने घर पर शुक्रवार शाम ही चस्पा कर दिया नोटिस**

कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार (फाइल फोटो)। आर्काइव

सादी वर्दी में पुलिस ने संभाला मोर्चा पेज>>5

मील का पत्थर

स्वदेशी एलसीए ने पहली बार किया 'अरेस्टेड लैंडिंग' का प्रदर्शन, रक्षा मंत्रालय ने कहा, नौसैनिक विमानन के इतिहास में सुनहरा दिन

स्वदेशी तेजस 'अरेस्टेड लैंडिंग' में भी पास

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के नौसैनिक संस्करण के विकास में एक अहम पड़ाव पार हो गया है। तेजस ने शुक्रवार को सफलतापूर्वक 'अरेस्टेड लैंडिंग' (कम जगह में लैंडिंग) करके विमान वाहक पोत पर उतरने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए परियोजना में शामिल पूरी टीम को बधाई दी है।

भारत चुनिंदा देशों में शामिल : एलसीए की पहली 'अरेस्टेड लैंडिंग' में शामिल सैन्य अधिकारियों ने बताया कि इस सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शुमार कर दिया है जिनके पास ऐसे विमान डिजायन करने की क्षमता है जो विमान वाहक पोत पर उतर सकते हैं।

आइएनएस विक्रमादित्य पर उतर सकेगा : रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 'भारतीय नौसैनिक विमानन के इतिहास में आज स्वर्ण अक्षरों का दिन है। गोवा में शॉर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी (एसबीटीएफ) आइएनएस हंस पर हुए परीक्षण ने इस विमान के भारतीय विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।'

स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक संस्करण का कम जगह में लैंडिंग (अरेस्ट लैंडिंग) का परीक्षण सफल रहा। एएनआइ

विकास में कई एजेंसियां शामिल : रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस परीक्षण ने एक नए दौर की शुरुआत की है जिसमें एक साझा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई एजेंसियां एक साथ आई हैं। तेजस का नौसैनिक संस्करण अभी विकास के चरण में है। इसके विकास में रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ विमानन विकास एजेंसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विमान अनुसंधान एवं डिजायन केंद्र, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अन्य संगठन शामिल हैं।

'टेक्स्टबुक लैंडिंग': डीआरडीओ सूत्रों ने तेजस की इस लैंडिंग को 'टेक्स्टबुक लैंडिंग' (सटीक लैंडिंग) करार दिया है। उन्होंने बताया कि दो सीटों वाले तेजस के इस नौसैनिक संस्करण ने 90 मीटर के क्षेत्र में सफलतापूर्वक 'अरेस्टेड लैंडिंग' की। पायलट ने विमान में 40 मिनट तक उड़ान भी भरी। उन्होंने बताया, 'एक सामान्य एलसीए को उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए एक किमी लंबे रनवे की जरूरत होती है। लेकिन नौसैनिक संस्करण को उड़ान भरने के लिए 200 मीटर और लैंडिंग के लिए 100 मीटर का रनवे चाहिए।'

क्या है अरेस्टेड लैंडिंग

विमान को कम जगह में उतारने के लिए रनवे पर तार लगा दिए जाते हैं। लैंडिंग के दौरान जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ता है तो वहां लगे तारों की मदद से उसकी गति को बेहद धीमा कर दिया जाता है।

छग में कांग्रेस विधायक ने अपने ही मंत्री पर लगाया घूस लेने का आरोप

नईदुनिया, अंबिकापुर : मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को अपनों के वार झेलने पड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तबादलों के एवज में मंत्री के बंगले से पैसों की मांग की जाती है। यही वजह है कि कांग्रेस नेताओं और विधायकों की अनुशंसा वाले तबादला आवेदनों की सुनवाई नहीं हुई। इसके विपरीत भाजपा के लोगों ने जो सूची बनाई, उसी के आधार पर आदेश जार कर दिया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री को भाजपा ने हाईजेक कर लिया है।

रामानुजगंज में शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बृहस्पति सिंह ने डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम पर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तबादले के एवज में शिक्षकों से छह माह का वेतन मांगा जा रहा है, जो निंदनीय है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह है कि वह ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि शिक्षा और आदिमजाति कल्याण विभाग भाजपाइयों से मुक्त हो जाए।

डूसू चुनाव में एबीवीपी का परचम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) का परचम लहराया। उसने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की है। वहीं, सचिव पद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआइ) के खाते में गया। पिछले साल भी एबीवीपी ने इन तीनों पदों पर जीत हासिल की थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विद्यार्थी परिषद को बधाई दी है। शाह ने अपने बयान में कहा, डूसू के चुनाव में एबीवीपी की भव्य विजय न सिर्फ देश के युवाओं में राष्ट्रवाद के अटूट संकल्प को दर्शाती है बल्कि यह राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के प्रति कटिबद्ध नए भारत की भी परिचायक है।

डूसू चुनाव समिति ने मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष पद पर प्रदीप तंवर और संयुक्त सचिव पद पर शिवांगी खरवाल विजयी घोषित हुईं। अक्षित ने एनएसयूआइ की चेतना त्यागी को 10 हजार से ज्यादा मतों से हराया। सचिव पद पर एनएसयूआइ के आशीष लांबा ने एबीवीपी के योगित राठी को और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की शिवांगी खरवाल ने एनएसयूआइ के अभिषेक चपराणा को हराया है। सभी पदों पर अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) तीसरे नंबर पर रहा। (पेज-2 भी देखें)

- **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,संयुक्त सचिव पद पर जीती एबीवीपी**
- **एनएसयूआइ ने सचिव के पद पर जमाया अपना कब्जा**

एबीवीपी के अध्यक्ष पद के विजेता अक्षित दहिया, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर और संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल। ध्रुव कुमार

4.44 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बवाना औद्योगिक क्षेत्र में एक जींस फैक्ट्री पर। फैक्ट्री को यह जुर्माना चुकाने के लिए दस दिन का समय दिया गया है। साथ ही इसे तत्काल प्रभाव से बंद भी कर दिया गया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 सितंबर 2019

लैंड पूलिंग दिल्ली के विकास का नया फ्रेमवर्क

योजना ▶ पुरी ने दी जानकारी, छह सितंबर तक पोर्टल के जरिये करीब साढ़े छह हजार हेक्टेयर जमीन की गई पंजीकृत

बोले, नई नीति के तहत करीब 17 लाख आवासीय इकाइयों का होगा निर्माण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को 'लैंड पूलिंग : बिल्डिंग इंडियाज कैपिटल' विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित लैंड पूलिंग नीति दिल्ली के विकास का एक नया फ्रेमवर्क है। पुरी ने बताया कि छह सितंबर 2019 तक पोर्टल के जरिये करीब साढ़े छह हजार हेक्टेयर जमीन पंजीकृत की गई। इसमें सबसे ज्यादा पंजीकरण जोन एन के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रति एक हजार हेक्टेयर भूमि में करीब 85 हजार आवासीय इकाइयों में 3,85,000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था होगी। नई नीति के तहत करीब 17 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण होगा, जिनमें से पांच लाख से भी अधिक आवासीय इकाइयां समाज के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए होंगी।

जल्द शुरू होगा मेट्रो कॉरिडोर का काम : इस दौरान पुरी ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में रुके हुए तीनों कॉरिडोरों को जल्द ही स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर कहा, सभी को पता है कि यह कॉरिडोर किसकी वजह से रुके हुए हैं, लेकिन अब बहुत देर नहीं लगेगी। केंद्र सरकार अगले कुछ ही माह में रिठाला-बवाना-नरेला, इंद्रलोक-इंद्रप्रस्, लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर को भी हरी झंडी दिखा देगी। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि लैंड पूलिंग नीति की सफलता काफी हद तक शहर के बुनियादी ढांचे के तेज, समयबद्ध नियोजन, विकास और पूंजी निवेश पर निर्भर करती है। ये इन क्षेत्रों के एकीकृत विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगा। बैजल ने कहा कि यह सम्मेलन पूलिंग नीति को सफल बनाने की दिशा में निवेशकों, साझेदारों, रियल एस्टेट डेवलपरों, बैंकिंग क्षेत्र और विशेषज्ञों को एक साथ लाने का एक बड़ा कदम है।

उन्होंने कहा कि 109 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए गए स्मार्ट सिटी समाधान इन नए शहरी केंद्रों को 'स्मार्ट पड़ोस' में बदल देंगे। नीति के तहत प्रस्तावित शहर स्तर के विकास से इन ग्रीन फील्ड क्षेत्रों में हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विश्व स्तरीय ढांचागत सुविधाएं यानी 24 घंटे पानी की आपूर्ति, बिजली, पाइप गैस कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेंगी।

सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा किया गया था। इस अवसर पर उपराज्यपाल अनिल बैजल, डीडीए के उपाध्यक्ष तरुण कपूर, फिक्की रियल एस्टेट कमेटी के प्रबंध निदेशक संजय दत्त के अलावा अनेक नगर नियोजक और बिल्डर भी उपस्थित थे।

बेहतर एफएआर से मिलेगा लाभ : लैंड पूलिंग नीति पर फिक्की में हुए सम्मेलन में यह भी सामने आया कि लैंड पूलिंग के तहत दिल्ली में निवेश करने वाले निवेशकों को फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) में छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें कम कीमत पर बेहतर जमीन मुहैया कराई जाएगी।

सम्मेलन में बिल्डरों ने भी अपनी बात रखी। एक सत्र में फिक्की रियल एस्टेट कमेटी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक संजय दत्त ने कहा कि सरकार ने बेहतर नीति बनाई है। सरकार को बिल्डरों को स्टांप ड्यूटी कम करने की दिशा में भी काम करना चाहिए। साथ ही बाहरी विकास शुल्क (ईडीसी) और जमीन फ्री होल्ड या लीज पर देने के निर्णय में भी राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सिंगल विंडो से ही बिल्डर को सभी अनुमतियां देने की पहल करनी चाहिए।

नीति को अधिक स्पष्ट बनाने की जरूरत : सम्मेलन में मौजूद बिल्डरों ने अलग-अलग जमीन के मालिकों के एक साथ आकर जमीन जोड़ने को बड़ी बाधा बताया। दिनेश डावर ने कहा कि नीति स्पष्ट नहीं है। पहले नीति में ईडीसी की राशि तय थी, लेकिन नई नीति में इसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। लोगों के एकजुट होकर आने में भी कई दिक्कतें सामने आएंगी। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने कहा कि यह भ्रांति है। कई जगह एकजुट होकर काम करने के उदाहरण हैं।

पुणे के मगरपट्टा मॉडल को सराहा : पुणे में 185 किसानों ने मिलकर 450 एकड़ जमीन पर लैंडपूलिंग योजना के तहत मगरपट्टा कॉलोनी बसाई। कार्यक्रम में मगरपट्टा को बसाने को लेकर प्रजेंटेशन दिया गया है। इस कॉलोनी को लैंडपूलिंग का बेहतरीन उदाहरण बताया गया है, जिसकी सराहना की गई। कॉलोनी के निर्माण और संचालन में सभी को शेयर दिया गया है। इससे किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसकी सफलता के बाद पुणे में लैंडपूलिंग योजना पर दो नई कॉलोनी बसाई जा रही हैं।

फिक्की में आयोजित सम्मेलन के दौरान उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। केंद्रीय मंत्री ने मेट्रो के चौथे चरण में रुके तीनों कॉरिडोर को जल्द स्वीकृति देने के संकेत दिए। जागरण

लैंड पूलिंग नीति

जमीन मालिक या मालिकों का समूह क्षेत्र विकास योजना (जेडडीपी) में परिसीमन किए गए क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकास के लिए किसी भी आकार की भूमि को पूल कर सकते हैं। इसके तहत एकत्रित की गई 60 फीसद भूमि का विकास बिल्डरों या उनके समूह द्वारा आवासीय और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, जबकि बाकी 40 फीसद भूमि का इस्तेमाल पानी, सीवरेज, बिजली सहित विभिन्न शहरी स्तर की बुनियादी सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाएगा।

कालिंदी कुंज के शिवघाट पर बनाए गए कृत्रिम तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया था। उन्हें निकालकर नदी के और करीब डाल दिया गया। विपिन शर्मा

नगर निगम ने ही डाल दीं नदी किनारे मूर्तियां

अरविंद कुमार द्विवेदी, नई दिल्ली

पर्यावरण के प्रति दिल्ली का प्रशासन व निगम कितना सजग व गंभीर है, इसकी बानगी शनिवार को दिखी। एनजीटी के आदेश पर यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों ने निगम का सहयोग करते हुए गड्ढों में गणपति विसर्जन किया। लेकिन निगम ने शनिवार को मूर्तियों को उठाकर रिज एरिया में डाल दिया। मूर्तियों के अवशेष रिज एरिया में क्यों डाले जा रहे हैं, यह पूछने पर मौके पर मौजूद कर्मचारी ने कहा कि उन्हें कृत्रिम गड्ढों की सफाई करने के लिए कहा गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि मूर्तियों के अवशेषों को कहां डाला जाए। इसलिए वह अपने हिसाब से इन मूर्तियों को फिलहाल इन गड्ढों से बाहर निकालकर खुले में रख रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि इन मूर्तियों को विसर्जन स्थल से भी करीब 100 मीटर नदी की ओर ले जाकर डाला जा रहा है। कर्मचारियों की इस लापरवाही से उस पूरी कवायद पर पानी फिर सकता है जिसके तहत इस बार यमुना के बजाय कृत्रिम गड्ढों में विसर्जन किया गया है।

हमारी जमीन पर नहीं डाल सकते अवशेष : इस बारे में दिल्ली के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विसर्जन के बाद मूर्तियों के अवशेष व पूजा सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करना निगम का काम है। वह हमारी जमीन पर इतनी बड़ी मात्रा में अवशेष जमा नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने कहा कि यह भी हो सकता है कि निगम वाले पहले अवशेषों को एक जगह एकत्र कर रहे हों और बाद में उसे ट्रकों से कहीं और ले जाया जाए।

पेड़ों की आड़ में डाल रहे अवशेष : मूर्तियों के अवशेष के ढेर लोगों को दिखाई न पड़ें, इसलिए गड्ढों से निकालकर अवशेष नदी के किनारे लगे पेड़ों के पीछे डाला जा रहा है। जबकि यह जगह नदी के और ज्यादा करीब है। जरा सी बारिश होने पर ये अवशेष बहकर फिर से नदी में चले जाएंगे। इस बारे में निगम का पक्ष जानने के लिए एसडीएमसी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक को कॉल किया गया लेकिन उन्होंने बात नहीं की।

इस तरह नुकसानदायक हैं अवशेष : प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टिक, सीमेंट, सिंथेटिक रंग, थर्मोकोल, लोहे की छड़, घास-फूस, पुआल, क्ले आदि से बनती हैं। इन्हें ऑयल पेंटों से रंगा जाता है। इनमें घातक रसायन मिले होते हैं। विसर्जन के बाद जैव अपघटनीय (बायोडिग्रेडेबल) सामग्री तो नष्ट हो जाती है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस और पेंट के घातक रसायन पानी में मिल जाते हैं। इससे पानी जहरीला हो जाता है। उसका असर जलीय वनस्पतियों, जीव-जंतुओं व इंसानों पर पड़ता है। ऑयल पेंट में मौजूद भारी धातुएं जैसे तांबा, जस्ता, क्रोमियम, कैडमियम, सीसा, लोहा, आर्सेनिक और पारा आदि जल स्रोतों में मिल जाते हैं। धातुएं नष्ट नहीं होती है, इसलिए वे धीरे-धीरे भोजन श्रृंखला का हिस्सा बनकर इंसान के शरीर में भी पहुंचती हैं और कई बीमारियों का कारण बनती हैं।

बीच-बचाव करने पर छात्र को चाकू से घायल किया

जासं, नई दिल्ली : द्वारका स्थित एक सरकारी स्कूल के दो छात्रों के बीच हो रहे झगड़े में बीच-बचाव करना एक छात्र को भारी पड़ गया। झगड़े कर रहे छात्रों में से एक ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित छात्र 12वीं में पढ़ता है। सात सितंबर को भोजनावकाश के समय वह बाथरूम गया तो देखा कि वहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले कुछ छात्र झगड़ा कर रहे थे। उसने झगड़े को शांत करने के इरादे से बीच बचाव किया, लेकिन झगड़ रहे छात्र शांत होने की बताए उससे से ही उलझ गए। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने झगड़ा खत्म कर सभी छात्रों को वहां से भेज दिया।

स्कूल की छुट्टी होने के बाद झगड़ रहे 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने दोस्तों को गेट पर बुला लिया और जैसे ही बीच-बचाव करने वाला 12वीं कक्षा का छात्र गेट पर पहुंचा तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। इसी दौरान एक लड़के ने चाकू से हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे शिक्षकों ने घायल छात्र को बचाया और अस्पताल पहुंचाया।

हांगकांग की नागरिकता हासिल करने को बना 89 साल का वृद्ध

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

81 वर्ष के बुजुर्ग का वेश धारण कर न्यूयार्क जाने की जुगत में पकड़े गए गुजरात के 32 वर्षीय युवक के मामले के ठीक चार दिन बाद ऐसा ही एक और मामला आइजीआइ एयरपोर्ट पर सामने आया है। हांगकांग की नागरिकता हासिल करने के लिए 68 वर्षीय शख्स 89 वर्ष का वृद्ध बन गया था। रूप बदलकर वह हांगकांग जाने में सफल भी हो गया, लेकिन लौटते सयम गुरुवार को वह आइजीआइ एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर पकड़ा गया। अधिकारियों को यात्री की उम्र से त्वचा के मेल न खाने से शक हुआ। आरोपित की पहचान पंजाब के मोंगा निवासी गुरदीप सिंह के रूप में हुई है। वह वहां मजदूरी करता था। एजेंट के माध्यम से उसने पंजाब में करनैल सिंह के नाम से अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया था।

आइजीआइ एयरपोर्ट पुलिस सहित अन्य एजेंसियां मामले की जांच में जुट गई हैं। आने वाले समय में फर्जीवाड़े में शामिल कई ट्रेवल एजेंटों की गिरफ्तारी संभव है। यह भी जांच की जाएगी कि क्या इसमें इमिग्रेशन अथवा अन्य विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत तो नहीं है।

एयरपोर्ट के पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया ने बताया कि 12 सितंबर को करनैल सिंह नाम का एक वृद्ध स्पाइस जेट की उड़ान संख्या एसजी-32 से हांगकांग से दिल्ली आया था। करनैल सिंह के पासपोर्ट की मुताबिक, उसकी उम्र 89 वर्ष थी। त्वचा से वह इतना वृद्ध नहीं लग रहा था। पुलिस ने जब आरोपित से पूछताछ की तो पता चला कि उसका असली नाम गुरदीप सिंह है और उसकी उम्र 68 वर्ष है।

वृद्ध बना गुजरात का युवक भी पकड़ा गया था : आठ सितंबर को आइजीआइ एयरपोर्ट पर सीआइएसएफ ने 81 वर्ष का बुजुर्ग बनकर न्यूयार्क जाने की कोशिश कर रहे गुजरात के अहमदाबाद निवासी 32 वर्षीय जयेश को दबोचा था। सुरक्षा कर्मियों को धोखा देने के लिए उसने व्हील चेयर ले रखी थी। उसने चेहरे पर वृद्ध का मेकअप किया था और पगड़ी भी बांध रखी थी। लेकिन कर्मियों को शरीर के अन्य अंगों की त्वचा से चेहरे की त्वचा मेल नहीं खाने के कारण यात्री पर शक हुआ। इसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने भी एजेंट के माध्यम से वृद्ध के नाम से फर्जी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज बना रखे थे।

एयरपोर्ट पर पकड़ा गया गुरदीप सिंह।

फर्जी पासपोर्ट के जरिये 2008 से भारत आता-जाता रहा

गुरदीप पहली बार अपने असली पासपोर्ट से वर्ष 1995 में हांगकांग गया था। इसके बाद से वह वहां लगातार आता-जाता रहा। वह वहां की नागरिकता (परमानेंट आइडी) पाने की जुगत में लगा था। अधिकारियों के अनुसार, चूंकि अधिक उम्र वालों को हांगकांग की नागरिकता आसानी से मिल जाती है, इसलिए उसने 2006 में पंजाब के एक एजेंट के जरिये फर्जी पासपोर्ट बनवाया। इसमें फोटो तो उसका ही लगा था, लेकिन बाकी चीजें बदल दी गईं। करनैल सिंह बना गुरदीप 2008 में फर्जी पासपोर्ट के आधार पर हांगकांग चला गया। फर्जी नाम पर उसने वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली और भारत आता-जाता रहा। अंतिम बार वह अगस्त 2018 में हांगकांग गया था। पुलिस ने बताया कि वह पगड़ी बांधे रहता था ताकि बाल को देख कोई उस पर शक न कर बैठे।

एएमयू में दाखिले की बेरहम कोचिंग से बचकर भागा बच्चा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

- **प्रतिदिन पढ़ाई का लक्ष्य पूरा न होने पर पीटते थे शिक्षक**
- **भूखा-प्यासा दो दिन रेलवे स्टेशन पर भटकता रहा बच्चा**

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में छठवीं कक्षा में दाखिले के लिए कोचिंग कर रहा कक्षा चार का बच्चा पिटाई के चलते भागकर शुक्रवार को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। जीआरपी को वह प्लेटफॉर्म पर मिला। जीआरपी ने उसे परिजनों को सौंप दिया। परिजन कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने जा रहे हैं।

जीआरपी के अनुसार पूछताछ में बच्चे ने बताया कि शहर की बैंक कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर में उसे प्रतिदिन पढ़ाई करने का लक्ष्य दिया जाता था और लक्ष्य पूरा न होने पर बेरहमी से पिटाई की जाती थी। खाना भी नहीं दिया जाता था। बच्चा बुधवार को कोचिंग सेंटर से बाजार में चाऊमीन खाने के बहाने से भाग निकला। यहां से वह अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उसके पास महज 20 रुपये थे। भूख लगने पर उसने 20 रुपये के बिस्किट खा लिए। वह दो दिन तक भूखा-प्यासा रेलवे स्टेशन पर भटकता रहा। गुरुवार देर रात को बच्चा ट्रेन में बैठकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। यहां वह जीआरपी को रोते हुए मिला। जीआरपी ने बच्चे से उसके घर का फोन नंबर लेकर कॉल कर जानकारी दी। अलीगढ़ के खैर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बच्चे के पिता बीएसएफ में त्रिपुरा में तैनात हैं। बेटे के लापता होने की सूचना मिलते ही वह त्रिपुरा से अलीगढ़ पहुंचे। माता-पिता समेत पूरा परिवार बच्चे तलाश में जुटा हुआ था। जब शुक्रवार को परिजनों ने बच्चे को घर पहुंचकर नहलाया तो उसकी कमर पर पिटाई के निशान थे। बच्चे की मां का कहना है कि वह कोचिंग सेंटर संचालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर संचालक ने दो साल बाद कक्षा छह में दाखिला कराने का दावा किया था।

बच्चे ने जीआरपी को बताया कि कोचिंग सेंटर में सभी बच्चों पर खेलने, टीवी देखने और इंटरनेट के इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रखी है। कोचिंग सेंटर में ही बच्चों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। बच्चों को पौष्टिक भोजन नहीं दिया जाता।

-अशोक सिसौदिया, थाना प्रभारी, जीआरपी गाजियाबाद

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनेगी नीति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही एग्रीगेटर नीति (निजी व सरकारी वाहनों को एक साथ लाने की नीति) लाएगी। इससे निजी बस ऑपरेटर भी दिल्ली में अपनी बसें चला सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस नीति को लाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस नीति को घोषित कर इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। इससे बड़े स्तर पर प्राइवेट सेक्टर के लोग लग्जरी बसों को चलाने में पैसा लगाएंगे। इससे निजी वाहनों पर चलने वाले लोगों का रुझान सार्वजनिक वाहनों की तरफ बढ़ेगा। इन बसों की आवाजाही के लिए एप बनाया जाएगा। एग्रीगेटर वह नीति है, जिसमें प्राइवेट बस आपरेटरर्स को बढ़ावा दिया जाता है।

उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाना बहुत जरूरी है। इसके तहत दिल्ली में 4,000 बसें अगले आठ-दस महीने में आ जाएंगी। इसमें एक हजार इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी। वहीं दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों के रूट का निर्धारण नए सिरे से किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया एक साल से चल रही है। इससे भी बसों की उपलब्धता काफी बढ़ जाएगी। मेट्रो फेस-4 लागू हो रहा है। सभी जगह से स्वीकृति आ चुकी है। लोगों को कॉलोनी के बाहर परिवहन सुविधा मुहैया कराना सरकार का लक्ष्य है।

समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न

किशन कुमार, नई दिल्ली

डूसू चुनाव के नतीजे घोषित होते ही किंग्सवे कैंप स्थित पुलिस लाइन में बनाए गए मतगणना केंद्र के बाहर एबीवीपी व एनएसयूआइ के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने ढोल-नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया। पिछले वर्ष हुई हिंसा को देखते हुए इस बार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर रखी थी। केंद्र को बाहर से पर्दे से ढका गया था, जिससे कि अंदर चल रहीं गतिविधियां कोई देख न सके। मतगणना केंद्र में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। केंद्र के बाहर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ अर्द्धसैनिक बल की टुकड़ियां मोर्चा संभाले हुए थीं। सुबह करीब पौने ग्यारह बजे तक रुझान आने शुरू हो गए थे। शुरू से ही एबीवीपी ने बढ़त बना रखी थी। दोपहर ढाई बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के उम्मीदवार काफी मतों से आगे निकल चुके थे। ऐसे में केंद्र के बाहर जुटे एबीवीपी समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं, सचिव पद को लेकर एनएसयूआइ व एबीवीपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। दोनों छात्र संगठन शक्ति प्रदर्शन कर रहे और सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक रहे थे।

दोपहर करीब साढ़े तीन बजे जैसे ही चुनावी नतीजे घोषित हुए तो एबीवीपी व एनएसयूआइ समर्थकों में उम्मीदवारों के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। मतगणना केंद्र से निकले विजयी उम्मीदवारों को कंधे पर उठाकर स्वागत किया।

डूसू चुनाव में एबीवीपी को मिली भारी जीत के बाद विवेकानंद प्रतिमा के आगे छात्रों ने पर्चे उड़ाकर कुछ इस अंदाज में खुशी मनाई। जागरण

डूसू चुनाव में खूब हुआ नोटा का इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में चारों पदों पर कुल 27 हजार 576 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। अध्यक्ष पद पर 5,495 मतदाताओं ने, उपाध्यक्ष पद पर 7879, सचिव पद पर 6507 और संयुक्त सचिव पद पर 7695 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। डूसू चुनाव में नोटा चौथे स्थान पर रहा।

चुनाव में थे 16 उम्मीदवार : डूसू चुनाव में 16 उम्मीदवार चार पदों पर खड़े हुए थे। मुख्य छात्र संगठनों के अलावा अध्यक्ष पद पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन के उम्मीदवार, उपाध्यक्ष पद पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन (इनसो) व एक निर्दलीय और संयुक्त सचिव पद पर एक निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था।

उम्मीदवारों को मिले वोट

अध्यक्ष पद	
अक्षित दहिया (एबीवीपी)	29,685
चेतना त्यागी (एनएसयूआइ)	10,646
दामिनी कैन (आइसा)	5,886
रोशनी (एआइडीएसओ)	1,460
नोटा	5,495
उपाध्यक्ष पद	
प्रदीप तंवर (एबीवीपी)	19,858
अंकित भारती (एनएसयूआइ)	11,284
आफताब आलम (आइसा)	8,217
दिपिन छजलाना (इनसो)	1,899
आलम वर्गीज (निर्दलीय)	3,896
नोटा	7,879
सचिव पद	
आशीष लांबा (एनएसयूआइ)	20,934
योगित राठी (एबीवीपी)	18,881
विकास कुमार (आइसा)	6,804
नोटा	6570
संयुक्त सचिव पद	
शिवांगी खरवाल (एबीवीपी)	17,234
अभिषेक चपराणा (एनएसयूआइ)	14,320
चेतना (आइसा)	3,025
हरीस मलिक (निर्दलीय)	3,025
नोटा	7,695

हालात

आवासीय योजना 2019 के बचे हुए ईडब्ल्यूएस फ्लैट डीडीए के लिए बने जी का जंजाल, ऑनलाइन स्कीम में सभी फ्लैट 10 से 40 फीसद तक की रियायती दरों पर दिए जा रहे हैं

आधी कीमत के बावजूद नहीं बिक रहे फ्लैट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना 2019 के बचे हुए ईडब्ल्यूएस फ्लैट अब डीडीए के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। 40 फीसद तक कीमत घटाने के बावजूद इन्हें लेने में लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। आलम यह कि इन फ्लैटों को बेचने के लिए नए सिरे से निकाली गई स्कीम में भी 15 दिनों के दौरान करीब 15 ही आवेदन आए हैं, जबकि फ्लैटों की संख्या साढ़े सात हजार से भी ज्यादा हैं। हताश-निराश डीडीए अब इन फ्लैटों को सरकारी कर्मचारियों के जरिये ठिकाने लगाने पर विचार कर रहा है।

6,536 फ्लैट 40 जबकि 960 फ्लैट 10 फीसद छूट पर उपलब्ध : इन फ्लैटों के लिए 30 अगस्त से शुरू की गई ऑनलाइन स्कीम में सभी फ्लैट 10 से 40 फीसद तक की रियायती दरों पर दिए जा रहे हैं। निर्माण लागत में 40 फीसद छूट नरेला के पॉकेट 1 ए, 1 बी और 1 सी में बने 6,536 फ्लैटों पर है, जबकि पाकेट जी 7/जी 8, सेक्टर ए में बने 960 फ्लैटों पर यह छूट 10 फीसद की है।

थमाए जा सकते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को

सूत्रों की मानें तो डीडीए अब इन फ्लैटों को केंद्र सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवंटित कर सकता है। इस आशय का प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

पांच लाख तक कीमत हुई कम : आवासीय योजना 2019 में दो श्रेणी के ईडब्ल्यूएस फ्लैट लांच किए गए थे। कुछ फ्लैट तो पुराने बने हुए थे, जबकि 6,536 फ्लैट नए थे। नए बने फ्लैटों में पार्किंग एवं लिफ्ट की सुविधाएं भी हैं। डीडीए की ओर से इन नए फ्लैटों की कीमत 17 से 19 लाख रुपये तक रखी गई थी, लेकिन 40 फीसद की छूट के बाद इनकी कीमत में पांच लाख रुपये तक का अंतर आ गया है। इसी तरह पुराने बने फ्लैटों की कीमत 10 लाख रुपये है, जिन पर 10 फीसद की छूट दी जा रही है। आवेदकों के मुताबिक इन फ्लैटों का आकार काफी छोटा है। जल बोर्ड के पानी का नेटवर्क भी नहीं है और परिवहन के साधनों की भी यहां समस्या है।

यह सही है कि नरेला के इन ईडब्ल्यूएस फ्लैटों को लेकर अब तक कोई खास रिस्पांस नहीं आया है। लेकिन स्कीम की अंतिम तिथि यानी 31 अक्टूबर तक हमारे पास समय है। उम्मीद है कि इन फ्लैटों में से काफी बिक जाएंगे। बचे फ्लैटों के लिए कोई दूसरी योजना बनाई जाएगी।

-तरुण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए।

आप विधायक की गिरफ्तारी पर रोक 21 तक बढ़ी

जासं, नई दिल्ली : नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने जांच अधिकारी को अखिलेश पति त्रिपाठी की मेडिकल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वर्तमान में वह एक निजी अस्पताल बीजेआरएम में भर्ती हैं।

गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए आप विधायक ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। न्यायाधीश ने 11 सितंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इस वारदात के अलावा विधायक पर चार और आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप विधायक फिलहाल एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर सवाल उठाते हुए विशेष न्यायाधीश ने पूछा कि विधायक का सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा है। हालांकि अदालत ने आप विधायक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर लगी रोक को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है।

देश भर में इस साल खुलेंगे 4000 आयुष स्वास्थ्य केंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- **सफदरजंग अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केंद्र और सिद्ध क्लीनिक अनुसंधान इकाई का हुआ उद्घाटन**

केंद्र सरकार के सफदरजंग अस्पताल में आयुष को बढ़ावा देने के लिए यूनानी चिकित्सा केंद्र व सिद्ध क्लीनिक अनुसंधान इकाई की शुरुआत की गई है। शुक्रवार को आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने इसका उद्घाटन किया। सफदरजंग में मरीजों के इलाज के साथ ही इन दोनों विधाओं में शोध भी हो सकेगा। इस साल देश भर में आयुष के चार हजार स्वास्थ्य केंद्र खोलने की सरकार की योजना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में विशेष रुचि ले रही है। आयुष के इस्तेमाल से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो सकती है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत डेढ़ लाख स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटरों में आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा देश में 12,500 आयुष स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। इसमें से चार हजार आयुष स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र इसी साल शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में देश के विभिन्न हिस्सों से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं।

सफदरजंग अस्पताल में यूनानी चिकित्सा केंद्र और सिद्ध क्लीनिक अनुसंधान इकाई के शुरू होने से इन चिकित्सा पद्धतियों से भी मरीजों का इलाज हो सकेगा। कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद व केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जर्नल ऑफ रिसर्च इन सिद्ध मेडिसिन के द्वितीय अंक का विमोचन भी किया गया।

25 फीसद किराये में कमी की गई है एसी चेयर कार व एक्जीक्यूटिव क्लास सिटिंग वाली चुनिंदा ट्रेनों में। इन ट्रेनों में शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर जैसी ट्रेनें शामिल हैं।

एससी–एसटी कानून बड़ी पीठ के हवाले

बड़ा मसला ▸ तत्काल गिरफ्तारी पर रोक के फैसले पर केंद्र ने दाखिल की थी पुनर्विचार याचिका

हालांकि संसद ने फैसले को निष्प्रभावी कर पुरानी व्यवस्था कर दी है बहाल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था, सरकार मानती है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला गलत

अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निरोधक कानून में तत्काल गिरफ्तारी और एफआइआर दर्ज करने पर रोक लगाने वाले कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनवाई करेगी। शुक्रवार को दो न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए तीन न्यायाधीशों की पीठ को विचार के लिए भेज दिया है। हालांकि कोर्ट के उस फैसले का अब कोई महत्व नहीं रह गया है क्योंकि सरकार ने संसद से कानून पारित कर फैसले को निष्प्रभावी करते हुए पुराने कड़े प्रावधान फिर बहाल कर दिए हैं। संशोधित कानून की वैधानिकता को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और याचिकाएं अभी लंबित हैं।

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 20 मार्च, 2018 को एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इस कानून में तत्काल गिरफ्तारी और एफआइआर दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही अभियुक्त की अग्रिम जमानत के रास्ते भी खोल दिए थे। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून के तहत जब भी शिकायत आएगी, पहले उसकी प्रारंभिक जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि शिकायत कहीं झूठी तो नहीं है। जांच अधिकारी संतुष्ट होने के बाद ही एफआइआर दर्ज करेगा। कोर्ट ने तत्काल गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी थी और कहा था कि आरोपित की गिरफ्तारी से पहले सक्षम अधिकारी या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की इजाजत लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का देशव्यापी विरोध हुआ था। जिसके बाद सरकार ने कानून में संशोधन कर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। यानी यह मामला पुराने फैसले पर है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने केंद्र सरकार की पुनर्विचार याचिका को तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजते हुए कहा कि मामले के महत्व को देखते हुए उनका मानना है कि इस पर तीन न्यायाधीशों की पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। पुनर्विचार याचिका पर बहस के दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा था कि कानून में संशोधन जरूर हो गया है, लेकिन सरकार मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। इसलिए कानून संशोधन के बावजूद कोर्ट पहले पुनर्विचार याचिका पर फैसला दे और बाद में संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे। इन दलीलों पर कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर पहले सुनवाई कर गत मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

संशोधित कानून भी है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन : हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लंबित होने के दौरान ही सरकार ने संसद से कानून संशोधन विधेयक पास कर कानून में संशोधन कर पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। इस कानून को विभिन्न याचिकाओं के जरिये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने गत वर्ष सात सितंबर को याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया था। हालांकि कोर्ट ने संशोधित कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता प्रिया शर्मा कहती हैं कि पुनर्विचार याचिका तीन न्यायाधीशों की पीठ को जाने के बाद वह अपनी कानून को चुनौती देने वाली याचिका भी मेंशन करके उसी के साथ लगाने का अनुरोध करेंगी। क्योंकि पहले भी दोनों मामले एक ही पीठ के सामने लगे थे। कोर्ट को दोनों मामले साथ ही साथ सुनने होंगे।

झटका

आइएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की समर्पण अर्जी खारिज

जासं, नई दिल्ली : आइएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आत्मसमर्पण याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को चिदंबरम की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि मनी लांड्रिंग मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेना जरूरी है, लेकिन उन्हें सही समय पर हिरासत में लिया जाएगा। वह पहले से ही सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत मे हैं और ऐसे में साक्ष्य से छेड़छाड़ होने की गुंजाइश नहीं है। चिदंबरम की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि ईडी का जवाब गलत है और सिर्फ चिदंबरम को पीड़ा देने वाला है।

हमसफर का घटा किराया स्लीपर कोच भी लगेंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ रेलवे ने मालभाड़ा घटाने के बाद यात्री किराया भी घटाया

हमसफर फाइल फोटो

मालभाड़े में रियायत के बाद अब यात्री किराए में भी छूट का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत प्रीमियम 'हमसफर' ट्रेनों से की गई है। इन ट्रेनों में आरक्षण की मांग में गिरावट को देखते हुए रेलवे ने फ्लेक्सी किराए को खत्म करने के साथ तत्काल किराए में कमी का ऐलान किया है। इसी के साथ इन ट्रेनों में स्लीपर क्लास के कोच लगाने का निर्णय भी लिया गया है। अभी इन ट्रेनों में केवल थर्ड एसी के कोच लगते हैं। वस्तुतः शुक्रवार को आनंद विहार-इलाहाबाद हमसफर में चार स्लीपर कोच लगा भी दिए गए। ये राहत 35 जोड़ा हमसफर ट्रेनों में लागू होगी।

तत्काल टिकट भी हुआ सस्ता : रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि हमसफर ट्रेनों के तत्काल टिकट की दरें भी कम की गई हैं। अब इनके तत्काल टिकट के लिए डेढ़ गुना के बजाय केवल 1.3 गुना किराया देना होगा। इसका मतलब हुआ कि अब हमसफर के तत्काल टिकट भी सामान्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के तत्काल टिकट की दर (यानी हमसफर का बेस किराया प्लस क्लास के अनुसार सामान्य तत्काल किराया) पर मिलेंगे। यही नहीं, अब हमसफर का बेस फेयर मेल-एक्सप्रेस ट्रेनो के बेस फेयर से 1.15 गुना होगा। अब तक ये सुपरफास्ट ट्रेनो के बेस फेयर का 1.15 गुना होता था।

करंट बुकिंग के टिकट में भी छूट : पहली चार्टिंग के बाद हमसफर के टिकट बेस फेयर में 10 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ बेचे जाएंगे। इन कदमों से भी हमसफर के प्रभावी किराए में कमी आएगी। ये राहत अग्रिम आरक्षण अवधि से लागू मानी जाएगी। इसके लिए पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इससे कुछ सप्ताह पहले रेलवे एसी चेयर कार व एक्जीक्यूटिव क्लास सिटिंग वाली चुनिंदा ट्रेनों के किरायों में 25 प्रतिशत तक की रियायत देने का ऐलान कर चुकी है। इनमें शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर तथा इंटरसिटी ट्रेने शामिल हैं।

यही नहीं बृहस्पतिवार को ही रेलवे ने मालभाड़े में 15-20 प्रतिशत तक की छूट देने का एलान किया था।

राहत

रॉबर्ट वाड्रा को विशेष अदालत ने दी विदेश जाने की अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मनी लांड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत पर चल रहे रॉबर्ट वाड्रा को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने विदेश जाने की अनुमति दे दी। प्रवर्तन निदेशालय के विरोध को नजरअंदाज करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने वाड्रा को 25 लाख के मुचलके पर 21 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्पेन जाने की अनुमति दी है।

विशेष अदालत ने कहा, ईडी का पूरा मामला मुख्य तौर पर दस्तावेज पर आधारित है, जबकि ईडी यह बताने में नाकाम रही है कि किसी भी स्तर पर वाड्रा ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है। बगैर किसी आधार के जांच एजेंसी मान रही है कि वाड्रा दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। वाड्रा दिल्ली के रहने वाले हैं और समाज में उनकी अलग पहचान है। उनके परिवार की संपत्ति भी भारत में ही है। ऐसे में सभी पहलुओं को देखते हुए आवेदक को स्पेन जाने की अनुमति दी जाती है। देश छोड़ने से पहले वाड्रा को अदालत को सूचना देनी होगी। साथ ही जांच एजेंसी को स्पेन का पता व मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराना होगा। वाड्रा दस्तावेजों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ज्ञात हो, वाड्रा ने व्यापार के सिलसिले में 21 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति की मांग की थी।

जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति मानने के लिए क्या जरूरी

माला दीक्षित, नई दिल्ली

▸ राम जन्मस्थान को न्यायिक पक्ष बनाने का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए उसकी ओर से जमीन पर मालिकाना हक का दावा किये जाने का विरोध कर रहे मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो जन्मस्थान को देवता की तरह न्यायिक व्यक्ति मानने के लिए जरूरी होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जब कहा, जमीन का टुकड़ा न्यायिक व्यक्ति कैसे माना जा सकता है और उसकी ओर से मुकदमा कैसे दाखिल किया जा सकता है तो कोर्ट ने उन पर सवालों की झड़ी लगा दी।

धवन ने रामलला के मुकदमे में जन्मस्थान को भी पक्षकार बनाने का विरोध करते हुए कहा कि 1989 में (रामलला की ओर से) जन्मभूमि पर मालिकाना हक का मुकदमा दाखिल किया गया। एक नई अवधारणा पैदा हुई जिसमें स्थान को न्यायिक व्यक्ति बताते हुए उसकी ओर से मुकदमा दाखिल किया गया। जमीन का टुकड़ा न्यायिक व्यक्ति कैसे हो सकता है। हिंदू पक्ष का मामला आस्था पर आधारित है। वे धार्मिक ग्रंथों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट को कानूनी पहलू भी देखना होगा। इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, उन्होंने मौखिक सुबूत भी पेश किये हैं। धवन ने कहा, 1950 के पहले का कौन सा मौखिक सुबूत उपलब्ध है। जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ ने कहा, हिंदुओं ने सुबूत दिये हैं। उनका कहना है कि जन्मस्थान न्यायिक व्यक्ति है। जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि आस्था पर सवाल नहीं हो सकता। जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति मानने के सवाल पर विचार हो सकता है।

धवन ने कहा, पहली बार 1989 में जन्मस्थान को न्यायिक व्यक्ति बताया गया। जस्टिस बोबडे ने कहा, इससे पहले कौन सा मौका आया था जब वह बताते कि यह जन्मस्थान है और यह न्यायिक व्यक्ति है। जस्टिस भूषण ने कहा, न्यायिक व्यक्ति कानून एक विकसित हो रही अवधारणा है। इसके 500 साल से होने की बात नहीं की जा सकती, लेकिन इस मामले में इस विकसित होती अवधारणा के दूरगामी परिणाम होंगे। अगर कोर्ट पूरे क्षेत्र को देवता मानने की दलील मान लेगा तो किसी दूसरे का उस पर कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। तभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वह बताएं कि देवता की ऐसी कौन सी विशेषताएं है जो किजन्मस्थान को देवता की तरह न्यायिक व्यक्ति मानने के लिए जरूरी होनी चाहिए। जिस पर विचार हो। धवन ने कहा कि हिंदू कहते हैं कि पहाड़, सरोवर, नदी सभी की पूजा होती है लेकिन मेरी दलील है कि यह वैदिक संस्कृति है जिसमें सूर्य-चंद्र सबकी पूजा होती है लेकिन उन्हें यहां नहीं बुलाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि उस स्थान की पवित्रता को लेकर हिंदुओं की आस्था है। धवन ने कहा कि जगह की पवित्रता होती है। संगम को पवित्र जगह माना जाता है लेकिन हर चीज को नहीं माना जा सकता। स्थान पवित्र होता है। काबा को भी पवित्र स्थान माना जाता है। उसमें दिव्यता अंतरनिहित है। जस्टिस बोबडे पूछा कि काबा स्वयंभू है या निर्मित है। इस पर वकील एजाज मकबूल ने कहा कि इसे पैगम्बर ने बनाया था। कोर्ट ने सवाल किया कि स्वयंभू किसे कहते हैं। धवन ने कहा, स्वयं भू (देवता) उसे कहते हैं जो आकार लेता है जैसे बर्फ जब लिंगम का आकार लेती है तो शिवलिंग की पूजा होती है। इस पर बोबडे ने कहा कि स्वयंभू खुद में विद्यमान है वह सृजित नहीं होता।

रामलला के निकट मित्र का किया विरोध : धवन ने रामलला के निकट मित्र बनकर देवकी नंदन अग्रवाल द्वारा मुकदमा दाखिल करने का विरोध करते हुए कहा कि अगर इस तरह किसी को भी देवता का निकट मित्र बनकर मुकदमा दाखिल करने की इजाजत दी जाएगी तो इससे तबाही आ जाएगी कोई भी आकर मुकदमा दाखिल कर देगा।

वहां बाबरी मस्जिद थी और मुस्लिम करते थे नियमित नमाज : मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील जफरयाब जिलानी ने हिंदू पक्ष की वहां मस्जिद न होने और 1934 के बाद से नमाज न पढ़े जाने की दलील का विरोध करते हुए कहा कि अयोध्या में उस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी और मुसलमान वहां 1934 से 1949 तक नियमित नमाज पढ़ते थे। जिलानी ने अपनी बात साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज भी कोर्ट के समक्ष पेश किये जिसमें इमाम के वेतन और 1934 में हुए दंगे में मस्जिद के कुछ टूट गए हिस्से के पुनर्निर्माण और मुआवजा दिये जाने से संबंधित थे।

विवादित ढांचा गिराने के मामले की सुनवाई कर रहे जज का कार्यकाल बढ़ा

नई दिल्ली, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 1992 में विवादित ढांचा ढहाने के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने कार्यकाल बढ़ाने संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती भी इस मामले का सामना कर रही हैं। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पेश किए गए शपथपत्र और आफिस मेमो का अवलोकन किया। उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी ने पीठ से कहा कि उन्होंने शीर्ष कोर्ट के निर्देशों का पालन कर लिया है। विशेष न्यायाधीश का कार्यकाल विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया गया है। मामले का निस्तारण करते हुए पीठ ने कहा, 'हम संतुष्ट हैं कि जरूरी काम कर लिया गया है।' शीर्ष कोर्ट ने 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव के आग्रह पर विचार करने को कहा था। शीर्ष कोर्ट ने 19 जुलाई को विशेष न्यायाधीश के कार्यकाल को सुनवाई पूरी होने और फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने जा रहे विशेष न्यायाधीश को केवल मामले में सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने के लिए विस्तार दिया जाएगा। शीर्ष कोर्ट ने उन्हें नौ महीने के भीतर फैसला सुनाने के लिए कहा था।

2020 के पहले 150 रेलवे स्टेशन होंगे 'ग्रीन'

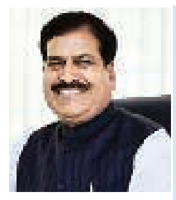

सुरेश अंगदी फाइल फोटो

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक कार्य पूरा करने का आह्वान

नई दिल्ली, प्रेट्र : अगले वर्ष यानी 2020 के पहले देश के 150 रेलवे स्टेशन 'ग्रीन' बनेंगे। रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगदी ने रेलवे अधिकारियों को इस संबंध में अगले वर्ष दो अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक यह कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

रेल राज्यमंत्री कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) और रेलवे मंत्रालय के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अंगदी ने कहा कि रेलवे का ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ाने पर विशेष जोर है। उन्होंने कहा, 'मैं इस अवसर पर सीआइआइ और रेलवे से आह्वान करता हूं कि दोनों मिलकर देश के 150 रेलवे स्टेशनों को ग्रीन स्टेशनों के रूप में बदलने के अभियान में जुट जाएं ताकि हम अगले वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को बड़े गर्व से मना सकें।' उन्होंने कहा कि इस समय देश के 12 रेलवे स्टेशन, पांच उत्पादन इकाइयां, 44 वर्कशॉप तथा 11 भवन 'ग्रीन सर्टिफाइड' हैं।

समझौते में दोनों संगठनों के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय के अलावा उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं में ऊर्जा प्रबंधन की कुशल गतिविधियों को शामिल करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ाना तथा उनके माध्यम से ऊर्जा और पर्यावरण पर सर्वोत्तम तरीकों को निरंतर साझा करना जैसी बातें शामिल हैं। रेल राज्यमंत्री ने कहा कि रेलवे हमेशा पर्यावरण को बढ़ावा देने के अभियान में शामिल रहा है।

रेलवे को 97 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष बचत : सीआइआइ ने पहले जुलाई 2016 में रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, रेलवे स्टेशनों, भवनों, उत्पादन इकाइयों और कार्यशालाओं में ऊर्जा प्रबंधन के साथ-साथ उन्हें 'ग्रीन' बनाने की दिशा में काफी काम हुआ। इन प्रयासों और पहलों के कारण रेलवे को प्रतिवर्ष 97 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

तीन तलाक कानून के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब–तलब

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाले कानून के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आंध्र प्रदेश के मुस्लिम वकीलों के संगठन की तरफ से यह याचिका दायर की गई है।

जस्टिस एनवी रमना ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी जोड़ दिया है। इस कानून के तहत एक बार में तीन तलाक को अपराध बनाया गया है। तीन तलाक देने पर तीन साल तक कैद की सजा का प्रावधान भी किया गया है। बिना वारंट के ही आरोपित की गिरफ्तारी भी की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है।

दो को छोड़ काली सूची से सभी सिख हुए बाहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▸ सूची में 314 सिखों का नाम था शामिल, अब बचे केवल दो

▸ अब यह 312 सिखों और उनके परिजनों का भारत आना होगा संभव

गुरुनानक देव की 550वीं जयंती के ठीक पहले मोदी सरकार ने वर्षों से विदेश में रह रहे उन सिखों को बड़ी राहत दे दी है, जिन्हें सरकार ने काली सूची में डाल रखा था। सरकार ने सूची में शामिल 314 में से 312 सिखों को बाहर कर दिया है। अब ये सिख और उनके परिजनों का भारत आना संभव हो सकेगा। यही नहीं, जरूरी मापदंड पूरा करने पर वे प्रवासी भारतीय (ओसीआइ) कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकेंगे।

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 1980 के दशक में देश-विदेश के कई सिख भारत विरोधी दुष्प्रचार के प्रभाव में आ गए थे। विदेश में रहने वाले बहुत से सिख भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए, वहीं देश से कई सिखों ने पलायन कर विदेश में राजनीतिक शरण ले ली। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण विदेश में रहने वाले 314 सिखों को काली सूची में शामिल कर दिया गया। परिणामस्वरूप उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को भारतीय वीजा जारी करने पर रोक लग गई। समय-समय पर इस काली सूची की समीक्षा के बाद इसमें कुल 314 सिख बचे हुए थे।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, काली सूची से बाहर किए जाने के बाद अब वे सिख और उनके परिजन भारत आ सकेंगे और सिख समुदाय से जुड़े धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही वे अपने पैतृक गांव भी जा सकेंगे। इससे उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलेगा। भारत में गुरुनानक देव की 550वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियां चल रही हैं। जाहिर है विदेश में बसे सिख समुदाय के लोग इस दौरान अपने धार्मिक स्थलों का दर्शन करने की योजना बना रहे हैं। काली सूची से बाहर होने के बाद इन लोगों के परिवारों को भी यह मौका मिल सकेगा। वैसे सुरक्षा कारणों से गृहमंत्रालय ने काली सूची में बच गए दो सिखों का नाम बताने से इन्कार कर दिया।

इंटरपोल ने नीरव मोदी के भाई नेहल के खिलाफ जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस

▸ पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपित नीरव का छोटा भाई है

▸ बेल्जियम के नागरिक नेहल पर नीरव की मदद करने का है आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंटरपोल ने 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपित नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मनी लांड्रिंग के आरोपों पर बेल्जियम के नागरिक नेहल (40 साल) के खिलाफ वैश्विक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। मनी लांड्रिंग मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है।

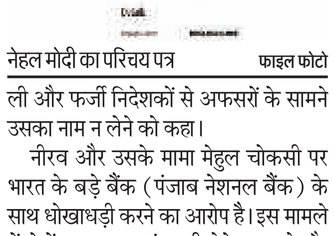

नेहल मोदी का परिचय पत्र फाइल फोटो

इंटरपोल या अंतरराष्ट्रीय पुलिस की ओर से जारी आरसीएन के अनुसार, नेहल दीपक मोदी का जन्म बेल्जियम के एंटवर्प में तीन मार्च 1979 को हुआ और वह अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी भाषा जानता है। ईडी ने इस मामले में दायर किए गए आरोपपत्र में नेहल को नामजद किया है। नेहल पर सुबूतों को नष्ट करने तथा नीरव के गैरकानूनी कार्यों की जानकारी होने के बावजूद उसकी मदद करने का आरोप है। ईडी ने आरोप लगाया कि पीएनबी घोटाले के सामने आने के बाद नेहल ने नीरव के विश्वासपात्र और कार्यकारी मिहिर आर. भंसाली के साथ दुबई से 50 किलोग्राम सोना और अच्छी खासी नकदी ली और फर्जी निदेशकों से अफसरों के सामने उसका नाम न लेने को कहा।

नीरव और उसके मामा मेहुल चोकसी पर भारत के बड़े बैंक (पंजाब नेशनल बैंक) के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस मामले में दोनों पर मुख्य षड्यंत्रकारी होने का आरोप है। यह बैंक धोखाधड़ी पिछले साल सामने आयी थी। आरोप है कि इस घोटाले में नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की। नीरव मोदी फिलहाल लंदन की जेल में बंद है और भारत में अपने प्रत्यर्पण के मुकदमे का सामना कर रहा है। बताया जाता है कि चोकसी एंटीगुआ में शरण लिए हुए है। इंटरपोल ने पहले धन शोधन मामले में नीरव मोदी, उसकी बहन पूर्वी मोदी और भंसाली के खिलाफ आरसीएन जारी किया था। सीबीआइ भी बैंक धोखाधड़ी के इस मामले की जांच कर रही है।

क्या है आरसीएन

किसी देश में अपराध करने के बाद फरार होने वाले को वहां के कानूनों के मुताबिक भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद संबंधित देश इंटरपोल से ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह करता है। किसी भगोड़े के खिलाफ जारी अपने आरसीएन में इंटरपोल 192 सदस्य देशों से उस व्यक्ति के वहां पाए जाने पर गिरफ्तार करने या हिरासत में लेने के लिए कहता है। इसके बाद उस व्यक्ति की उसके देश में वापसी या प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की मंजूरी का शतक

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : जनता से संवाद की जरूरत में रेडियो की ताकत को देखते हुए मोदी सरकार ने 118 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार के इस कदम के बाद जल्द ही ये सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना प्रसारण भी शुरू कर देंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय की सौ दिन की उपलब्धियों में सामुदायिक रेडियो को शामिल करते हुए जावडेकर ने कहा कि अगले चार से छह महीने में सभी नये मंजूर किए गए सामुदायिक रेडियो केंद्र अपने कार्यक्रम प्रसारित करने लगेंगे। मंत्रालय ने सभी मंजूर नये रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए आधिकारिक पत्र जारी कर दिए हैं। इन 118 नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में से 16 माओवादी हिंसा प्रभावित जिलों में खोले जाएंगे। जबकि 25 तटीय जिलों में और 17 विकास के लिए आकांक्षी जिलों में स्थापित किए जाने हैं। पूर्वोत्तर में तीन, जम्मू–कश्मीर में ऐसे दो स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। सामुदायिक रेडियो का लाइसेंस सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों, सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं व गैर सरकारी संगठनों को जारी किए हैं। देश भर में पहले से ही 260 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना प्रसारण कर रहे हैं। जावडेकर ने कहा कि जनता से संवाद के अलावा सामुदायिक रेडियो के फैलाव से स्थानीय कलाकारों को भी अपनी कला क्षमता दिखाने का बड़ा अवसर मिलेगा। सामुदायिक एफएम रेडियो स्टेशनों की प्रसारण पहुंच 10 से 15 किलोमीटर के इलाके में होती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अपने कार्यक्रम का 50 फीसद कंटेंट स्थानीय स्तर पर ही निर्माण करना होता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

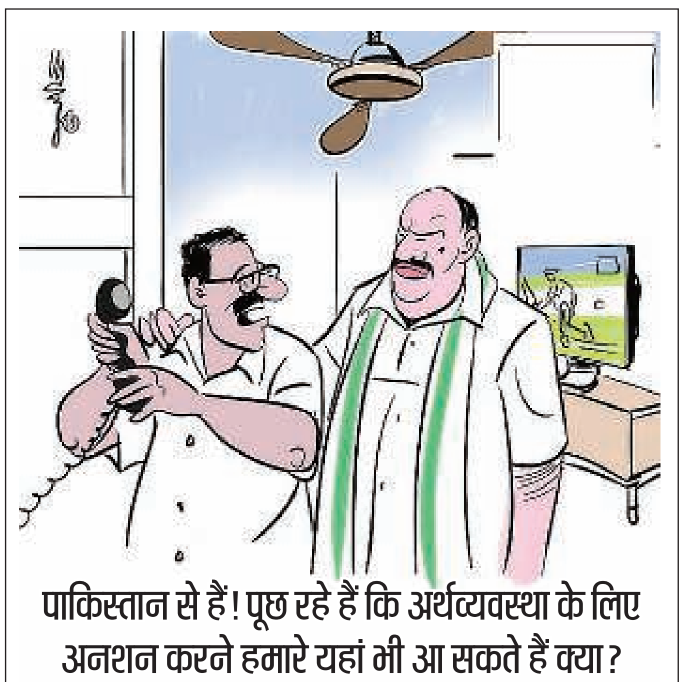

कांग्रेसी सीएम भी करेंगे चुनावी वादे निभाने की 'ब्रांडिंग'

संजय मिश्र, नई दिल्ली

▸ सूबे में घमासान थामने को प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मंत्रियों की रोस्टर ड्यूटी लगाने का सोनिया का निर्देश

▸ कांग्रेस शासित राज्यों के साथ केंद्र के सौतेले व्यवहार से जनता को रूबरू कराने पर दिया जोर

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सरकार के कामकाज की मार्केटिंग को भी तवज्जो देने की सलाह दी है। इस क्रम में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारों को अपने एक साल पूरा होने के मौके पर कामकाज को नायाब तरीके से जनता के बीच 'शो-केस' करने को कहा गया है। सरकार और प्रदेश कांग्रेस संगठन में घमासान पर सख्त तेवर अपनाते हुए पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्रियों पर सरकार व संगठन में बेहतर समन्वय की जवाबदेही तय की है। सरकार में पार्टी नेताओं की सुनवाई के लिए हर हफ्ते प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में राज्य के एक मंत्री की बैठने की व्यवस्था शुरू करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में सूबों के मंत्रियों की 'रेस्टर डयूटी' लगाने की व्यवस्था शुरू करने को भी कहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष पद दोबारा संभालने के बाद पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की हुई पहली बैठक में मौजूदा सियासी हालात देखते हुए इन कदमों को जरूरी माना गया है। पार्टी का मानना है कि भाजपा और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह सरकार के छोटे से छोटे काम को बड़े इवेंट के तौर पर प्रचारित करने का ट्रेंड शुरू कर दिया है, उसमें विपक्षी पार्टियों की राज्य सरकारों के लिए भी अपने काम को जनता के दिलो-दिमाग में बिठाना जरूरी हो गया है। इसके मद्देनजर ही अगले नवंबर में अपने एक साल का कार्यकाल पूरा कर रहे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से उनके पूरे कामकाज की समीक्षा की गई। इन सरकारों की पहली सालगिरह को शो-केस करने की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व के इस रुख से साफ है कि अपनी राजनीतिक चुनौतियों के दौर में कांग्रेस नेतृत्व को भी अब अपनी सरकारों के कामकाज की मार्केटिंग की जरूरत का अहसास होने लगा है। मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों के चुनावी वादों पर कितना अमल हुआ है और जो वादे अभी पूरे करने हैं उस पर भी चर्चा हुई। सोनिया ने सभी मुख्यमंत्रियों से जनता से किए चुनावी वादे पूरा करने में कोई समझौता नहीं करने की स्पष्ट हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा करके ही हम भाजपा से बेहतर शासन चलाने का अपना ट्रैक रिकार्ड देश के सामने ला सकते हैं।

केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में कांग्रेस शासित राज्यों में आ रही समस्याओं और विपक्ष शासित प्रदेशों के साथ केंद्र सरकार के सौतेले रवैये पर भी मुख्यमंत्रियों ने पार्टी हाईकमान से चर्चा की। मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से और बेहतर सहयोग की अपेक्षा जताई तो पार्टी नेतृत्व ने भी इस मुद्दे पर उनके साथ पूरी तरह खड़े होने का भरोसा दिया। सोनिया गांधी ने इस क्रम में केंद्र की भाजपा सरकार पर कांग्रेस सरकारों को अस्थिर करने की कोशिशों का भी उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्रियों को अपने कामकाज की ताकत से इसका मुकाबला करने की सलाह दी। सोनिया ने मुख्यमंत्रियों से यह भी कहा कि केंद्र के अड़ंगे को जनता के सामने रखकर कर भाजपा की ऐसी राजनीति का पर्दाफाश किया जाना जरूरी है। आर्थिक मंदी की वजह से राज्यों के सामने आ रही चुनौतियों और उनसे स्थानीय स्तर पर निपटने के प्रयासों पर भी मंत्रणा हुई।

सोनिया ने बैठक में राज्य सरकारों और प्रदेश कांग्रेस के बीच घमासान पर गंभीर रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्रियों से साफ कहा कि सरकार व संगठन में समन्वय उनकी जिम्मेदारी है। राजस्थान और मध्यप्रदेश में खासतौर पर सरकार व पार्टी संगठन में खुले झगड़े को अस्वीकार्य बताते हुए हाईकमान ने मुख्यमंत्रियों से सभी समूहों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया।

दस जनपथ पर हुई इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, एके एंटनी और अहमद पटेल के साथ कांग्रेस शासित पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, मध्यप्रदेश के कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, राजस्थान के अशोक गहलोत और पुड्डूचेरी के सीएम वी. नारायण सामी मौजूद थे। सोनिया ने पूर्वोत्तर राज्यों के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन को मजबूत बनाने पर भी अलग से बैठक की।

REUNION IAS
IAS V.K.TRIPATHI PCS
NEW BATCH (Optional)
राजनीति विज्ञान
IGP से कक्षा प्रारम्भ... 17 SEP. 2019 3 PM TO 6 PM
NEW BATCH सामान्य अध्ययन-II (मुख्य परीक्षा)
अंतर्राष्ट्रीय संबंध
I.R. से कक्षा प्रारम्भ 17 SEP. 2019 11:30 AM TO 2:00 PM
301, 307 TOP FLOOR, SATIJA HOUSE, MUKHERJEE NAGAR DELHI-9
9999421659-58

1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुआ था और तब 72.65 फीसद वोट पड़े थे। उस वक्त का रिकॉर्ड 2014 में टूटा और 76.13 फीसद मतदान हुआ।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 सितंबर 2019

कम पढ़े-लिखे नहीं बन पाए सरपंच, विस में ठोकेंगे ताल

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

▸ **विधानसभा चुनाव में शैक्षिक योग्यता नहीं जरूरी, पंचायत चुनाव में शिक्षा की शर्त ने तोड़ दिया था सपना**

▸ **मौजूदा विधानसभा में सर्वाधिक 25 विधायक स्नातक, 17 विधायक 12वीं पास और 20 ग्रेजुएट बिजनेसमैन**

हरियाणा कारण

हरियाणा में जो लोग कम पढ़े-लिखे होने के कारण पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाए थे, अब डंके की चोट पर विधानसभा चुनाव में दावेदारी कर सकेंगे। पंचायत चुनावों के विपरीत उनके सामने न शैक्षिक योग्यता की शर्त रहेगी और न बिजली बिल भरने, सहकारी बैंकों का ऋण चुकाने और घर में शौचालय बनवाने की शर्त।

मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही पंचायती राज नियमों में संशोधन कर सरपंची के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के सामने दसवीं पास होने की शर्त रखी थी। महिलाओं व अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। इसी तरह पंच पद के लिए अनुसूचित महिला की शैक्षणिक योग्यता पांचवीं पास रख दी गई। इसके उलट विधानसभा चुनावों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे कम पढ़े-लिखे व्यक्ति भी चुनाव जीतकर विधायक बन सकते हैं। राज्य की 90 सदस्यीय मौजूदा विधानसभा की बात करें तो भाजपा पटौदी से भाजपा विधायक बिमला चौधरी बहुत कम पढ़ी लिखी हैं। चार विधायकों ने 8वीं पास कर रखी है तो आठ विधायक 10वीं से आगे नहीं बढ़ पाए।

हालांकि, मौजूदा विधानसभा में सर्वाधिक 25 विधायक स्नातक हैं। इसके अलावा 17 विधायकों ने 12वीं पास कर रखी है तो 20 ग्रेजुएट बिजनेसमैन और 12 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। दो विधायक पीएचडी व एक विधायक अन्य शिक्षा प्राप्त हैं। भाजपा के 47 विधायकों में एक निरक्षर, चार विधायक दसवीं पास, नौ विधायक 12वीं पास, 14 विधायक स्नातक, आठ विधायक पोस्ट ग्रेजुएट, नौ विधायक ग्रेजुएट बिजनेसमैन, एक पीएचडी व एक अन्य शिक्षा प्राप्त हैं।

कांग्रेस के 17 विधायकों में से एक विधायक आठवीं पास, तीन विधायक 12वीं पास, तीन विधायक ग्रेजुएट, सात ग्रेजुएट बिजनेसमैन, दो पोस्ट ग्रेजुएट व एक पीएचडी हैं। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक 12वीं पास थे तो अकाली दल का एकमात्र विधायक ने दसवीं कर रखी है। पांच आजाद विधायकों में एक आठवीं, एक दसवीं, एक 12वीं, एक ग्रेजुएट व एक पोस्ट ग्रेजुएट हैं।

13वीं विधानसभा में 75 विधायक करोड़पति : हरियाणा विधानसभा में 75 विधायक करोड़पति हैं। नौ विधायक ऐसे भी चुनकर आए, जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसी तरह दोबारा चुनकर आए 21 विधायकों ने पिछले पांच साल में अपनी जायदाद 9.80 करोड़ रुपये बढ़ी हुई दिखाई है। पिछले चुनावों में दिए शपथपत्र के मुताबिक आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई व उनकी पत्नी हांसी से विधायक रेणुका बिश्नोई के पास 80 करोड़ रुपये की जायदाद है। सिरसा से इनेलो विधायक मक्खन लाल सिंगला की संपत्ति 72 करोड़, जबकि तोशाम से कांग्रेस की विधायक चुनी गई किरण चौधरी की जायदाद करीब 70 करोड़ है। डबवाली से इनेलो विधायक नैना सिंह चौटाला की संपत्ति 60 करोड़ है। बादशाहपुर से भाजपा विधायक राव नरबीर सिंह की जायदाद 49 करोड़ रुपये है। ऐलनाबाद से इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला 43 करोड़ और समालखा से निर्दलीय विधायक रवींद्र मछरौली 31 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की संपत्ति 61 लाख थी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब विधायकों की सूची में शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दिए शपथपत्र में उनकी संपत्ति 61 लाख थी। गरीब विधायकों में विशंभर वाल्मीकि के बाद कालांवाली से शिरोमणि अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह की संपत्ति 28 लाख रुपये, दादरी से इनेलो विधायक राजदीप फौगाट की संपत्ति 33 लाख, नीलोखेड़ी से भाजपा विधायक भगवान दास कबीरपंथी की संपत्ति 37 लाख, फिरोजपुर-झिरका से इनेलो विधायक नसीम अहमद की संपत्ति 38 लाख रुपये थी। खरखौदा से कांग्रेस के जयवीर सिंह की संपत्ति 42 लाख, हथीन से इनेलो के केहर सिंह रावत की 48 लाख, शाहबाद से भाजपा के कृष्ण बेदी की संपत्ति 56 लाख व गुहला से भाजपा के कुलवंत बाजीगर की संपत्ति भी 61 लाख रुपये थी।

चौटाला परिवार में एकजुटता की कोशिशों को झटका, दुष्यंत ने सात उम्मीदवार किए घोषित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

दुष्यंत सिंह चौटाला फाइल

हरियाणा में जननायक जनता पार्टी (जजपा) द्वारा सात उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित करने के साथ ही चौटाला परिवार में एकजुटता की खाप पंचायतों की कोशिश को गहरा धक्का पहुंचा है। खाप पंचायतें पिछले कई दिनों से अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत सिंह चौटाला के बीच राजनीतिक एकजुटता की कोशिश कर रही थीं। इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला व अभय सिंह चौटाला द्वारा इसके लिए खाप पंचायतों को अधिकृत करने तथा पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मध्यस्थता के बावजूद कोई हल नहीं निकला।

इनेलो से अलग होकर अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला ने शुक्रवार को अपनी पार्टी के सात उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट घोषित करने से दो दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने यह कहकर कि पहले परिवार के दूसरे सदस्यों के बीच राजनीतिक एकजुटता कराओ, खाप पंचायतों की मुहिम पर ब्रेक लगा दिया था। जजपा से पहले आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उसमें जजपा ने एक पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, पूर्व विधायक रामकुमार गौतम तथा पूर्व विधायक अनूप धानक को चुनावी रण में उतारा है। अनूप धानक उन नेताओं में शामिल हैं, जो चौटाला परिवार में बिखराव के बाद से दुष्यंत सिंह चौटाला के खेमे में खड़े हैं।

पूर्व मंत्री हर्ष कुमार हथीन से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व विधायक रामकुमार गौतम को नारनौंद से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व विधायक अनूप धानक अपने मौजूदा विधानसभा क्षेत्र उकलाना से ही चुनाव लड़ेंगे। पानीपत ग्रामीण से देवेंद्र कादियान, महेंद्रगढ़ से राव रमेश पाल, नारनौल से कमलेश सैनी तथा बावल से श्याम सुंदर को टिकट दिए गए हैं। रमेश पाल भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी छोड़कर दो दिन पहले ही जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।

नवीन जयहिंद कर रहे फील्ड में जाकर प्रत्याशियों की घोषणा : हरियाणा में आम आदमी पार्टी जजपा से पहले 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। जजपा और आम आदमी पार्टी का हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में गठबंधन था, जो अब टूट चुका है। बड़खल से धर्मबीर भड़ाना, बल्लभगढ़ से हरेंद्र भाटी, होडल से करण डागर, हांसी से मनोज राठी, फतेहाबाद से लक्ष्य गर्ग, महेंद्रगढ़ से अजय शर्मा, किलोई से फौजी मुनिपाल अत्री, असंध से अनूप संधू, बहादुरगढ़ से अनीता और उकलाना से मनजीत रंगा पत्रकार के टिकट घोषित किए गए हैं। आप की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने बताया कि जल्द ही एक और सूची जारी की जाएगी। जयहिंद फील्ड में जाकर प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं।

छग में 82 फीसद आरक्षण पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नईदुनिया, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ में जातीय आरक्षण में की गई वृद्धि को लेकर शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा है। इस मामले में वेद प्रकाश सिंह ठाकुर और आदित्य तिवारी ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर 82 फीसद आरक्षण दिए जाने को चुनौती दी है। दोनों याचिकाओं पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की पीठ में प्रारंभिक सुनवाई हुई। पीठ ने मामले में महाधिवक्ता को राज्य शासन से निर्देश लेकर 10 दिन में जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

58 फीसद का मामला अभी विचाराधीन : छत्तीसगढ़ में 2012 में जातीय आरक्षण में बदलाव किया गया था। इससे आरक्षण की सीमा 58 फीसद पहुंच गई थी। यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने फिर इसमें बदला की घोषणा कर दी। इससे आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण के साथ राज्य में आरक्षण की कुल सीमा 82 फीसद पहुंच गई है। इसमें अनुसूचित जाति को 32, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 और अनुसूचित जनजाति को 13 फीसद आरक्षण का प्रावधान है।

एक और याचिका पेश : इस मामले में पुनेश्वर नाथ मिश्रा, पुष्पा देवी, संजय तिवारी, शुभम शुक्ला व अन्य ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से शुक्रवार को एक और याचिका दाखिल की है। इस मामले में हाई कोर्ट में यह तीसरी याचिका है।

सीएम व मंत्रियों के वेतन पर अब आयकर नहीं भरेगी उप्र सरकार

बड़ा बदलाव ▸ 1981 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार में लागू हुई थी व्यवस्था

मंत्रियों की गरीबी का हवाला देकर बनाया गया था कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

योगी आदित्यनाथ फाइल

क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल को मंत्री के तौर पर दिए जाने वाले वेतन-भत्ते पर आयकर की अदायगी राज्य सरकार 38 वर्षों से साल-दर-साल अपने खजाने से वहन करती आ रही है। 'राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है' जैसे नारे के नायक रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उप्र के मुख्यमंत्री रहते 1981 में इस व्यवस्था का सूत्रपात किया था। हालांकि मीडिया में यह तथ्य उजागर होने पर योगी सरकार ने लगभग चार दशकों से जारी इस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्णय किया है कि सरकार द्वारा आयकर अदा करने संबंधी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। ऐसे में अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अपने वेतन-भत्ते पर लागू आयकर खुद अदा करना होगा।

मंत्रियों की कमजोर आर्थिक स्थिति का दिया था हवाला : उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था 'उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, एलाउएंसेज एंड मिसलेनियस एक्ट, 1981' के तहत लागू है। तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस कानून को बनाए जाने के दौरान इसकी वकालत करते हुए कहा था कि सरकार के ज्यादातर मंत्री कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के हैं और उनकी आमदनी बहुत कम है। लिहाजा उन्हें मंत्री के तौर पर मिलने वाले वेतन-भत्ते पर पड़ने वाले आयकर के बोझ को राज्य सरकार वहन करे। संबंधित एक्ट में यह प्रावधान है कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन आयकर से मुक्त रहेगा। वेतन पर आयकर की अदायगी राज्य सरकार करेगी।

अब तक 19 मुख्यमंत्री और करीब 1000 मंत्री : उत्तर प्रदेश ने 19 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल देखे हैं। इनमें कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी, श्रीपति मिश्र और वीर बहादुर सिंह, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मायावती और भाजपा के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ की सरकारें और उनमें शिरकत करने वाले विभिन्न दलों के तकरीबन 1000 मंत्री शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मंत्रिमंडल के आयकर का बिल लगभग 86 लाख रुपये था जिसे सरकारी खजाने से अदा किया गया।

1981 में बढ़ा था वेतन : उप्र में मुख्यमंत्री और मंत्रियों का मूल वेतन पहले 12 हजार रुपये प्रतिमाह था जिसे अखिलेश यादव की सरकार में बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया। इसके पहले वर्ष 1981 में मुख्यमंत्री का वेतन बढ़ाया गया था।

मुख्यमंत्री-मंत्रियों का मासिक वेतन 1.64 लाख रुपये

- 40 हजार रुपये मूल वेतन
- 50 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
- 30 हजार रुपये चिकित्सा प्रतिकर भत्ता
- 20 हजार रुपये सचिवालय भत्ता
- 24 हजार रुपये दैनिक भत्ता (800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से)

गुजरात में 5000 स्थलों पर मनेगा मोदी का जन्मदिन

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

सितंबर का माह गुजरात के लिए कई खुशियां लेकर आया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है जिसे सेवा सप्ताह के रूप में राज्य में पांच हजार स्थलों पर मनाया जाएगा। इसके अलावा, सरदार सरोवर बांध 138 मीटर के जलस्तर को छूने वाला है और राज्य में भाजपा की सदस्य संख्या करीब डेढ़ करोड़ हो गई है यानी हर चौथा व्यक्ति भाजपा का सदस्य बन चुका है।

मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी की मौजूदगी में गांधीनगर भाजपा मुख्यालय श्रीकमलम पर आयोजित समीक्षा बैठक में नर्मदा नीर के स्वागत के लिए महाआरती का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन 14 से 21 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। साथ ही राज्य में भाजपा के 46 लाख नए सदस्य बनने पर भी उत्सव मनाकर उनका स्वागत करने का फैसला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल सरदार सरोवर बांध पहुंचकर नर्मदा के नीर की महाआरती कर नर्मदा माता का स्वागत करेंगे। नर्मदा बांध में लगातार पानी की अच्छी आवक के साथ यह जल्द ही अपने पूर्ण जलस्तर 138 मीटर को छूने वाला है। भाजपा अध्यक्ष वाघाणी ने कहा कि वर्ष 1995 से राज्य में भाजपा सरकार है। केशुभाई पटेल, नरेंद्र मोदी, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के रूप में बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। बांध पहली बार ऐतिहासिक जल स्तर तक भरने वाला है। भाजपा राज्यभर में 5000 स्थलों पर उत्सव मनाकर नर्मदा नीर का स्वागत करेगी व प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की खुशियां मनाएंगे।

प्रधानमंत्री को नमो वन का तोहफा देंगी मेनका गांधी

धर्मेन्द्र मिश्रा, सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में 20 बीघे से अधिक जमीन पर देश का पहला नमो वन विकसित होने जा रहा है। सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन 17 सितंबर को यह तोहफा देना चाहती हैं। इसके लिए अधिकारियों ने जमीन खोज ली है। यहां मेनका गांधी की मौजूदगी में एक साथ 10 हजार पौधे रोपे जाएंगे। नमो वन में ज्यादातर औषधीय, फलदार एवं छायादार पौधे लगाए जाएंगे।

पर्यावरण से मेरा प्रेम बहुत पुराना है। पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं की अहमियत इंसानों से कम नहीं है। यह बात सबको समझनी होगी। जब धरती पर पेड़-पौधे व जीव-जंतु नहीं रहेंगे तो इंसानों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। पीएम मोदी पर्यावरण संतुलन बनाने व ग्लोबल वार्मिंग रोकने को बेहद चिंतित व प्रयत्नशील हैं। इसलिए उनके जन्मदिन पर यह तोहफा देने का विचार आया।

-मेनका गांधी, भाजपा सांसद, सुलतानपुर

आज भाजपा के हो जाएंगे शिवाजी के वंशज व राकांपा सांसद भोसले

राज्य ब्यूरो, मुंबई : छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज व सतारा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद उदयनराजे भोसले शनिवार को भाजपा के हो जाएंगे। वह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता लेंगे। यह जानकारी भोसले ने खुद ट्वीट करके दी।

शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति की पदवी धारण करने वाले उदयनराजे भोसले उनके 13वें वंशज हैं। वह 2009 से राकांपा के टिकट पर लगातार सतारा से सांसद चुने जाते रहे हैं तथा फिलहाल पार्टी के चार सांसदों में से एक हैं। पिछले कई दिनों से यह हवा गर्म थी कि वह राकांपा का दामन छोड़ भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। चर्चा थी कि वह करीब 15 दिनों पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की सोलापुर रैली के दौरान पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

छत्रपति भोसले ने शुक्रवार को खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि वह शनिवार को दिल्ली में भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी, भाजपा अध्यक्ष शाह, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी उपस्थित रहेंगे। भाजपा में शामिल होने के अगले दिन रविवार को ही भोसले मुख्यमंत्री फड़नवीस के साथ अपने गृहनगर सतारा में एक रैली में हिस्सा लेंगे।

छत्रपति भोसले का भाजपा में जाना राकांपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खासतौर से मराठा मतों के संदर्भ में। भाजपा समाज को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देकर पहले ही राकांपा के एकमुश्त मराठा वोटबैंक में सेंध लगा चुकी है। अब मराठा समाज के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों का भी भाजपा में जाना राकांपा के लिए एक और बड़ा झटका है। 15 दिन पहले ही उनके चचेरे भाई एवं सतारा विधानसभा सीट से राकांपा विधायक शिवेंद्रराजे भोसले भी भाजपा का दामन थाम चुके हैं।

छत्रपति शिवाजी महाराज के कोल्हापुर वाले परिवार यानी छत्रपति शाहू जी महाराज के वर्तमान वंशज संभाजी राजे भोसले वैसे तो सीधे भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उसकी सरकार में ही राष्ट्रपति की तरफ से राज्यसभा सदस्य मनोनीत किए गए हैं।

शिवकुमार की सेहत का ध्यान रखकर पूछताछ करे सीबीआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ **विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता की रिमांड 17 सितंबर तक बढ़ाई**

कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की रिमांड राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार दिन और बढ़ा दी। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट पेश कर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने रिमांड केवल 17 सितंबर तक बढ़ाई। विशेष न्यायाधीश ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह शिवकुमार के स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखे फिर पूछताछ करे।

सीबीआइ की विशेष अदालत ने कहा कि शिवकुमार के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को देखते हुए जांच अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनकी नियमित जांच हो और उन्हें डॉक्टरों द्वारा बताई गईं दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। शिवकुमार से उनके डॉक्टर रंगा नाथन भी मिल सकेंगे। परिवार के सदस्यों एवं वकील को हर दिन आधे घंटे मिलने की अनुमति होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान डीके शिवकुमार सवालों के कपटपूर्ण और गलत जवाब दे रहे हैं। उनके नाम पर कई बेनामी संपत्तियां हैं।

डीके शिवकुमार को शुक्रवार को ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। एएनआइ

जांच एजेंसी मनी लांड्रिंग से जुड़े दस्तावेज के संबंध में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इस पर अदालत ने कहा कि मेरा मानना है कि शिवकुमार आगे पांच दिन में भी सवालों के जवाब नहीं देंगे, तो फिर आप उनको हिरासत में क्यों लेना चाहते हैं। इस पर एएसजी ने कहा कि मामले में कई अन्य आरोपितों से उनका सामना कराकर पूछताछ करनी है। शिवकुमार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रिमांड बढ़ाने की मांग का विरोध किया।

आजम के रिसॉर्ट में अखिलेश ने कहा-हम जेल जाने को तैयार

जागरण संवाददाता, रामपुर

उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सांसद आजम खां पर दर्ज मुकदमों को लेकर कहा कि भाजपा वालों तुम जेलें बनाओ, हम जेल जाने को तैयार हैं। वह शुक्रवार देर रात सांसद आजम खां के हमसफर रिसॉर्ट में पहुंचे। जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, जब भी हम जेल गए हैं, तब हमारी सरकार बनी है। आजादी के बाद अगर किसी नेता पर सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए तो वह नेताजी मुलायम सिंह यादव हैं, जिनके खिलाफ एक ही रात में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे। अब आजम खां के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आजम खां जैसे समाजवादी नेता पर बकरी चोरी और भैंस चोरी के इल्जाम में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। आजम खां पर सिर्फ इसलिए मुकदमे दर्ज कराए जा रहे है, क्योंकि उन्होंने गरीबों और कमजोरों के बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई है। सरकार चाहे जितने जुल्म करा ले, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा।

दुष्कर्म के आरोपितों को बचा रही भाजपा : हमारी सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, लेकिन अब देख लीजिए, कैसे लोग सरकार में बैठे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे-कैसे मुकदमे हैं। उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कितने मुकदमे हैं। जब ऐसे लोग सरकार चलाएंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा। भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। संसद में तमाम महिला सांसद एकजुट हो गई थीं, लेकिन उन्नाव की घटना को लेकर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां तो सरकार ही दुष्कर्म के आरोपितों को बचा रही है। दरअसल, उनमें भाजपा का विधायक भी शामिल रहा है। इसी तरह शाहजहांपुर में भाजपा नेता के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करने में भी पुलिस आनाकानी कर रही है।

आजम खां से हमारा पारिवारिक रिश्ता

अखिलेश ने कहा कि आजम खां से हमारा कोई सियासी रिश्ता नहीं, बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने हमें उसी तरह माना, जैसे उन्होंने अब्दुल्ला को माना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उन्हें परिवार का सदस्य मानें। जब हम पर परेशानी आई। नेताजी पर परेशानी आई, तब आजम खां ने हमारा साथ दिया।

पकड़े जाने के डर से दूल्हा बन कर रामपुर पहुंचे सपा नेता

अखिलेश यादव के रामपुर दौरे को लेकर दिन भर प्रशासन अलर्ट रहा। जिले के साथ ही पड़ोसी जनपदों में पुलिस पूरी तरह चौकन्नी रही। बाहरी नेताओं को रामपुर जाने से रोकने की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसके बावजूद संभल के जिलाध्यक्ष फिरोज खां तमाम कार्यकर्ताओं सहित पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गए। वह दूल्हा बने और कार्यकर्ता बराती। उसके बाद आराम से उनकी गाड़ियां पुलिस के सामने से गुजरती हुईं रामपुर पहुंच गईं।

अखिलेश का विरोध कर रहे 300 कांग्रेसियों को पुलिस ने पकड़ा : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का विरोध कर रहे 300 कांग्रेसियों को पुलिस ने पकड़ लिया। इसके बाद सभी को बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। कांग्रेस के कई नेता अखिलेश के रामपुर आगमन का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश उपाध्यक्ष मुतीउर्रहमान खां और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाला को नोटिस भी जारी किया गया था। फैसल लाला को शुक्रवार को पार्टी से छह साल के लिए निकाल भी दिया गया।

जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की ईडी करेगा जांच

जासं, रामपुर : सपा सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन कर रही जौहर ट्रस्ट के सभी सदस्यों की संपत्ति की जांच ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) करेगा। इस संबंध में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने मामला ईडी को सौंप दिया है। शिकायत में कहा था कि 2012 में सपा की सरकार बनने पर आजम खां 560 एकड़ भूमि पर जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था। इसमें सारे नियम और कानून ताक पर रखते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। आरोप है कि सांसद ने यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए अपने ठेकेदारों, उद्योगपतियों आदि से करोड़ों रुपये चंदे के रूप में लेकर काले धन को सफेद करने का प्रयास किया। चंदा देने वाले सैकड़ों लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं है कि उनके नाम की रसीदें काट दी गई हैं।

आले हसन खां और सपाइयों पर एक और मुकदमा : पुलिस ने पूर्व सीओ सिटी आले हसन खां और सपाइयों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। इसमें जल निगम के अभियंता और दारोगा भी नामजद हैं। इन पर मकान में घुसकर मारपीट, लूटपाट, छेड़छाड़ जैसे आरोप लगे हैं।

कर्ज माफी योजना भी नहीं रोक पाई किसानों की आत्महत्याएं

हकीकत

पंजाब सरकार अब तक 4609 करोड़ रुपये का कर्ज कर चुकी है माफ, पांच लाख 61 हजार 886 किसानों को मिल चुका है योजना का लाभ, इसके बावजूद आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें रहती हैं सुर्खियों में

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

पंजाब में दो लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने के बावजूद किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही हैं। आए दिन किसानों की आत्महत्या की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। दरअसल, किसानों के कर्ज का मामला न सुलझने का एक बड़ा कारण सरकारों द्वारा असल मुद्दे से हाथ खींचना है। जहां किसान अपनी फसलों की वाजिब कीमतों की मांग कर रहे हैं वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे किसानों की न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित करना ही एकमात्र रास्ता है। ऐसा करके ही कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सकता है।

सत्ता में आने से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद उन्होंने डॉ. टी. हक के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसने कर्ज माफी के लिए किसानों की दो कैटेगरी बनाई। पहली कैटेगरी में ढाई एकड़ से कम वाले किसान थे और दूसरी में पांच एकड़ से कम वाले किसान थे। इन किसानों के दो-दो लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने की सिफारिश की जिसे लागू किया गया।

कर्ज माफी से नहीं दिखा सुधार। प्रतीकात्मक

पंजाब के पांच लाख 61 हजार 886 किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला है। इन किसानों के 4609 करोड़ रुपये के कर्ज माफ किए गए हैं। कामर्शियल बैंकों के 1.45 लाख किसानों के केस अभी माफी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कृषि विभाग ने सरकार से इसके लिए 1632 करोड़ रुपये की मांग की है। सरकार ने किसानों के अलावा खेतिहर मजदूरों का भी 200 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया है।

नहीं मिल रही वाजिब कीमतें : राजेवाल

भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल की मानें तो बड़ा सवाल यह है कि क्या किसानों को उनकी फसलों की उचित कीमतें दी जा रही हैं? उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि किसानों पर 90 हजार करोड़ रुपये का कर्ज चढ़ा है। यह कर्ज नहीं, बल्कि सरकारों को उनकी फसलों की पूरी कीमत न देकर उनको घाटा पहुंचाया गया है। यही नहीं, किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन गेहूं और धान के अलावा किसी भी फसल को किसी भी एजेंसी से खरीदने का प्रबंध नहीं करवाया गया है। ऐसे में किसानों को अपनी फसलें बाजार भाव पर बेचनी पड़ती है, जिसे व्यापारी गठजोड़ बनाकर औने-पौने दामों पर खरीदते हैं।

पंजाब में सात महीनों में 645 किसानों ने दी जान

प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को लेकर अनधिकृत आंकड़े पर विश्वास करें तो इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक 645 किसान कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर चुके हैं। इस तरह से हर दिन औसतन कम से कम तीन किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

किसानों की आमदनी तय करना ही समस्या का हल : दविंदर शर्मा

कृषि नीतियों के विशेषज्ञ दविंदर शर्मा का कहना है कि आज सबसे बड़ा सवाल किसानों की आमदनी सुनिश्चित करने का है। सरकारी महकमों में सेवादार की आमदनी 18 हजार रुपये सुनिश्चित की गई है, लेकिन किसानों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोआपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 19 सालों में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपये कीमत कम दी गई है। नीति आयोग के मुताबिक, 2011-12 से लेकर 2016-17 तक किसानों की आमदनी 0.44 फीसद प्रति वर्ष की रफ्तार से बढ़ी है। 2017-18 में यह जीरो फीसद और 2018-19 में माइनस में चली गई है। जब तक किसानों की आमदनी तय करने पर नीति फोकस नहीं की जाती तब तक किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकेंगी।

नए आरक्षण रोस्टर की समीक्षा करेगी उत्तराखंड सरकार

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण के नए रोस्टर में पेच फंस सकता है। कैबिनेट मंत्री और रोस्टर तय करने वाली कैबिनेट उपसमिति के अध्यक्ष यशपाल आर्य की कड़ी नाराजगी और इस्तीफे की धमकी के बाद सरकार के रुख में बदलाव के संकेत हैं। मंत्री को मनाने में सरकार को कामयाबी मिली है, लेकिन आरक्षण के नए रोस्टर की समीक्षा होगी। यह काम कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता वाली उपसमिति कमेटी को सौंपा जाएगा। यह उपसमिति सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर के साथ ही पदोन्नति में आरक्षण मामले पर भी सरकार को सिफारिशें देगी। इन सिफारिशों के मिलने तक नए आरक्षण रोस्टर पर रोक तय है।

नया आरक्षण रोस्टर सरकार के लिए गर्म दूध बन गया है। जिस कैबिनेट उपसमिति ने आरक्षण रोस्टर तैयार किया, उसके अध्यक्ष यशपाल आर्य ही इसके विरोध में आ गए हैं। बीती 28 अगस्त को कैबिनेट बैठक में आरक्षण के नए रोस्टर को मंजूरी दिए जाने के बाद यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण रोस्टर का शासनादेश जारी नहीं करने और इस मामले को फिर पुनर्विचार के लिए कैबिनेट उपसमिति में भेजने की पैरवी की थी। आर्य के पत्र और आपत्ति के बावजूद सरकार ने बीते बुधवार को कैबिनेट बैठक से कुछ ही देर पहले नए आरक्षण रोस्टर का आदेश भी जारी कर दिया। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद उक्त शासनादेश जारी होने की जानकारी मिलने पर यशपाल आर्य ने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कड़ी नाराजगी जताते हुए इस्तीफे की धमकी दी थी। हालांकि यशपाल आर्य की आपत्ति के बावजूद नए आरक्षण रोस्टर के शासनादेश को उच्चानुमोदन के बाद जिस तरह जारी किया गया, उसे सरकार की ओर से आरक्षण मामले में लिए गए स्टैंड के तौर पर भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आर्य की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उपसमिति ने केंद्र सरकार और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश की ओर से अपनाए गए आरक्षण रोस्टर के आलोक में उत्तराखंड के लिए नया रोस्टर तैयार किया।

747 आतंकियों और उनके समर्थकों को पकड़ा है वर्ष 2015 से अब तक सेना व सुरक्षाबलों ने जम्मू-कश्मीर में। इस दौरान 26 आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2019 में अब तक आठ आतंकी आत्मसमर्पण कर चुके हैं।

रोशनी अधिनियम में धोखाधड़ी की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा

सख्त रुख ▶ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने ब्यूरो को तेजी से मामले की जांच के निर्देश दिए

कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिज्ञों पर सरकारी जमीन पर कब्जे के लगे थे आरोप

सत्यपाल मलिक। फाइल फोटो

राज्य ब्यूरो, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को आदेश दिया कि रोशनी अधिनियम के तहत अनियमितताओं और धोखाधड़ी से संबंधित सभी मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो करेगी। अधिनियम लागू होने के बाद राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों और राजनीतिज्ञों पर सरकारी जमीन कब्जाने के आरोप लगे थे। जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम, 2001 जिसे रोशनी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, इसे वर्ष 2001 में पारित किया था। इसके बाद बड़ी संख्या में अनियमितता और धोखाधड़ी की शिकायतें तत्कालीन राज्य सरकार को मिलने लगीं। ऐसी शिकायतें थीं कि जम्मू और श्रीनगर जिलों में उच्च मूल्य की भूमि अनियमित रूप से या धोखाधड़ी से कई ऐसे लोगों ने हासिल कर ली हैं जो हकदार नहीं थे।

इन रिपोर्ट को आधार बना राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्देश पर वर्ष 2018 में रोशन अधिनियम को भावी रूप से निरस्त कर दिया था। ताकि सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के तहत कोई और धोखाधड़ी न हो। सरकार के इस कदम का व्यापक स्वागत किया। हालांकि, जम्मू और श्रीनगर की विशेष रूप से दोनों राजधानियों में पिछली अनियमितताओं के बारे में रिपोर्ट जारी हैं। ऐसे में राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्ण अभियान शुरू करने की बात कहते हुए दोनों जिलों के सभी मामलों की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया है कि मामले को तेजी से हल किया जाए।

क्या था रोशनी अधिनियम : वर्ष 2001 में तत्कालीन सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्टेट लैंड (रहने वालों को मालिक बनाने) अधिनियम को मंजूरी दी। इसे रोशनी अधिनियम का नाम दिया गया क्योंकि सरकार ने कहा कि सरकारी (नजूल) जमीनों पर रहने वाले लोगों से बाजार के भाव वसूल करके उन्हें जमीनों का मालिकाना अधिकार दिया जाएगा। सरकार ने इससे 25 हजार करोड़ का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा और यह तय किया गया कि इस राशि से राज्य में बिजली ढांचे को विकसित किया जाएगा। क्योंकि इस राशि से घर-घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा था।

जनहित याचिका भी हुई थी दायर

रोशनी अधिनियम के खिलाफ हाईकोर्ट में एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जनहित याचिका भी दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोशनी अधिनियम के तहत आने वाली जमीनों के किसी भी तरह के लेनदेन (खरीद-फरोख्त या ट्रांसफर) पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। जनहित याचिका में इस कानून को चुनौती देते हुए कहा कि यह कानून पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है और राजनेताओं ने अपने चहेतों को खुश करने के लिए ऐसा काला कानून बनाया जिसमें सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों को सलाखों के पीछे डालने की बजाय उन्हें जमीनों का मालिक बनाया गया। आरोप लगाया गया था कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों में से अधिकतर राजनेता और उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे।

पीडीपी नेता के परिवार को बंधक बना अंगरक्षक की राइफल छीन भागे आतंकी

▶ किश्तवाड़ में लगाया गया कर्फ्यू, आतंकियों की तलाश में अभियान

▶ पीडीपी नेता के भाई की कार लेकर भागे आतंकी, सुबह गाड़ी बरामद

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़

जम्मू के किश्तवाड़ में आतंकियों ने एक और सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए पीडीपी के जिला प्रधान एडवोकेट शेख नासिर हुसैन के परिवार को रातभर बंधक बनाए रखा और सुबह उनके अंगरक्षक की इनसास राइफल छीनकर फरार हो गए। आतंकी नासिर हुसैन के छोटे भाई की कार भी ले गए, जो शुक्रवार सुबह डुल इलाके में बरामद कर ली गई। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने किश्तवाड़ शहर में कर्फ्यू लगाने के साथ पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिला।

यह वारदात जिला मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर दूर गुंरियन मोहल्ले में हुई। गुरुवार रात करीब 11 बजे चार आतंकी हथियारों के साथ पीडीपी के जिला प्रधान शेख नासिर हुसैन के घर में जबरन घुस गए। उन्होंने घर के सभी सदस्यों को एक बंधक बना लिया। उस समय घर पर नासिर हुसैन, उनकी पत्नी, दो छोटे बच्चे और माता-पिता के अलावा उनका भाई डॉक्टर नजीर हुसैन उनकी पत्नी, बच्चे और नौकर सहित कुल 10 लोग थे। उस समय नासिर हुसैन का अंगरक्षक (पीएसओ) घर पर नहीं था।

परिवार को रस्सियों से बांधकर मुंह में ठूस दिया कपड़ा : पीडीपी नेता के भाई नजीर ने बताया कि आतंकियों के पास एक एके-47 राइफल और दो के पास पिस्टल थी। उन्होंने घर की महिलाओं व बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें रस्सियों से बांधकर दूसरे कमरे में ले गए। आतंकियों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, ताकि वे चिल्ला न सकें। आतंकियों ने परिवार को कहा कि उन्हें पीडीपी नेता नासिर हुसैन और उनके पीएसओ को मारने का निर्देश है। इसलिए पीएसओ को बुलाओ। वह दोनों को अपने साथ लेकर जाएंगे।

आतंकियों और अंगरक्षक के बीच हुई हाथापाई : सुबह जब नासिर का पीएसओ घर आया तो आतंकियों ने चालाकी से उसे भी दबोच लिया और उसकी इनसास राइफल भी छीन ली। इस दौरान पीएसओ की आतंकियों के साथ हाथापाई भी हुई। इसके बाद आतंकी नासिर के छोटे भाई डॉक्टर नजीर हुसैन की कार जेके-17- 6571 में सवार होकर वहां से फरार हो गए। जाते समय वह बाहर से घर पर ताला लगा गए। आतंकियों के जाने के बाद पीएसओ ने किसी तरह अपनी रस्सी खोली और घटना की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी। इसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने घर पहुंचकर सुबह करीब 11 बजे सभी को बाहर निकाला।

पुलिस ने कहा-आतंकियों की कर ली गई है पहचान

डीएसपी हेडक्वार्टर सनी गुप्ता ने बताया कि आतंकियों की पहचान कर ली गई है। इनमें ओसामा बिन जावेद, हरुन वानी, नावेद और साजिद शामिल हैं। ये सभी वही आतंकी वही हैं, जो पहले भी किश्तवाड़ में कई वारदात में शामिल रहे हैं।

किश्तवाड़ में दूसरी बार अंगरक्षक से छीनी गई राइफल

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शेख नासिर हुसैन के अंगरक्षक से एके-47 राइफल छीनने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस साल हथियार छीनने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 8 मार्च 2019 को आतंकियों ने शहीदी मजार इलाके में डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा के अंगरक्षक दिलीप कुमार के घर में घुसकर उससे एके-47 राइफल और 90 गोलियां छीनी थीं। उस राइफल का इस्तेमाल आरएसएस के नेता चंद्रकांत शर्मा और उनके अंगरक्षक राजेंद्र सिंह की हत्या में किया गया था।

कश्मीर में जुमे पर शरारती तत्वों ने की हिंसा भड़काने की कोशिश

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

कश्मीर में धीरे-धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों को यह रास नहीं आ रहा। जुमे पर हिंसा भड़काने की उनकी कोशिश को अवाम ने सिरे नहीं चढ़ने दिया। शुक्रवार को पूरे कश्मीर में सिर्फ श्रीनगर के संवेदनशील क्षेत्रों में ही हिंसक झड़पें हुई। हालांकि सुरक्षाबलों ने जल्द ही उन पर काबू पा लिया। प्रशासन ने शुक्रवार को श्रीनगर के डाउन-टाउन, उत्तरी और दक्षिण कश्मीर में चार जगहों पर पाबंदियां लगा रखी थी। जबकि अन्य किसी जगह कोई निषेधाज्ञा नहीं रही। इसी बीच एतिहासिक जामिया मस्जिद में नमाज-ए-जुमा नहीं हुई।

प्रशासन ने श्रीनगर के सिविल लाइंस, लाल चौक और उसके साथ सटे इलाकों में किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा रखी थी। सिर्फ डाउन-टाउन में जामिया मस्जिद, हजरतबल दरगाह के आसपास और उत्तरी व दक्षिण कश्मीर में चार जगहों पर पाबंदियां लगाई थीं। प्रमुख बाजार और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। गली-मुहल्लों के अलावा कुछेक अन्य जगहों पर सुबह छह बजे से नौ बजे तक तीन घंटे के लिए और उसके बाद शाम को रोजमर्रा के साजो सामान की दुकानें खुलीं। सरकारी कार्यालय और स्कूल खुले। सड़कों पर आम लोगों और वाहनों की आवाजाही सामान्य रही। जामिया मस्जिद, हजरतबल दरगाह और खानकाह मौला में पाबंदियों के चलते नमाज-ए-जुमा नहीं हुई। अन्य सभी मस्जिदों में नमाज-ए-जुमा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर रखे थे। बेमिना, सौरा और डाउन-टाउन के कुछेक हिस्सों में शरारती तत्वों ने नारेबाजी करते हुए जुलूस निकलाने का प्रयास किया। सुरक्षाबलों पर पथराव भी किया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई कर स्थिति पर काबू पा लिया।

लैंडलाइन सेवा है बहाल

पांच अगस्त को प्रशासन ने वादी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंदियों को लागू करने के अलावा सभी तरह की संचार सेवाओं को ठप कर दिया था। करीब एक सप्ताह बाद प्रशासन ने हालात में सुधार देख पाबंदियों को राहत देनी शुरू कर दी थी। गुरुवार को वादी से दिन की निषेधाज्ञा को हटा लिया था। लैंडलाइन फोन सेवा पूरी वादी में बहाल की जा चुकी है। सरकारी कार्यालय और स्कूल खुलने लगे हैं।

कश्मीरी आतंकियों से हो सकता है खालिस्तानी उग्रवादियों का गठजोड़

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▶ हैंडलर की तलाश में कश्मीर से पंजाब तक छापेमारी, पुलवामा से दो और संदिग्ध हिरासत में

▶ एक बड़े हवाला नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं सभी आतंकी

▶ लखनपुर में पकड़े गए जैश-ए-मुहम्मद के तीनों आतंकियों से पूछताछ जारी

जम्मू के लखनपुर में पकड़े गए जैश-ए-मुहम्मद के तीन आतंकियों के हैंडलर और अन्य साथियों को पकड़ने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी कश्मीर से लेकर पंजाब तक पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलवामा से दो और संदिग्धों को पूछताछ के लिए कथित तौर पर हिरासत में लिया है। वहीं, पकड़े गए आतंकियों के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। संबंधित अधिकारियों की मानें तो जल्द ही कश्मीरी आतंकियों और खालिस्तानी उग्रवादियों के आपसी गठजोड़ और एक बड़े हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश होगा।

जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से आतंकी और अलगाववादी एजेंडे की नाकामी से हताश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ पूरी तरह हताश है। आइएसआइ आतंकी संगठन जैश के जरिए जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहती है। खुफिया तंत्र ने बीते सप्ताह ही इस साजिश का पता लगाते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर दिया था।

पंजाब के नेटवर्क का किया इस्तेमाल : घाटी में आतंकियों को हथियारों की खेप उपलब्ध कराने के लिए आइएसआइ ने पंजाब में सक्रिय अपने नेटवर्क का सहारा लिया। अमृतसर में इसी नेटवर्क से हथियार लेकर एक ट्रक से कश्मीर लौटते जैश के तीन आतंकियों को गुरुवार को लखनपुर में पकड़ा था। उबैद, जहांगीर और सबील नामक ये तीनों आतंकी कश्मीर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल, तीनों पुलिस रिमांड पर हैं और इनसे पूछताछ जारी है।

ट्रक मालिक की तलाश जारी

सूत्रों ने बताया कि इन आतंकियों से मिले सुराग के आधार पर कश्मीर से लेकर पंजाब तक कई जगह छापेमारी की गई है। दक्षिण कश्मीर में गत रोज पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था। शुक्रवार को दो और लोगों को इसी मामले में पूछताछ के लिए कथित रूप से हिरासत में लिया गया है। इनमें से एक ट्रक मालिक का करीबी बताया जाता है। वहीं, ट्रक मालिक की तलाश भी जारी है।

बड़े हवाला कारोबार का हो सकता है पर्दाफाश

पकड़े गए आतंकियों के मोबाइल फोन से मिले कुछ नंबरों और एसएमएस के आधार पर पुलिस ने कुछ लोगों की निशानदेही की है। इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है या फिर इनके ठिकानों पर लगातार दबिश देकर हिरासत में लिया जा रहा है। मोबाइल फोन का डाटा पूरी तरह खंगालने के लिए उनकी फॉरेंसिक जांच भी कराई जा रही है।

पांच टुकड़ों में विभाजित होने वाला है पाक : इंद्रेश कुमार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार का कहना है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए खत्म करने के बाद पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया है। अब वह पांच-छह टुकड़ों में विभाजित होने की कगार पर है। भारत से अलग होकर 1947 में अस्तित्व में आए पाकिस्तान का विभाजन 1971 में हुआ। अब पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाबी पाकिस्तान क्षेत्र बिखरने और टूटने के कगार पर हैं। पूरा विश्व मान रहा है कि पाकिस्तान दिन-ब-दिन आर्थिक रूप से भी कमजोर होता जा रहा है।

इंद्रेश कुमार नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और विश्व हिंदी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे में 80 हजार वर्ग किलोमीटर, चीन के कब्जे में 43 हजार किलोमीटर क्षेत्र लेना शेष बचा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया गया। यह बहुत बड़ा सच है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों बाद दुनिया के मानचित्र पर पाकिस्तान रहेगा या नहीं इस पर भी वैश्विक स्तर पर चर्चा होने लगी हैं। उन्होंने कहा कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। पाकिस्तान जन्मा हुआ देश है और भारत अजन्मा है। उन्होंने कहा कि यह भी संभव है कि पांच-सात वर्षों में हिंदी सम्मलेन का आयोजन लाहौर में हो। उन्होंने कार्यक्रम में लोगों से यह अपील की कि वे ईश्वर से रोटी-कपड़ा और तरक्की मांगें, लेकिन उसमें एक चीज और मांगे कि उनकी मृत्यु अखंड भारत में हो।

हिंदी को पेट की भाषा बनाने की जरूरत : मृदुला सिन्हा

गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने कहा कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इसे पेट यानी रोजगार की भाषा बनाने की जरूरत है। जब यह पेट की भाषा बनेगी तब हर व्यक्ति अपने बच्चे को हिंदी में पढ़ाने में गर्व महसूस करेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बिना भाषा के किसी भी राष्ट्र की पहचान अधूरी होती है।

न्यूज गैलरी

अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे लोन

नई दिल्ली : सज्जाद लोन के संगठन जम्मू-कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 370 समाप्त किए जाने को चुनौती दी है। यह याचिका जेकेपीसी ने अपने प्रवक्ता अदनान अशरफ के माध्यम से दायर की है। याचिका में राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पांच अगस्त और छह अगस्त के संवैधानिक आदेश असंवैधानिक हैं क्योंकि राज्य सरकार की ली गई सहमति असंवैधानिक है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन भी है। (प्रेट्र)

पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत क्षेत्र में भेजे जा रहे अधिकारी : रावत

नई दिल्ली : सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को कहा कि सेना की परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए 206 अधिकारियों को क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इसी प्रकार क्षेत्र में तैनात अधिकारियों की जानकारी बढ़ाने के लिए वापस मुख्यालय में बुलाया जा रहा है। यह सेना की पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है। रावत ने यहां मीडिया से बातचीत में कहा, 'रक्षा मंत्रालय ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। अब हम लोग योजना को मूर्त रूप दे रहे हैं।' (एएनआइ)

अर्धसैनिक बलों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू होगा

नवीन नवाज, श्रीनगर

▶ पहले चरण में बीएसएफ और सीआरपीएफ होंगी भर्तियां

जम्मू-कश्मीर के युवाओं का देश सेवा के प्रति जोश देखते हुए केंद्र सरकार ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। पहले चरण में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में राज्य के करीब दो हजार युवकों को भर्ती किया जाएगा। इसके बाद सीमा सशस्त्र बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आइटीबीपी) और सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स (सीआइएसएफ) के लिए भर्ती रैलियां की जाएंगी।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद राज्य के युवाओं ने खुलकर आतंकी और राष्ट्र विरोधी एजेंडे को ठेंगा दिखाया है। आतंकियों की धमकियों के बावजूद हजारों स्थानीय युवा गत दिनों हुई सैन्य भर्ती रैली में शामिल हुए थे। प्रस्तावित भर्ती सिर्फ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के योग्य युवाओं के लिए होगी।

भर्ती की रूप रेखा तैयार की जा रही : भर्ती अभियान को शुरू करने के लिए आवश्यक रूप रेखा को तय किया जा रहा है। प्रस्तावित भर्ती में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों के अलावा उन शहरों और कस्बों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां के लोगों का केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में प्रतिनिधित्व नाममात्र ही है। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया केंद्र सरकार के उस वादे को पूरा करेगी जो रोजगार के नए अवसरों के सृजन से जुड़ा है।

सफल न होने वाले युवाओं का मिलेंगे मौके : पहले चरण में होने वाली भर्ती बीएसएफ और सीआरपीएफ की एक साथ नहीं चलेगी। भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद दूसरी भर्ती शुरू होगी ताकि जो युवक किसी एक बल में भर्ती होने में विफल रहे हों वे दूसरी भर्ती में अपना भाग्य आजमा सकें।

जम्मू-कश्मीर के युवाओं पर आधारित होगी बटालियन

बीएसएफ और सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर के युवाओं पर आधारित एक-एक बटालियन तैयार करेंगे। बीएसएफ और सीआरपीएफ के बाद एसएसबी, आइटीबीपी और सीआइएसएफ में भी करीब दो हजार युवाओं को भर्ती करने की योजना है।

40 दिनों बाद उमर अब्दुल्ला से हुई नेशनल कांफ्रेंस के दो सांसदों की मुलाकात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ हरि निवास में मसूदी और लोन ने अलग-अलग डेढ़ से दो घंटे बिताए

▶ सियासी हल्कों में नेशनल कांफ्रेंस की नई सियासी रणनीति की अटकलें

उमर अब्दुल्ला। फाइल फोटो

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला शुक्रवार को करीब 40 दिन बाद अपनी पार्टी के दो सांसदों सेवानिवृत्त जस्टिस हसनैन मसूदी और मुहम्मद अकबर लोन से मिले। दोनों ने अलग-अलग मुलाकात की। इसके बाद से स्थानीय सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि नेकां जल्द राज्य में नई सियासी रणनीति का एलान करते हुए गतिविधियों को शुरू करेगी।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चार अगस्त की मध्यरात्रि से राज्य प्रशासन ने गुपकार स्थित हरि निवास में एहतियातन हिरासत में रखा है। वहीं, उनके पिता डॉ. फारूक अब्दुल्ला अपने घर में ही नजरबंद हैं। हसनैन मसूदी ने उमर के साथ मुलाकात पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करने से इन्कार किया है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि न्यायालय ने हमें इस मुद्दे पर मीडिया या किसी अन्य के साथ बातचीत से मना किया हुआ है। संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि दोनों सांसद उमर के लिए फल और कुछ अन्य सामान बतौर उपहार लेकर आए थे। उमर की इन नेताओं के साथ क्या बातचीत हुई, इससे अनभिज्ञता जताते हुए उन्होंने कहा कि मुलाकात के समय सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अकेले ही थे। उमर साथियों से मिलने के बाद संतुष्ट नजर आ रहे थे।

नेशनल कांफ्रेंस से संबंधित सूत्रों ने बताया कि दोनों सांसदों ने बीते दिनों श्रीनगर में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात पर उनकी राय ली है। उन्होंने जम्मू स्थित पार्टी नेताओं से विभिन्न स्तरों और माध्यमों से बातचीत की है। उन्होंने लोगों के मूड और पार्टी कार्यकर्ताओं की राय से उमर को अवगत कराया है। कहा जा रहा है कि दोनों सांसद पार्टी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला से मिले हैं, लेकिन इसकी हमें जानकारी नहीं है।

सांसदों की याचिका पर कोर्ट ने दिया था निर्देश : नेकां सांसद हसनैन मसूदी और मुहम्मद अकबर लोन ने उमर और डॉ. फारूक से कई बार कथित मुलाकात का प्रयास किया था, लेकिन संबंधित प्रशासन ने उन्हें मौका नहीं दिया था। उन्होंने बीते सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर गत रोज फैसला सुनाते हुए संबंधित प्रशासन को निर्देश दिया था कि वह दोनों सांसदों को उनके नेताओं से मिलवाएं। इसके साथ सांसदों को निर्देश दिया कि मुलाकात शिष्टाचार, कुशलक्षेम जानने तक होनी चाहिए।

महबूबा से मिलने के लिए प्रशासन से संपर्क

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के लिए भी उनकी पार्टी के तीन नेताओं ने संबंधित प्रशासन से संपर्क किया है। बताया जा रहा है उनकी भी अगले एक-दो दिन में मुलाकात होगी।

हवाला कारोबारी के यहां ईडी की छापेमारी, करोड़ों की नकदी बरामद

जागरण संवाददाता, जयपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा के हवाला कारोबार से जुड़े आरोपितों के जयपुर और दिल्ली के ठिकानों पर शुक्रवार को कार्रवाई की। ईडी की जयपुर प्रांत इकाई ने जयपुर व दिल्ली में नौ ठिकानों पर छापेमारी कर चार करोड़ 25 लाख रुपये जब्त किए हैं। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं।

ईडी को जयपुर के कैलाश खंडेलवाल के हवाला कारोबार में शामिल होने की सूचना मिली थी। ऐसे में जयपुर में कैलाश खंडेलवाल, उनके भाई कमल खंडेलवाल, सहयोगी एमडी बांगड और कुनाल लढ्ढा के आवास व कार्यालयों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में अधिकारियों को 4.25 करोड़ की नकदी मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन की पर्चियों के साथ ही दुबई से भारत में हो रही सोने की तस्करी के लिंक भी मिले हैं। उक्त सभी आरोपित भारतीय मुद्रा के बदले अमरीकी डॉलर, यूरो, पाउण्ड आदि के हवाला के कारोबार में लिप्त थे। ईडी के मुताबिक ये विदेशी मुद्राएं भारतीय मुद्रा के बदले विदेश में बसे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराई जाती थीं। ईडी के अधिकारियों को भारत और हांगकांग में स्थित फर्जी कंपनियों के दस्तावेज भी मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन कंपनियों का उपयोग आयात-निर्यात में किया जाता होगा।

चंद्रायन-2

लैंडर से संपर्क स्थापित करने की खत्म होती जा रही उम्मीदें

विक्रम से दोबारा संपर्क जोड़ने के लिए अब बचे हैं सिर्फ सात दिन, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है

बेंगलुरु, प्रेट्र : चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने की उम्मीदें धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं। इन दोनों ही उपकरणों को चांद पर 14 दिनों (चंद्रमा के एक दिन) तक काम करना था। अब हफ्ते भर का वक्त बचा है और अभी तक लैंडर से दोबारा संपर्क स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस सफलता नहीं मिली है।

सात सितंबर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। लैंडर के अंदर ही रोवर प्रज्ञान है। लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लगभग पांच घंटे बाद रोवर प्रज्ञान उससे बाहर आता और विभिन्न शोध कार्यों को अंजाम देता।

ऑर्बिटर ने लैंडर को देखा : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आठ सितंबर को कहा था कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर में लगे कैमरे ने चांद की सतह पर पड़े लैंडर की तस्वीर कैद की है। ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्ष में चक्कर लगा रहा है। सात सितंबर को तड़के विक्रम तय रास्ते से भटक गया था और चांद की सतह पर उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। तब से लैंडर से संपर्क स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं।

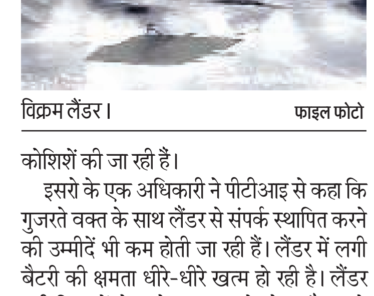
विक्रम लैंडर। फाइल फोटो

इसरो के एक अधिकारी ने पीटीआइ से कहा कि गुजरते वक्त के साथ लैंडर से संपर्क स्थापित करने की उम्मीदें भी कम होती जा रही हैं। लैंडर में लगी बैटरी की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। लैंडर सही दिशा में होता तो उस पर लगे सोलर पैनल से उसकी बैटरी रिचार्ज हो सकती थी।

हार्ड लैंडिंग से नुकसान की आशंका : इसरो के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हार्ड लैंडिंग के चलते लैंडर विक्रम चांद की सतह पर दिशा सही नहीं है। इसके चलते भी उससे संपर्क स्थापित करने में मुश्किल हो रही है। हार्ड लैंडिंग से लैंडर को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है।

विभिन्न तरीकों से होगी जांच : समाचार एजेंसी आइएएनएस से चेन्नई में इसरो के एक पूर्व अधिकारी ने बताया कि लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग में विफलता के असल कारणों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी को कई तरीके अपनाने होंगे, उससे मिले डाटा की जांच करनी होगी, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। अधिकारी ने बताया कि इसरो यह भी पता लगाएगा कि क्या प्रक्षेपण के दौरान किसी खामी की अनदेखी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि गलत डाटा भी संपर्क टूटने का कारण हो सकता है।

समस्याओं, दुर्घटनाओं से निखरता है अनुसंधान : हैरोशे

नई दिल्ली, प्रेट्र : फ्रांसीसी भौतिकशास्त्री और नोबल पुरस्कार विजेता सर्ज हैरोशे ने शुक्रवार को यहां कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में समस्याओं, दुर्घटनाओं और हैरान करने वाली घटनाओं से अनुसंधान में और निखार आता है। उन्होंने कहा कि भारत को चंद्रयान-2 मिशन में मिली विफलता को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए।

भौतिकी के लिए 2012 में नोबल पुरस्कार पाने वाले 75 वर्षीय हैरोशे यहां 'नोबेल प्राइज सीरीज 2019' में शामिल होने आए हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 मिशन एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इस तरह के प्रोजेक्ट से सरकार भी पूरी तरह जुड़ी रहती है। उन्होंने कहा कि शोध के क्षेत्र में इस तरह की खामियां सामान्य हैं। इन खामियों का पता लगाकर उन्हें दूर करना चाहिए और फिर से प्रयास करना चाहिए।

सादी वर्दी में पुलिस ने संभाला मोर्चा

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

राजीव कुमार की गिरफ्तारी से रोक हटने के बाद उनके आवास के बाहर भारी संख्या में सादी वर्दी में कोलकाता पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सीबीआइ सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार का कुछ पता नहीं चल रहा है। उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका मोबाइल स्वीच ऑफ है।

राजीव के समर्थन में ममता ने खोल दिया था मोर्चा : इसी साल फरवरी महीने में पूछताछ के लिए जब सीबीआइ राजीव कुमार के घर पहुंची थी तो काफी हाई बोल्टेज ड्रामा चला था। कोलकाता पुलिस ने सीबीआइ अधिकारियों को पकड़ लिया था। इतना ही नहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो राजीव के बचाव में मोर्चा ही खोल दिया था। वह न केवल राजीव के घर पहुंचीं थीं बल्कि उनके समर्थन में धरने पर भी बैठ गईं थीं। ऐसे में सीबीआइ और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। केंद्र ने सीबीआइ के दफ्तर पर पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात कर दिया था। ऐसे में यह मामला समूचे देश में सुर्खियों में रहा था।

विपक्षी दल हो गए थे एकजुट : ममता ने जब धरना दिया तो उनके समर्थन में विपक्षी दल एकजुट हो गए थे। ममता ने छह फरवरी को उस समय धरना समाप्त किया जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार से न्यूट्रल जगह (कोलकाता से बाहर) पर पूछताछ में सहयोग करने का आदेश दे दिया। साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

मामले में कब-क्या हुआ

नौ फरवरी : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजीव कुमार से सीबीआइ ने शिलांग में कई दिनों तक पूछताछ की।

17 मई : सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी। हाई कोर्ट जाने को कहा।

27 मई : सीबीआइ ने पूछताछ के लिए राजीव कुमार को तलब किया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का रूख किया।

30 मई : हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने कुमार की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ा दी।

3000 रुपये के करीब होगा मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) का किराया। अगले साल मार्च-अप्रैल तक इस परियोजना के विशेष ट्रैक और अन्य परियोजनाओं का काम शुरू हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 सितंबर 2019

भोपाल में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान नाव पलटी, 11 की मौत

दुर्भाग्यपूर्ण ▶ संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा, छह को बचाया गया

कमलनाथ ने मृतकों के परिजनों को 11-11 लाख की मदद का ऐलान किया

नईदुनिया, भोपाल

भोपाल में शुक्रवार तड़के साढ़े चार बजे भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जित करते समय नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। छह लोगों को बचा लिया गया। मुख्यमंत्री कमलानाथ ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मृतक के परिजनों को 11-11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। दो नाविक फरार हैं। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के अनुसार भक्त भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए जहांगीराबाद इलाके में पुलिस मुख्यालय के पास खटलापुरा घाट पर पहुंचे। यहां क्रेन की मदद से मूर्ति को दो नाव पर रखा गया था। घाट से करीब 40 फीट दूर जाने पर मूर्ति को विसर्जित किया जा रहा था कि तभी वजन ज्यादा होने से एक नाव पलट गई। उस नाव में सवार लोग दूसरी नाव पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। इससे वह भी पलट गई। मामले में दो नाविकों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। दोनों फरार हैं।

भोपाल में शुक्रवार को गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान पलटी नाव। (वीडियो ग्रैब)

इनकी हुई मौत : रोहित मौर्य (20), प्रवीण उर्फ सन्नी ठाकरे (22), हरि राणा (20), विशाल उर्फ जोगा सोनवाने (22), करन लुड़ेरे (19), राहुल वर्मा (18), परवेज खान (12), विक्की उर्फ आवेश समसेरिया (19), अर्जुन शर्मा (16), राहुल मिश्रा (18) और अरूण मालवीय (18)। सभी मृतक भोपाल के पिपलानी क्षेत्र के रहने वाले थे।

बंजर भूमि सुधारने के वादे पर खरा उतरेगा भारत : जावडेकर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत ने पर्यावरण संरक्षण और बंजर भूमि को सुधारने के अपने प्रयासों से दुनिया को न सिर्फ लुभाया है, बल्कि वह उनका भरोसा भी जीतने में कामयाब रहा है। इसका अंदाजा यूएनसीसीडी (यूनाइटेड नेशन्स कंवेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टीफिकेशन) की सीओपी (कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज)-14 के अंतिम दिन जारी हुए दिल्ली घोषणापत्र से लगाया जा सकता है। इसमें सभी देशों ने बंजर भूमि को सुधारने और पर्यावरण संरक्षण के भारत के प्रयासों का खुले दिल से स्वागत किया है। इसके साथ ही भारत ने जिस तरीके से आगे बढ़कर बंजर भूमि के सुधारने के 2030 के अपने लक्ष्य में वृद्धि की है। उसे भी बड़ा कदम बताया है।

पेरिस समझौते के तहत भारत को 2030 तक 210 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना था। इसमें भारत में बढ़ोतरी करते हुए अब 260 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया है। पीएम मोदी ने सीओपी-14 में इसका एलान किया था। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस वैश्विक सम्मेलन के अंतिम दिन शुक्रवार को बतौर सीओपी-14 अध्यक्ष पत्रकारों से चर्चा के दौरान दुनिया को फिर से यह विश्वास दिया कि भारत ने जो लक्ष्य तय किया है, वह तय समय से पूरा करेगा।

उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने का अपील की। हालांकि उन्होंने पेरिस समझौते से दुनिया के कुछ बड़े देशों के मुकरने के सवाल पर कहा कि सभी देश एक अंतरराष्ट्रीय समझौते से बंधे हुए हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए दुनिया के सामने दिए गए वचन से पीछे लौटना आसान नहीं होगा।

यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव इब्राहिम थियाव ने भी इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में सीओपी-14 के आयोजन तारीफ की और कहा कि दुनिया को सूखे और पलायन से बचाने की दिशा में यह काफी उपयोगी सम्मेलन रहा है। साथ ही दिल्ली घोषणा पत्र के जरिये आने वाले दिनों में जो कदम उठाए जाने है, वह भी काफी सशक्त होंगे। दुनिया में इससे बदलाव देखने मिलेगा। थियाव ने कहा कि इस मुहिम में हमने मानवीय भागीदारी खासकर महिलाओं को जोड़ने की बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा कि सीओपी-14 में ज्यादातर देशों का साफ मानना है कि जब तक इनमें मानवीय सहभागिता नहीं बढ़ेगी, तब तक इस समस्या से निजात पाना संभव नहीं होगा।

2030 तक भारत ने 260 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को सुधारने का तय किया लक्ष्य

प्रकाश जावडेकर फाइल

सीओपी-14 में 170 देशों ने की शिरकत

ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में 2 से 13 सितंबर तक चले सीओपी-14 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन समेत दुनिया के 170 देशों ने हिस्सा लिया। जावडेकर ने बताया कि इनमें करीब 60 देशों के मंत्री ने भी शिरकत की। इसके साथ दुनिया भर के पांच हजार से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा है।

जमीन उपजाऊ बनाने में निजी क्षेत्र को जोड़ने पर नजर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बंजर जमीन को सुधारने से पर्यावरण के ठीक होने के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी। करोड़ों नई नौकरियां भी पैदा होंगी। जिसे ग्रीन जॉब नाम दिया गया है। अकेले भारत ने यदि बंजर जमीन सुधारने के अपने 2030 के लक्ष्य को पूरा किया, तो इससे उसकी जीडीपी में एक फीसद से ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। साथ ही इससे देश में करीब चार करोड़ नए रोजगार भी सृजित होंगे।

बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए दुनिया ने जिस प्रमुख विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, उसमें एक बड़ा विषय मजबूत वित्तीय तंत्र खड़ा करना भी था। इसके जरिए दुनिया को इस संकट से उबारने के लिए निवेश जुटा सके। मौजूदा समय में दुनिया के करीब 190 देश बंजर भूमि की समस्या से घिरे हुए हैं। इनमें भारत भी शामिल है, जिसकी करीब 30 फीसद भूमि इससे प्रभावित है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में सभी देशों से वित्तीय तंत्र बनाने के साथ निजी क्षेत्र को इस मुहिम में शामिल कर निवेश पर जोर दिया गया है। दुनिया इस मुद्दे पर इसलिए भी सहमत है, क्योंकि ज्यादातर देश बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की मुहिम में लगने वाली राशि को लगाने की स्थिति में नहीं हैं। इनमें ज्यादातर अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं। खुद भारत भी इनमें शामिल है। जहां मौजूदा समय में कुल 960 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि मौजूद है। एक अनुमान के मुताबिक इसे जमीन को ठीक करने के लिए भारत को करीब चार लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

यूएनसीसीडी की सीओपी-14 में जारी किए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र से दुनिया ने सूखे और जल संरक्षण से निपटने के लिए भी एकजुटता दिखाई है।

वाहनों के कागजी दस्तावेज दिखाने जरूरी नहीं होंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वाहन चालकों से डिजिटल डाक्यूमेंट स्वीकार करने के बारे में राज्यों को नए सिरे से एडवाइजरी जारी की जाएगी। इस संबंध में पिछले वर्ष 19 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, लेकिन उसके बारे में कई पुलिसकर्मियों को जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर अनजान बन रहे हैं।

पिछले साल नवंबर में जारी एडवाइजरी में सभी राज्यों के प्रधान सचिवों, परिवहन सचिवों, पुलिस महानिदेशकों को कहा गया था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट तथा परमिट या प्रदूषण प्रमाणपत्र (पीयूसी) को डिजिटल, इलेक्ट्रानिक या ऑनलाइन रूप में वैसे ही माना व स्वीकार किया जाएगा जैसे कागजी दस्तावेज माने व स्वीकार किए जाते हैं। डिजिटल डाक्यूमेंट कागजी दस्तावेज की भांति ही कानूनी रूप से वैध हैं। इसलिए पुलिसकर्मी इन्हें स्वीकार करने से इन्कार नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी सूचना मिल रही है पुलिसकर्मी इसे मानने से इन्कार कर रहे हैं। खासकर छोटे शहरों में यह समस्या आ रही है।

दस्तावेज की तस्वीरों को नहीं माना जाएगा डिजिटल डाक्यूमेंट : दस्तावेज की तस्वीरों को डिजिटल डाक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। इसके लिए सड़क मंत्रालय के 'एम परिवहन' एप अथवा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'डिजिलॉकर' एप को डाउनलोड कर दस्तावेज हासिल करने होंगे। ये एप आपके डीएल, आरसी, इंश्योरेंस, परमिट, पीयूसी आदि के बारे में पूरी जानकारी देंगे। एम-चालान एप में डीएल, वाहन या परमिट का नंबर डालते ही पूरा डाक्यूमेंट सामने आ जाएगा। इसमें वाहन का ई-चालान कितनी बार हुआ है यह भी पता चल जाएगा। इसमें किराए पर ली गई टैक्सी (ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर) के चालक के बारे में भी जानकारी प्राप्त होगी। डिजिलॉकर उतना ही सुरक्षित है जितना ऑनलाइन बैंक एकाउंट।

झारखंड में तीन माह तक नहीं लगेगा भारी जुर्माना

जेएनएन, नई दिल्ली

हाल ही में लागू संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी चालान से लोगों को राहत देने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को झारखंड सरकार ने नए कानून के तहत भारी भरकम जुर्माने से तीन माह तक राहत देने का फैसला किया। इस दौरान पुराने कानून के तहत ही कार्रवाई होगी। हरियाणा सरकार तीन दिन चालान नहीं काटने का निर्णय कर चुकी है।

मालूम हो कि नए वाहन कानून का गैर भाजपा शासित राज्य शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर राज्यों ने विचार-विमर्श के बाद इसे लागू करने की बात कही है, लेकिन भाजपा शासित गुजरात की सरकार द्वारा चालान दरों में कमी की घोषणा के बाद राहत देने सिलसिला तेज हो गया है। शुक्रवार को हुई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तीन माह तक यातायात नियमों को लेकर लोगों के बीच सघन जागरूकता अभियान चलाया जाए। इस अवधि में लोगों को अपनी गाड़ियों के कागजात अपडेट कराने का भी समय मिल जाएगा।

विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हरियाणा सरकार ने गत गुरुवार से तीन दिन तक चालान नहीं काटने का फैसला किया। शुक्रवार से रविवार तक किसी वाहन का चालान नहीं काटा जाएगा। पुलिसकर्मी फूल देकर ट्रैफिक नियमों का पालन करने की गुजारिश करेंगे।

बिहार में जुर्माने के डर से नहीं निकाल रहे गाड़ियां : बिहार में जुर्माने की डर से आधे-अधूरे कागजात वाली गाड़ियां सड़कों से हट गई हैं। पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस माह 1 से 8 सितंबर के बीच पेट्रोल के मामले में इंडियन ऑयल की बिक्री में 19 फीसद, भारत पेट्रोलियम की बिक्री में 24.2 फीसद और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बिक्री में 20.2 फीसद की गिरावट है। डीजल में भी यही हाल है।

चंडीगढ़ में प्रशासक और सांसद के अलग-अलग सुर : केंद्र शासित चंडीगढ़ में नये कानून को लागू करने को लेकर प्रशासक वीपी सिंह बदनौर और भाजपा सांसद किरण खेर के अलग-अलग सुर सामने आए हैं। शुक्रवार को हुई बैठक में बदनौर ने दो महीने नरमी बरतने का डीजीपी को सुझाव दिया तो सांसद किरण खेर ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है नरमी बरतने की, पुलिस नियम तोड़ने पर सख्ती बरते।

उप्र में मौके पर पुरानी तो कोर्ट जाने पर नई दर से चालान : उत्तर प्रदेश में चालान के दो सिस्टम चलेंगे। राज्य के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अशोक कटारिया ने कानपुर में स्पष्ट किया कि प्रदेश में यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान की पुरानी दरें ही लागू हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नई दरों से चालान न करें। हालांकि, मौके पर चालक जुर्माना न भरकर कोर्ट जाता है तो वहां नई दर से शमन शुल्क वसूला जाएगा।

रविदास मंदिर मामले की स्वीकार्यता पर सोमवार को विचार करेगा कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पूजा-पाठ के संवैधानिक अधिकार की दुहाई दे दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को दोबारा बनवाए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट पहले इस बात पर विचार करेगा कि याचिका सुनवाई योग्य है कि नहीं। यह याचिका हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गत 10 अगस्त को मंदिर तोड़ा गया था। शुक्रवार को न्यायमूर्ति आर भानुमती और एएस बोपन्ना की पीठ ने मामले पर संक्षिप्त सुनवाई में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल किये जाने पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि यह मामला संविधान मे मिले पूजा अर्चना के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि वह स्थान पवित्र है क्योंकि वहां संत रविदास स्वयं रहे थे। संत रविदास के करोड़ों अनुयायी मंदिर तोड़े जाने से आहत हुए हैं। इस पर कोर्ट ने सिंह से पूछा कि मंदिर कैसे ढहा। सिंह ने कहा कि एक अवैध कब्जाधारी ने मंदिर की संपत्ति पर दावा करते हुए 1992 में केस दाखिल किया था और वह सुप्रीम कोर्ट तक से केस हार गया। डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का कब्जा अपने पास ले लिया था और फिर उसे ढहा दिया। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि ऐसे में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। सिंह ने कहा कि संपत्ति से जुड़े उस मामले में रविदास समुदाय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था क्योंकि वह रिप्रजेन्टेटिव सूट नहीं था। ऐसे मे वे लोग कोर्ट के उस आदेश से बंधे नहीं है। उनकी उस मंदिर में आस्था थी और उनका पूजा-अर्चना का संवैधानिक अधिकार बाधित हुआ है। शुरुआत में कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता को दूसरी कोर्ट में मामला लगवाने के लिए रजिस्ट्री के पास जाने को कहा। लेकिन बाद में सिंह के अनुरोध पर कोर्ट मामले पर सोमवार को विचार करने को तैयार हो गया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पहले वह याचिका की स्वीकार्यता पर ही विचार करेंगे। कोर्ट ने अभी तक याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया है।

याचिका में उस भूमि को पवित्र बताते हुए वहां पूजा-अर्चना का अंतरिम अधिकार मांगा गया है जबकि मुख्य मांग है कि मंदिर और सरोवर की पुर्नस्थापना कराई जाए। मंदिर को प्राचीन बताते हुए प्लेस ऑफ वरशिप कानून 1991 का हवाला भी दिया गया है।

घूंघट में फोटोग्राफी...

यह हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के पालदा गांव की 65 वर्षीय लोकप्रिय फोटोग्राफर शांता बाई। इनका अपने काम के प्रति जज्बा काबिल-ए-तारीफ है। ग्रामीण परिवेश के बावजूद शांता 2003 से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रही हैं। गांव में कहीं भी शादी-ब्याह हो अथवा कोई अन्य कार्यक्रम लोग फोटोग्राफी के लिए उन्हें ही बुलाते हैं। डिजीटल कैमरों के दौर में भी वह रील वाले मैनुअल कैमरे का ही इस्तेमाल करती हैं। उनका रहन-रहन एकदम साधारण है और हमेशा घूंघट में रहती हैं। शुक्रवार को ब्रजभूमि फाउंडेशन की ओर से 51 महिलाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए सम्मानित किया गया, उनमें शांता भी एक थी। प्रफुल्ल चौरसिया 'आशु' (नईदुनिया)

राकांपा नेता सुप्रिया सुले को कैब चालक ने किया परेशान

मुंबई, आइएएनएस : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार की बेटी व सांसद सुप्रिया सुले को गुरुवार को मध्य रेलवे के दादर टर्मिनस पर पहुंचने पर एक कैब चालक ने परेशान किया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) से इसकी शिकायत की। आरपीएफ ने शीघ्र ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया। सुले ने इसके लिए आरपीएफ की तारीफ भी की। शिकायत में सुले ने कहा है कि कैब चालक कुलजीत सिंह मल्होत्रा उनकी ट्रेन के डिब्बे में घुस गया और उन पर टैक्सी सेवा लेने के लिए दबाव बनाने लगा। उन्होंने कहा, 'दो बार मना करने के बाद उसने मेरा रास्ता रोक दिया। मुझे परेशान किया और बेशर्मी के साथ तस्वीर लेने की भी कोशिश की।' सुले ने बाद में इस मामले पर ट्वीट भी किया। रेल मंत्री पीयूष गोयल को टैग करते हुए उन्होंने पोस्ट किया, 'कृपया इस मामले को देखें, ताकि दोबारा यात्रियों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर कानूनन ग्राहकों की खोज वैध है, तब भी रेलवे स्टेशन या एयर पोर्ट और यहां तक कि अधिकृत टैक्सी स्टैंड पर भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।' आरपीएफ ने कैब चालक को पकड़ लिया और उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया। टिकट न होने पर उसके खिलाफ 260 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ड्राइविंग लाइसेंस न होने और वर्दी न पहनने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने भी आरोपित के खिलाफ 400 रुपये का जुर्माना लगाया।

ज्वार खाओ रोग भगाओ

ज्वार एक स्वास्थ्यवर्धक मोटा अनाज है। पूरी दुनिया में इसकी दो दर्जन से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन ज्वार की केवल एक ही किस्म जिसे बायकलर ज्वार कहते हैं, जिसे मनुष्य खा सकता है। ज्वार की रोटी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। औषधीय गुणों के साथ इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में ज्वार का सेवन शीतलता प्रदान करता है। आइए जानते हैं, ज्वार को अपने भोजन में शमिल करने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

रोगों के लिए रामबाण

- इसमें मौजूद फाइबर आपकी भूख को नियंत्रित रखता है, जिसके कारण आपके खाने की मात्रा कम हो जाती है और काफी समय तक आपको भूख का एहसास नहीं होता, जो आपको अपना वजन घटाने में सहायता करता है।
- इसमें मौजूद में एंटीऑक्सीडेंट कैंसर को रोकने में सहायता करते हैं।
- इसमें मौजूद आयरन की एनीमिया के खतरे को कम करता है।
- ज्वार में पाए जाने वाले दो प्रकार के खनिज, कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के ऊतकों के समुचित विकास के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं।
- इसमें अति आवश्यक विटामिन बी 3 का एक प्रकार पाया जाता है, जिसे नियासिन कहते हैं। यह नियासिन भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करके, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
- ज्वार के चोकर में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जिसे टेनिन कहते हैं। यह एंजाइम हमारे शरीर द्वारा स्टार्च के अवशोषण पर उचित रोक लगा कर, शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोज के स्तर को संतुलित व नियमित करने में सहायता करता है, जिसके कारण मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के ग्लूकोज के स्तर में तेजी से होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिलती है, और इस वजह से मधुमेह के दौरे और उससे उत्पन्न अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को रोकने में भी मदद मिलती है।
- ज्वार की रोटी आपको सीलिएक नामक एलर्जी से सुरक्षित रखती है।

घरेलू इलाज में मददगार

- इसका आटा पानी में घोलकर लेप करने से शरीर की जलन दूर हो जाती है।
- भुनी हुई ज्वार जिसे 'फल्या' या 'खील' कहते हैं। बतासों के साथ खाने से पेट की जलन ठीक हो जाती है।
- ज्वार के आटे को पानी में मिलाकर रात में गाढ़ा उबाल लिया जाए और अंधेरी जगह में रख दिया जाए, सुबह इसमें जीरा और छाछ मिलाकर पीने से पेट की जलन कम होती है। इससे एसिडिटी में काफी फायदा होता है।
- ऐसा माना जाता है कि पीलिया रोग होने पर इसके बीजों को उबालकर रोगी को इसका पानी देने से रोग दूर हो जाता है।

लाए बदलाव

पर्यावरण संरक्षण संग स्वच्छता का संदेश दे रहे जमदेशपुर के समरजीत, लगा चुके हैं 1200 पेड़, खुद उठाते हैं ट्री गार्ड का खर्च

भगवान और महापुरुषों के नाम पर रख दिए पेड़ों के नाम

निर्मल प्रसाद, जमशेदपुर

झारखंड में जमशेदपुर पूर्वी के गोलमुरी इलाके में जब आप सड़क से गुजरेंगे तो बरबस नजरें कुछ पेड़ों पर टिक जाएंगी। तार की जाली से घेरे गए इन पेड़-पौधों के बाड़े पर भगवानों और महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं। इन पेड़ों को उन्हीं का प्रतीक माने जाने की अपील भी की गई है। खास बात यह है कि पेड़ों के भगवान के नाम से नामकरण में यहां सर्वधर्म सद्भाव भी दिखता है। राम, कृष्ण, रहीम, गुरु नानक देव, गुरु गोबिंद सिंह और रविदास के रूप ये पेड़-पौधे पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। जमशेदपुर के समरजीत सिंह चावला पिछले कई वर्षों से पेड़-पौधों का संरक्षण और संवर्धन कुछ इसी अंदाज में कर रहे हैं।

समरजीत बताते हैं कि पेड़-पौधे हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। सदियों से ये पूज्य रहे हैं। वह कहते हैं कि पेड़-पौधों के आसपास लोगों को मल-मूत्र त्याग करते और गंदगी फैलाते देखते थे तो तकलीफ होती है। ऐसे में बहुत सोच-विचार कर पहले पेड़-पौधे लगाने और फिर उनकी देखभाल करने और उनके आसपास गंदगी न फैलाने के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके बाद भी गंदगी देख दुख होता था। फिर मन में एक विचार आया और पेड़-पौधों को अपने खर्च से तार की जाली (ट्री गार्ड) से घेरकर उन पर भगवान, महापुरुषों के नाम लिखवा दिए। अब कोई भी पेड़-पौधों के आसपास गंदगी फैलाता हुआ नजर नहीं आता।

जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में पेड़ों के साथ खड़े समरजीत सिंह चावला। जागरण

चलाया प्रभावी अभियान : गोलमुरी के विजयनगर निवासी समरजीत 2002 में उषा मार्टिन कंपनी से शिफ्ट मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए। अब वह 78 साल के हैं। जब वह गोलमुरी में रहने के लिए आए तो यहां गंदगी का अंबार देखकर मन दुखी हो गया। इसलिए खुद ही पूरे क्षेत्र की सफाई करने का बीड़ा उठाया। अपने पैसों से वॉल पेंटिंग करा कर लोगों से अपील की कि कचरा कूड़ेदान में ही डालें। जहां से कचरे की सफाई की, वहीं एक पौधा भी लगा दिया।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें www.jagran.com/topics/positive-news

18 वर्षों से कर रहे पौधरोपण

समरजीत पिछले 18 वर्षों में लगभग 1200 पौधे लगा चुके हैं। पेड़ों को बचाने के लिए अपने पैसे से ट्री गार्ड लगाते हैं। एक ट्री गार्ड की कीमत लगभग छह हजार रुपये है। यह काम वह अपनी पेंशन से देते हैं। वह अब तक अपने आवासीय क्षेत्र विजयनगर, आकाशदीप प्लाजा के सामने वाली सड़क, शिव मंदिर लाइन, मिलन रोड व बस्ती के मुख्य द्वार पर पौधे लगाकर उन्हें भगवान व महापुरुषों का नाम दे चुके हैं। वह हर दिन खुद पौधों की देखरेख कर उन्हें पानी भी देते हैं। समरजीत के साथ इस नेक काम में उनके परिजन भी साथ देते हैं।

कामिनी, रात की रानी, अशोक, जावा के पौधों से फूल खिलते हैं तो देख कर मन झूम उठता है। अब तो इनका उपयोग स्थानीय लोग भी पूजा-पाठ के लिए करते हैं। जीवन बचाए रखने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है।
-समरजीत सिंह चावला, पर्यावरण प्रेमी, जमशेदपुर

केबीसी-11 के पहले करोड़पति बने बिहार के सनोज राज

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

अगर खुद पर दृढ़ विश्वास हो तो मनचाही मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। ऐसे ही दृढ़ विश्वास के साथ कौन बनेगा करोड़पति-11वें सीजन की हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठकर बिहार के जहानाबाद जिले के डोंगरा गांव के सनोज राज ने एक करोड़ रुपये जीत लिए हैं। इस जीत के साथ ही सनोज केबीसी की 11वें सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं। एक करोड़ जीतने के बाद सनोज ने सात करोड़ का सवाल भी खेला, लेकिन सही जवाब न पता होने की वजह से उन्होंने आगे न खेलने का फैसला किया।

सिविल सर्विसेस की तैयारी कर रहे सनोज को जब अमिताभ बच्चन ने बताया कि एक करोड़ के लिए दिया गया उनका जवाब सही है, तब वह खो गए थे। अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। बचपन से केबीसी देखते आ रहे सनोज का कहना है कि हॉट सीट पर दिल की धड़कनें तेज थीं। उनका कहना है कि अमिताभ सर ने अपनी बातों और सरलता से माहौल को काफी सरल बना दिया था। उनकी वजह से स्टेज का डर खत्म हो गया था। 13 सदस्यीय संयुक्त परिवार में रहने वाले सनोज के पिता किसान हैं। सनोज पिता पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए पश्चिम बंगाल से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कैंपस सेलेक्शन के बाद नौकरी करने लगे। साथ ही सनोज सिविल सर्विसेस की तैयारी भी कर रहे हैं। यूपीएससी की पढ़ाई उन्हें केबीसी के सवालों के सही जवाब देने में काम आई। आईएएस बनने की इच्छा रखने वाले के साथ वह पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं। वह ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहते हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण में मदद मिले।

बिहार के सनोज राज (वीडियो ग्रैब)

66,399 पदों के लिए उत्तराखंड में होंगे पंचायत चुनाव। 20 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ प्रारंभ होगी चुनाव की प्रक्रिया। मतदान छह, 11 व 16 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 21 अक्टूबर को होगी।

पुलिस की निगरानी में चिन्मयानंद

शिकंजा ▶ शुक्रवार को दिन में घंटों जांच के बाद रात को अचानक दोबारा आश्रम पहुंची एसआइटी

एक कमरा छोड़ बाकी आश्रम सील

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

दुष्कर्म के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर विशेष जांच दल (एसआइटी) का शिकंजा कसने लगा है। एसआइटी के सदस्य गुरुवार-शुक्रवार रात लगभग 3 बजे मुमुक्षु आश्रम स्थित स्वामी चिन्मयानंद के आवास दिव्य धाम पहुंचे थे। वहां भूतल पर कार्यालय व एक कांफ्रेंस हॉल है, प्रथम तल पर पांच कमरे हैं। इनमें एक चिन्मयानंद का शयन कक्ष है। बाकी चार कमरे भी उन्हीं के उपयोग के लिए हैं। एसआइटी ने इनमें से एक कमरा छोड़ शयन कक्ष समेत बाकी कमरे और भूतल पर उनका कार्यालय व कांफ्रेंस हॉल सील कर दिया। इसके साथ ही एक गारद फोर्स तैनात कर दी जो चिन्मयानंद की हर वक्त निगरानी करेगी। उन्हें हिदायत दी गई है कि जो कमरा खुला छोड़ा गया है, उसी में रहें। इसके बाद शुक्रवार तड़के करीब 4.30 बजे टीम चली गई। इससे पहले गुरुवार को भी एसआइटी ने चिन्मयानंद से करीब सात घंटे तक पूछताछ की थी।

छात्रा व उसके परिजनों को बुलाया : शुक्रवार सुबह ही एसआइटी ने छात्रा व उसके परिजनों को सूचना भेज दी कि आश्रम पहुंचें।

शाहजहांपुर स्थित एसएस कॉलेज में अवकाश घोषित किए जाने के बाद तैनात पुलिस फोर्स। जागरण

दोपहर सवा बजे पहले पुलिस सुरक्षा में छात्रा व उसके पिता आश्रम पहुंचे। छात्रा को दिव्य धाम ले जाया गया। उससे चिन्मयानंद के कमरे के बारे में पूछा गया। आरोप था कि चिन्मयानंद उसे वहीं बुलाते थे, इसके बारे में जानकारी ली गई। इसके बाद सील कमरे को खोला गया, छात्रा को वहां ले जाकर कुछ बयान दर्ज किए गए। फोरेंसिक टीम ने भी वहां से सुबूत एकत्र किए। शुक्रवार रात करीब दस बजे एसआइटी दोबारा मुमुक्षु आश्रम पहुंच गई। स्वामी चिन्मयानंद से कुछ और सवाल किए।

अचानक कर दी गई छुट्टी : आश्रम परिसर में ही चिन्मयानंद के एसएस परास्नातक डिग्री कॉलेज और एसएस लॉ कॉलेज संचालित होते हैं। शुक्रवार सुबह दस बजे अचानक कॉलेज में अवकाश का नोटिस लगा दिया गया। माना जा रहा है कि शनिवार को भी कॉलेज में जांच होगी।

मोबाइल बाहर रखवा देते थे, खुफिया कैमरे से बनाया वीडियो : बीते मंगलवार को कथित तौर पर स्वामी चिन्मयानंद का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। छात्रा जिसे मुंहबोला भाई बता रही थी, उस संजय सिंह ने जागरण को बताया कि वीडियो इसी साल का बना हुआ है। जनवरी में छात्रा ने उसे स्वामी चिन्मयानंद के बारे में कई बातें बताईं। संजय ने वीडियो बनाने को कहा तो छात्रा ने कहा, कमरे में बुलाने से पहले चिन्मयानंद उसका मोबाइल फोन बाहर ही रखवा देते हैं। तब ऐसा कैमरा खरीदा जो चश्मे पर लगा था। वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया इस पर कहा कि चिन्मयानंद ने अपने गुर्गों से छात्रा का नहाते हुए वीडियो बना लिया था। सबक सिखाने के लिए वही रास्ता हमने अपनाया। कहा कि कुछ और सुबूत भी हैं।

... बस संजय की चिंता थी : कथित तौर पर चिन्मयानंद के वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार शाम को ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसे रंगदारी प्रकरण से जोड़ा गया था। जिसमें कार सवार पांच युवक स्वामी चिन्मयानंद को मैसेज कर मांगे गए पांच करोड़ रुपये आदि पर बातचीत कर रहे है। उसमें शामिल संजय के तहेरे भाई ने जागरण को बताया कि कार में हम लोग ही थे। चूंकि संजय लड़की की मदद कर रहा था इसलिए हम उसके साथ हो गए। हमें लड़की या चिन्मयानंद से कोई मतलब नहीं।

विकास के खिलाफ नहीं पर जंगल नष्ट नहीं होने चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने गोवा सरकार से कहा है कि वह सतत विकास के विरुद्ध नहीं है, लेकिन वन क्षेत्र को किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन सिर्फ इसलिए गोवा को बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास राष्ट्रीय औसत से अधिक वन क्षेत्र है। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।

जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने शुक्रवार को सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह उन नेताओं के खिलाफ हैं जो अदालती आदेशों को अपने विवेकहीन मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। खंडपीठ ने कहा कि सतत विकास के लिए हम आपके साथ हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जंगल उजाड़ देंगे। हम आपको एक भी पेड़ काटने की इजाजत नहीं देंगे।

इससे पहले, मेहता ने कोर्ट को बताया कि गोवा में करीब 62 फीसद जंगल है। यह राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि तो क्या इससे आपको इसे नष्ट करने का अधिकार मिल गया। आप भाग्यशाली हैं कि इतना बड़ा वन क्षेत्र है। हमारा निवेदन यही है कि इसे नष्ट न करें। मेहता ने अदालत को बताया कि वह वन क्षेत्र को कतई नष्ट नहीं करना चाहते हैं। वह गोवा में कोई भी पेड़ काटने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ उस याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें गोवा पर 4 फरवरी, 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने की अपील की गई है।

अधिक तापमान के चलते बिहार में एईएस ने बरपाया था कहर

- केंद्रीय जांच टीम ने केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट
- किसी खाद्य पदार्थ को नहीं माना जिम्मेदार, टीम ने बीमारी से बचाव के कई सुझाव भी दिए

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों पर कहर बरपाने वाली एईएस (एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) का नाता किसी फल या खाद्य पदार्थ से नहीं, बल्कि तेज गर्मी से है। जब तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहता है तो बच्चों के बीमार होने की संख्या बढ़ जाती है। केंद्रीय टीम की जांच और शोध में यह बात सामने आई है। टीम के प्रमुख वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के राष्ट्रीय सलाहकार डॉ. अरुण कुमार सिंह ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए बीमारी से बचाव के कई सुझाव भी दिए हैं। ज्ञात हो कि एईएस से उत्तर बिहार में इस वर्ष छह सौ से अधिक बच्चे पीड़ित हुए। इनमें से 160 ने दम तोड़ दिया।

अरब-राजस्थान भी रहा शोध का केंद्र बिंदु : डॉ. अरुण ने सर्वाधिक गर्मी प्रभावित इलाके को केंद्र बिंदु मानकर शोध किया। वह बताते हैं कि राजस्थान या सऊदी अरब में काफी गर्मी पड़ती है लेकिन, अंतर यह है कि वहां हर साल गर्मी में एक तरह का तापमान रहता है। जबकि, मुजफ्फरपुर में हर साल गर्मी में तापमान एक समान नहीं रहता है। यहां जिस साल 40 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान होता है, उस समय बच्चे बीमार होते हैं। शोध में पता चला कि वर्ष 2012 और 2014 में तापमान ज्यादा रहा। तब भी बच्चे प्रभावित हुए थे। इस साल भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा, इसलिए ज्यादा बच्चे बीमार हुए। उनका मानना है कि किसी इंफेक्शन या वायरस से यह बीमारी नहीं हो रही।

कार्निटाइन की कमी पाई गई : वर्ष 2014 में एईएस का प्रकोप ज्यादा था, तब अमेरिका में बच्चों के खून और पेशाब की जांच कराई गई थी। इस साल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु में जांच कराई गई। 2014 की तरह इस बार की भी रिपोर्ट सामान्य है। इस बार एक नई बात सामने आई कि बच्चों में कार्निटाइन की कमी मिली। यह शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। इलाज के क्रम में कार्निटाइन की मात्रा दी गई तो बच्चे जल्द स्वस्थ हुए।

तेज धूप में निकलने और खेलने से हुए पीड़ित : बीमार बच्चों की पैथोलॉजी और मांसपेशियों की जांच हुई तो पाया गया कि उनका सिर्फ मस्तिष्क ही नहीं, बल्कि हार्ट (हृदय) और लिवर (यकृत) सहित दूसरे अंग भी प्रभावित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तीन से चार साल के बच्चे बीमार पाए गए। वे ऐसे बच्चे थे, जो पहली बार तेज धूप में निकले और दो-तीन दिन खेलते रहे। उसके बाद माइट्रोकांड्रिया ने एनर्जी बनाना कम कर दिया। बीमार हुए तो उनको बचाना मुश्किल हो गया।

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल। फाइल

2012-13 में हुए शोध में सामने आई थी यही बात

श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. गोपाल शंकर सहनी ने कई वर्ष पहले एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पर एक शोध किया था। 2012-2013 में मेडिकल जर्नल में प्रकाशित शोध में यही बात सामने आई थी कि इस बीमारी का रिश्ता गर्मी से है।

टीम ने सरकार को ये दिए सुझाव

- सर्वाधिक गर्मी यानी मई-जून में गांव में बच्चों के खेलने की जगह बने, जहां अस्थायी या स्थायी टेंट या शेड बनाया जाए। वहां सुबह 11 से दो बजे के बीच छोटे बच्चे खेलें।
- मई-जून में आंगनबाड़ी सेंटर की ओर से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए।
- परिजन बच्चों को दोपहर में नहीं जाने दें। ज्यादा से ज्यादा पानी दें।
- बच्चों को ज्यादा देर तक भूखे पेट नहीं रहने दिया जाए।
- गर्मी के दिन में शिविर लगाकर कार्निटाइन की जांच हो तथा उसकी आपूर्ति की जाए।
- यदि बच्चा बीमार हो तो तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाए।
- सरकारी अस्पताल में आइसीयू व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

दो हजार करोड़ के रक्षा सौदों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मिलेगा भारी बढ़ावा

सरकार ने देश की सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपये की रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से मेक इन इंडिया की नीति और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को भारी बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया। इस फैसले के बाद सेनाओं के लिए देश में ही बने दो हजार करोड़ रुपये की लागत के हथियार खरीदने का रास्ता साफ हो गया है।

रक्षा खरीद परिषद (डीएसी) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सेना के टी-72 और टी-90 टैंकों की 125 मिमी. की तोपों के लिए विशेष गोले, आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज्ड डिस्कार्डिंग सेबोट (एपीएफएसडीएस) के स्वदेशी विकास और उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है।

वहीं डीएसी की इस बैठक में रक्षा शोध एवं विकास संगठन द्वारा विकसित और भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित मैकेनिकल माइन लेयर (सेल्फ प्रोपेल्ड) भी खरीदने का फैसला लिया गया है। इससे भारतीय थलसेना की स्वचालित तरीके से बारुदी सुरंगे बिछाने की क्षमता में भारी इजाफा होगा। गौरतलब है कि सरकार रक्षा साजो सामान के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति लागू कर रही है। इसके तहत विदेशी हथियार कंपनियों को भी भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

'आकाश' के लिए बीईएल के साथ करार : रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ मिलकर वायुसेना के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम की सात स्क्वाड्रन खरीदने का करार किया है, जिसकी लागत 5357 करोड़ तक आएगी। इन मिसाइलों को देश के अलग-अगल हिस्सों में तैनात किया जाएगा। बीईएल इस मिसाइल सिस्टम को तीन वर्ष के अंदर वायुसेना को सौंपेगा।

चेन्नई में अवैध होर्डिंग ने ली महिला इंजीनियर की जान, हाई कोर्ट सख्त

- हाई कोर्ट की टिप्पणी, सड़क रंगने के लिए सरकार को कितना खून चाहिए
- सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी की तरफ से चेन्नई में लगाया गया था होर्डिंग

चेन्नई, प्रेट्र : तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के पदाधिकारी की तरफ से शादी समारोह के लिए लगाए गए होर्डिंग ने 23 वर्षीय महिला इंजीनियर की जान ले ली। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'राज्य सरकार को सड़क रंगने के लिए और कितने लीटर खून की जरूरत है।' इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी गम और गुस्सा छाया रहा।

पुलिस के अनुसार, महिला इंजीनियर की पहचान आर. शुभश्री के रूप में हुई। जब वह एक सॉफ्टवेयर फर्म में ड्यूटी पूरी करने के बाद गुरुवार को घर लौट रही थी तो पल्लावरम तोराईपक्कम रोड पर एक होर्डिंग उसकी स्कूटी पर गिर पड़ा। वह असंतुलित होकर सड़क पर गिर पड़ी और पीछे से आ रहे एक टैंकर ने उसे कुचल दिया। आनन-फानन में लोग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। टैंकर चालक को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारी जनाक्रोश के बाद पुलिस ने अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

आर. शुभश्री। फाइल फोटो

हमने सरकार से विश्वास खो दिया है : कोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एम. सत्यनारायण और एन. सेशासयी की पीठ ने इससे संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की। पीठ ने कहा, 'यह नौकरशाही की विफलता है। देश में जिंदगी के प्रति कोई सम्मान नहीं है। हमने सरकार से विश्वास खो दिया है। जरा कल्पना कीजिए, वह महिला इंजीनियर देश की जीडीपी में योगदान दे सकती थी। क्या नेता अपनी पारिवारिक शादी बिना किसी बैनर के नहीं कर सकते?' कोर्ट ने कहा कि अब राजनीतिक दलों को इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करना चाहिए।

इस घटना के बाद राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध होर्डिंग के खिलाफ आक्रोश भड़क गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। इस बीच सत्ताधारी अन्नाद्रमुक और मुख्य विपक्षी दल द्रमुक ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ऐसे होर्डिंग न लगाएं, जिनसे आम लोगों को परेशानी हो। दूसरे दलों ने भी ऐसी ही अपील की।

ईडी ने 'पीडब्ल्यूसी' को जारी किया 230 करोड़ जुर्माने का नोटिस

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुराष्ट्रीय अकाउंटिंग कंपनी प्राइसवाटरहाउस (पीडब्ल्यूसी) प्राइवेट लिमिटेड और छह अन्य के खिलाफ विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन मामले में 230 करोड़ रुपये से ज्यादा के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि फेमा के तहत इस नोटिस को ईडी के विशेष निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा जांच पूरी कर लेने के बाद जारी किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी और छह अन्य ने गलत तरीके से 'अनुदान' दिखाकर 'प्राइसवाटरहाउस कूपर्स सर्विसेज बी.वी.' से विदेशी निवेश हासिल किया था ताकि फेमा के प्रावधानों से बच सकें। इस निवेश के लिए उन्हें सरकार या कहें भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी हासिल करना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने फेमा के दृष्टिकोण से कंपनी के मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन की जनहित याचिका के आधार पर दिया था। अधिकारियों ने बताया कि यह कंपनी फाइनेंशियल फोरेंसिक, फाइनेंशियल रिस्क कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, डील्स एंड ट्रांजेक्शंस और टैक्स मैटर्स समेत वित्तीय सेवाएं देने में संलिप्त थी।

सीबीआइ डीआइजी को घूस देने की कोशिश में कंपनी अधिकारी गिरफ्तार

- सोमा एंटरप्राइजेज के वाइस प्रेसिडेंट ने लंबित जांच को खत्म करने के लिए दिया था दो करोड़ का प्रस्ताव
- 11 सितंबर को सीबीआइ ने दर्ज की थी शिकायत

नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमा एंटरप्राइजेज के वाइस प्रेसिडेंट पीआर राव को सीबीआइ ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। राव पर कंपनी के खिलाफ चल रही जांच को खत्म करने के लिए सीबीआइ के डीआइजी स्तर के अधिकारी को दो करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप है।

सीबीआइ इस मामले में गुरुवार की सुबह गृह मंत्रालय के अधिकारी धीरज सिंह व एक अन्य दिनेश चंद गुप्ता को गिरफ्तार कर चुकी है। गुप्ता की तरफ से सीबीआइ अधिकारी को रिश्वत की पेशकश करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले वर्ष 2013 में भी वह एजेंसी के एसपी विवेक दत्त को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश कर चुका है। वर्ष 2017 में सीबीआइ की विशेष अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दत्त को बरी कर दिया था, लेकिन गुप्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अधिकारी ने बताया, गृह मंत्रालय के पुलिस-1 डिवीजन में तैनात सिंह ने कथित तौर पर ए. गर्ग को बैठक के लिए बुलाया और वहीं पर सोमा एंटरप्राइजेज के खिलाफ लंबित जांच को खत्म करने के लिए बतौर रिश्वत दो करोड़ रुपये की पेशकश की। यह पेशकश राव की तरफ से की गई थी। तमिलनाडु कैडर के आइपीएस अधिकारी गर्ग ने इसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और एक शिकायत दर्ज कराई।

11 सितंबर 2019 को शिकायत दर्ज होने के बाद सीबीआइ ने गर्ग के दावे की पुष्टि के लिए दूसरी शाखा के एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी। तय हुआ कि एक अधिकारी गर्ग का ड्राइवर बनकर जाएगा और आरोपितों के साथ होने वाली बात को रिकॉर्ड करेगा।

गर्ग ने सिंह और गुप्ता को दफ्तर के पास सीएनजी स्टेशन पर बुलाया। बुधवार को गर्ग अपनी सरकारी कार से सीएनजी स्टेशन पहुंचे तो सिंह व गुप्ता आकर उनकी कार में बैठ गए। इस दौरान गुप्ता ने राव से भी बातचीत की और दस लाख रुपये बतौर एडवांस देने की बात तय हुई। साक्ष्यों के आधार पर सीबीआइ ने आरोपितों को गिरफ्तार किया।

झांसी में पिता के हत्यारे की गिरफ्तारी न होने पर सिख युवती ने मुंडवाया सिर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पिता के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी न होने पर झांसी में एक सिख युवती ने अपना सिर मुंडवा दिया है। साथ ही यह संकल्प किया है कि जब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हर दिन वह सिर मुंडवाती रहेंगी। मामला सामने आने पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने झांसी के पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया है। एसपी को 18 सितंबर को विस्तृत रिपोर्ट के साथ आयोग के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

झांसी निवासी युवती पुनीत सिंह के पिता जोगिंदर सिंह की हत्या 22 अगस्त को कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद 25 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, इसके बावजूद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस से जब सहयोग नहीं मिला तो सिख युवती ने अपने बाल मुंडवा दिए। उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग को बताया कि उनके पिता के हत्यारे दबंग किस्म के हैं। वे रोज पुनीत सिंह को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस मामले को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में युवती ने पड़ोस में रहने वाले वीरेंद्र कुमार खंडेलवाल व राजीव कुमार खंडेलवाल को नामजद किया है।

ऑस्ट्रेलिया से लौटी नटराज की मूर्ति की पूजा

दक्षिण तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी गई नटराज की ढाई फीट की कांस्य प्रतिमा 37 साल बाद शुक्रवार को चेन्नई पहुंची। मूर्ति की प्रतिष्ठा से पहले विधिवत पूजा की गई। इस मूर्ति को तिरुनेलवेली जिले के कल्लीदैईकुरिची क्षेत्र स्थित अरमवलार्थ नयाकी अम्मान मंदिर से चुरा कर देश से बाहर भेज दिया गया। बाद में यह ऑस्ट्रेलिया के संग्रहालय में मिली। जिसे कानूनी प्रक्रियाओं के बाद स्वदेश लाया गया। जांच अधिकारी नटराज की मूर्ति को दिल्ली से तमिलनाडु एक्सप्रेस से चेन्नई लेकर पहुंचे थे। प्रेट्र

परिवार में तूफान

लालू के बेटे-बहू का झगड़ा घर-आंगन, कोर्ट-कचहरी से निकल सड़क पर पहुंचा, रोनी सूरत वाली तस्वीर वायरल, कुछ देर बाद लौट आईं ससुराल, तेवर से लगा अब ससुराल में सहज नहीं, चल रहा है तलाक का केस

ससुराल से रोते निकलीं राबड़ी की 'सुलक्षणी बहू' ऐश्वर्या

राज्य ब्यूरो, पटना

लालू प्रसाद यादव के बेटे-बहू में अलगाव का मामला घर-आंगन, कोर्ट-कचहरी से निकलकर अब सड़क पर भी दिखने लगा है। लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय शुक्रवार को अपने ससुराल से रोती हुई बाहर निकलीं तो चर्चा सरेआम होने लगी। कहा जा रहा है कि वह मायके गईं और कुछ ही देर बाद फिर ससुराल लौट आईं। ऐश्वर्या की चाल, रोनी सूरत और तेवर से लगा कि राबड़ी देवी की 'सुलक्षणी बहू' ससुराल में अब सहज नहीं हैं। शादी के बाद जब ऐश्वर्या अपने ससुराल आई थीं, तो रांची जेल में बंद लालू प्रसाद को मेडिकल आधार पर सशर्त जमानत मिल गई थी, जिसके बाद राबड़ी ने ऐश्वर्या को सुलक्षणी बहू बताया था।

राबड़ी के घर से रोती हुई निकलीं और पिता की गाड़ी में बैठ गईं : शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे ऐश्वर्या राबड़ी के सरकारी आवास के मुख्य दरवाजे से रोती हुई बाहर निकलीं और सड़क पर सामने लगी अपने पिता की गाड़ी में जाकर बैठ गई। ऐश्वर्या घर से अकेली निकली थीं।

ऐश्वर्या के लिए अंदर नहीं जाती गाड़ी : बता दें कि लालू परिवार के किसी भी सदस्य के आने-जाने के क्रम में गाड़ी अंदर आवास परिसर तक जाती है। वहीं, ऐश्वर्या को कहीं जाना होता है तो वह मुख्य दरवाजे तक पैदल आती हैं और घर आने पर भी गाड़ी उन्हें बाहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद वह पैदल ही अंदर आती हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद नेता लालू प्रसाद यादव के ज्येष्ठ पुत्र तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या शुक्रवार को राबड़ी देवी के आवास से रोते हुए बाहर निकली। (सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज)

ऐश्वर्या के लिए बंद है ससुराल की रसोई : लालू परिवार से जुड़े सूत्र बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही ऐश्वर्या का ससुराल में रहना मुश्किल हो गया है। शुरू में बेटे-बहू के झगड़े में तेजप्रताप को छोड़कर लालू का पूरा परिवार ऐश्वर्या के साथ खड़ा दिख रहा था, किंतु यह क्रम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। ऐश्वर्या के मायके से जुड़े सूत्र बताते हैं कि मतदान के बाद से ही उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। खाने पर बंदिश और आने-जाने पर पहरा बिठा दिया गया। लालू परिवार की रसोई ऐश्वर्या के लिए बंद है। खाने के लिए उन्हें या तो मायके से मदद लेनी पड़ती है या बाजार से मंगाना पड़ता है।

छह महीने में मांगा तलाक, फिर भी ऐश्वर्या ने नहीं छोड़ा घर : तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी पिछले साल 12 मई को हुई थी। वहीं, एक नवंबर को तेजप्रताप की ओर से तलाक मांग लिया गया। इसके बाद से ही उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास में आना-जाना छोड़ दिया और अपने लिए राजधानी में एक अलग सरकारी आवास आवंटित करा लिया। हालांकि शादी के बाद से ऐश्वर्या अपने ससुराल में ही रह रही है।

डीयू से पढ़ीं ऐश्वर्या को था शादी से एतराज : लालू और चंद्रिका राय के परिवार ने बड़ी हसरत और धूमधाम से तेजप्रताप के साथ ऐश्वर्या की शादी की थी। सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या के साथ तेजप्रताप की तस्वीरें बताती हैं कि कुछ दिनों तक दोनों के संबंध भी अच्छे चल रहे थे। कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी ऐश्वर्या को यह शादी पसंद नहीं थी। किंतु परिवार के दबाव में आखिरी समय में सहमति दी थी।

चीन सीमा पर युद्धाभ्यास में होवित्जर और चिनूक भी होंगे शामिल

नई दिल्ली, एएनआइ : भारतीय सेनाएं अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर आधुनिक अमेरिकी हथियार प्रणालियों के साथ युद्धाभ्यास की योजना बना रही हैं। इनमें अल्ट्रा लाइट एम777 होवित्जर तोप और हैवी-लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं।

हिम विजय कूटनाम वाले इस युद्धाभ्यास का मूल मकसद नवगठित 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर की युद्ध क्षमता को परखना है। युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सेना भी शामिल होगी, जो युद्धाभ्यास में वास्तविक युद्ध की तरह सुरक्षा प्रदान करेगी। सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने एएनआइ को बताया कि युद्धाभ्यास के दौरान 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को अल्ट्रा लाइट एम777 होवित्जर तोप के साथ तैनात किया जाएगा। दुश्मन के क्षेत्र में तत्काल तेज और निर्णायक कार्रवाई करने की इनकी क्षमता को परखा जाएगा।

इस युद्धाभ्यास में अमेरिकी हैवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए ऊंचाई वाले इलाकों में होवित्जर तोप समेत भारी हथियारों को एयरलिफ्ट करने की उसकी क्षमता का परीक्षण किया जा सके। इन हेलीकॉप्टरों को औपचारिक रूप से 25 मार्च को चंडीगढ़ एयरबेस में वायु सेना में शामिल किया गया था। वायु सेना ने चिनूक को अभी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात नहीं किया है। सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इन्हें पूर्वोत्तर में तैनात किया जा सकता है, इसलिए युद्धाभ्यास में इनके इस्तेमाल की योजना बनाई गई है।

वर्तमान परिदृश्य में खुद को तैयार रखें कमांडर : धनोआ

जासं, प्रयागराज : एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कमांडरों को आधुनिक तकनीक से अपडेट रहने को कहा। साथ ही निर्देश दिए कि वह खुद को वर्तमान परिदृश्य में हमेशा तैयार रखें। धनोआ शुक्रवार को मध्य वायु कमान मुख्यालय में कमांडरों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें देश के 13 कमांडरों ने भाग लिया।

Downloaded from: www.iascgl.com

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 सितंबर 2019

दैनिक जागरण

इंसान अपने बारे में जैसी कल्पना करता है, वैसा बन जाता है

कानून के शासन पर सवाल

आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से लंबी पूछताछ की। उन पर दुष्कर्म का आरोप उनके ही प्रबंधन वाले कॉलेज की एक छात्रा ने लगाया है। इस छात्रा का यह भी आरोप है कि चिन्मयानंद ने उसके साथ अन्य छात्राओं की भी जिंदगी बर्बाद की है। कायदे से यह सनसनीखेज आरोप सार्वजनिक होते ही स्थानीय पुलिस को चिन्मयानंद के खिलाफ जांच-पड़ताल करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह अच्छा नहीं हुआ कि इस मामले में कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रा की शिकायत का संज्ञान लिया। उसने ही उत्तर प्रदेश पुलिस को मामले की छानबीन करने के लिए विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश दिए। क्या इस तरह के मामलों में पुलिस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तभी करेगी जब न्यायपालिका उनका संज्ञान लेगी? यह वह सवाल है जिसका जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस को देना चाहिए। निःसंदेह चिन्मयानंद प्रभावी व्यक्ति हैं, लेकिन क्या इसके आधार पर वह पुलिस की कार्रवाई से बचे रहेंगे या फिर उनके खिलाफ मुश्किल से कार्रवाई शुरू हो सकेगी? फिलहाल किसी के लिए कहना कठिन है कि उन पर लगे आरोपों की सच्चाई क्या है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उन पर पहले भी दुष्कर्म के आरोप लग चुके हैं। हालांकि ताजा मामले में चिन्मयानंद के खिलाफ आए वीडियो को उनके वकील ने फर्जी बताया है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह उनकी छवि को तार-तार करने वाला है।

विशेष जांच दल के लिए यह आवश्यक है कि वह चिन्मयानंद के खिलाफ आए वीडियो के साथ-साथ उस मामले की भी जांच करे जिसमें उनसे कथित तौर पर फिरौती मांगी गई है। इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि जांच-पड़ताल तेजी के साथ इस तरह हो कि यथाशीघ्र दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निःसंदेह यह एकलौता ऐसा मामला नहीं जिसमें स्थानीय पुलिस समय रहते सही तरह कार्रवाई करती नहीं दिखी। इसके पहले उन्नाव दुष्कर्म मामला इसीलिए सीबीआइ के पास गया, क्योंकि पीड़ित परिवार पुलिस के रवैये से संतुष्ट नहीं था। कानून के शासन के लिए यह ठीक नहीं कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ जांच करते समय पुलिस किसी तरह के दबाव में दिखे। दुर्भाग्य से एक अर्से से यही देखने को मिल रहा है। नेताओं और धर्मगुरुओं के मामले में ऐसा कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। जब ऐसा होता है तो आम जनता के बीच यही संदेश जाता है कि रसूख वालों से त्रस्त लोगों के लिए न्याय पाना अभी भी मुश्किल बना हुआ है। नीति-नियंता यह ध्यान रखें तो बेहतर कि ऐसे संदेश कानून के शासन को नीचा दिखाते हैं।

बंगाल में छठा पे कमीशन

केंद्र समेत कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तनख्वाह मिल रही है। परंतु बंगाल में अब तक छठा पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ था। जबकि केंद्र सरकार ने 2006 में ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कर्मियों व अधिकारियों का वेतनमान बढ़ा दिया था। अब करीब 14 वर्ष बाद आगामी वर्ष 2020 में एक जनवरी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को छठा वेतन आयोग के मुताबिक वेतन देने का एलान किया है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में सरकारी कर्मचारियों के संगठन की सभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़कर 17,990 रुपये होगा। वहीं ग्रेच्युटी को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है। ममता ने कहा कि आज ही छठे वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए गठित कमीशन की प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। उन्होंने कहा कि कमीशन जो भी सिफारिश करेगा वे उसे मान लेंगी। राज्य में सातवां वेतन आयोग लागू नहीं होने से सरकारी कर्मचारी ममता से बेहद नाराज चल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा छठे वेतन आयोग को लागू करने के लिए गठित कमीशन के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने कहा कि कर्मचारियों को बढ़ा वेतन देने से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सिफारिशें एक जनवरी से प्रभावी होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद सचिवालय में बैठक कर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर सकी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से लेकर कई और तरह की दिक्कतें थीं। इसके बाद उन्होंने आयोग के चेयरपर्सन अभिरूप सरकार से भी बात की थी। आयोग के अध्यक्ष अभिरूप सरकार ने मूल वेतन में 2.57 फीसद वृद्धि की सिफारिश की है। इससे राज्य सरकार पर 10000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हाल के लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों ने भाजपा का समर्थन किया था, जिसका खमियाजा राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को सीटों के नुकसान के रूप में झेलना पड़ा। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी को सरकारी कर्मचारियों के संगठन की जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्होंने जब पहली बैठक की तो पता चल गया कि वेतन वृद्धि न होने की वजह से सरकारी कर्मचारी तृणमूल सरकार से खासे नाराज हैं।

हिंदी के विस्तार में है अन्य भाषाओं का हित

कृपाशंकर चौबे

देश में जब भी हिंदी के विरोध में कहीं से कोई आवाज उठती है तो उसका लाभ जाने-अनजाने अंग्रेजी के हिस्से में ही जाता है

अवधेश राजपूत

हिंदी की महत्ता तभी स्थापित हो गई थी जब वह स्वाधीनता संग्राम के समय समूचे देश को आपस में जोड़ने वाली सबसे सशक्त संपर्क भाषा बन गई थी। उस दौर के सभी नेताओं का मानना था कि अगर कोई भारतीय भाषा देशवासियों को एकजुट करने में सहायक बन सकती है तो वह हिंदी ही है। हिंदी की सामर्थ्य को गांधी ने भी समझा और नेता जी सुभाषचंद्र बोस ने भी। आचार्य बिनोवा भावे ने कहा था कि यदि मैंने हिंदी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भूदान, ग्राम-दान का संदेश जनता तक न पहुंचा पाता। हिंदी ने राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। उसे यह भी बोध रहा कि भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं के पूर्ण विकास से ही संभव है। हिंदी में वह शक्ति है कि वह अपने माध्यम से भारत को जोड़ सके। हिंदी को अपना स्थान अभी भी हासिल करना है। उसे इस मिथ्या धारणा को भी तोड़ना है कि विकास की भाषा तो अंग्रेजी ही है। अगर अंग्रेजी सचमुच विकास की भाषा होती तो पहले जापान और फिर जर्मनी और चीन ने अपनी भाषा में चमत्कारिक प्रगति न हासिल की होती।

हाल के समय में हिंदी ने उल्लेखनीय प्रगति और पहुंच स्थापित की है, लेकिन केवल इतने से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि वह देश की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा बन गई है। हिंदी ज्ञान अर्जन की, विज्ञान एवं तकनीक की और सरकारी एवं गैर सरकारी कामकाज यानी रोजगार की सक्षम भाषा भी बननी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी उसे अपना मुकाम हासिल होगा। इस मुकाम को हासिल करने में हिंदी को गैर हिंदी भाषियों का सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। यह तभी हासिल हो सकता है जब हिंदी के प्रति अन्य भाषा-भाषियों की आशंकाओं को दूर करने में सफलता मिलेगी। गैर हिंदी भाषियों में हिंदी को लेकर किसी तरह की आशंका उपजने न पाए, इसके लिए हिंदी प्रेमियों को सतर्क रहना होगा और इस क्रम में उन हिंदीतरभाषियों का स्मरण करना होगा जिन्होंने विभिन्न कालखंडों में हिंदी के विस्तार में योगदान किया। इसे गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के उन लोगों को भी स्मरण रखना चाहिए जो रह-रहकर किसी न किसी बहाने हिंदी का विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं। ऐसा करके वे हिंदी के साथ ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का भी अहित करते हैं, क्योंकि देश में जब भी हिंदी के विरोध में कहीं से कोई आवज उठती है तो जाने-अनजाने उसका लाभ अंग्रेजी के हिस्से में जाता है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी के वर्चस्व से तभी लड़ा जा सका जब हिंदी भाषी छात्रों के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के छात्र एकजुट हुए। इस एकजुटता को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी से उपजी अंग्रेजियत की संस्कृति यानी खुद को विशिष्ट समझने की मानसिकता हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक खतरा बनी हुई है।

बहुत कम लोग इससे परिचित होंगे कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्म हिंदीतर क्षेत्र कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में तब हुआ जब वहां हिंदुस्तानी भाषा विभाग के प्रमुख बांग्लाभाषी तारिणी चरण मित्र थे। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 'उदंत मार्तंड' हिंदीतरभाषी क्षेत्र कलकत्ता से ही 30 मई, 1826 को निकला। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र 'समाचार सुधावर्षण' भी कलकत्ता से ही 1854 में निकला। इसे बांग्लाभाषी श्यामसुंदर सेन ने निकाला था। बांग्लाभाषी जस्टिस शारदाचरण मित्र ने देवनागरी लिपि के विस्तार के उद्देश्य से 'देवनागर' नामक पत्रिका 1907 में निकाली। हिंदी में पहला एमए होने का गौरव नलिनी मोहन सान्याल नामक एक बांग्लाभाषी ने पाया। ऐसा इसलिए हो सका, क्योंकि देश में पहली बार 1919 में हिंदी में एमए की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में तत्कालीन कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी ने शुरू कराई। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के हिंदी प्रेम को देखते हुए ही 20 दिसंबर, 1928 को कलकत्ता में आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन की स्वागत समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। वहां उन्होंने हिंदी के पक्ष में ऐतिहासिक भाषण हिंदी में ही दिया। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने शांतिनिकेतन में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी को 1930 में हिंदी शिक्षक नियुक्त किया और 1940 में हिंदी भवन की स्थापना की। इसी तरह पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत के हिंदीतरभाषियों ने विभिन्न कालखंडों में हिंदी को सींचने का महत्वपूर्ण काम किया।

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि देवनागरी लिपि के लिए एक हिंदीतरभाषी लेखक ने अपनी शहादत तक दी। ये थे बिनेश्वर ब्रह्म। वह असम में 'देवनागरी के नवदेवता के तौर पर जाने जाते हैं। हिंदी को राष्ट्रीय स्वरूप देने में सबसे अधिक योगदान महात्मा गांधी का है। 1934 में पूर्वोत्तर भारत में हिंदी प्रचार महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही प्रारंभ हुआ। 1936 में उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना की और दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार के लिए अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को मद्रास भेजा था। देवदास गांधी के साथ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक 1918 में मद्रास गए और दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार-कार्य शुरू किया। वे दोनों दक्षिण भारत के सर्वप्रथम हिंदी प्रचारक माने जाते हैं। इसके पहले 1927 में दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार कार्य को हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के नियंत्रण से अलग करके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा नामक संस्था बनाई गई। यह संस्था आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में हिंदी का प्रचार-प्रसार कर रही है।

दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्यों के कारण दक्षिण भारत के हर राज्य में स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी में पठन-पाठन प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 1941 में मलयालम की प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्रिका 'मातृभूमि' में एक हिंदी खंड दिया जाने लगा। उसे केरल की पत्रकारिता की ऐतिहासिक घटना माना जाता है। लगभग एक वर्ष तक 'मातृभूमि' में हिंदी स्तंभ के तहत हिंदी कविता, कहानी, लेख, यात्रा वृतांत छपते रहे। वास्तव में भारतीय भाषाओं के बीच पारस्परिक साझेदारी और आपसी संवेदना की ऐसी समझ का विकास होने पर ही अखिल भारतीय बोध का विस्तार होगा और तभी हिंदी दिवस सही अर्थों में अखिल भारतीय स्तर पर मनाया आएगा। आज अगर हिंदी राजभाषा के दर्जे तक सीमित है तो शायद इसीलिए कि सभी भारतीय भाषाओं के लोग इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वह राष्ट्रभाषा बने। यह समझने की जरूरत है कि हिंदी का विस्तार और विकास ही अन्य भारतीय भाषाओं के हित में है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

वक्त की मांग है महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा

डॉ. प्रीति अदाणी

अगर हम आर्थिक महाशक्ति बनना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने होंगे

किसी भी समुदाय, वर्ग का सशक्तीकरण एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक परिवर्तन है जिसे प्रकट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। महिलाएं परिवारों के सशक्तीकरण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इससे उनकी पीढ़ी में तो बदलाव आता ही है, समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयासों के साथ उन उपायों पर नजर रखना जरूरी है जिनसे कहीं जल्द सार्थक नतीजे सामने आते हों। अगर हम बदलाव की बड़ी पहल करना चाहते हैं तो महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता लाना महत्वपूर्ण होगा। महिलाओं के लिए कमाई के अवसर पैदा करने वाली सामुदायिक पहल संशय के माहौल को दूर करने में मददगार बनती है। आमतौर पर ग्रामीण भारत की महिलाएं चुनौतियों के दो व्यापक स्तरों पर जूझती हैं। पहला, आत्मविश्वास की कमी को लेकर और दूसरे, धारणाओं से लड़ने का दबाव, लेकिन जीविकोपार्जन के अवसर प्रदान करने वाली योजनाओं के जरिये इन दबावों से अच्छी तरह निपटा जा सकता है।

भारत में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। कुछ वर्ष पहले मैकिंजी ग्लोबल ने अपने एक अध्ययन में दावा किया था कि अगर भारत अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के लिए समान अवसर पैदा कर सके तो वह साल 2025 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत तक वृद्धि कर सकता है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया था कि दुनिया भर में लिंगभेद की समस्या को समाप्त करने से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर की भारी वृद्धि हो सकती है। जब एक गृहिणी आत्मनिर्भर हो जाती है तो उसका लाभ बढ़ी हुई पारिवारिक आय तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि उसके द्वारा परिवार में लाए गए परिवर्तन पीढ़ियों की सोच में दिखने लगते हैं। इसीलिए अपने माता-पिता की तुलना में नई पीढ़ी शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास के प्रति ज्यादा जागरूक है। महिलाओं में वित्तीय स्वतंत्रता देश में सांस्कृतिक परिवर्तन प्रारंभ करने की क्षमता रखती है। स्किल इंडिया अभियान यानी कौशल प्रशिक्षण के जरिये करीब 17.72 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षित 10 में से लगभग 8 महिलाओं को या तो आजीविका के अवसर मिले हैं या उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद स्व-रोजगार शुरू किया है। इनमें से अधिकांश परिधान, ब्यूटी एंड वेलनेस और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में शामिल हुई हैं। इन आंकड़ों से दो बातें उभर कर सामने आती हैं। अपनी भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बावजूद आज महिलाएं घूंघट से परे जीवन को देखने के लिए उत्सुक हैं। इसका यह भी अर्थ है कि रोजगार का एक बाजार मौजूद है जो इस अप्रयुक्त कार्य बल का उपयोग करना चाहता है। हालांकि किसी क्षेत्र विशेष में निपुणता आवश्यक है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। आज महिलाओं के भीतर अपनी पहचान को सामने लाने और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए गहरी उत्सुकता है। चूंकि भारत को दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में माना जा रहा है, इसलिए आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध होंगे। हमें इस मौके का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के लिए अधिक से अधिक अवसर पैदा करने की राह आसान करनी चाहिए।

महिलाओं के लिए स्वतंत्र वातावरण बनाने के अलावा वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए उन्हें शिक्षित करना भी उतना ही आवश्यक है। समावेशी विकास को लेकर सरकारी सुधारों के माध्यम से बचत बैंक खाता खोलने के प्रति पहले ही व्यापक जागरूकता आ चुकी है। अब खाते में न्यूनतम धन रखने की आवश्यकता, बीमा योजनाओं और संपत्ति में निवेश करने की पेशकश सहित कई प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि महिलाएं वित्तीय रूप से सुरक्षित हों। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष श्वाब क्लॉज के अनुसार भविष्य की नौकरियां शीर्ष कंपनियों द्वारा नहीं, युवा उद्यमियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। हम देख सकते हैं कि भारत में महिलाओं की एक नई पीढ़ी युवा उद्यमी के रूप में तैयार होने की कगार पर है। निश्चित रूप से यह आगे चलकर दूसरी महिलाओं के लिए नौकरियों का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाएगी।

(लेखिका अदाणी फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले

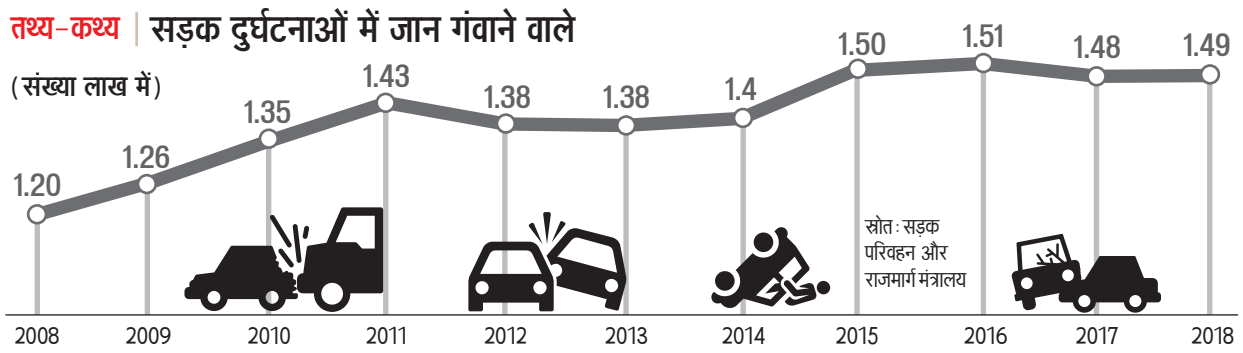

ऊर्जा

भोजन का संस्कार

भोजन इस धरती पर सभी प्राणियों के शरीर के पोषण के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे तन को ऊर्जा प्राप्त होती है और मन को संस्कार। यह हमारे शरीर को स्वस्थ तथा मन को पवित्र रखता है, किंतु भोजन की शुद्धता एवं इसके पकाने की प्रकृति पर मानव मन के स्वास्थ्य तथा चित्त की पवित्रता निर्भर करती है। भोजन की शुद्धियां चार प्रकार की होती हैं-क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, काल शुद्धि तथा भाव शुद्धि। भोजन बनाते समय या ग्रहण करते समय हमें क्षेत्र अर्थात स्थान की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पवित्र तथा स्वच्छ स्थान पर बनाया गया तथा ग्रहण किया गया भोजन शरीर को स्वस्थ तथा मन को सात्विक बनाता है। लिहाजा चौके में बिना नहाए हुए, गंदे तथा रोगी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए।

द्रव्य शुद्धि का आशय यह है कि भोजन बनाने के लिए आवश्यक सामग्री किन साधनों से प्राप्त की गई है-अनीति, अनाचार, अधर्म तथा पाप के धन से प्राप्त खाद्यान्न से निर्मित भोजन हमारे मन तथा आत्मा दोनों को दूषित करता है। पवित्रता, परिश्रम तथा ईमान की कमाई से अर्जित धन से प्राप्त भोजन मन को सुसंस्कृत करता है तथा आत्मा को परिष्कृत करता है। काल शुद्धि का अर्थ है, भोजन को सही समय पर करना। नियमित रूप से तथा भूख लगने पर ही भोजन करना शास्त्रों में उत्तम माना गया है। सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त के पूर्व किया गया भोजन ही श्रेष्ठ होता है।

इसके अतिरिक्त भोजन पर मानव भावों का भी बड़ा असर पड़ता है। क्रोध, लोभ, काम, चिंता, तनाव, भय तथा अन्य विकृत मानवीय भावों की मनःस्थिति में तैयार किया गया तथा ग्रहण किया गया भोजन मन तथा शरीर को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसीलिए जब कभी आप इस तरह की मनोदशा में हों तो भोजन न तो ग्रहण करना चाहिए और ना ही बनाना चाहिए। तो फिर क्या यह लाजिमी नहीं है कि भोजन को महज क्षुधा तृप्ति के साधन के रूप में नहीं, बल्कि मानव के आत्मिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में पोषित और सम्मानित किया जाना चाहिए?

श्रीप्रकाश शर्मा

कैसे मिलेगी बालश्रम से मुक्ति

लालजी जायसवाल

सभी देशों को अपने प्रयासों में तेजी लाकर दुनिया को बालश्रम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए

पिछले दिनों ब्यूनसआयर्स में बालश्रम पर लगभग 100 देशों का सम्मेलन हुआ था जिसमें यह चिंता जाहिर की गई थी कि अधिकांश सदस्य देश 2025 तक बालश्रम को समाप्त करने के अपने लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। दरअसल इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का वह अनुमान है जिसके अनुसार विश्व भर में आज से सात वर्ष बाद भी लगभग एक अरब 21 करोड़ बच्चे अलग-अलग कार्यों में संलग्न पाए जा सकते हैं। अभी भी विश्व में पांच से 17 वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या एक अरब 52 करोड़ है। जाहिर है सभी देशों को अपने प्रयासों में तेजी लाकर दुनिया को बालश्रम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। भारत में बालश्रम का एक प्रमुख कारण औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी निरीक्षकों की कमी का होना भी है, जिसके फलस्वरूप यहां लगभग 71 फीसद बच्चे आज भी कृषि कार्य में लगे हैं जिनमें से 69 फीसद बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अतः यह अहसास करना लाजमी है कि इस स्थिति में देश का भविष्य कैसा होगा?

आज भी भारत में प्रतिदिन लगभग 40.3 लाख बच्चे स्कूल के बजाय काम पर जाते हैं। बालश्रम से निरक्षरता और गरीबी बढ़ती है। बच्चों का सामाजीकरण न होने से बच्चा समाज में अपनी भूमिका नहीं निभा पाता है जिससे समाज के मानवीय मूल्यों का क्षरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव व्यापार, आतंकवाद एवं ड्रग माफिया जैसे अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। आज समाज में पनपते अपराधों के पीछे कालांतर में बालश्रम की भूमिका है। सरकार से यही अपेक्षा है कि वह इसे रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाएगी। दुख की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत भारत सरकार बालश्रम के घृणित कार्यों को समाप्त करने की समय सीमा तक निर्धारित नहीं कर पाई है। देश के संविधान में बच्चों को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे परिणामों का सामने आना कई सवाल खड़े करता है।

बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षित समाज एवं देश की बढ़ती जनसंख्या है। गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा के बजाय यदि श्रम में ही लगे रहते हैं तो उसकी गरीब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गरीब को कमाने वाला चाहिए, लेकिन वह दूसरे पक्ष को कभी नहीं देखता कि गरीब परिवार का बच्चा पढ़-लिख कर परिवार की गरीबी दूर कर सकता है और सभ्य समाज का निर्माण भी कर सकता है। बच्चों को पारिवारिक उद्यम में संलग्न करना भी बालश्रम का कारण बनता है। बाल मजदूरी से बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बाधित हो जाता है। कानून को कड़ाई से लागू करने के साथ-साथ शिक्षा इस समस्या को दूर करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। सरकार को ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि सभी गरीब बच्चे पढ़ सकें और फिर रोजगार हासिल कर सही दिशा में बढ़ सकें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत

शंकर शरण द्वारा लिखित आलेख 'हिंदू-मुस्लिम संवाद का सही आधार' में देश की हिंदू-मुस्लिम एकता के बीच फंसी हुई फांस को जिस साफगोई से रेखांकित किया गया है, वह आजाद भारत की जमीनी हकीकत है। माना कि भारत विभाजन में जिन्ना की मतवादी जिद जिम्मेदार रही, लेकिन उससे कहीं अधिक हमारी उदारता ने बेड़ा गर्क किया था। यदि जिन्ना की दुर्नियत को समय रहते भांप लिया जाता तो आज देश की तस्वीर दूसरी होती। मजे की बात यह रही कि भारत विभाजन के बाद भी उदारता की यह बयार अपनी गति से बहती रही और मुस्लिम बहुल कश्मीर में अस्थायी अनुच्छेद-370 और 35-ए के द्वारा देश के एक वर्ग को विशिष्टता का जामा पहना दिया गया। बाद में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कांग्रेसी राजनीति ने देश के संसाधनों पर पहला हक एक वर्ग विशेष का बताकर उदारता की सभी सीमाएं तोड़ दीं। तुष्टीकरण की विकृत राजनीति ने ही कश्मीर की शैव-सूफी दर्शन से समन्वित कश्मीरियत को छिन्न-भिन्न करने का काम किया। तत्कालीन केंद्र सरकार चाहती तो आतंकवाद की इस विभीषिका को रोक सकती थी, लेकिन तुष्टीकरण के कारण ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में यह जरूरी है कि जब एक पक्ष अपने को पीड़ित मानकर स्वयं के संरक्षण की बात करे तो उसे दूसरे पक्ष की उस पीड़ा को नजरंदाज नहीं करना चाहिए जो केरल, कश्मीर, असम और पश्चिम बंगाल में वह भोगता है। ऐसे में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को मजबूत करने के लिए किया जाने वाला कोई भी प्रयास इस जमीनी हकीकत के मद्देनजर ही होना चाहिए कि राष्ट्र की प्रगति और शांति के लिए इस देश के हिंदू-मुस्लिम बराबर के जिम्मेदार हैं।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

चालान में तकनीक जरूरी

नया मोटर वाहन कानून सड़क पर चलने वालों लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, ताकि सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा मुहैया कराया जा सके। इसके अतिरिक्त इसमें राष्ट्रीय परिवहन नीति बनाने की संभावना का भी उल्लेख किया गया है। यद्यपि जुर्माने की राशि अधिक है। बढ़े हुए जुर्माने राशि से वाहन चलाने वालों में अनुशासन बढ़ेगा और देश की सड़कें सुरक्षित होंगी। इस अधिनियम से सड़क दुर्घटना में होने वाली घटनाओं में कमी आएगी। कुछ राज्य जुर्माने की राशि को लेकर सहमत नहीं हैं। ऐसे में राशि में अंतर और भ्रम से बचने के लिए केंद्र सरकार को अधिनियम का एक बुनियादी ढांचा तैयार करना था और क्रियान्वयन की जवाबदेही राज्यों पर छोड़ देनी चाहिए थी। लोगों में स्व-अनुशासन की आदत डालनी होगी। इसके साथ ही समय पर सड़क, यातायात सिग्नल आदि की उचित देखभाल होनी चाहिए। पुलिस को तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। इससे न केवल निगरानी लागत में कमी आएगी, बल्कि लोगों की प्रताड़ना की आशंका घटेगी और परिणाम बेहतर होंगे।

sbbandhe95@gmail.com

कब समझेंगे जल का महत्व?

पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए पानी की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन इसकी सबसे अधिक प्राथमिकता होने के बावजूद, इसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक हो रहा है। हमारे जीवन का मुख्य केंद्र पानी है, लेकिन हम अपनी योजनाओं में इस केंद्र बिंदु पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर रहे हैं। हम विकसित तो हो रहे हैं, लेकिन पृथ्वी से जल के स्तर को कम करते जा रहे हैं। आज जिस तरह विकास हो रहा है, वो जल और जीवन के लिए नरक का दरवाजा खोल रहा है। आखिर कब हम समझेंगे कि जल ही जीवन है।

praveensingh9910@gmail.com

देश में आर्थिक मंदी

इस समय देश में आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट है। भारत की जीडीपी दर 5.8 फीसद से घटकर 5 फीसद पर आ गई है। कृषि विकास दर में गिरावट, निर्माण सेक्टर में गिरावट और आय सृजन, बचत व खपत में गिरावट इस मंदी के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार इस संकट की घड़ी से निकलने के पुख्ता कदम उठा रही है। सरकार के प्रयास व देशवासियों के सहयोग से इससे जल्द निजात पाएंगे।

ashish.sharma100210@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

आजकल

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
वरिष्ठ अर्थशास्त्री

सुहानी हो हमारे शहरों की तस्वीर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया है। इसके लिए शहरी बुनियादी ढांचे में विकास सबसे जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों में बुनियादी ढांचे पर 100 लाख करोड़ रुपये खर्च करने के निर्णय से इस मुहिम को लाभ होगा। जिन देशों में शहरों की जितनी ज्यादा प्रगति होती है, वहां आर्थिक अवसरों की उपलब्धता उतनी ही अधिक होती है। शहर किसी भी राष्ट्र के विकास के आधार स्तंभ होते हैं

हाल ही में सात सितंबर को मुंबई में तीन नई मेट्रोलाइन की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि हम वर्ष 2024 तक देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने शहरों को 21वीं सदी के वैश्विक शहरों के मुताबिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचे और रहने योग्य अनुकूलताओं से सुसज्जित करना होगा। हमें अपने शहरों को वैश्विक जरूरतों के मुताबिक विकसित करना होगा। इससे दुनिया में हमारी धमक बढ़ेगी।

इन तमाम पहलुओं के बीच जब हम अपने शहरों की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे शहर बुनियादी ढांचे और जीवन अनुकूलताओं के मद्देनजर दुनिया के शहरों से बहुत पीछे हैं। हमारे बड़े शहरों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। बीते चार सितंबर को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआइयू) द्वारा प्रकाशित जीवन अनुकूलता सूचकांक (लिवेबिलिटी इंडेक्स) में कहा गया है कि नई दिल्ली और मुंबई जीवन की विभिन्न अनुकूलताओं और रहने की बेहतर परिस्थितियों के मामले में पहले की तुलना में पीछे हो गए हैं। दुनिया भर के 140 शहरों के सर्वेक्षण में नई दिल्ली छह स्थान फिसलकर 118वें तथा मुंबई दो स्थान फिसलकर 119वें पायदान पर रहा। जिन पैमानों पर विवेचना की गई, उनमें स्थिरता, संस्कृति, परिवेश, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचा और शिक्षा क्षेत्र को शामिल किया गया था। ईआइयू के मुताबिक सांस्कृतिक क्षेत्र के अंक में गिरावट के कारण मुंबई रैंकिंग में दो स्थान फिसल गया। वहीं सांस्कृतिक, पर्यावरण स्कोर और अपराध दर में वृद्धि के कारण स्थिरता स्कोर में गिरावट से नई दिल्ली की स्थिति इस सूचकांक में कमजोर हुई है। इस सूची में ऑस्ट्रिया का वियना लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा।

ऐसे समय जब भारत में तेजी से विकसित होते नए शहरों का परिदृश्य दिख रहा है, तब इनमें नए वैश्विक शहरों की जरूरत के मुताबिक विकास के मापदंडों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विश्व के प्रतिष्ठित थिंकटैंक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा दुनिया के 780 बड़े और मझोले शहरों की बदलती आर्थिक तस्वीर और आबादी की बदलती प्रवृत्ति को लेकर पिछले दिनों प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2019 से 2035 तक दुनिया के शहरीकरण में काफी बदलाव देखने में आएगा। रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त दुनिया के अधिकांश विकसित शहर जैसे न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन, लॉस एंजिलिस, बीजिंग, पेरिस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि अपना दबदबा बनाए रखेंगे। किंतु तेजी से विकसित होते हुए नए वैश्विक शहरों की रफ्तार के मामले में शीर्ष के 20 शहरों में पहले 17 शहर भारत के होंगे और उनमें भी सबसे पहले दस शहर भारत के ही होंगे। इन पहले 10 शहरों में सूरत, आगरा, बंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई और विजयवाड़ा वास्तव में चमकीले वैश्विक शहरों के रूप में दिखाई देंगे।

इसमें दोराय नहीं कि भारत के शहरों में उद्योग-कारोबार का जो विकास हो रहा है, उससे भारत दुनिया के आर्थिक परिदृश्य पर तेजी से उभरता दिख रहा है। कुछ आर्थिक विशेषज्ञों की यह भी राय है कि शहरों के कारण ही भारत की वैश्विक काराबोर, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक नवाचार के मामले में विशेष पहचान बनी है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि भारतीय शहरों में सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार तथा नई प्रौद्योगिकी के लिए दुनिया की कंपनियां तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों की बड़ी-बड़ी कंपनियां नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय आइटी प्रतिभाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शहरों में अपने ग्लोबल इनहाउस सेंटर (जीआइसी) तेजी से बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं।

उल्लेखनीय है कि हमारी प्रतिभाएं शहरों में इसलिए रहना चाहती हैं, क्योंकि वहां विश्वस्तरीय रोजगार अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लेसमेंट सेंटर बनता जा रहा है। भारत के शहरों से विकसित देशों के लिए आउटसोर्सिंग का प्रवाह तेज होता जा रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां व्यावसायिक कार्यस्थल पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी कम दरों पर उपलब्ध हैं।

यह सही है कि देश में बढ़ते औद्योगीकरण और कारोबारी विकास के कारण भी शहरीकरण की रफ्तार बढ़ रही है। पर क्या उसी अनुपात में सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? नहीं। शहरों की बड़ी आबादी मूलभूत चिकित्सा सेवा से भी वंचित है। सड़क, बिजली, पानी के मोर्चे पर भी समस्याएं बढ़ी हैं। बड़ी संख्या में बच्चे उपयुक्त शिक्षा से वंचित हैं। जरूरी है कि शहर सुनियोजित रूप से विकसित हों। शहर आधुनिक बुनियादी सुविधाओं, यातायात व संचार साधनों से सुसज्जित हों। शहरों में विकास की बुनियादी संरचना, मानव संसाधन के बेहतर उपयोग, जीवन की मूलभूत सुविधाओं तथा सुरक्षा संबंधी इंतजाम के लिए सुनियोजित प्रयास जरूरी हैं। हमें नई जरूरतों के मुताबिक शहरों के विकास का रोडमैप बनाना होगा। नए शहरों में सड़कों का उपयुक्त मॉडल अपनाया जाए। नए शहरों को तत्परता से निर्मित करने के लिए सरकार द्वारा आसान कर्ज के साथ-साथ निजी क्षेत्र से निवेश के सार्थक प्रयास किए जाएं। नए शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल उपयुक्त होगा।

इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मद्देनजर हमें अपने शहरों की चिंता करनी ही होगी। वैश्विक जरूरतों की पूर्ति करने वाले शहरों के विकास की दृष्टि से भारत के लिए यह अच्छा संयोग है कि अभी देश में ज्यादातर शहरी ढांचे का निर्माण बाकी है और शहरीकरण की चुनौतियों के मद्देनजर देश के पास शहरी मॉडल को परिवर्तित करने और बेहतर सोच के साथ शहरों के विकास का पर्याप्त समय मौजूद है। ऐसे में हमें वियना, मेलबर्न, सिडनी, टोक्यो जैसे वैश्विक गुणवत्तापूर्ण शहरों से सीख लेनी होगी। शहरों को बेहतर रहन-सहन के लायक बनाने के लिए शासन-प्रशासन के साथ-साथ सभी वर्गों के लोगों को एकजुट प्रयास करने होंगे। बेहतर शहरीकरण के साथ निश्चित रूप से हम अधिक विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित कर पाएंगे, अधिक प्रतिभाओं का लाभ ले पाएंगे।

हम आशा करें कि केंद्र और राज्य सरकारें हमारे शहरों को सुनियोजित ढंग से बेहतर सोच के साथ संवारेंगी, ताकि ये शहर राष्ट्रीय और वैश्विक जरूरतों की पूर्ति के अनुरूप लाभप्रद दिखाई दें और हमारे लोगों के लिए आर्थिक-सामाजिक खुशहाली का जरिया भी बनें।

रोजगार के बदलते स्वरूप की चुनौतियां

रीतेंद्र कंवर शेखावत

आज 21वीं सदी में हर क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल होती दुनिया में रोजगार की परिभाषा और कार्य का स्वरूप बदल रहा है। अल्पकालिक व घर बैठे किए जाने वाले कार्य (वर्क फ्रोम होम) के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। आज एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उभर रही है जिसे नाम दिया जा रहा है- गिग अर्थव्यवस्था। दरअसल इसमें स्वतंत्र (फ्रीलांस) कार्य और एक निश्चित अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार शामिल हैं। गिग इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर होती है। एप आधारित कैब कंपनियों से जुड़कर टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर तथा खाना डिलीवर करने वाले, वेब डिजाइन करने वाले प्रोफेशनल आदि असल में गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं। इन सभी को अपने काम के एवज में रकम तो मिलती है, लेकिन ये कामगार इन प्लेटफॉर्म के कर्मचारी नहीं होते हैं, बल्कि जितना काम किया या जो टास्क पूरा किया उसके लिए भुगतान होता है।

आज दुनिया की करीब 20 प्रतिशत वर्क फोर्स गिग इकोनॉमी के जरिये अपनी आजीविका चलाती है। अमेरिका में इसका तेजी से विस्तार हुआ है जहां लगभग 35 प्रतिशत वर्कफोर्स इसका हिस्सा है। भारत और चीन में भी इसका चलन तेजी से बढ़ा है।

गिग अर्थव्यवस्था के लाभों की समीक्षा की जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों को काम के विकल्प और अवसर पहले से ज्यादा उपलब्ध होते हैं। कंपनी को इससे बहुत फायदे हैं, जैसे स्थायी कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। कार्यालय स्थल पर खर्च कम होता है। यह महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो इस अवधारणा पर काम करती हैं कि शादी या बच्चे के जन्म के कारण जॉब छोड़ भी सकती हैं। इसके जरिये सेवानिवृत्त लोग भी सक्रिय रह सकते हैं जो उन्हें अकेलेपन व अवसाद से दूर रखेगा तथा वे अपने बच्चों या पेंशन पर निर्भर रहने के बजाय खुद कमा सकते हैं। गिग इकोनॉमी में श्रमिकों की दक्षता और उत्पादकता स्थायी व पूर्णकालिक पेशेवरों की तुलना में काफी अधिक है। इसके जरिये अधिक विशेषज्ञ लोगों को कुछ समय के लिए काम पर रखा जा सकता है। नई स्टार्ट-अप कंपनियों और उद्यमियों, जिनके पास ज्यादा वितीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं वे भी अनुबंध के कर्मचारियों या फ्रीलांसरों की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जहां तक बात गिग इकोनॉमी से हानि की है, तो इससे लंबे समय तक बेरोजगारी, जॉब सुरक्षा तथा अनिश्चित आमदनी का भय सदैव बना रहता है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सहयोगियों/ श्रमिकों को पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव अकुशल श्रमिकों पर पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कुशल श्रमिकों की अपेक्षा अवसर की उपलब्धता कम है। इससे सामाजिक- आर्थिक असमानता बढ़ने का खतरा बना रहता है।

अगर विकसित देश जैसे अमेरिका और विकासशील देश जैसे भारत की गिग अर्थव्यवस्था के संदर्भ में तुलना की जाए तो यह पता चलता है कि अमेरिका में इतना अधिक श्रम गिग इकोनॉमी का भाग इसलिए है, क्योंकि वह सक्षम है, जबकि भारत में बड़ी संख्या में लोग इस व्यवस्था का हिस्सा इसलिए हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। यहां के लोग मजबूरी और बेरोजगारी के कारण इस व्यवस्था को अपना रहे हैं।

ऐसे में आने वाले समय में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी तमाम तकनीकें जब आपस में मिलेंगी तो उत्पादन और निर्माण के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अतः आने वाला समय गिग इकोनॉमी का होगा, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आज गिग इकोनॉमी काफी हद तक अनियंत्रित है, भारत में इस व्यवस्था के तहत उभरते स्टार्टअप्स को संतुलित तरीके से विनियमित करने की आवश्यकता है, ताकि स्टार्टअप्स और श्रमिकों या कामगारों, दोनों को ही इस क्षेत्र में कुछ सहूलियतें उपलब्ध हो सकें। पूर्व की औद्योगिक क्रांतियों के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि इन परिवर्तनों से सर्वाधिक प्रभावित वे समूह होते हैं जो अपनी कौशल क्षमता में निश्चित समय के भीतर वांछनीय सुधार लाने में असमर्थ होते हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त समय के साथ-साथ संसाधन भी उपलब्ध कराए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

खरी-खरी

इंग्लिश-मीडियम में हिंदी-डे

जगदीश ज्वलंत

विभागीय आदेश के पालन की विवशता ने समस्या खड़ी कर दी। स्कूल इंग्लिश-मीडियम का था और उसमें हिंदी-दिवस मनाए जाने का आदेश था। परेशान डायना मेम ने डिसूजा मेम को चेंबर में बुलाया। उन्हें हिंदी प्रिय थी। वे कभी-कभी बोलती भी थीं। डायना मेम ने अपनी चिंता उन्हें थोप दी। डिसूजा मेम ने कहा- कल ही तो हिंदी के पेंशनर शास्त्रीजी आए थे, हिंदी पढ़ाने का आवेदन लेकर। हमने ही उन्हें लौटा दिया। क्यों ना हम उन्हीं को हिंदी-डे का चीफ गेस्ट बनाकर इनवाइट कर लें? शास्त्रीजी का भी सम्मान हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने। किंतु निशाना उल्टा पड़ा। उन्हें ये नहीं पता था कि हिंदी सम्मान से अधिक स्वाभिमान चाहती है। शास्त्रीजी ने अस्वीकृति प्रेषित करते हुए लिखा- मैं अपनी मातृभाषा को दिवस की औपचारिकता के निर्वहन हेतु प्रदर्शित कर उसे अपमानित करना नहीं चाहता।

अब क्या किया जाए? डिसूजा मेम ने ही सुझाव दिया कि मेरे मिस्टर के एक फ्रेंड हैं कवि भूरेलाल भस्मासुर। सम्मान के नाम पर झट आ जाएंगे। भस्मासुर वास्तव में हिंदी के खलनायक थे। फटी आवाज से गला फाड़कर जब वे कठिन शब्दों की वर्षा करते, तो तालियां गड़गड़ाने लगतीं। वे हिंदी-शब्दकोश सामने रखकर लिखते थे। मजाल है कोई समझ जाए। इसी मूर्खतापूर्ण योग्यता के बल पर आज वे मंचों पर छा रहे थे। वे भस्मासुर थे। जिस पर हाथ रख दें वहीं भस्म। आजकल हिंदी उनके निशाने पर थी।

आज हिंदी-डे के मुख्य अतिथि वही भस्मासुरजी मंच के मध्य में विराजित हैं। एक तरफ डायना मेम दूसरी तरफ डिसूजा मेम, तीसरी तरफ चपरासी हार लिए खड़ा है। चौथी तरफ रोमन लिपि में हिंदी अमर रहे का पोस्टर लगा है। बीच में सहमे हुए बच्चे बैठे हैं।

उनके पास जो मौलिक है वह रचना नहीं है, और जो रचना है वह मौलिक नहीं है। ताली के इशारे के लिए बच्चे डिसूजा मेम की ओर देख रहे हैं। और मेम यह तय नहीं कर पा रही हैं कि कहां ताली बजानी चाहिए। एक सांस में खिंच रही रचना में ताली की संभावना ही नहीं बन पा रही है। किंतु कार्यक्रम के सफलता की संभावना बन चुकी है। विडियोग्राफी, फोटोग्राफी, हारों का ढेर। स्टाफ, बच्चे, चपरासी। स्टैंड, माइक, लाउडस्पीकर। टेबल, कुर्सियां आदि। सभी गवाह थे, दिवस की पूर्णता के प्रमाण के, कार्यक्रम की सफलता के। आज हिंदी-डे पर सभी की उपस्थिति थी, नहीं थी तो सिर्फ हिंदी।

ट्वीट-ट्वीट

खुद दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली की हवा सुधर गई है। वह यह भी कहती है कि पराली के धुएं से हालात बिगड़ सकते हैं। फिर ऑड-ईवन की क्या जरूरत? सीपीसीबी ने कहा था कि इससे वायु गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

यदि कांग्रेस आरएसएस की तरह बनना चाहती है तो उसे तीन चीजें करनी होंगी- विचारों व नेतृत्व में स्वदेशी को तरजीह दे, परिवार भक्त के बजाय देश भक्त बने और सरनेम के ऊपर प्रतिभा तथा कठिन परिश्रम को रखे। क्या ऐसा कर पाएगी?

शहजाद जयहिंद@Shehzad_Ind

गुलाम कश्मीर में एक रैली में इमरान खान, 'मैंने कश्मीर का सफीर बनने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूं, फिर मुसलमान हूं और फिर इंसान हूं।' जबर्दस्ती? उनसे कश्मीर का दूत बनने के लिए किसने कहा? कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि वह सऊदी अरब के दूत हैं।

स्मिता प्रकाश@smitaprakash

इश्तियाक अमजद

वर्षा जल संरक्षण से मुमकिन पेयजल का समाधान

धरती पर मौजूद कुल पानी में कितने प्रतिशत हिस्सा मीठे जल का है, यह जानने के लिए हमें दुनिया का चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक गूगल सर्च हमें तुरंत एक अंक वाला प्रतिशत बता देगा। यह आंकड़ा इतना छोटा है कि मीठे पानी की कमी खतरे की घंटी बजा रही है। इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य यह है कि मीठे जल की इस मामूली-सी मात्रा का भी अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर और ध्रुवीय आइस कैप्स के रूप में है, और एक बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे है, हमारी आंखों से दूर, और शेष जो कुछ भी है, उसे ही हम नदियों और झीलों के रूप में देखते हैं। हालांकि प्रकृति तो विभिन्न उद्देश्यों से भूजल को हमसे छिपाए रखने का इरादा रखती है, लेकिन हमने कुछ ज्यादा ही अक्लमंदी दिखाते हुए इसे खींच निकालने के तरीके ढूंढ लिए और अंततः सतह के नीचे के पानी को खत्म कर डाला। अब हम उस समस्या से लड़ रहे हैं जो हमने खुद ही खड़ी की है। दरअसल अपशिष्ट पदार्थों का समुचित ढंग से पृथक्करण और प्रबंधन न होने के चलते अथाह कचरा पैदा हो रहा है। यह अंततः जल संसाधनों में जाकर मिलता है और उन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ता। ये जहरीले तत्व पानी में रहते हैं या जल स्रोत की तलहटी में जमा हो जाते हैं। परिणामस्वरूप जल प्रदूषण पानी की गुणवत्ता में गिरावट का कारण बनता है जिससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल असर पड़ता है। साथ ही जहरीले प्रदूषक तत्व रिसकर जमीन के नीचे जमा भूजल में भी मिलते जाते हैं। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अरबों लोग निवास करते हैं जो गरीबी और भुखमरी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। चूंकि पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और गरीबी में कमी लाने के लिए पानी एक बुनियादी आवश्यकता है, इसलिए समझदारी भरे तरीकों से जल प्रबंधन किसी समाज के सामाजिक- आर्थिक विकास पर सकारात्मक असर डाल सकता है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि

मौजूदा समय में दुनिया भर में करीब 25 प्रतिशत लोगों को साफ पेयजल नहीं मिल पाता है। आगामी एक दशक में दुनिया की आबादी में एक अरब से अधिक की वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक बदलाव के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडे के तौर पर संयुक्त राष्ट्र ने संवहनीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए जिन्हें वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है। विश्व के नेताओं ने सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे अंगीकार किया था। यह एजेंडा 2030 तक 'सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और संवहनीय प्रबंधन सुनिश्चित करने' का लक्ष्य निर्धारित करता है।

ऐसे में हमारे लिए पहला सबक जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन करना होना चाहिए। यह हम सब की जिम्मेदारी भी है। इसी मकसद से आनंदना, कोका-कोला इंडिया फाउंडेशन द्वारा देश के सैकड़ों गांवों में जलभरण संरचनाएं स्थापित की गई हैं। इन जल संरचनाओं को झाबुआ (मध्य प्रदेश), धौलपुर, सीकर और अलवर (राजस्थान) और झांसी (उत्तर प्रदेश) जैसे क्षेत्रों में स्थापित किया गया है।

सूखे के दौर के लिए बारिश के दिनों में पानी जमा करना हमारे लिए दूसरा सबक होना चाहिए। आखिर क्यों मानसून के दौरान अधिकांश शहरों और कस्बों में सड़कों पर पानी भर जाता है और फिर हम ही सूखे मौसम में पानी खरीदते हैं? क्योंकि हम मानसून के दौरान मिले अतिरिक्त पानी के जरिये अपनी जमीन को प्रभावी ढंग से रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। यही पानी तो सूखे के समय काम आता है। हमने वर्षा जल संचयन की इस बुनियादी समझ को जल परियोजनाओं में अपनाया और बारिश के पानी को यूं ही बहकर बर्बाद हो जाने से रोकने के लिए चेक डैम, बांध, तालाब आदि बनाए। इससे मिट्टी का कटाव कम होता है और भूमि में नमी संरक्षित होती है।

हमें यह भी समझना होगा कि पानी बचाना एक बार का काम नहीं है, यह रोज की बात है। निर्माण के बाद भी जल संरचनाओं को निरंतर रखरखाव की दरकार होती है। उन्हें ऐसी गतिविधियों से बचाया जाना चाहिए जिनके चलते पानी में रासायनिक प्रदूषकों और कचरे के मिलने का खतरा पैदा हो सकता है।

पानी की उपलब्धता का हमारे अस्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसमें संवहनीय सामाजिक- आर्थिक विकास के साथ-साथ ऊर्जा और खाद्य उत्पादन भी शामिल है। हमें उस वक्त के बारे में विचार करना होगा जब हमें बहुत लंबे समय तक पानी के बिना रहने के कारण गर्मी, प्यास और बेचैनी महसूस होने लगेगी। अब कल्पना कीजिए कि यह चरम स्थिति स्थायी वास्तविकता बन रही है। ऐसे में आगे बढ़कर इस दिशा में काम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

(लेखक जल संरक्षण कार्यों से जुड़े हैं)

जागरण जनमत

कल का परिणाम

नए मोटर वाहन अधिनियम में जुर्माने की राशि को लेकर कुछ राज्यों की आपत्ति उचित है?

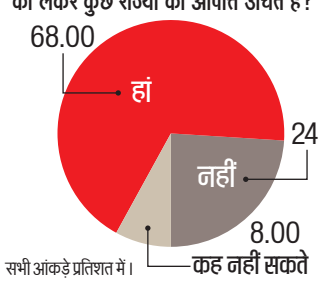

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दिल्ली सरकार का ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

बेटा इंग्लिश मीडियम नाती फुल अंग्रेज,
हिंदी दिवस मनाइए आप सजाकर मेज!
आप सजाकर मेज पढ़ो फूहड़ कविताएं,
आगे बैठे लोग तालियां खूब बजाएं।
बजट देय सरकार और दें भाषण नेता,
हिंदी का कल्याण न ऐसे होगा बेटा!!

- ओमप्रकाश तिवारी

हिंदी दिवस

सिंहासन पर विराजमान हो हिंदी

डॉ. जयकुमार जलज
शिक्षाविद और साहित्यकार

आज हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनावों में जीत हासिल करने तक में इसकी महत्ता बढ़ गई है, अन्य कई क्षेत्रों में तो पहले से ही है

संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश भाषाओं की वंशज होने के कारण हिंदी का भारतीय संस्कृति में तो महत्व था ही, अब कुछ वर्षों से वह भारतीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। अनेक विधानसभाओं का चुनाव जिताने के साथ अब लोकसभा चुनाव की जीत का माध्यम भी वह है। समूचे देश में वह समझी जाती है और मतदान को दिशा देने में समर्थ है। बीते लोकसभा चुनाव में वह जीत का प्रमुख कारक रही। उन राजनेताओं को भी, जो हिंदी में बोलना शान के खिलाफ समझते थे, हिंदी में बोलने के लिए विवश होना पड़ा।

हिंदी की अंतर्निहित शक्ति को महात्मा गांधी ने बहुत पहले भांप लिया था। उनके सान्निध्य में रहने वाले अनेक राजनेता भी उनसे सहमत थे। डॉ. राममनोहर लोहिया ने तो हिंदी के लिए मैदानी संघर्ष भी किया था। संस्कृति की अपेक्षा राजनीति की गति शिप्र होती है। इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि अब हिंदी का प्रचलन अधिक तेज गति से होगा। राजनीति के पदचिह्न तो जरूर उथले रहेंगे, किंतु संस्कृति उन्हें गहराई देती हुई चलेगी। आज हिंदी देश की अघोषित राष्ट्रभाषा है।

हिंदी की राजनीतिक हैसियत का ही यह कमाल है कि उसका समर्थन ही नहीं, उसका विरोध भी चुनाव में जीत दिलाता है। इसीलिए तमिलनाडु में पिछले सात दशकों में हिंदी विरोध के मुद्दे को सदैव जिंदा रखा गया है। नई शिक्षा नीति के मसौदे का त्रिभाषा सिद्धांत कहीं नहीं कहता कि हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. के कस्तूरीरंगन ने स्पष्ट किया है कि त्रिभाषा सिद्धांत अत्यंत लचीला है। राज्य और यहां तक कि स्कूल भी तय कर सकते हैं कि उनके छात्र कौन-सी तीसरी भाषा पढ़ेंगे। त्रिभाषा सिद्धांत में छात्रों को मातृभाषा और अंग्रेजी के साथ कोई भी एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़नी है। अगर तमिलनाडु के छात्र तमिल और अंग्रेजी के साथ उड़िया पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। उन्हें ही तय करना है कि उनका भविष्य किस तीसरी भाषा के पढ़ने से संवरेगा। लोग नादान नहीं हैं कि वे तीसरी भाषा हिंदी न चुनें। हिंदी का विरोध कहीं होता नहीं है, कराया जाता है। जितना कराया जाता है, उससे ज्यादा दिखाया जाता है।

कई साल पहले प्रसिद्ध साहित्यकार बालकवि बैरागी का अपने कुछ मित्रों के साथ चेन्नई जाना हुआ। टैक्सी ड्राइवर बोला, 'नो हिंदी! आइदर तमिल ऑर इंग्लिश।' बैरागीजी ने इंग्लिश बोलकर टैक्सी कर ली। रास्ते में उन्होंने अपने साथियों से कहा, 'यार, मध्य प्रदेश में ड्राइवरों के इतने सरकारी पद खाली हैं, पर्याप्त आवेदन ही नहीं आए।' ड्राइवर ने टैक्सी को धीमा किया, पीछे मुड़कर पूछा, 'साहब, आवेदन कब तक कर सकते हैं? मेरा भाई अच्छी ड्राइविंग जानता है।'

क्या हम हिंदी भाषी लोग खुद हिंदी विरोधी नहीं हैं? क्या हमें अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूल नहीं चाहिए? क्या हमारी प्रादेशिक सरकारें गांवों तक में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का सपना नहीं दिखातीं? क्या हमें अपने शिक्षकों से यह सुनने को नहीं मिलता कि 'अरे, हिंदी में क्या पढ़ना-पढ़ाना?' क्या हमारे हिंदी के शिक्षक समर्पण भाव से पढ़ा रहे हैं? क्या वे ईमानदारी से पढ़ा रहे अपने विभागीय सहयोगी का उपहास उड़ाते हुए यह नहीं कहते कि इन्हें तो पढ़ाने का बड़ा शौक है?

हमारा हिंदी बोलना तो फिर भी थोड़ा गनीमत है, किंतु लिखना? क्या हमारी पत्र-पत्रिकाओं, बाजारों में लगे साइन बोर्ड, दफ्तरों, शिक्षण संस्थाओं, निमंत्रण व सम्मान पत्रों, सूचनाओं, टेलीविजन विज्ञापनों में हिंदी वर्तनी की टांग नहीं तोड़ी जा रही है? और जिनसे हिंदी सीख रहे अहिंदी भाषा-भाषी असमंजस में पड़ जाते हैं? शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, पर स्वाभाविक और टिकाऊ परिवर्तन वह होता है, जो जनता के बीच से आता है, वह नहीं जो प्रकाशनों की लापरवाही से जन्मा होता है और कृत्रिम होता है। आज अनेक वाक्यों में 'हिंदी' शब्द का प्रयोग करके, क्या हम हिंदी को गाली के अर्थ में प्रयोग करने का दुष्कर पाप नहीं कर रहे हैं?

हिंदी भाषागत अपनी अनेक गलतियों को हम बोलियों के माथे मढ़ने के भी आदी हो गए हैं। अहिंदी भाषियों से उम्मीद करने से पहले हम खुद से ही उम्मीद क्यों नहीं करते? अशुद्ध वर्तनी अशुद्ध उच्चारण को और अशुद्ध उच्चारण अशुद्ध वर्तनी को जन्म देता है। क्या हमें इस दुष्चक्र को तोड़ने की दिशा में भी सक्रिय नहीं होना चाहिए?

हिंदी के सिर जीत का सेहरा ही नहीं बंधता, हार का ठीकरा भी फूटता है। अगर नेताओं को लगता है कि उनके बयान से गलत संदेश जा रहा है, तो उन्हें यह कहते देर नहीं लगती कि 'ऐसा उनके हिंदी न जानने के कारण हुआ है!' लेकिन क्या यह शर्मनाक नहीं है कि इस देश में अपने सत्तर साला राजनीतिक जीवन के बावजूद वे हिंदी नहीं जानते? खैर, 'जो हुआ सो हुआ', अब तो हिंदी सीख लीजिए। जनता में रहेंगे तो हिंदी अपने-आप आ जाएगी। सच तो यह है कि ऐसे तमाम लोग हिंदी जानते हैं, पर यह बताने में कि उन्हें हिंदी आती है, उन्हें निम्न- मध्यवर्गीयता की गंध आती है।

हिंदी अपने आंतरिक बलबूते पर आगे बढ़ी है। संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी ने उसे दास बनाने की कोशिश की। कई क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी की समान-धर्मा उर्दू ने भी उस पर आंखें तरेरीं। आज हिंदी की ही कई बोलियां उसके साथ मुंहजोरी कर रही हैं। लेकिन वह अपनी विनम्र दृढ़ता और जरूरी लचीलेपन के साथ गंगा की तरह सतत प्रवाहमान है। वह जानती है कि संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों से आए शब्दों का उसमें सहज समाहन और गति देगा। इसलिए वह उन्हें सदैव स्वीकार करती रही है। राजनीति ने तो हिंदी का लोहा मान लिया है, पर अब हमें भी हिंदी के अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। जब हम हिंदी बोलने, लिखने और पढ़ने में लापरवाही और कोताही नहीं बरतेंगे, तब और सिर्फ तब हिंदी का गौरव स्थापित होगा।

हमारे संविधान के दो निर्णय दूरदर्शी न होने से गलत रहे। पहला, कश्मीर को विशेष दर्जा देने का और दूसरा, सिंहासन पर बैठी हिंदी के बजाय अंग्रेजी से राजकाज चलवाने का। पहले में तो सुधार हो गया। दूसरा सुधरने में उस गौरव की निर्णायक भूमिका होगी, जो हम हिंदी को देंगे।

1888 में बिहार से निकली एक कहानी ने बुलंद कर दी हिंदी की किस्मत

अरविंद शर्मा, पटना

चंद्रकांता ने तिलिस्म और अय्यारी का ऐसा जाल बुना की इसे पढ़ने के लिए अन्य भाषाओं के लोगों ने भी सीखी थी हिंदी

भारतीय भाषाओं का पहला समृद्ध उपन्यास चंद्रकांता, जिसने बिहार से निकल हिंदी की किस्मत बुलंद कर दी। देवकीनंदन खत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनार गढ़, चकिया और नौगढ़ से लेकर बिहार के कैमूर और बराबर की पहाड़ियों तक तिलिस्म, अय्यारी, चमत्कार और जालसाजी हरकतों का ऐसा जाल बुना कि अन्य भाषाओं के लोग भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी भाषा की ओर मुखातिब होने लगे। पिछले सवा सौ साल के दौरान ऐसे बहुत कम हिंदी प्रेमी साक्षर या निरक्षर होंगे, जिन्होंने चंद्रकांता को पढ़ा, सुना या देखा नहीं होगा।

देवकीनंदन खत्री

चंद्रकांता संतति पुस्तक का कवर पेज

वर्ष 1888 में चंद्रकांता का प्रकाशन काशी के हरि प्रकाश प्रेस में हुआ था। तब देवकीनंदन की उम्र महज 27 वर्ष थी। मुजफ्फरपुर के पूसा में 29 जून, 1861 को जन्मे देवकीनंदन के दिमाग में चंद्रकांता का प्लॉट उस वक्त आया, जब वह बिहार के टिकारी स्टेट में दीवान हुआ करते थे। उनकी युवावस्था (18 से 26 वर्ष) टिकारी में बीती थी। लेखक की इतनी कम उम्र में उसकी रचना में इतनी रवानी, शिल्प-शैली इतनी सहज, पात्र इतने सजीव, बुनावट इतनी जटिल और कल्पना का फलक इतना विराट था कि चंद्रकांता के मुकाबले की रचना हिंदी साहित्य में अभी तक असंभव है। वह हिंदी के पहले तिलिस्मी लेखक थे।

हिंदी को आम लोगों की भाषा बनाया : देवकीनंदन के जमाने में भारत में सिर्फ छह फीसद लोग ही साक्षर थे। तब उर्दू की तरह हिंदी का विकास भी नहीं हो पाया था। यह 19वीं सदी का अंतिम दौर था। कोर्ट-कचहरियों में उर्दू-फारसी का बोलबाला था। लिहाजा उनका मकसद अपनी रचनाओं के जरिये देवनागरी लिपि के साथ-साथ हिंदी भाषा का प्रचार करना था। यह आसान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। तिलिस्म और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी में भी जगह दी।

टिकारी में तैयार हुआ था चंद्रकांता का प्लॉट : चंद्रकांता का प्लॉट देवकीनंदन के दिमाग में टिकारी प्रवास के दौरान ही आ गया था। टिकारी राज परिवार से गहरे जुड़े रजनीश वाजपेयी के मुताबिक, देवकीनंदन की मां पूसा के ईस जीवनलाल मेहता की बेटी थीं। इनका बचपन पूसा में बीता था। टिकारी राज में इनके नाना का हाथी का हौदा बनाने और लकड़ी का पुश्तैनी कारोबार था। इनके नाना की महाराजा गोपाल शरण सिंह के पिता राजा अंबिका शरण सिंह से अच्छी दोस्ती थी। राजदरबार में प्रतिष्ठा भी। देवकीनंदन 18 साल की उम्र में ही टिकारी आ गए थे, जहां बाद में दीवान नियुक्त हो गए। 1886 में टिकारी का साथ तब छूटा जब गया के तत्कालीन जिलाधिकारी जॉर्ज ग्रियर्सन ने टिकारी राज को अपने अधिकार में लेकर कोर्ट ऑफ वार्ड घोषित कर दिया। इससे दीवान का पद स्वतः समाप्त हो गया। तब देवकीनंदन का ठिकाना काशी हो गया, जहां चंद्रकांता का अधिकांश भाग लिखा गया और प्रकाशन हुआ। खत्री ने अपने एक अन्य उपन्यास कुसुम कुमारी में भी जहानाबाद के पंडुई राज और टिकारी की चर्चा की है।

25 देशों में रहा है हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का जलवा

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

100 से अधिक का प्रकाशन हुआ है विदेश में

कई देशों में अब भी हिंदी में हो रहा है प्रकाशन

हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का जलवा विदेश में भी रहा है। अब तक 25 देशों से 100 से अधिक हिंदी की पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें कुछ दर्जन पत्र-पत्रिकाएं तो अब भी प्रकाशित हो रही हैं।

मुंबई निवासी डॉ.जवाहर कर्नावट के पास इनमें से 23 देशों की 95 पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक (राजभाषा) के पद से सेवानिवृत्त हुए डॉ. कर्नावट को ये पत्र-पत्रिकाएं जुटाने के लिए करीब 22 देशों की यात्राएं करनी पड़ी हैं। इन यात्राओं के दौरान वह अनेक अनुभवों से दो-चार हुए और इन देशों में हिंदी की पैठ देखकर चकित भी, क्योंकि पिछले करीब 120 वर्षों में इतने देशों से प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का अपना इतिहास और उन्हें प्रकाशित करने के अपने कारण रहे हैं। इनमें कई पत्रिकाएं तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बुलंद करने का माध्यम भी बनीं।

120 साल पहले ही हो गई थी प्रकाशन की शुरुआत : लंदन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'पुरवाई' को देखकर डॉ. कर्नावट की विदेश से निकलने वाली हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के बारे में जानने की रुचि जागी। वह 1999 में वहां हो रहे विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस पत्रिका को देखकर उन्हें लगा कि ऐसी अन्य देशों से निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं की भी खोजबीन की जानी चाहिए। इसी खोजबीन की कड़ी में उन्हें पता चला कि भारत से कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाए गए गिरमिटिया मजदूरों के देशों मारीशस, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, गुयाना, त्रिनिडाड और टोबैगो आदि में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत तो करीब 120 वर्ष पहले ही हो गई थी। दूसरी श्रेणी में इंग्लैंड, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश थे, जहां भारतीय कारोबार या किसी अन्य कारण से गए। करीब 116 साल पहले दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित फीनिक्स आश्रम से चार जून, 1903 को महात्मा गांधी ने जिन चार भाषाओं में 'इंडियन ओपिनियन' नामक आठ पृष्ठ का अखबार निकाला था, उसमें दो पृष्ठ हिंदी के थे। बाकी छह पृष्ठों में गुजराती, तमिल और अंग्रेजी की सामग्री प्रकाशित थी। पाठकों की संख्या कम होने के कारण कुछ वर्ष बाद इस पत्र से हिंदी और तमिल को हटा गया, लेकिन 1913 में इसमें पुनः हिंदी को जोड़ना पड़ा।

मुंबई निवासी डॉ. जवाहर कर्नावट फाइल

जापान में प्रकाशित ज्वालामुखी पत्रिका के वर्ष 1980 के अंक का मुख्य पृष्ठ।

डॉ. कर्नावट के संग्रह से

अखबार से दी आजादी की लड़ाई को हवा : 'इंडियन ओपिनियन' में ही हिंदी का काम देखने वाले भवानी दयाल संन्यासी ने कुछ समय बाद अपना अखबार 'धर्मबीर' निकालना शुरू किया। उससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो 'हिंदी' नाम से ही एक अन्य अखबार शुरू किया। इस पत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी सामग्री भी भरपूर होती थी। इसका दिवाली विशेषांक तो अद्भुत होता था। गांधी जी ने जब डॉ. मणिलाल को मॉरीशस भेजा तो वहां उन्होंने आजादी की लड़ाई को हवा देने के लिए 'द हिंदुस्तानी' नामक द्विभाषी अखबार निकाला। इसकी देखादेखी वहां और भी कई अखबार निकाले जाने लगे। इन अखबारों में मॉरीशस में भारतीयों पर अत्याचार की खबरों को प्रमुखता दी जाती थी। मॉरीशस में 50 से ज्यादा हिंदी पत्र-पत्रिकाएं निकल चुकी हैं। फिजी में भी यही स्थिति रही। वहां 1935 में शुरू हुआ 'शांतिदूत' तो अब भी निकल रहा है। पहले तो यह पूरी तरह देवनागरी में ही छपता था। अब इसके कुछ पृष्ठ रोमन में छपने लगे हैं, लेकिन भाषा अब भी हिंदी ही है। इसी समूह का 'फिजी सन' नामक अखबार निकलता तो अंग्रेजी में है, लेकिन इसका दिवाली विशेषांक हिंदी में ही छपता है।

भारत आजाद हुआ तो बंद कर दिया प्रकाशन : विदेश की हिंदी पत्र-पत्रिकाओं पर शोध कर उनके इतिहास लेखन में लगे डॉ. कर्नावट बताते हैं कि इसी शोध की कड़ी में उन्हें 2005 में लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी जाना पड़ा। वहां से उन्हें अलग-अलग देशों में प्रकाशित होने वाली कई पत्र-पत्रिकाओं के बारे में पता चला। इन्हीं में से कुछ थीं, जापान से प्रकाशित होनेवाली 'जापान भारती', 'सापुरा की बयार' और 'ज्वालामुखी'। ज्वालामुखी के तो संपादक भी जापानी ही थे।

अमेरिका में हुआ गदर का प्रकाशन : लाला हरदयाल की 'गदर पार्टी' 1913 में बनी, तो एक नवंबर, 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हिंदी का अखबार 'गदर' शुरू किया गया। इस अखबार के साथ समय-समय पर देशभक्ति की कविताओं के संग्रह 'गदरी रिसाला' के नाम से छापे जाते थे। जो लोकप्रिय होते थे। द्वीतीय विश्वयुद्ध के दौरान सिंगापुर से रोमन लिपि में 'जवान' नामक हिंदी पत्र निकलता था। जब भारत आजाद हुआ तो 'अब आप आजाद हैं' यह मुख्य शीर्षक देकर इस पत्र का प्रकाशन बंद करने की घोषणा कर दी गई, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरा हो चुका था।

दैनिक जागरण

सबरंग

शहर को जानने के...

नई दिल्ली, शनिवार, 14 सितंबर, 2019

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com

https://www.facebook.com/jagransabrang/

दिल्ली के बाशिंदों की जुबानी, खाने की कहानी

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान

दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

भारत के विभाजन (1947) के बाद दिल्ली का तेजी से विस्तार हुआ और देश के कोने-कोने से व्यक्ति कामधाम की तलाश में यहां आए। और इस कारण राजधानी में शीघ्र ही प्रादेशिक और अंतरराष्ट्रीय विविधता वाला भोजन उपलब्ध हो गया। जबकि दिल्ली की पाक कला ने, शहर के स्वभाव के अनुरूप, यहां आकर बसने और घर बनाने वाले अनेक व्यक्तियों और समुदायों से व्यंजनों और मसालों को सीखा तथा अपनाया।

'न्यू दिल्ली डाउन द डिकेड्स' में ध्रुव एन चौधरी लिखते हैं कि आजादी से पहले कनॉट प्लेस में 'डेवीकॉस' चौ और 'वेंगर्स' नामक दो महत्वपूर्ण पेस्ट्री शॉप और रेस्त्रां थे, जिनके मालिक यूरोपीय थे। तब क्वींसवे (अब जनपथ) पर मौजूद कॉफी हॉउस, 'द इंडिया कॉफी हाउस' कहलाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति तक कॉफी हाउस, जो कि सभी के लिए खुला था, में अधिकतर अमेरिकी सैनिक कॉफी पीते और डोनट खाते नजर आते थे। बाद में यह कॉफी हाउस एक बैरक, जो कि थियेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग कहलाती थी, के बगीचे में स्थानांतरित हो गया। अपने नाम के अनुरूप इस इमारत का रंगमंच से कोई लेना-देना नहीं था और यह इमारत आज के पालिका बाजार के स्थान पर थी।

'सेलिब्रेटिंग दिल्ली' पुस्तक में प्रीति नारायण लिखती है कि दिल्ली की समृद्ध पाककला में सबसे पहले पंजाबियों ने अपना योगदान दिया। करिश्माई कुंदनलाल के शुरू किए गए मशहूर मोती महल ने तंदूरी खाने खासकर चिकन को प्रसिद्धि दिलवाई। ऐसा कहा जाता है कि जवाहर लाल नेहरु की फरमाइश पर उन्हें विमान यात्राओं में तंदूरी चिकन परोसा जाता था। सर्वत्र मिलने वाला तंदूरी चिकन भी मोती महल की ही देन था। यहां तक कि असली दिल्ली के खाने का ठिकाना माने जाने वाले करीम ने भी तंदूरी चिकन को अपनी भोजन सूची में शामिल किया। करीब 25 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के संपादक रहे रवि दयाल के अनुसार, बीसवीं सदी के पांचवे दशक के आखिरी वर्षों तक नई दिल्ली में रहने वालों के लिए मोती महल एक सर्वाधिक आकर्षण वाला ठिकाना था। तो वहीं मेंडस होटल के बार और नाइट-क्लब शहर के लोगों की कल्पनाशीलता का भाग थे। दयाल ने अपने समय की दिल्ली के हवा-पानी का वर्णन करते हुए लिखा है कि बीसवीं सदी के सातवें दशक तक आपको पीने के पानी को उबालने या छानने की जरूरत नहीं होती थी। आप बीमार होने की चिंता को छोड़कर, बेझिझक पटरी वालों से ककड़ी और चाट खा सकते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का मतलब था, दरियागंज और लाल किला होकर गुजरना। यहां काफी देर ठहरना होता था क्योंकि इन इलाकों से होकर गुजरने वाली बसों की अदला-बदली करनी पड़ती थी। इन ठहरावों के दौरान व्यक्ति को बस स्टैंडों के पास बने ढाबों और खाने के दुकानों को जानने का मौका मिलता था।

'दिल्ली, द फर्स्ट सिटी' पुस्तक में बीबीसी के पूर्व पत्रकार और पुरानी दिल्ली निवासी सतीश जैकब लिखते हैं कि बीसवीं सदी के पांचवें दशक में एक रुपये में चालीस किलो गेहूं या चार किलो देसी घी मिलता था। दो पैसे में आपको पराठों और शोरबे वाले मांस का एक शानदार भोजन उपलब्ध था। तब सुख-साधनों का स्तर ऊंचा था तो लोगों में बहुतायत की एक भावना थी। यही कारण है कि तब सड़क किनारे बने खाने की दुकानों में दाल के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। भोजन में दाल निश्शुल्क परोसी जाती थी। सतीश लिखते हैं कि तब खानसामा का एक महत्वपूर्ण किरदार होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पुरानी दिल्ली के लोग बेहतर खाने की तमीज रखने वाले अपने दोस्तों के लिए धीमी आंच पर आहिस्ता-आहिस्ता पकने वाले स्वादिष्ट पकवानों से मेजबानी करना पसंद करते थे। यहां तक कि मेरे वालिद, जो कि कोई नवाब नहीं थे, महीने में दो बार रात के खाने की महफिलें रखते थे। इनके लिए खाना तैयार करने के लिए पूरी मेहनत के साथ व्यापक तैयारियां की जाती थीं।

पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध चित्रकार अंजलि इला मेनन, जिनके पिता राष्ट्रपति के चिकित्सक थे, ने अपनी किशोरावस्था में दिल्ली में बिताए समय के बारे में लिखा है। उनके संस्मरण के अनुसार, बावर्चीखाना घर के मुख्य भाग से जुदा था पर वह एक टाइल वाली छत के रास्ते से जुड़ा हुआ था। वहां पर लकड़ी से जलने वाले तीन चूल्हे और उसके नीचे तंदूर था। इस पुरानी रसोई में हैरतअंगेज खाने की चीजें मिलती थीं। जहां पर न केवल देसी जायके का खाना बल्कि केक और कस्टर्ड, पाई और सपनों के स्वाद वाली पेस्ट्री मिलती थी। एक सैनिक परिवार में बरती जाने वाली किफायत में जहां बगीचे में उगने वाली हर चीज का उपयोग होता था, जिनसे मुरब्बे और अचार बनाए जाते थे। ऐसे में, हमेशा शानदार खाने से भरी मेज की याद स्थायी है। कभी-कभार भोजन के लिए कनाट प्लेस जाने के अलावा मोती महल में रात्रि भोज का दुर्लभ अवसर मिल जाता था। नहीं तो छावनी में जिंदगी पूरी तरह अपने में सिमटी हुई थी। तब पचास के दशक में (मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा) हुसैन जामा मस्जिद इलाके के नाज होटल में रहते थे। हमारे दोस्तों का एक समूह बहुधा कॉलेज की कक्षाओं को छोड़कर दोपहर के खाने के लिए सामूहिक रूप से फ्लोरा रेस्त्रां पहुंच जाता था।

दिल्ली में पहले जमाने वाला मुगलई

जायका अब कहां

आज यदि सर्वाधिक प्रयोग किसी चीज पर हो रहे हैं तो वह है खानपान...कुजीन..व्यंजन..भोजन...रसोई जो नाम दे लीजिए। लेकिन इसके बारे में जब बात हो, तो जरा शिद्दत से हो, तल्लीनता से हो, उसी भूख और स्वाद से हो। जल्दबाजी में न हो। क्योंकि आजकल रसोई भी बहुत जल्दबाजी में पकाई जाती है। खाना जितने सुकून से बनेगा उतनी लजीजियत देगा। और बात जब पारंपरिक जायके की हो वो भी मुगलई परंपरा की तो थोड़ी नफासत भी रहनी चाहिए। हाल ही में गुरुग्राम, सनसिटी निवासी पाक इतिहासकार व पर्शियन स्कॉलर सलमा युसुफ हुसैन ने एक किताब लिखी जो खासी चर्चा बटोर रही है। किताब आपको मुगल बादशाह शाहजहां की रसोई से निकले इतिहास और उसकी जायके की खुशबू के बेहद करीब नजर आएगी। 'द मुगल फीस्ट' के नाम से आई इस पुस्तक के बारे में प्रियंका दुबे मेहता ने सलमा युसुफ हुसैन से विस्तार से बात की, प्रस्तुत हैं बातचीत के प्रमुख अंश :

बातचीत

'द मुगल फीस्ट' पुस्तक की लेखिका पाक इतिहासकार सलमा युसुफ हुसैन

● 'द मुगल फीस्ट' लिखने की प्रेरणा कैसे मिली?

- मैंने भारतीय व्यंजनों पर विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के प्रभाव का अध्ययन किया है। जहांगीर के शासनकाल की पाक कला और उसकी बारीकियों को बताने के लिए 'अलवान-ए-नेमत' लिखी थी और अब शाहजहां कालीन जायकों और उसकी यात्रा पर 'द मुगल फीस्ट' लिखी है। इन दोनों किताबों की मेनु स्क्रिप्ट (हस्तलिपि) मुझे विभिन्न प्रदर्शनियों में मिली। एक ब्रिटिश प्रदर्शनी में मिली पर्शियन हस्तलिपि 'नुस्खा-ए-शाहजहानी' को समझकर, उस पर अध्ययन करके उसे 'द मुगल फीस्ट' के रूप में उतारा है।

● आपकी इस किताब को केवल अनुवाद नहीं, बल्कि पुनर्लेखन कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है?

-मैंने इस मेनु स्क्रिप्ट को जस का तस अनुवाद करने की जगह रेसिपीज को पहले खुद बनाया। स्वाद चखा और फिर लिखा है। इसके अलावा हर व्यंजन के विकास की ऐतिहासिक यात्रा का जिक्र भी है कि किस तरह से खान-पान के क्षेत्र में लगातार प्रयोग हुए हैं।

● आज की आधुनिक रसोई के बारे में क्या कहेंगी?

-आज की रसोई बेहद फास्ट हो गई है। उस समय खाना आसान था, रचनात्मकता बहुत थी। तब धीमी आंच पर खाना बनाने की परंपरा होती थी। आज हम भोजन बनाने में समय नहीं देते। इसीलिए व्यंजनों का सुस्वाद भी बहुत बदल गया है। खाने ने अपनी पहचान खो दी है। उस समय भोजन पतीले में नहीं बल्कि दकन में बनता था जिसमें आंच हर तरफ से लगती थी।

● कहा जाता है कि मुगलकाल में पाक कला को खास समृद्धि मिली?

-मैंने इतिहास देखा और पढ़ा और पाया कि जहांगीर के काल में ही फूड डेकोरेशन और गार्निशिंग की विधा इजाद की गई थी। जहांगीर की बेगम नूरजहां पारसी थीं ऐसे में वे ईरानी व्यंजन संस्कृति को भारत लाईं। उन्होंने भोजन को रंगने की विधा की शुरुआत भी की। इसी दौरान खाने में फलों का प्रयोग होना शुरू हुआ था। नुस्खा-ए-शाहजहानी में कबाब से ज्यादा पुलाव का जिक्र मिलता है।

● ऐसी कुछ रेसिपीज के बारे में बताएं जिनसे उस दौर में फूड गार्निशिंग के प्रमाण मिलते हों?

-उस समय जो पुलाव या गोश्त बनता था उसे बड़ी ही रचनात्मक तरीके से बनाया जाता था। ऐसा ही एक था नारंज पुलाव (संतरे का पुलाव)। इसे बनाने के लिए धीमी आंच पर पहले बोटियां रखी जाती थीं फिर चावल रखते थे। बड़ी-बड़ी तीन नारंगियां लेकर उनका गूदा निकाल दिया जाता था। एक में पिश्ते का हरे रंग का हलवा, एक में कीमा और एक में जाफरान से रंगे चावल परोसे जाते थे। इसे तले हुए किशमिश और बादाम से सजाया जाता था।

इसी तरह से मोती पुलाव बनता था। उस समय गोश्त तगड़े होते थे। अंडा फेंटकर, सोने और चांदी के वर्क घोलकर उसे चिकन के इसोफेगस (भोजन नलिका) में उड़ेल दिया जाता था। अब इस इसोफेगस को थोड़ी-थोड़ी दूरी पर धागे से बांध दिया जाता था। पानी गर्म करके उसकी भाप से इसे पकाया जाता था। अब धागे खोलने पर सफेद व सुनहरे मोती निकलते दिखाई देते थे और इससे पुलाव की डेकोरेशन की जाती थी।

● मुगलों के बाद भोजन के क्षेत्र में कितना विकास हुआ?

-मुगलई भोजन में सबसे ज्यादा योगदान जहांगीर और शाहजहां का ही था। उसके बाद औरंगजेब ने इस क्षेत्र में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि उनका ध्यान युद्धों में लगा रहता था। जब वह शासक बना तो वह शाकाहारी बन गया था। मुगल कालीन पांडुलीपियों में शाकाहारी भोजन को भी जगह दी गई है। अलवान-ए-नेमत में दाल की कई रेसिपी मिलती हैं। औरंगजेब के समय में कुमूली यानी चने की दाल का पुलाव बनता था। वैसे मुगलों के बाद खाने के विकास की क्या स्थिति थी, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है।

दिल्ली-एनसीआर में बिकने वाला मुगलई जायका कितना मुगलई है? अगर दिल्ली में विशुद्ध मुगलई भोजन करना हो तो कहां जाना चाहिए?

बात केवल दिल्ली की ही नहीं है, पूरे देश में, यहां तक कि अवध में भी वह असल जायका मिलना बेहद मुश्किल है। इसका कारण यही है कि खाना पकाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। भोजन से असल मुगल टेस्ट देने वाला जाफरान और वह केवड़ा नहीं मिलता। भोजन को चटपटा और मसालेदार बनाने की होड़ में उसकी रूह निकाल ली जाती है। पुरानी दिल्ली में मुगलई भोजन मिलता है। लेकिन अगर आप परंपरागत मुगल भोजन की बात करेंगे तो वह कहीं नहीं मिलेगा। यह केवल आपको घर पर ही मिल सकता है। वह भी तब जब आप उसे पूरे धैर्य और एक निर्धारित विधि से बनाएंगे। इसके अलावा फाइव स्टार होटलों में भी मिल सकता है वह भी कहीं-कहीं। उस असल स्वाद की गारंटी वहां भी नहीं है।

● दिल्ली पर मुगलों ने लंबे समय तक शासन किया, तो यहां के जायके में उस परंपरा का एहसास आपको शोध के समय हुआ होगा?

-मुगलई भोजन को दिल्ली से जोड़कर जरूर देखा जाता है लेकिन स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। मैंने दिल्ली में काफी शोध किया है। पुरानी दिल्ली की गलियों का जायका चखा है लेकिन कहीं वह संतुष्टि नहीं मिली। मैंने आइटीसी में काम किया है और वहां का मेन्यू भी बनाया है। करीम का जायका भी चखा है लेकिन वहां भी अब वह बात नहीं रह गई। उसी के पास जवाहर रेस्त्रां में फिर भी कुछ बेहतर मुगलई खाना मिलता है। पहले छोटे-छोटे केटेरर्स हुआ करते थे, एक फ्लोरा रेस्त्रां हुआ करता था। अब वह सब खत्म हो गए हैं।

● अपनी रचनाओं को अन्य किताबों से अलग बनाने के लिए क्या करती हैं?

-आज व्यंजन पर खूब लिखा जा रहा है लेकिन कहां तक...सिर्फ रेसिपी तक। मैं अपनी रचनाओं में यह बताने की कोशिश करती हूं कि खाना हमारी संस्कृति से जुड़ा है। जब तक भौगोलिक स्थितियां, हमारे मसाले, हमारी आबोहवा, प्रकृति आदि के बारे में हमें पता नहीं होगा, हम भोजन को बेहतर तरीके से कैसे बना सकेंगे? मैंने अपनी किताबों में बताया है कि भोजन को भाप से किस प्रकार से पकाया जाता था। जैसे बर्तन में पानी उबलता था फिर उस पर कपड़ा मलमल का फिर घी, फिर कपड़ा, उसपर चिकन या गोश्त रखते थे। इसी तरह से और धीमी आंच के लिए मचान बनाए जाते थे। इस तरीके से बने भोजन के स्वाद का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब जानकारी मेरी इस किताब में है।

● पाक इतिहासकार होने के नाते भारतीय परंपरागत जायकों को मुगलई से बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही हैं?

-मेरी शोध का केंद्र मुगलकालीन व्यंजन रहे हैं। ऐसे में मैं उन्हें और बेहतर बनाने के लिए पहले नई-नई डिशेज पर काम कर रही हूं और फिर किताबों के जरिए उन्हें घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रही हूं जिसमें काफी हद तक मुझे कामयाबी भी मिली है।

कॉर्पोरेट जगत में हिंदी की धमक

दिल्ली दिल से

विवेक शुक्ला

लेखक व इतिहासकार

हिंदी हैं हम

बंगाली मार्केट से सटे तानसेन मार्ग पर स्थित देश के प्रमुख कारोबारियों की संस्था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 50 साल से अधिक पुरानी इमारत में कुछ साल पहले तक संवाद से लेकर तमाम सम्मेलनों की भाषा अंग्रेजी ही हुआ करती थी। हिंदी के लिए यहां कोई जगह नहीं थी, पर अंग्रेजी का वह एकछत्र राज अब ढह गया है। अब हिंदी ने उद्योग और वाणिज्य जगत में अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआइआइ) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) जैसे उद्योग मंडलों के नुमाइंदों के साथ हिंदी में ही बातचीत करते हैं।

बोर्ड रूम में हिंदी: हालांकि पहले भी मारवाड़ी, उत्तर और पश्चिम भारत से जुड़ी कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां जैसे भारती एयरटेल के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, हीरो समूह के प्रमुख पवन मुंजाल, साउथ वेस्ट के अध्यक्ष सज्जन जिंदल आदि हिंदी में ही अपने पेशेवरों से बातचीत करते थे। अब हिंदी बड़ी कंपनियों की बोर्ड रूम में भी प्रवेश कर गई है। साउथ दिल्ली स्थित एसोचैम और सीआइआइ के दफ्तरों में भी हिंदी खूब बोली-सुनी जा रही है। अंग्रेजी के वर्चस्व को हिंदी तोड़ नहीं रही है, पर वह अपने लिए नई जमीन अवश्य तैयार कर रही है। ओंकार सिंह कंवर (अपोलो टायर्स), रीतू राज सिन्हा (एसआइएस सिक्योरिटी), संतोख चावला (फन एंड फूड विलेज), बीके मोदी (मोदी समूह) जैसे तमाम दिल्ली से संबंध रखने वाले बड़े उद्यमियों के अलावा जिन कंपनियों का प्रबंधन मारवाड़ियों के हाथों में है, वहां पर हिंदी पूरी ठसक के साथ मौजूद है।

अपोलो टायर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार सिंह कंवर को आप फिक्की के दफ्तर में या अपनी कंपनी की बोर्ड की बैठकों में अंग्रेजी के साथ हिंदी मजे से बोलते हुए सुन सकते हैं। अगर उन्हें कहीं कोई भाषण देना होता है तो वे आमतौर पर लिखा हुआ भाषण ही पढ़ते हैं। भाषण में जटिल अंग्रेजी शब्द हिंदी या गुरुमुखी में लिखे होते हैं। बोर्ड रूम में गुजराती, सिंधी और अन्य भारतीय भाषाएं भी सुनाई देती हैं।

पुराने उद्योग घराने में आज भी है दबदबा: दिल्ली के पुराने उद्योग घराने डीसीएम समूह में हिंदी के लिए सदैव खास स्थान रहा। लाला श्रीराम से लेकर भरत राम और लाला चरत राम हिंदी प्रेमी थे। इसी समूह ने दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स और लेडी श्रीराम कॉलेज स्थापित किया। ये रामलीला को भी आयोजित करता रहा। इस बीच हिंदी की बढ़ती हुई ताकत पर सबसे सटीक टिप्पणी तमिल भाषी एचसीएल टेक्नोलॉजी के खरबपति चेयरमैन शिव नाडार करते हैं। वे कहते हैं हिंदी पढ़ने वाले छात्रों को इसके माध्यम से अपने करियर को चमकाने में लाभ मिलता है। करीब बीस सालों से विज्ञापन की दुनिया में अपना खास स्थान रखने वाले मशहूर एड गुरु प्रसून जोशी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि कॉर्पोरेट इंडिया को हिंदी की ताकत मालूम है, हिंदी के बाजार की व्यापकता का अंदाजा है। इसी तथ्य की रोशनी में हिंदी पट्टी के लिए विज्ञापन का बजट सर्वाधिक होता है। जोशी कहते हैं कि यदि आप अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते तो बिजनेस जगत में सफल होना भी आपके लिए कड़ी चुनौती होगा।

विदेश के दिल में हिंदी: आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारोबारी भी बड़े पैमाने पर हिंदी का ज्ञान हासिल कर रहे हैं ताकि उनका भारत प्रवास ज्यादा सार्थक हो सके। भारतीयों से अपने उत्पाद की जानकारी उन्हीं की भाषा में बात कर अच्छी तरह ले सकें। दिल्ली-गुरुग्राम में काम करने वाले सैकड़ों जापानी, चीनी और कोरियाई कंपनियों के कारोबारी दिल्ली में रहते हुए हिंदी सीख लेते हैं। ये हिंदी के शिक्षक या फिर उन संस्थानों में जाकर हिंदी सीख रहे हैं, जहां विदेशी या राजनयिकों को हिंदी पढ़ाई जा रही है।

गुप्ता जी की पाव भाजी में

मक्खन सा स्वाद

जायका

एक तरफ बड़े से तवे पर मक्खन से सिक रहे पाव दूसरी तरफ भाजी को तवे पर गर्म करने में व्यस्त कारीगर...प्याज, हरी चटनी, नींबू के साथ गर्मागर्म पाव भाजी प्लेट में देख लोग उसे खाने को बेताब हो उठते हैं। ऊपर से भाजी पर मक्खन का टुकड़ा स्वाद को दोगुना कर देता है। एक प्लेट से जी नहीं भरता तो ग्राहक खाते हुए दूसरे प्लेट का भी ऑर्डर दे रहे हैं। वहीं जो लोग कतार में हैं, वे उत्सुकता के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कब लोग टेबल खाली करे और उन्हें पाव भाजी खाने का मौका मिले। दरियागंज फ्रूट मार्केट स्थित गुप्ता जी पाव वाले दुकान पर रोजाना यही दृश्य देखने को मिलता है।

रेहड़ी से दुकान तक का सफर: दुकान मालिक दीपक गुप्ता कहते हैं मेरे पिता रामधनी के संघर्षों का फल है यह पाव भाजी की दुकान। हमारा परिवार पहले दरियागंज में ही किराए के मकान में रहता था। सन् 1984 के पहले से ही पिता दरियागंज में रेहड़ी लगाते थे। इसी रेहड़ी पर वे पाव भाजी बेचते थे। लेकिन रेहड़ी पर दुकान खोलने के बहुत पहले से ही उनका संघर्ष जारी था। रेहड़ी से पहले जूस की दुकान व अन्य दुकानों पर काम कर एक-एक पाई जोड़ा, बावजूद इसके घर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदार के यहां काम सीखने की सोची। जीजा बच्चूलाल गुप्ता की मुंबई में पाव भाजी की दुकान थी। पिजा जी वहां पहुंचकर करीब चार महीने काम किया। इस दौरान पूरी तन्मयता के साथ पाव भाजी बनाना सीखा। इसके बाद वह रेहड़ी पटरी पर पाव भाजी बेचने लगे।

भेल पूरी और सेव पूरी में भी लाजवाब: लोगों को रामधनी की पाव भाजी इतनी पसंद आई कि उन्होंने रेहड़ी से दुकान तक का सफर तय कर लिया। यहां स्पेशल बटर पाव भाजी, पाव भाजी, भेल पूरी, सेव पूरी, वडा पाव एक्स्ट्रा पाव भी मिलता है। दीपक कहते हैं हमारी यूएसपी मसाले हैं। दरअसल, हम पाव भाजी का मसाला घर पर ही बनाते हैं। दुकान से खड़ा मसाला खरीदकर हम घर पर खुद उसे पीस कर तैयार करते हैं। यहां भेल पूरी और सेव पूरी का स्वाद भी शानदार होता है। खस्ता पापड़ी के ऊपर, उबले आलू, प्याज, हरी चटनी, लहसुन चटनी, खजूर चटनी, सेव भुजिया, धनिया और मसाले डाल कर ग्राहकों को परोसी सेव पूरी खाने में बहुत स्वादिष्ट है।

संजीव कुमार मिश्र

दाम
पाव भाजी 60 रुपये
बटर पाव भाजी 80 रुपये

गुप्ता जी की दुकान पर भाजी तैयार करता कारीगर जागरण

वैष्णो चाट भंडार

कमला नगर, छोटी गली चक्कर स्थित यह दुकान बटर पाव भाजी के लिए जानी जाती है। यहां चाट, गोलगप्पे और मटका कुल्फी का स्वाद भी उम्दा है।

झक्कास का खास स्वाद

पंजाबी बाग स्थित झक्कास पाव भाजी में आपको मुंबइ का स्वाद मिलेगा। दाम भी बजट में है। 100 रुपये से शुरू।

न्यू अर्जुन बांबे

मॉडल टाउन 3 में न्यू अर्जुन पाव भाजी दुकान पर आप जैन पाव भाजी का भी स्वाद ले सकते हैं। यहां जितना मसाला या तीखा आप खाना चाहे उसी अनुसार भाजी तैयार की जाती है।

प्रदीप पाव भाजी

मयूर विहार फेस 2 स्थित प्रदीप पाव भाजी दुकान पर साधारण पाव भाजी के अलावा जैन पाव भाजी और डबल फ्राई पाव भाजी मिलती है। महज 100 रुपये में सुस्वाद ले सकते हैं।

कुमार के पाव

कृष्णा नगर स्थित यह दुकान क्रिस्पी पाव भाजी के लिए मशहूर है। लोग यहां तवा पुलाव भी खूब खाते हैं।

रवींद्र भवन, भविष्य के भारत की झलक

नायाब वास्तु

हबीब रहमान ने देश की आजादी के बाद राजधानी दिल्ली में बहुत सी खास इमारतों के डिजाइन तैयार किए। रहमान (1915-1999) कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली आए। उन्होंने सरकारी कॉलोनियों से लेकर सरकारी भवनों के डिजाइन तैयार किए। 1961 में उन्होंने रवींद्र भवन का डिजाइन बनाया। यह राजधानी का उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट था।

दरअसल, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के क्रियाकलापों को एक छत के नीचे सुचारु रूप से चलाने के मकसद से ही रवींद्र भवन की संकल्पना की गई थी।

तीन अकादमियों का पर्याप्त स्थान देना सबसे बड़ी चुनौती: संस्थागत नजरिए से देखें तो ये तीनों स्वायत्त संस्थान थे। इनका मकसद विविध विधाओं को जन जन तक पहुंचाना था। इस नेक नियति के लिए इन्हें विस्तृत जगह की भी दरकार थी। तीन एकड़ में फैले रवींद्र भवन में तीन अकादमियों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हबीब रहमान ने इसे मुमकिन कर दिखाया। रवींद्र भवन कॉपरनिकस मार्ग एवं फिरोजशाह रोड के कोने पर स्थित है। इन दोनों ही मार्गों पर इसका प्रवेश द्वार भी खुलता है। भवन देखकर आप तुरंत कहेंगे कि इसके डिजाइन में परंपरा और भविष्य के भारत की झलक मिलती है।

तीन भागों में दिखता है भवन अंदर प्रवेश करने पर : भवन का वास्तु तैयार कराते समय यह बताया गया था कि इसमें ना केवल प्रशासनिक अधिकारी बैठेंगे, बल्कि गैलरी भी चाहिए जिसमें बड़े स्तर पर प्रदर्शनी आदि का आयोजन किया जा सके। इस भवन का डिजाइन यदि ध्यान से देखें तो भवन में प्रवेश करते ही यह तीन भागों में बंटा दिखाई देगा। अंदर सीढ़ियां हैं, जो इसे विभाजित करती है। सीढ़ी के दोनों तरफ अकादमियां हैं। 120 डिग्री के कोण पर कम या ज्यादा समान लंबाई के तीन भागों के साथ प्रशासनिक ब्लॉक है। प्रत्येक भाग में 4 मंजिला भवन है। ललित कला अकादमी प्रदर्शनी ब्लॉक के पास है, जहां एक गलियारे से पहुंचते हैं। पहले प्रथम तल पर ही एक पुस्तकालय बनाया गया था। जिसका अधिकतर हिस्सा सामने बगीचे की तरफ खुलता था। जबकि प्रदर्शनी ब्लॉक, बेसमेंट और दो अपर फ्लोर में विभाजित है। यहां की गैलरी में पर्याप्त स्थान है। सीढ़ी से उपर जाने पर दांये व बायीं तरफ गलियारे हैं। इन गलियारों में दोनों तरफ ऑफिस बनाए गए हैं। वास्तु निर्माण के समय प्रकाश की उचित व्यवस्था की गई थी। यह ध्यान रखा गया था कि सुबह एवं दोपहर में पर्याप्त प्रकाश मिले। प्रदर्शनी ब्लॉक आरसीसी फ्रेम, फीलर दीवारों वाली है।

फिरोजशाह रोड स्थित रवींद्र भवन जागरण

पंडित जवाहरलाल नेहरु को रवींद्र भवन का नक्शा दिखाते हुए हबीब रहमान जागरण

नेहरु जी ने कर दिया था खारिज : प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने रवींद्र भवन के पहले डिजाइन को खारिज कर दिया था, क्योंकि उसमें किसी सरकारी दफ्तर का पुट नजर आ रहा। उन्होंने कहा कि नाम के अनुरूप इसमें रवींद्र नाथ टैगोर का स्वभाव नजर नहीं आ रहा है। हालांकि इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप देने के बाद वे बहुत खुश थे। हबीब ने इसमें जालियों और बगिचों के लिए भी जगह दी थी। रवींद्र भवन के परिसर में प्रवेश करते ही आपको लगता है मानो आप कला और संस्कृति के संसार में आ गए हों। उनके काम में कितनी विविधता रही। वे काल्पनिक वास्तुकार थे। उन्होंने वास्तु की दुनिया का नया व्याकरण रचा। इस भवन को बनाने के बाद हबीब रहमान ने कहा था कि यहां आकर सुकून मिलता है। इसे बनाने में परंपरागत भारतीय वास्तु के तत्व मसलन छज्जा, जाली, ओवर हैंगिंग छत आदि का ध्यान रखा गया है। यह पहली इमारत है जो मुझे सौंदर्यात्मकता संतोष प्रदान करती है। मुझे लगता है कि यह रवींद्र जी की वजह से ही संभव हो पाया।

संजीव कुमार मिश्र

गुणवत्ता में सुधार करें भारतीय स्टील कंपनियां : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टील इंडस्ट्री से ग्लोबल मार्केट में टिकने लायक अच्छे उत्पाद बनाने का अनुरोध किया है। प्रधान इंडस्ट्री के सीइओ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी स्टील इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन अभी गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने हाल में रूस गए एक प्रतिनिधि मंडल की अगुआई की थी। इस दौरान रूस के साथ ऑयल, गैस, स्टील और कोयला सेक्टर में द्विपक्षीय व्यापार को लेकर बातचीत हुई थी।

हम सरकार के विकास अनुमानों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं। केंद्र के हिस्से से अगले पांच वर्षों के लिए राज्यों को कितना मिलना चाहिए, इसके लिए हम स्वतंत्र रूप से फैसला लेंगे।

— एनके सिंह
चेयरमैन, वित्त आयोग

सेंसेक्स	37,384.99 ▲ 280.71	निफ्टी	11,075.90 ▲ 93.10	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 38,695 ▲ ₹70	चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 48,400 ▲ ₹172	$ डॉलर	₹ 71.07 ▼ ₹ 0.06	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 60.19

राहत ▶ फाइल में अब असेसी का नाम और फोटो नहीं होगा

आइटी असेसमेंट आठ अक्टूबर से होगा नेमलेस-फेसलेस

इससे पक्षपात, रिश्वतखोरी और बेवजह तंग करने की संभावनाओं पर लगेगी लगाम

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार करदाताओं के लिए ऑनलाइन असेसमेंट स्कीम लेकर आई है। इसे बिना चेहरे और बिना नाम वाला असेसमेंट (मूल्यांकन) का नाम दिया गया है। सरकार ने इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि स्कीम विजयादशमी यानी आठ अक्टूबर से प्रभाव में आ जाएगी।

इस स्कीम के तहत किसी तरह की सुनवाई के लिए करदाता या असेसी (जिसके टैक्स का मूल्यांकन होना है) को स्वयं या अपने किसी आधिकारिक प्रतिनिधि को टैक्स अधिकारी के समझ पेश करने की जरूरत नहीं होगी।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि टैक्स मूल्यांकन में करदाता और टैक्स विभाग के बीच जरूरत से ज्यादा बातचीत होती है। ऐसे मामलों में टैक्स अधिकारी कई बार गैर जरूरी चीजों को अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा था कि इस समस्या से निपटने के लिए फेसलेस इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट स्कीम लाई जाएगी।

प्रक्रिया होगी सरल-सहज। प्रतीकात्मक

जरूरत पर पेशी का मौका भी

अगर किसी मामले में असेसी (जिसके टैक्स का मूल्यांकन होना है) व्यक्तिगत सुनवाई चाहता है, तो उसे टैक्स अधिकारी के सामने पेश होने का मौका दिया जाएगा। यह सुनवाई वीडियो लिंक या इसी तरह के किसी अन्य माध्यम से की जाएगी।

ऐसे होगा असेसमेंट

- इस स्कीम के तहत एक नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा
- यह सेंटर असेसमेंट के लिए अपनी ओर से नोटिस जारी करेगा
- 15 दिनों में इस नोटिस का जवाब मिलने के बाद सेंटर स्वचालित तरीके से मामले को किसी असेसिंग ऑफिसर के पास भेज देगा
- असेसिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसकी असेसिंग करेगा
- करदाता जब आइटी वेब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड कर लेगा, तो उसे टेक्स मैसेज और ई-मेल के जरिए इसकी पुष्टि की सूचना मिल जाएगी

हालांकि टैक्स असेसमेंट की यह नई स्कीम स्वैच्छिक है। करदाता पुराने तरीके से भी टैक्स असेसमेंट करवा सकते हैं।

अप्रैल-अगस्त में 3.2 प्रतिशत बढ़ा निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश का निर्यात कुल 227.36 अरब डॉलर रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.20 प्रतिशत अधिक है। खास बात यह है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक पांच महीनों में व्यापार घाटा घटकर 40.89 अरब डॉलर रह गया है जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 51.13 अरब डॉलर था। हालांकि निर्यात के आंकड़ों को देखें तो इस वर्ष अगस्त में यह 26.13 अरब डॉलर रहा है जो पिछले साल के समान महीने की तुलना में 6.05 प्रतिशत कम है। पिछले साल अगस्त में 27.81 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात हुआ था।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अगस्त में लौह अयस्क, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, मसाले, समुद्री उत्पाद, कोयला और अन्य खनिजों का निर्यात सकारात्मक रहा है। राहत की बात यह है कि अगस्त 2019 में आयात में भी कमी आयी है। अगस्त 2019 में आयात 39.58 अरब डालर रहा है जो पिछले साल समान महीने के मुकाबले 13.45 प्रतिशत कम है। आर्गेनिक और इनॉर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोलियम, क्रूड और मशीनरी, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के आयात में कमी आई है। इस साल अगस्त में सोने का आयात 62 प्रतिशत घटकर 1.36 अरब डॉलर रहा है। इस साल अगस्त माह में व्यापार घाटा कम होकर 13.45 अरब डॉलर रहा है जबकि पिछले वित्त वर्ष के समान महीने में यह 17.92 प्रतिशत था।

त्योहारी सीजन के लिए रीयल मी का बड़ा एलान, 16 को बेचेगी एक्सटी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- 64 मेगापिक्सल कैमरे वाले रीयल मी एक्सटी के साथ कई एसेसरीज लांच
- सोमवार को सिर्फ एक दिन के लिए होगी पहली ऑनलाइन बिक्री

मोबाइल हैंडसेट बाजार में शीर्ष तीन कंपनियों में शामिल होने के लक्ष्य के साथ चीन की मोबाइल कंपनी रीयल मी ने त्योहारों के सीजन के लिए नए फोन समेत कई एसेसरीज भी बाजार में उतारने की घोषणा की है। कंपनी ने 64 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ नया एक्सटी मोबाइल फोन लांच किया है जिसकी कीमत 15,999 रुपये से शुरू होगी। इस फोन पहली ऑनलाइन बिक्री सिर्फ एक दिन के लिए सोमवार को की जाएगी।

कंपनी का इरादा इस साल मोबाइल हैंडसेट बाजार में 15 परसेंट बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने का है। इस वर्ष कंपनी को डेढ़ से दो करोड़ मोबाइल हैंडसेट भारतीय बाजार में बिकने की उम्मीद है। कंपनी के इंडिया सीईओ माधव सेठ ने कहा 'उम्मीद है कि तीसरी तिमाही समाप्त होने तक 1.5 करोड़ से 1.1 मोबाइल हैंडसेट की बिक्री तक पहुंच जाएंगे।' कंपनी ने अपने नवीनतम एक्सटी मोबाइल के तीन वेरिएंट बाजार में उतारे हैं। चार जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले हैंडसेट की कीमत 15,999 रुपये होगी। जबकि छह जीबी रैम और 64 जीबी मेमोरी वाले हैंडसेट की कीमत 16,999 रुपये होगी। वहीं आठ जीबी रैम और 128 जीबी मेमोरी वाले रीयल मी एक्सटी की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। ये फोन पर्ल व्हाइट और पर्ल ब्लू के आकर्षक रंगों में उतारे गए हैं।

कंपनी के मुताबिक एक्सटी देश का पहला ऐसा मोबाइल है जिसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाडकोर कैमरा इस्तेमाल किया गया है। फोन का फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। फोन का प्रोसेसर 10एनएम ओक्टा कोर स्नैपड्रेगन 712 एईआइ है जो 2.3 गीगाहर्ट्ज के सीपीयू के साथ बेहतरीन परफार्मेंस देता है। यह प्रोसेसर गेमिंग के अनुभव को भी अनूठा बनाता है। इन उत्पादों की बिक्री फ्लिपकार्ट और कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर होगी। ये सभी उत्पाद फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कंपनी ने त्योहारी सीजन में बिक्री की संभावनाओं को देखते हुए एसेसरीज की एक पूरी सीरीज उतारने का एलान किया है। इसके तहत वायरलैस रीयल मी ईयरफोन और रीयल मी पावर बैंक जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं।

त्योहारी सीजन पर सभी की निगाहें लगी हैं। इनमें मोबाइल कंपनियां भी शामिल हैं। फाइल

सबसे तेज विकास वाली बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा भारत

वाशिंगटन, प्रेट्र : अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत दुनियाभर में सबसे तेज गति से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दुनिया की इस अग्रणी वित्तीय संस्था का कहना है कि भारत की विकास दर इस वर्ष भी चीन से ज्यादा रहेगी।

रिपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए आइएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने कहा भारत की आर्थिक विकास दर उम्मीद के अनुरूप नहीं है। लेकिन अगले कुछ समय में कई तरह के आंकड़े आएंगे और उनसे नई तस्वीर बनेगी। संस्था के मुताबिक कॉरपोरेट और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के साथ-साथ एनबीएफसी सेक्टर भी पिछले कुछ समय के दौरान भारत की विकास दर को सुस्त करने में जिम्मेदार रहा है।

गौरतलब है कि आइएमएफ ने इसी साल जुलाई में घटती घरेलू मांग के चलते ग्रोथ रेट के अनुमान को 0.3 परसेंट तक घटा दिया था। आइएमएफ के मुताबिक भारतीय इकोनॉमी इस वर्ष सात और अगले वर्ष 7.2 परसेंट तक विकास दर हासिल कर सकती है।

- 2019 में ग्रोथ रेट सात और 2020 में 7.2 परसेंट रहने का अनुमान

भारतीय कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ रेट 11 तिमाहियों के निचले स्तर पर

नई दिल्ली : रेटिंग एजेंसी इकरा के मुताबिक भारत की 642 कंपनियों का सम्मिलित रेवेन्यू ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 11 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गया है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में इन कंपनियों का रेवेन्यू ग्रोथ रेट गिरकर 5.7 परसेंट रह गया। कंज्यूमर-ओरिएंटेड सेक्टर में 7.7 परसेंट तक की कमी दर्ज की गई। ऑटो सेक्टर में भी सुस्ती का दौर रहा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यात्री वाहन बिक्री में 18 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। जबकि इसी दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में 12 परसेंट की गिरावट देखी गई।

बीपीएसएल से जुड़े मामले में एनक्लैट पहुंची जेएसडब्ल्यू

नई दिल्ली, प्रेट्र : जेएसडब्ल्यू स्टील मनी लांड्रिंग के एक मामले में बचाव के लिए एनक्लैट के पास जा पहुंची है। यह मामला भूषण पावर एंड स्टील से जुड़ा हुआ है, जिसकी दिवालिया प्रक्रिया में जेएसडब्ल्यू (जिंदल ग्रुप) ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल में कहा था कि दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कानून का उल्लंघन किया गया है। जेएसडब्ल्यू ने एनसीएलटी के उस आदेश को भी एनक्लैट में चुनौती दी है, जिसमें भूषण पावर एंड स्टील के मुनाफे का बंटवारा करने का आदेश दिया गया था। यह मुनाफा दिवालिया प्रक्रिया के दौरान कमाया गया था। जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली एनक्लैट की बेंच इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी।

इसी सप्ताह एनसीएलटी ने जेएसडब्ल्यू को कर्ज में डूबी बीपीएसएल के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी थी। यह सौदा 19,700 करोड़ में तय हुआ था। एनसीएलटी ने अपने आदेश में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के रूप में उभरेगा भारत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री का दायरा बढ़ाने और इसे एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में आ रही दिक्कतों पर विचार करने के लिए सरकार ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी तमाम बड़ी कंपनियों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बैठक में इस सेक्टर के समक्ष आने वाली चुनौतियों और प्रोत्साहनों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

बैठक में एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, क्वालकॉम, शाओमी, डेल, एचपी, बॉश, सिस्को, फ्लैक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, नोकिया, एलजी और पैनासोनिक के सीईओ के हिस्सा लेने की उम्मीद है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के प्रत्येक वर्ग मसलन मोबाइल हैंडसेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज, कंपोनेंट, टेलीकॉम और एलईडी लाइटिंग की हिस्सेदारी होगी।

आइटी सचिव अजय प्रकाश साहनी ने पत्रकारों को इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इंडस्ट्री से यह जानना चाहती है कि मैन्यूफैक्चरिंग को विस्तार देने की उनकी क्या योजनाएं हैं। साथ ही कंपनियां सप्लाई चेन और वैल्यू एडीशन की क्या योजनाएं बना रही हैं। 'हम इंडस्ट्री के सुझावों पर खुले दिमाग से विचार को तैयार हैं।'

इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में होगा बड़ा काम। फाइल

- सेक्टर के कंपनी प्रमुखों की सरकार के साथ बैठक सोमवार को
- केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ होगा सेक्टर के विकास पर विमर्श

अभी यह स्थिति

- पिछले कुछ वर्षों में देश में मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में तेजी से वृद्धि हुई है
- घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग 2014-15 में 29 अरब डॉलर की थी जो बढ़कर 2018-19 में 70 अरब डॉलर पर पहुंच गयी है
- मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है
- एलसीडी, एलईडी टीवी की मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों की संख्या भी 10 से बढ़कर पिछले पांच वर्षों में 35 हो गई है
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में करीब 20 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं

बैठक इसलिए महत्वपूर्ण

- सरकार ने साल 2025 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग का संपूर्ण इकोसिस्टम स्थापित कर उसका टर्नओवर 400 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है
- सरकार चाहती है कि दुनिया की सभी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां भारत में अपनी मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करें
- वर्तमान में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते कारोबारी विवाद के दौर में भारत एक आकर्षक मैन्यूफैक्चरिंग हब के तौर पर उभर रहा है
- भारत में न केवल बेहतर टेलेंट उपलब्ध है, बल्कि अन्य देशों के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी काफी प्रतिस्पर्धी है

सोना 70 रुपये चढ़ा, चांदी में 172 रुपये की आई मजबूती

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले कई सत्रों से उछलता-गिरता सराफा बाजार शुक्रवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुआ। इस दौरान सोना 70 रुपये सुधरकर 38,695 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। कारोबार के आखिर में चांदी का भाव 172 रुपये की मजबूती के साथ 48,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर था।

एचडीएफसी सिक्युरिटीज के सीनियर कमोडिटीज एनालिस्ट तपन पटेल का कहना था कि डॉलर के मुकाबले रुपये में थोड़ी अस्थिरता का फायदा सोने को मिला। हालांकि बाद में रुपये के मजबूत होते ही पीली धातु के भाव में उछाल का सिलसिला भी रुक गया। दूसरी तरफ, चांदी को संस्थागत खरीदारों और सिक्का निर्माताओं का सीमित साथ मिला।

न्यूयॉर्क में सोना बढ़त के साथ 1,505 डॉलर, जबकि चांदी भी उछलकर 18.17 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर कारोबार कर रहे थे। नई दिल्ली में 99.9 फीसद खरा सोना 38,695 रुपये, जबकि 99.5 फीसद खरा सोना 38,525 रुपये प्रति 10 ग्राम का उपलब्ध था।

चीनी, शराब और पर्यटन क्षेत्र के नियम हों उदार : कांत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- नीति आयोग के सीईओ ने की पर्यटन, शराब व चीनी उद्योग के क्षेत्र में सुधार की वकालत
- कहा - राज्यों के सहयोग से सुधारी जा सकती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चीनी, शराब और पर्यटन के क्षेत्र में नियमों को आसान बनाएं। कांत का कहना था कि इससे देश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन और देश की विकास दर को बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

चीनी, शराब और पर्यटन उद्योग के अध्ययन पर आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करते हुए कांत ने कहा कि सरकार सिर्फ एक सहायक की भूमिका निभा सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित यह रिपोर्ट 'फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन' ने तैयार की है। रिपोर्ट में चीनी उद्योग, पर्यटन और शराब उद्योग के संबंध में कई सुधारों की सिफारिश की गई है।

इस फाउंडेशन की सिफारिशों का महत्व इसलिए है क्योंकि इसकी स्थापना नीति आयोग के ही वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने की थी। इस फाउंडेशन के चेयरमैन डॉ. रामगोपाल अग्रवाल नीति आयोग में विशिष्ट फेलो के रूप में तैनात हैं। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पर भारत का रैंक 77वां है। कांत ने कहा कि राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार आया है लेकिन कई क्षेत्रों में अब भी नियंत्रण की स्थिति है और उन क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। अब भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां इंस्पेक्टर राज कायम है। इन क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन भी बेहद कम रहा है। खासकर अल्कोहल पेय, चीनी जैसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत में अभी काफी वृद्धि की गुंजाइश है। पर्यटन के लिए भी कई क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत है। चीनी उद्योग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी स्थिति सुधारने के लिए राज्यों ने कई कदम उठाए हैं।

रेट कट की आस में शेयर मार्केट में तेज उछाल

मुंबई, प्रेट्र : पिछले सत्र में गिरावट के बाद शुक्रवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में जबरदस्त उछाल देखा गया। आरबीआइ द्वारा एक और रेट कट की उम्मीद के चलते निवेशकों में उत्साह दिखा। इस दौरान फाइनेंशियल और आइटी स्टॉक में जमकर निवेश हुआ।

दिन के कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 280.71 अंक यानी 0.76 परसेंट के उछाल के साथ 37,384.99 पर बंद हुआ। दिन में एक समय यह 37,413.50 तक जा पहुंचा था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 11,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया। इस दौरान यह 93.10 अंक यानी 0.85 परसेंट की बढ़त के साथ 11,075.90 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स में सबसे बड़ा उछाल वेदांता, आइसीआइसीआइ बैंक, ओएनजीसी, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआइ, महिंद्रा, इंफोसिस, एचसीएल, बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ। इस दौरान इन कंपनियों के शेयरों में 2.72 परसेंट तक उछाल दर्ज किया गया। दूसरी ओर सन फार्मा, भारती एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आइटीसी और एचयूएल के शेयर 1.41 परसेंट तक लुढ़क गए। जानकारों के मुताबिक घटते इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट और खुदरा मंहगाई के संकतों के चलते निवेशकों का मनोबल बढ़ा। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा अतिरिक्त नीतिगत उपायों के कारण भी ग्लोबल मार्केट में उत्साह रहा। उधर एशिया के अन्य बाजारों में ट्रेड वार की नरमी का सीधा असर दिखाई पड़ा।

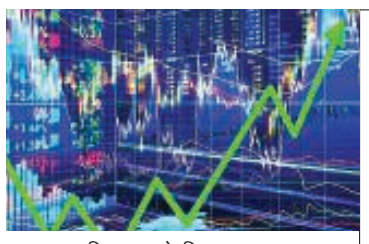
शुक्रवार का दिन बाजार के लिए अच्छा रहा।

- ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों का बाजार पर रहा असर
- फाइनेंशियल और आइटी स्टॉक में हुआ जमकर निवेश

यस बैंक के खिलाफ अफवाहों की जांच की मांग

नई दिल्ली : यस बैंक और मोर्गन क्रेडिट ने एनएसई के निगरानी और जांच विभाग से बैंक के खिलाफ उड़ रही अफवाहों की जांच करने की मांग की है। यस बैंक के प्रमोटर्स का कहना है कि इन अफवाहों की वजह से बैंक के शेयरों को बहुत नुकसान हुआ है। धोखाधड़ी से प्रभावित सीजी पावर में हितधारक होने और क्रेडिट रेटिंग में लगातार गिरावट के चलते बैंक के प्रमोटर्स को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल में यस बैंक के स्टॉक की कीमत 275 रुपये थी, जो अब घटकर सिर्फ 64 रुपये रह गई है। इसके अलावा बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के विवादित निष्कासन के कारण भी बैंक को नुकसान उठाना पड़ा है।

चालू तिमाही में 17 दिनों तक प्लांट बंद रखेगी महिंद्रा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अग्रणी वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा है कि वह इस महीने के अंत में खत्म हो रही चालू तिमाही में अपने संयंत्रों में 17 दिनों तक उत्पादन बंद रखेगी। प्लांट बंद रखने के दिनों की यह संख्या तीन महीनों को मिलाकर है और कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस महीने कितने दिनों के लिए प्लांट बंद रहेंगे। शुक्रवार को कंपनी ने कहा कि चालू तिमाही में बिक्री की कमी को देखते हुए उत्पादन रोकने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले अगस्त में कंपनी ने कहा था कि ऑटोमोटिव प्लाटों में जुलाई-सितंबर के बीच 8 से 14 दिनों तक उत्पादन बंद रखा जाएगा। अब बंद रखने की मियाद तीन दिन और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सितंबर के आखिरी तीन दिन कृषि उपकरणों का भी उत्पादन भी नहीं किया जाएगा।

कंपनी ने कहा कि प्लांट बंद करने से वाहनों की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि पर्याप्त स्टॉक है। कुछ सप्ताह पहले हिंदुजा समूह की अशोक लेलैंड ने 16 दिनों तक उत्पादन बंद रखा था। टाटा मोटर्स भी चालू तिमाही में लगभग एक सप्ताह प्लांट बंद रख चुकी है।

पहल की जरूरत

तालाब व जलाशयों के पट्टे को बैंक कर्ज से जोड़ने की जरूरत, मत्स्य पालन का बुनियादी ढांचा मजबूत करने को 7522 करोड़ मंजूर, मत्स्य क्षेत्र की संभावनाओं के दोहन के लिए चाहिए विशिष्ट स्तर की जागरूकता

मत्स्य पालन की राह में अभी कम नहीं अड़चनें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आमदनी को दोगुना करने की सरकार को मंशा को पूरा करने के लिए मत्स्य पालन पर सरकार का जोर है। इससे जहां देश के डेढ़ करोड़ मछुआरों की जिंदगी बदल जाएगी, वहीं उत्तरी राज्यों में छोटे व सीमांत किसानों की आमदनी को दोगुना करने में मदद मिलेगी। लेकिन उत्तरी राज्यों में मत्स्य पालन की राह की अड़चनें भी कम नहीं हैं। इसे दूर करने के लिए केंद्र के साथ राज्यों को भी कारगर पहल करनी होगी।

सरकार ने आम बजट में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 7,522 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसका उपयोग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मद में किया जाएगा। इससे मत्स्य पालन के लिए हार्बर, लैंडिंग सेंटर, सीड फार्म, फीड और मछलियों में होने वाली बीमारी का उपचार करने के संसाधन तैयार किए जाएंगे। मछली उत्पादन की रफ्तार किसी और पशुधन उत्पाद के मुकाबले कई गुना अधिक है।

केंद्रीय पशुधन व मत्स्य पालन राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने इस बारे में बताया कि केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाकर इसे प्रोत्साहित करना शुरु कर दिया है, लेकिन असल चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों को पहल करनी होगी। सबसे बड़ी मुश्किल उत्तरी राज्यों में मछली पालन करने वालों के सामने है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तालाब, पोखर, झील और अन्य जलाशयों का पट्टा लेने वाले छोटे व सीमांत किसानों को बैंक से कर्ज नहीं मिल पाता है। मत्स्य पालन उद्योग क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करने वाले अनमोल फीड के प्रबंध निदेशक अमित सरावगी का कहना है कि मछली पालन में निवेश बहुत जरूरी है। सिर्फ तालाब व जलाशय होने से ही बात नहीं बनती है, बल्कि मत्स्य पालक को इसके लिए फिश सीड, आहार और अन्य कई मदों में धनराशि की जरूरत होती है। मत्स्य पालकों में जागरुकता की कमी इससे भी बड़ी चुनौती है। मछली पालन एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसमें थोड़ा पैसा करके अच्छी कमाई की जा सकती है। सरावगी का कहना है कि इससे सामान्य के मुकाबले उत्पादन में आठ गुना तक अधिक वृद्धि की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में मछली पालकों को हर साल एक निश्चित मात्रा में मछली का आहार मुफ्त में वितरित करती है। इसका नतीजा यह होता है कि अगले साल से मछली पालक किसान खुद मछली आहार की खरीद करने लगता है।

उत्तरी राज्यों में पंजाब व हरियाणा को छोड़ बाकी राज्यों में मछली की मांग व आपूर्ति में भारी अंतर है। इन राज्यों समेत बिहार और उत्तर प्रदेश में भी मछली की मांग आंध्र प्रदेश से ही पूरी की जाती है। इन राज्यों में मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं है, जिनका दोहन करने की तत्काल जरूरत है।

देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां मछली उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। फाइल

प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन घोषित

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- प्याज निर्यात पर परोक्ष रोक, उठाए गए कारगर कदम
- जमाखोरों पर कार्रवाई के बाद निर्यात पर पाबंदी

प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने ताबड़तोड़ कई कदम उठाए हैं। कई राज्यों में प्याज की मंहगाई रोकने के लिए इसके जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर परोक्ष रूप से रोक लगाने के लिए उसका वैधानिक न्यूनतम निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन घोषित कर दिया है।

पिछले कुछ दिनों के भीतर ही प्याज की कीमतें ज्यादातर महानगरों में 20-30 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 40-50 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं। केंद्र शुक्रवार को सरकार द्वारा लिए इस फैसले से प्याज की मंहगाई पर नियंत्रण पाने में सहूलियत होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। देश से सालाना 15 लाख टन प्याज का निर्यात किया जाता है। जबकि देश में प्याज का वार्षिक कुल उत्पादन 1.7 से 1.8 करोड़ टन रहता है।

इसलिए उठाना पड़ा कदम

- महाराष्ट्र व कर्नाटक में बाढ़ की वजह से प्याज की फसल प्रभावित हुई थी, जिससे दूसरे राज्यों में कीमतें लगातार बढ़ने लगीं
- राजधानी दिल्ली में प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पिछले महीने ही मदर डेयरी की दुकानों से 23.90 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब बिक्री शुरू की गई थी
- प्याज की कीमतों में आई तेजी के चलते खुदरा महंगाई की दर में मामूली तेजी देखी गई जो अगस्त में बढ़कर 3.21 फीसद हो गई

तीसरी बहस के बाद बिडेन की दावेदारी मजबूत

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए हुई दो प्राइमरी बहस में कमजोर पड़ने के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन ने तीसरी बहस में शानदार प्रदर्शन कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी से 20 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी पेश की थी। ह्यूस्टन में गुरुवार को हुई तीसरी बहस में केवल दस दावेदार ही हिस्सा ले पाए। अन्य दावेदार बहस की शर्तें पूरी करने में विफल रहे थे। बहस खत्म होने के बाद बिडेन सभी पोल में आगे चल रहे हैं। सीनेटर बर्नी सैंडर्स दूसरे और एलिजाबेथ वॉरेन तीसरे स्थान पर हैं। अन्य दावेदारों में कोई भी अपने लिए चार फीसद से ज्यादा समर्थन नहीं जुटा पाया।

बहस के दौरान बिडेन ने बड़ी मजबूती से खुद को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया। ओबामा प्रशासन में वह उपराष्ट्रपति थे।

राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को चुनौती देने के लिए विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के दावेदारों में हुई बहस

डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के प्रत्याशी की दावेदार कमला हैरिस। रायटर

कमला हैरिस ने ट्रंप पर साधा निशाना

भारतवंशी सीनेटर कमला हैरिस ने भी तीसरी प्राइमरी बहस में शानदार प्रदर्शन किया। उनके निशाने पर राष्ट्रपति ट्रंप रहे। अपने भाषण की शुरुआत ही उन्होंने ट्रंप की आलोचना के साथ की और कहा कि हेल्थकेयर पर बहस के बीच हमसब ट्रंप को भूल गए। उन्होंने ट्रंप पर कई कटाक्ष किए जिस पर खूब तालियां बजीं। अंत में उन्होंने कहा, 'ट्रंप अब आप वापस जाएं और फॉक्स न्यूज देखें।'

हेल्थकेयर, विदेश में चल रहे सैन्य अभियान और शरणार्थियों के मुद्दे पर उन्होंने कई बार उपराष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्यकाल का हवाला दिया। एक अन्य दावेदार जूलियन कास्त्रो ने जब उनकी उम्र को निशाना बनाना चाहा तो 76 साल के बिडेन के संतुलित जवाब से कास्त्रो का दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया।

हेल्थ केयर के मुद्दे पर भिड़े बिडेन, सैंडर्स और वॉरेन : बहस में हेल्थ केयर अहम मुद्दा रहा। सैंडर्स और वॉरेन दोनों ने 'सबके लिए मेडिकेयर' की नीति का समर्थन किया। वहीं बिडेन ने इस स्वास्थ्य बीमा की आलोचना की। इसे महंगा बताते हुए उन्होंने ओबामाकेयर (स्वास्थ्य बीमा योजना) में ही सुधार लाने पर जोर दिया।

यमन में यूएन मिशन की अगुआई करेंगे भारत के अभिजीत

वाशिंगटन, एएनआइ : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को यमन में अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अभिजीत को यमन के हुदैदा शहर में यूएन मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभिजीत हुदैदा समझौते को सहायता देने वाले यूएन मिशन (यूएनएमएचए) की अगुआई करने के साथ ही रिडिप्लायमेंट कोआर्डिनेशन कमेटी (आरसीसी) का अध्यक्ष पद भी संभालेंगे।

वह डेनमार्क के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल लॉलेसगार्ड की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल 31 जनवरी से 31 जुलाई तक यह जिम्मेदारी संभाली थी। अभिजीत के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेना का 39 साल का लंबा अनुभव है। वह 2009 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र के शांतिरक्षक अभियान विभाग में उप सैन्य सलाहकार और सैन्य सलाहकार रह चुके हैं। वह कंबोडिया में भी संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने अफ्रीका और पश्चिम एशिया में संयुक्त राष्ट्र की कई जांच की अगुआई भी की है। अभिजीत 2013 में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए थे।

अमेरिका में डिबेट के दौरान मची अफरा-तफरी

टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन में अमेरिकी प्रेसीडेंशियल डिबेट के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, जब आव्रजन कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप कार्यक्रम स्थल में घुस आया और नारेबाजी शुरू कर दी। 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के दावेदारों के बीच यह डिबेट चल रही थी। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाला। रायटर

न्यूज गैलरी

चीन में 'टैंक मैन' की तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर का निधन

जकार्ता : चीन के थ्येनआनमन चौक पर 'टैंक मैन' की तस्वीर लेने वाले फोटोग्राफर चार्ली कोल (64) का पिछले सप्ताह निधन हो गया। वह इंडोनेशिया के बाली में रह रहे थे। चीन में 5 जून, 1989 को लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान थ्येनआनमन चौक पर टैंकों की कतार के सामने खड़े अज्ञात व्यक्ति की तस्वीर कोल ने ही खींची थी। उन्हें इस तस्वीर के लिए 1990 में वर्ल्ड प्रेस फोटो का पुरस्कार भी मिला था। उनकी यह तस्वीर 1989 में चीन में लोकतंत्र के समर्थन में हुए प्रदर्शन की विश्व प्रसिद्ध छवि बन गई। (आइएएनएस)

दुबई में आम चुराने पर भारतीय को हो सकती है जेल

दुबई : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई एयरपोर्ट पर काम करने वाले 27 वर्षीय भारतीय को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उस पर 2017 में एक यात्री के बैग से दो आम निकालने का आरोप है। अदालत 23 सितंबर को फैसला सुना सकती है। दोषी पाए जाने पर उसे जेल की सजा के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। (एएनआइ)

फिलीपींस में धोखाधड़ी में 270 चीनी नागरिक गिरफ्तार

मनीला : फिलीपींस की पुलिस ने लाखों डॉलर की वित्तीय धोखाधड़ी में 270 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। लोगों को करीब 100 करोड़ रुपये का चूना लगा चुके चीन के इस गैंग के चार लोगों को पुलिस ने बुधवार को राजधानी मनीला में पकड़ा था। इसके बाद गैंग से जुड़े अन्य चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। (एएफपी)

पलंबर की पिटाई कराने पर सऊदी की राजकुमारी को सजा

पेरिस : फ्रांस की कोर्ट ने सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान की बहन को 10 माह की सजा सुनाई है। यह फिलहाल निलंबित रहेगी। पेरिस में 2016 में राजकुमारी ने लग्जरी आवास में अपने अंगरक्षक से एक पलंबर की पिटाई कराई थी। बादशाह सलमान की बेटी हस्सा बिंत सलमान पर अपने अंगरक्षक को पलंबर की पिटाई करने का आदेश देने का आरोप है। (एएफपी)

कांगो में ट्रेन हादसे में 50 लोगों की मौत

लुबुमबशी : दक्षिण पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में गुरुवार को एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने से 50 लोगों की मौत हो गई। मानवीय कार्यों के मंत्री स्टीव एमबिकयी ने ट्वीट के जरिये इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'एक और हादसा! मयीबारिदी के पास तंगानयिका प्रांत में सुबह तीन बजे एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की आशंका है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।' कांगो में रेल हादसे आम हैं। वहां रेलवे की स्थिति बेहद खराब है। जर्जर पटरियों पर बहुत पुराने इंजन के जरिये ट्रेनों का परिचालन होता है। इनमें कई तो 1960 के आसपास से ही परिचालन में हैं। एएफपी

जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तानी पीएम इमरान ने उगली आग

बौखलाहट ▶ कहा- कश्मीर में अत्याचार से पूरी दुनिया में बढ़ेगा आतंकवाद

अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद पाक के नेता कर रहे हैं भड़काऊ बयानबाजी

मुजफ्फराबाद, रायटर : गुलाम कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उम्मीद के मुताबिक जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ खूब आग उगली। उन्होंने कहा, 'कश्मीर में भारत जिस तरह की दमन की कार्रवाई कर रहा है उसे पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी देख रही है, इससे आतंकवाद और बढ़ेगा।' जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत सरकार के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और वहां के नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं।

इमरान ने कहा, अत्याचार जब सीमा पार कर लेता है तो लोग जलालत भरी जिंदगी से बेहतर मौत को मानने लगते हैं। यही स्थिति आतंकवाद को जन्म देती है और यही स्थिति भारत सरकार जम्मू-कश्मीर में बना रही है। भारत ने जिन हजारों निर्दोष लोगों को कैद कर रखा है, उन्हें वह आतंकवाद की ओर बढ़ा रहा है। इस स्थिति के खिलाफ न केवल भारतीय मुस्लिम खड़े होंगे बल्कि पूरी दुनिया

इमरान खान। रायटर

की सवा अरब मुस्लिम आबादी में भी गुस्सा बढ़ेगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आमसभा में कश्मीर का मसला उठाएंगे और दुनिया से कश्मीरियों को इंसाफ दिलाने की मांग करेंगे। इमरान के गुलाम कश्मीरियों को नियंत्रण रेखा के पार न जाने की अपील की। कहा कि वह न्यूयॉर्क जा रहे हैं, वहां पर पूरा मामला रखेंगे और दुनिया का समर्थन मांगेंगे। इससे पहले पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू-कश्मीर का मामला उठाया था।

गुलाम कश्मीर के राजनीतिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि पीएम इमरान की रैली फ्लॉप रही। इतनी बड़ी तैयारियों के बाद भी रैली में महज कुछ लोग ही आए थे।

अमेरिका दौरे पर ट्रंप से दो बार मिलेंगे इमरान

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस माह संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान दो बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। दो महीने में ट्रंप से यह उनकी दूसरी मुलाकात होगी। इमरान ने गत जुलाई में बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका का पहला दौरा किया था।

यूएन मुख्यालय में इमरान के कार्यक्रम के अनुसार, दोनों नेताओं की पहली बातचीत लंच के दौरान होगी और इसके बाद शाम को वे फिर चाय पर मिलेंगे। इमरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए 21 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। वह 27 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद महासभा में उनका यह पहला भाषण होगा।

इस दौरान इमरान कश्मीर का मुद्दा उठा सकते हैं। गत जुलाई में इमरान की ह्वाइट हाउस में ट्रंप से वार्ता हुई थी। उस दौरान ट्रंप ने कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी।

'आतंक का अड्डा है पाक कश्मीर पर कर रहा दुष्प्रचार'

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : पाकिस्तान को आतंकवाद का अड्डा बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर मुद्दे पर आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण बातें प्रचारित करने के लिए उसकी लताड़ लगाई है। कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय संस्था के मंच का दुरुपयोग है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी द्वारा जम्मू-कश्मीर का मसला उठाए जाने की कड़ी निंदा की। लोधी ने अपने वक्तव्य में कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कई संकल्पों का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने दावा किया कि सुरक्षा परिषद के कहने पर ही जम्मू-कश्मीर से कर्फ्यू हटाया गया और संपर्क के साधनों को चालू किया गया। सुरक्षा परिषद ने गिरफ्तार लोगों को रिहा करने के लिए भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी

संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने उठाया था जम्मू-कश्मीर का मसला, भारत ने की निंदा

सचिव संदीप कुमार बायप्पू ने कहा, पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच का लगातार दुरुपयोग कर रहा है। उसकी बातें महत्वहीन सत्य से परे हैं लेकिन वह दुर्भावनापूर्ण प्रचार बंद नहीं कर रहा। जबकि सत्य यह है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़कर आतंकियों के जरिये निर्दोष लोगों की हत्या करवा रहा है। यह सिलसिला लंबे समय से जारी है। बायप्पू ने कहा, जहां तक सुरक्षा परिषद का सवाल है तो वह दुनिया की बहुत बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वह जमीनी हकीकतों से कटा हुआ है। इसीलिए उसने ऐसे मसले पर चर्चा आयोजित कर डाली जो भारत का आंतरिक मामला है और पाकिस्तान का उससे कोई मतलब नहीं है।

पाक सेना के खिलाफ प्रदर्शन : बलूचिस्तानी और सिंधी कार्यकर्ताओं ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में जुल्म ढहा रही है। एएएनआइ

संरा मानवाधिकार प्रमुख को भारत ने बताई पाक की करतूत

जिनेवा, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की प्रमुख मिशेल बैचलेट से वरिष्ठ भारतीय राजनयिक ने मिलकर उन्हें जम्मू-कश्मीर पर भारत की स्थिति की जानकारी दी। बताया कि जम्मू-कश्मीर में जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। वहां के लोगों का जीवन पटरी पर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश जारी रहने से चिंता है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने बैचलेट को भारत सरकार के उन कदमों की जानकारी दी जिनसे जम्मू-कश्मीर में लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। उन्हें कश्मीरी लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद से जुड़ी जानकारियां भी दी गईं। जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को लेकर कुछ दिन पहले पाकिस्तानी अधिकारी बैचलेट से मिले थे और उनके समक्ष भारतीय इलाके की गलत तस्वीर पेश की थी।

इसी के बाद संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त ने जम्मू-कश्मीर में सरकारी बंदिशों से जनजीवन थम जाने पर चिंता जताई थी। इसी के बाद भारतीय राजनयिक विजय ठाकुर सिंह ने बैचलेट से मिलकर जम्मू-कश्मीर की सही स्थिति की जानकारी दी और पाकिस्तान के कुत्सित प्रयासों की कलई खोली। बताया कि पाकिस्तानी सेना के साए में आतंकी कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार हैं, जो वहां आकर निर्दोष लोगों को मारकर जनजीवन प्रभावित करने का मंसूबा बांधे हुए हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने किशोर बेटे को दी धूमपान से दूर रहने की सलाह

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ने 13 साल के अपने बेटे बैरन को भी ई-सिगरेट और धूमपान से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिका में ई-सिगरेट की समस्या गंभीर होती जा रही है और ट्रंप प्रशासन इस पर प्रतिबंध की तैयार कर रहा है। ई-सिगरेट के इस्तेमाल से होने वाली फेफड़ों की रहस्यमय बीमारी से अब तक छह लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग बीमार हैं।

ट्रंप प्रशासन ने बीते बुधवार को एलान किया था कि जल्द ही विभिन्न फ्लेवर वाली ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ह्वाइट हाउस में पत्रकारों के इस सवाल पर कि क्या ई-सिगरेट को लेकर आपने अपने किशोर बेटे से बात की है। ट्रंप ने कहा, 'मैंने और मेलानिया ने उसे ई-सिगरेट से दूर रहने को कहा है। हमें ई-सिगरेट पीना पसंद नहीं। मुझे धूमपान पसंद नहीं।' ट्रंप ने तीन शादियां की हैं। पहली पत्नी इवाना से उनके तीन बच्चे हैं -डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, इवांका और एरिक ट्रंप। दूसरी पत्नी मार्ला मैपल्स से ट्रंप की एक बेटी है जिसका नाम टिफेनी है। सबसे छोटा बैरन ट्रंप और मेलानिया का बेटा है।

क्या है ई-सिगरेट : इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई-सिगरेट एक तरह का बैट्री चालित उपकरण है जिसे धूमपान के विकल्प के तौर पर विकसित किया गया है। इसमें तंबाकू की जगह निकोटीन, ग्लिसरीन या ग्लाइसोल आदि को लिक्विड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

किम जोंग से मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप ने इच्छा जताई

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन से मुलाकात की इच्छा जताई है। ट्रंप ने कहा कि वह इस साल किसी दिन किम से मुलाकात करना चाहेंगे और किम भी उनसे मिलने को पहले से उत्सुक हैं। ट्रंप का इस बयान से कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर अमेरिका से फिर बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया था। इस बीच, ट्रंप बीते बुधवार को जॉन बोल्टन को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद से हटा चुके हैं। ट्रंप ने बोल्टन पर यह कार्रवाई उत्तर कोरिया समेत ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ी अमेरिकी विदेश नीति पर अलग राय रखने के कारण की थी।

48 साल बाद बांग्लादेश ने सीमा पर लगे स्तंभों से हटाया पाक का नाम

ढाका, आइएएनएस : मुक्ति संग्राम के 48 साल बाद बांग्लादेश ने सीमा पर लगे सभी स्तंभों (पिलर्स) से पाकिस्तान का नाम हटा दिया है। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा पर इन पिलर्स को स्थापित किया गया था।

प्रधानमंत्री शेख हसीना की निर्देश पर बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश (बीजीबी) ने अपने कोष से इस कार्य को पूरा किया है। मालूम हो कि 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश पृथक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। बीजीबी ने मीडिया को एक बयान जारी कर बताया कि बांग्लादेश के सभी बॉर्डर स्तंभों पर पाकिस्तान/पाक के स्थान पर बांग्लादेश/बीडी अंकित कर दिया गया है।

भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सीमा पर 8,000 से ज्यादा स्तंभ स्थापित किए गए थे। इन पर भारत/पाक (भारत-पाकिस्तान) अंकित था। ये स्तंभ सीमावर्ती इलाकों सतखिरा, जेसोर, चुडंगा, कुश्तिया, राजशाही, चपाईनवाबगंज, नौगांव, मेमेनसिंह, जमालपुर, सुनामगंज, सिलहट, ब्राह्मणबरिया, कोमिला और चटगांव इलाकों में स्थापित किए गए थे।

अमेरिका में ओपॉयड दवाएं बेचने के आरोप में आठ भारतवंशी गिरफ्तार

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिका में ओपॉयड (नशीली दर्द निवारक) दवाएं बेचने के आरोप में भारतीय मूल के आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि वे भारत से करोड़ों डॉलर की बिना ब्रांड वाली दवाएं मंगवाकर अमेरिका में बेचते थे। इन ओपॉयड दवाओं को अमेरिकी डाक या कूरियर के जरिये ग्राहकों को भेजा जाता था।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, आठों आरोपितों एजिल सेजियान (46), मुकुल चुग (24), गुलाब (45), दीपक मनचंदा (43), पार्थीबन नारायनसामी (58), बलजीत सिंह (29), हरप्रीत सिंह (28) और विकास एम वर्मा (45) को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। वे न्यूयॉर्क शहर के क्वींस इलाके में स्थित एक गोदाम से अपने धंधे को अंजाम देते थे। यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब ट्रंप प्रशासन ने ओपॉयड संकट से निपटने के लिए अमेरिकी राज्यों को दो अरब डॉलर (करीब 14 हजार करोड़ रुपये) दिए हैं। अमेरिकी एजेंसियां पिछले साल जनवरी से ही भारत से अमेरिका में बड़े पैमाने पर सिंथेटिक ओपॉयड ट्रामाडोल समेत अन्य दवाओं के आयात की जांच कर रही थीं।

भारत से मंगवाकर अमेरिकी डाक सेवा के जरिये करते थे आपूर्ति

प्रतीकात्मक

25 साल तक हो सकती है सजा

दोषी पाए जाने पर एजिल सेजियान को 25 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जबकि बाकी आरोपियों को पांच साल तक जेल हो सकती है। एजिल पर मनी लांड्रिंग का भी आरोप है।

ग्राहकों का रखते थे पूरा हिसाब-किताब

आरोपी अपने ग्राहकों का रोजाना का हिसाब-किताब रखते थे। ग्राहकों के नाम के साथ उन्हें भेजी गई गोलियों की मात्रा और मूल्य भी लिखा जाता था।

ओपॉयड दवाओं का प्रयोग नशे के लिए भी करते हैं लोग

अफीम से बनने वाली दर्द निवारक दवाओं को ओपॉयड कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका नशे के लिए प्रयोग करते हैं। अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी के अनुसार, देश में ओपॉयड के चलते साल 1999 से 2017 के दौरान करीब चार लाख लोगों की मौत हुई।

हुआ समझौता

दिग्गज डिजिटल कंपनियों के टैक्स को लेकर अमेरिका से चल रहे विवाद का हल निकालने में जुटे हैं यूरोपीय देश

जांच से बचने के लिए गूगल देगी एक अरब डॉलर

पेरिस, एएफपी : फ्रांस में कॉरपोरेट टैक्स धोखाधड़ी के मामले में जांच खत्म करने के लिए गूगल 1.07 डॉलर (करीब 7602 करोड़ रुपये) देने को राजी हो गई है। कोर्ट में हुए समझौते के तहत गूगल फ्रांस सरकार को यह रकम चुकाएगी। तकनीक की दिग्गज कंपनी गूगल पर 2011-14 के बीच कार्पोरेट कर में धोखाधड़ी करने का आरोप था। टैक्स धोखाधड़ी के लिए गूगल 50 करोड़ यूरो का जुर्माना भरेगी। वहीं कर विभाग के अन्य आरोपों को खत्म करने के लिए 46.5 करोड़ यूरो का भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, हमें खुशी है कि उससे फ्रांस में कई साल से चल रहा टैक्स विवाद खत्म हो गया है।'

फ्रांस के बजट मंत्री गेराल्ड डारमैनिन और न्यायाधीश निकोल बेलुबेट ने समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह यह फ्रांस प्रशासन द्वारा बीते दो साल में कई गई मेहनत का परिणाम है। यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब फ्रांस व अन्य यूरोपीय देश दिग्गज डिजिटल कंपनियों के टैक्स को लेकर अमेरिका से चल रहे विवाद का हल निकालने में जुटे हैं। दरअसल, अमेरिका की अन्य प्रौद्योगिक कंपनियों की तरह गूगल का भी यूरोपीय मुख्यालय आयरलैंड में है। बड़ी कंपनियों को आकर्षित करने के

2011 से 2014 के बीच कॉरपोरेट कर में धोखाधड़ी करने का आरोप था

फ्रांस सरकार को रकम चुकाएगी गूगल। फाइल

लिए वहां कार्पोरेट टैक्स मात्र 12.5 फीसद ही है। फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों का कहना है कि इससे कंपनियां भारी मुनाफा तो कमाती हैं लेकिन उचित टैक्स नहीं भरती हैं। इसी के चलते जुलाई में फ्रांस की संसद ने नया विधेयक पारित कर प्रौद्योगिक कंपनियों के लिए नई टैक्स दरें तय की थी। ब्रिटेन सरकार भी ऐसा ही करने की योजना में है।

फ्रांस में 2015 से चल रही थी जांच

सबसे पहले 2015 में फ्रांस के एंटी-फ्रॉड प्रॉसिक्यूटर ने गूगल के खिलाफ जांच शुरू की थी। 2016 में पेरिस स्थित गूगल के मुख्यालय की तलाशी ली गई थी। इस अभियान का नाम 'ट्यूलिप' रखा गया था जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी व विशेषज्ञ शामिल थे।

पहले भी इस तरह का हो चुका है समझौता

2016 में हुए समझौते के तहत गूगल ने ब्रिटेन सरकार को 160,000 डॉलर (करीब 1.16 करोड़ रुपये) चुकाए थे। फिर इटली में कर को लेकर हुआ विवाद खत्म करने के लिए कंपनी 30.6 करोड़ यूरो (करीब 2409 करोड़ रुपये) चुकाने पर सहमति दी थी।

पांच भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों को यूएन मेडल

नई दिल्ली, प्रेट्र : दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत सराहनीय सेवाओं के लिए पांच भारतीय महिला पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि चंडीगढ़ पुलिस में इंस्पेक्टर रीना यादव, महाराष्ट्र पुलिस में डीएसपी गोपिका जहागिरदार, एमएचए में डीएसपी भारती सामांत्रे, एमएचए में इंस्पेक्टर रागिनी कुमारी और राजस्थान पुलिस में एएसपी कमल शेखावत को संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी सूडान के जुबा में मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मिशन में मेडल परेड के दौरान इन महिला अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इन अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र प्रावधानों के तहत दक्षिणी सूडान में संघर्ष के दौरान नागरिकों की बेहतरीन सुरक्षा की थी।

ये महिला अधिकारी सामुदायिक पुलिसिंग, प्रशासनिक, संचालन ड्यूटी के साथ ही स्थानीय प्रशासन की क्षमता को बढ़ाने के कार्यों में लगी हुई थीं।

इटली में सीवेज टैंक में उतरे चार सिखों की हुई मौत

रोम, प्रेट्र/आइएएनएस : उत्तरी इटली के एक डेयरी फार्म के सीवेज टैंक में उतरे भारतीय मूल के चार सिखों की मौत हो गई। आशंका जताई गई है कि वे गोबर की खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले टैंक में बनी कार्बन डाइआक्साइड की चपेट में आ गए। चारों पंजाब के रहने वाले थे।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह घटना गुरुवार को दक्षिणी मिलान के पाविया शहर के पास स्थित एरिना पो इलाके के एक डेयरी फार्म में हुई। मृतकों में प्रेम (48) और तरसेम सिंह (45) भाई थे, जो फार्म चला रहे थे। जबकि बाकी दो श्रमिक थे। उनकी पहचान अरमिंदर सिंह (29) और मनजिंदर सिंह (28) के रूप में की गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि खेतों में गोबर की खाद डालने के लिए टैंक को खाली करते समय एक श्रमिक उसमें फंस गया था। उसे बचाने के लिए तीनों लोग भी टैंक में उतरे थे। दोपहर के भोजन पर जब वे घर नहीं गए तो उनकी पत्नियां मौके पर पहुंचीं। उन्हें टैंक में एक का शव दिखा। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने मास्क लगाकर टैंक को खाली किया और सभी शवों को बाहर निकाला।

पंजाब के रहने वाले चारों लोगों में से दो थे सगे भाई

इटली की कृषि मंत्री ने जताया दुख

इटली की कृषि मंत्री टेरेसा बेलानोवा ने सिखों की मौत पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, 'कार्यस्थल पर सुरक्षा का अपरिहार्य अधिकार है और हमें इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास करने चाहिए।'

पाविया प्रांत में सबसे बड़ा डेयरी फार्म : इतालवी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, दोनों भाइयों ने अपने डेयरी फार्म का 2017 में पंजीकरण कराया था। उनका डेयरी फार्म इटली के पाविया प्रांत में सबसे बड़ा माना जाता है।

36 टी-20 मैच खेल चुके दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक पहली बार कप्तानी करने जा रहे हैं। नियमित कप्तान फाफ डुप्लेसिस को भारत के खिलाफ होने वाली टी-20 सीरीज में नहीं लिया गया है।

पहले टी-20 के लिए धर्मशाला पहुंचे क्रुणाल पांड्या ● एएनआइ

आसान नहीं होगी टी-20 सीरीज

विश्व कप के बाद दक्षिण अफ्रीका की पहली सीरीज कैरेबियाई दौरे पर जीत से चार्ज है टीम इंडिया

मुनीष गारिया ● धर्मशाला

यह तो तय है कि विश्व टी-20 रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज दक्षिण अफ्रीका और चौथे पायदान पर मौजूद भारत की टीमों के बीच रविवार से यहां शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 सीरीज आसान नहीं होने वाली है। विश्व कप के बाद लंबा आराम लेकर मेहमान टीम पहली बार मैदान में उतरेगी। वहीं, कैरेबियाई दौरे पर टी-20 सहित तीनों प्रारूपों की सीरीज खेलकर और जीतकर भारतीय टीम चार्ज हो चुकी है। यही वजह है कि पहला मैच शुरू होने से दो दिन पहले मेजबान टीम धर्मशाला पहुंची तो दक्षिण अफ्रीकी टीम ने एक दिन आराम करने के बाद शुक्रवार को अपने खिलाड़ियों को क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में खुद को ढालने का पूरा मौका दिया।

क्वे को चाहिए सटीकता: दक्षिण अफ्रीकी ने शुक्रवार को एक घंटे वार्मअप किया। इसके बाद अंतरिम निदेशक इनोक क्वे के नेतृत्व में टीम ने अभ्यास किया। खास बात यह है कि क्वे चाहते हैं कि उनके गेंदबाज सीरीज में लाइन और लेंथ से भटके नहीं। यही वजह थी कि चाइनामैन तबरेज शम्सी और बायें हाथ के तेज गेंदबाज ब्यूरेन हेंड्रिक्स ने बिना बल्लेबाजों के नेट पर गेंदबाजी अभ्यास किया। शम्सी ने सटीकता और ब्यूरेन ने यॉर्कर पर फोकस रखा। दोनों गेंदबाज करीब डेढ़ से दो घंटे गेंदबाजी करते रहे। ब्यूरेन विकेट के बीचों बीच यॉर्कर डाल रहे थे तो दूसरी ओर शम्सी का ध्यान सटीक लाइन लेंथ पर था।

बल्लेबाजों का हिटिंग पर जोर: अंतिम दो दिनों में टीम पावर हिटिंग पर जोर दे रही है। मिलर, रीजा हेंड्रिक्स, जूनियर डाला, ड्वेन प्रिटोरियस लंबे शॉट का अभ्यास करते दिखे। वहीं जॉर्ज लिंडे, एंडिले फेलुकवायो ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया। क्वे रबादा की गेंदबाजी के साथ ही उनकी बल्लेबाजी पर भी ध्यान देते दिखे। पीले रंग की जर्सी में अभ्यास करने पहुंची अफ्रीकी टीम ने अभ्यास से पूर्व स्टेडियम में सीरीज के लिए अपनी जर्सी भी लांच की।

हमेशा से टेस्ट में छाप छोड़ना चाहता था : बुमराह

मुंबई, प्रेट्र : अपने करियर की शुरुआत में सीमित ओवरों का विशेषज्ञ करार दिए गए गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शुक्रवार को कहा कि टेस्ट क्रिकेट में भी मनचाही सफलता मिलना सपना सच होने जैसा है। बुमराह ने 12 टेस्ट में 62 विकेट ले लिए हैं। उन्हें सीमित ओवरों का गेंदबाज माना जाता था, लेकिन जब मौके मिले तो उन्होंने साबित किया कि वह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सुपरहिट हैं। बुमराह ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरे लिए टेस्ट क्रिकेट काफी महत्वपूर्ण था और मैं हमेशा टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था। मैं ऐसा क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था जो टी-20 और वनडे ही खेले। मैं टेस्ट क्रिकेट को काफी अहमियत देता हूं और इसमें हमेशा से छाप छोड़ना चाहता था। मेरा यह मानना रहा है कि मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है तो टेस्ट में भी कर सकता हूं। अभी सफर शुरू हुआ है। सिर्फ 12 टेस्ट खेले हैं, लेकिन यह सपना सच होने जैसा है। बुमराह ने कहा कि सफेद जर्सी में खेलने का अहसास ही अलग है। टीम की सफलता में योगदान देने से मुझे काफी संतोष मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बने बुमराह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट खेलकर आत्मविश्वास बढ़ा है और उसी की वजह से लय कायम रख सका हूं।

अभ्यास सत्र के दौरान कुछ इस तरह नजर आए एंडिले फेलुकवायो ● प्रेट्र

पंत खुद के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखें : क्लूजनर

धर्मशाला : दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर लांस क्लूजनर को लगता है कि रिषभ पंत जैसी बेहतरीन प्रतिभा के धनी खिलाड़ी को खुद के बजाय दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए। क्लूजनर ने कहा कि निकट भविष्य में भारत के लिए और अधिक निरंतर प्रदर्शन के मद्देनजर पंत को ऐसा करना चाहिए। क्लूजर का मानना है कि पंत की काबिलियत देखते हुए वनडे में 22.90 और टी-20 में 21.57 का औसत बेहतरीन नहीं दिखता, लेकिन यह दिखाता है कि वह समय से आगे चल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका टीम के बल्लेबाजी कोच के तौर पर 48 साल के क्लूजनर इस समय भारत में हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह बताना काफी मुश्किल होगा, लेकिन उनके जैसा बेहतरीन खिलाड़ी खुद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। क्लूजनर जब दिल्ली की सफेद गेंद वाली सीनियर टीम के सलाहकार थे, तब उन्हें पंत के खेल को देखने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि पंत को खुद को थोड़ा समय देना चाहिए और थोड़ा सा समय उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका प्रदान करेगा। लोग सोचते हैं कि खिलाड़ी अधिकतर चीजें अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन क्लूजनर का मानना है कि अगर खिलाड़ी दूसरों की गलतियों से सीख लेता है तो यह काफी फायदेमंद साबित होगा। क्लूजनर ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो चीज आपको आगे ले जाती है, वह है खुद गलतियां किए बिना दूसरों की गलतियों से सीख लो। आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हो, लेकिन गलती को महसूस करने, उसे सही करके बेहतर खिलाड़ी बनने में काफी समय लगता है। अगर आप दूसरे खिलाड़ी को गलती करते हुए देखते हो तो आप तेजी से सीखोगे और तेजी से सुधार करोगे।

भारतीय क्रिकेट टीम पहुंची धर्मशाला

धर्मशाला : पहले मुकाबले के लिए टीम इंडिया कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में शुक्रवार शाम धर्मशाला पहुंच गई। विराट ब्रिगेड करीब चार बजे कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंची। यहां से विशेष बस के जरिये कंडी स्थित एचपीसीए के होटल 'द पवेलियन' चली गई। भारतीय टीम शनिवार को शाम के सत्र में मैदान में अभ्यास करने पहुंचेगी।

संगकारा और लारा की याद दिलाते हैं डिकॉक

गौतम गंभीर
फ्लिक

मुझे यह मौसम पसंद है। यह चिपचिपा है, लेकिन अभी क्रिकेट के बारे में चर्चा बहुत रोमांचक है। यह एक सत्र, नई आशाओं, नए लक्ष्यों की शुरुआत है। मेरे लिए दिल्ली के लिए खेलने के अपने शुरुआती दिनों में साल के इस समय का मतलब नए बल्लों को लेने के लिए मेरठ की यात्रा करना भी था। लकड़ी की गंध, एक बल्ले के निर्माता के कारखानों में नई विलो का परीक्षण करने की आवाज और फिर नए दस्ताने और लेग गार्ड पहनना, ये सब भावनाओं की एक भीड़ के साथ मेल खाता है। 20-21 वर्ष की आयु में एक नई किट होने का मतलब है कि आपके पास दुनिया है।

भारतीय टीम के लिए काम शायद ही खत्म हो। आइपीएल के बाद वे विश्व कप में गए और वेस्टइंडीज में सीरीज के बाद घर वापसी हुई। मुझे नहीं लगता कि एक आधुनिक भारत का क्रिकेटर उस रोमांच से संबंधित हो सकता है, जिसे मैं समझ रहा था।

दक्षिण अफ्रीका के भारत के दौरे को लेकर यही कहूंगा कि मेहमान इसे विश्व कप की भुलाने वाली याद के बाद अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय सीरीज से जोड़कर देख सकते हैं। मुझे क्विंटन डिकॉक पसंद हैं। वह बायें हाथ के उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से हैं जिनसे मैं हमेशा प्रभावित हुआ, लेकिन कभी उनके जैसा नहीं बन पाया। वह मुझे कुमार संगकारा और ब्रायन लारा की याद दिलाते हैं। उम्मीद है कि वह कप्तान के रूप में सफल होंगे।

मेजबान भारत एक युवा और विकसित हो रहे विरोधी को लेकर अपने जीभ लपलपा रहा होगा। धर्मशाला बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं है और ऊंचाई पर होने के कारण विज्ञान के लोग मुझे बताते हैं कि हवा के कारण गेंद तेजी से जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर बल्लेबाजी के लिए पिच अच्छी है तो बहुत सारी बाउंड्री लगेंगी। यह युवा भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक और मौका है। मनीष पांडे अपनी 29 साल की उम्र से कम के लगते हैं। श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज में खुद को साबित किया। केएल राहुल सफेद गेंद के प्रारूप में एक ताकत हैं। रिषभ पंत हमेशा रोमांचक खेल दिखाते हैं, लेकिन उन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा। उन्हें मेरे पसंदीदा संजू सैमसन कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यह एक रोचक सीरीज है क्योंकि अगले साल टी-20 विश्व कप के लिए कई खिलाड़ी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं।

मैं रोहित शर्मा को टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में देखकर खुश हूं। यह उनके लिए एक और अवसर है। किसी भी अन्य बल्लेबाज से ज्यादा रोहित ने आइपीएल में मेरी कप्तानी के दौरान चुनौती दी, लेकिन उन्हें टेस्ट में अपनी चमक बिखेरनी होगी।

THE ULTIMATE INVERTER BATTERY
EXIDE INVATUBULAR

इंग्लैंड के पास स्मिथ का तोड़ नहीं

एशेज सीरीज

ऑस्ट्रेलिया ने चायकाल तक बनाए चार विकेट पर 147 रन, स्मिथ का अर्धशतक, पूरे किए सीरीज में 700 रन

जागरण न्यूज नेटवक, नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास कोई तोड़ नहीं है। ऐसा एक बार फिर साबित हुआ जब लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जा रहे एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को चायकाल तक ऑस्ट्रेलिया ने चार विकेट पर 147 रन बना दिए। स्टीव स्मिथ हालांकि एक और अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे हैं। दूसरे दिन चायकाल की घोषणा तक स्मिथ 59 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ मिशेल मार्श 12 रन बनाकर खड़े हैं। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 294 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया मेजबान टीम से अभी भी 147 रन पीछे है।

पहले सत्र में दो विकेट खोने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दूसरे सत्र में भी दो विकेट खोए। मार्नस लाबुशाने स्मिथ का अच्छा साथ दे रहे थे। उन्होंने स्मिथ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए टीम के लिए 69 रनों की साझेदारी की। 83 के कुल स्कोर पर लाबुशाने, जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू दे दिए गए। लाबुशाने 84 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 48 रन बनाने में सफल रहे। मैथ्यू वेड (19) स्मिथ के साथ विकेट पर जम पाते उससे पहले ही सैम कुर्रन ने उन्हें 118 के कुल स्कोर पर आउट कर दिया। इस बीच स्मिथ ने अपना एक और अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह स्मिथ का इस एशेज में तीसरा अर्धशतक है। वह अभी तक 97 गेंदों का सामना कर आठ चौके और एक छक्का लगा चुके हैं। इससे पहले, दिन की शुरुआत आठ विकेट के नुकसान पर 271 रनों के साथ करने वाली मेजबान टीम ने अपने बाकी के दो विकेट दूसरे दिन 23 रनों का इजाफा कर खो दिए। जोस बटलर अपने खाते में छह रन और जोड़कर 70 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। जैक लीच (21) के रूप में इंग्लैंड ने अपना आखिरी विकेट खोया। यह दोनों विकेट मिशेल मार्श ने लिए। मार्श ने कुल पांच विकेट अपने नाम किए। पैट कमिंस ने तीन और जोश हेजलवुड ने दो बल्लेबाजों को पवेलियन पहुंचाया।

अपनी पहली पारी खेलने उतरी ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर का विकेट एक बार फिर जल्दी गिर गया। वार्नर (5 रन) इस बार आर्चर का शिकार बने। 14 के कुल स्कोर पर मार्कस हैरिस भी आर्चर की गेंद पर स्लिप में बेन स्टोक्स के हाथों लपके गए।

पांचवें एशेज टेस्ट के दूसरे दिन अर्धशतक जमाने के बाद अभिवादन स्वीकार करते ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ ● रायटर

छठे नंबर या उससे नीचे खेलकर बल्लेबाजों के सीरीज में 700 से ज्यादा रन

बल्लेबाज	रन	देश	बनाम	पारी	वर्ष
डॉन ब्रैडमैन	806	ऑस्ट्रेलिया	दक्षिण अफ्रीका	5	1931
ग्राहम गूच	752	ऑस्ट्रेलिया	भारत	6	1990
डॉन ब्रैडमैन	715	ऑस्ट्रेलिया	भारत	5	1947
जैक कैलिस	712	दक्षिण अफ्रीका	वेस्टइंडीज	6	2003
स्टीव स्मिथ	701*	ऑस्ट्रेलिया	इंग्लैंड	6	2019

2 बार टेस्ट सीरीज में 700 रन बनाए स्मिथ ने। इस मामले में उन्होंने सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा, एवर्टन वीक्स की बराबरी की। सबसे ज्यादा बार 700 रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रैडमैन (5) के नाम है

8 बार एक एशेज सीरीज में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके वार्नर। एक टेस्ट सीरीज में ऐसा करने वाले वह विश्व क्रिकेट के पहले ओपनर बने

10 लगातार पारी में 50 से अधिक रन बनाए स्मिथ ने इस सीरीज में। वह एक ही देश के खिलाफ ऐसा करने वाले अकेले बल्लेबाज बने

भारतीय पहलवानों की नजर ओलंपिक कोटे पर

नूर सुल्तान (कजाखस्तान), प्रेट्र : भारत के शीर्ष पहलवानों के लिए यहां शनिवार से शुरू हो रही विश्व चैंपियनशिप में असली परीक्षा होगी, क्योंकि इसमें वे प्रतिष्ठा की ही नहीं, बल्कि टोक्यो ओलंपिक क्वालीफिकेशन की भी उम्मीद लगाए होंगे।

बजरंग ने इस सत्र की सभी चार प्रतिस्पर्धाओं में खिताब जीते हैं। वह 65 किग्रा वर्ग में नंबर एक और शीर्ष वरीय पहलवान के तौर पर मैट पर उतरेंगे, लेकिन उनका कमजोर 'लेग डिफेंस' उनके लिए परेशानी बन सकता है। 25 वर्षीय बजरंग ने दो विश्व चैंपियनशिप पदक जीते हैं, लेकिन वह स्वर्ण नहीं जीत पाए हैं। विनेश ने नए वजन वर्ग से सत्र की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने 50 से 53 किग्रा में खेलने का फैसला किया। वह पांच फाइनल तक पहुंचीं, जिसमें तीन स्वर्ण जीते। विनेश की निगाहें पहले विश्व पदक पर लगी हैं। पिछले साल कोहनी की चोट के कारण उन्हें बुडापेस्ट चैंपियनशिप से बाहर होना पड़ा था। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने ही भारत को पुरुष फ्रीस्टाइल में विश्व खिताब दिलाया है, लेकिन वह आठ साल बाद विश्व चैंपियनशिप में वापसी कर रहे हैं। 74 किग्रा में उनके प्रदर्शन पर सभी की नजरें लगी होंगी। दीपक पूनिया 18 साल की उम्र में भारत के पहले जूनियर विश्व चैंपियन बनने के बाद यहां पहुंचे हैं। रियो ओलंपिक की कांस्य विजेता साक्षी मलिक ने 2017 कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जीतने के बाद से कोई खिताब नहीं जीता है। वहीं, दिव्या काकरान ने इस सत्र में दो स्वर्ण और इतने ही कांस्य पदक जीते हैं। गुरप्रीत सिंह (77 किग्रा) और हरप्रीत सिंह (82 किग्रा) ग्रीको रोमन में भारत की सर्वश्रेष्ठ उम्मीद होंगे।

टीम: पुरुष फ्रीस्टाइल : रवि कुमार (57 किग्रा), राहुल अवारे (61 किग्रा), बजरंग पूनिया (65 किग्रा), करण (70 किग्रा), सुशील कुमार (74 किग्रा), जितेंदर (79 किग्रा), दीपक पूनिया (86 किग्रा), परवीन (92 किग्रा), मौसम खत्री (97 किग्रा) और सुमित मलिक (125 किग्रा)। **पुरुष ग्रीको रोमन :** मंजीत (55 किग्रा), मनीष (60 किग्रा), सागर (63 किग्रा), मनीष (67 किग्रा), योगेश (72 किग्रा), गुरप्रीत सिंह (77 किग्रा), हरप्रीत सिंह (82 किग्रा), सुनील कुमार (87 किग्रा), रवि (97 किग्रा) और नवीन (130 किग्रा)।

महिला फ्रीस्टाइल : सीमा (50 किग्रा), विनेश फोगाट (53 किग्रा), ललिता (55 किग्रा), सरिता (57 किग्रा), पूजा ढांडा (59 किग्रा), साक्षी मलिक (62 किग्रा), नवजोत कौर (65 किग्रा), दिव्या काकरान (68 किग्रा), कोमल भगवान गोले (72 किग्रा) और किरण (76 किग्रा)।

नौकरी की चाहत ने बदल दी स्वप्ना की जिंदगी

योगेश शर्मा ● नई दिल्ली

प्रेरणा

- बर्मन ने कहा, मेरा अधूरापन ही मेरी सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा
- दीपिका पल्लीकल व सिमरनजीत कौर ने भी साझा किए अनुभव

रिक्शाचालक की बेटी स्वप्ना बर्मन की बस इतनी चाहत थी कि वह किसी खेल में हिस्सा ले और उनकी नौकरी लग जाए, जिससे वह अपने परिवार का जीवनयापन अच्छे से कर सके। जकार्ता एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय हेप्टाथलन एथलीट बर्मन ने यह नहीं सोचा था कि इस नौकरी की चाहत उनकी और उनके परिवार की जिंदगी बदल देगी।

एशियन गेम्स से पहले बर्मन को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता तो उनके बदतर हालात भी अच्छे में बदल गए। यहां गुरुवार को एडिडास ने कैनवस के रूप में वीआरसीटी जैकेट लांच किया। इस दौरान बर्मन ने कहा कि मेरा अधूरापन ही मेरी सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं बहुत गरीब परिवार से थी और मेरी कोशिश यही थी कि खेल कोटा के आधार पर नौकरी मिल जाए। फिर धीरे-धीरे मैं अपने खेल में सुधार करती रही और टूर्नामेंटों में हिस्सा लेने लगी। जब मैं पदक जीतने लगी तो मुझे विश्वास आ गया कि मैं एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में पदक जीत सकती हूं। इस दिशा में मेरी पहली कोशिश सफल रही और मैंने एशियन गेम्स में स्वर्ण जीता। इस पदक के बाद मुझे कंपनियों से करार मिलने लगे और पैसों की दिक्कत भी कम हो गई।

जूतों से लगता था डर : बर्मन के दोनों पैर में छह-छह अंगुलियां हैं, जिसकी वजह से वह जूते पहनने से डरती थीं। बर्मन ने कहा कि एशियन गेम्स से पहले की बात है जब मैं किसी दुकान पर जाती थी तो मुझे जूतों से डर लगता था क्योंकि ये जूते मेरे पैरों में ठीक तरह से आते नहीं थे और मेरे पैरों में दर्द होता था। फिर एडिडास ने मेरे लिए खास जूते बनाए, जिससे अब मेरे पैरों में दर्द नहीं होता और अब मैं अच्छे से टूर्नामेंटों में हिस्सा लेती हूं।

महिलाओं को नहीं आंके कम : इस दौरान भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल भी मौजूद थीं। उनका कहना है कि किसी भी चीज में महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए। दीपिका ने कहा कि मेरे खेल में ही राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों को ज्यादा इनामी राशि मिलती थी और महिलाओं को कम। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि ऐसा क्यों होता है। मैं यह नहीं कह रही कि मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम महिलाएं भी पुरुषों से कम मेहनत नहीं करती हैं। उनको मिलने वाली ज्यादा राशि का मैंने विरोध किया और चैंपियनशिप से हट गई थी। इसके बाद पुरुष और महिला दोनों को समान राशि मिलने लगी।

मुक्केबाजी का था जुनून : भारतीय महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर ने कहा कि मुझे शुरू से इस खेल का जुनून था जिसके कारण मैं इसमें आई। पापा ने मेरा मुक्केबाजी में आने का समर्थन नहीं किया, लेकिन मम्मी की मदद के कारण मैं यहां तक पहुंच पाई।

मैं जब रिंग में उतरती हूं तो उससे पहले बस यही सोचती हूं कि मुझे स्वर्ण पदक जीतना है ताकि मैं साबित कर सकूं कि मेरा इस रिंग में आने का फैसला सही था। मैं पुरुष मुक्केबाजों के साथ भी अभ्यास करती हूं। इससे मेरा अभ्यास अच्छे से हो जाता है।

ओसाका ने दूसरी बार बदला कोच

टेनिस डायरी

टोक्यो, एएफपी: जापानी टेनिस सुपरस्टार नाओमी ओसाका ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह अपने कोच जर्मेन जेंकिंस के साथ काम नहीं करेंगी। उन्होंने इस साल उन्होंने दूसरी बार अपने कोच से अलग होने का फैसला किया है। वह इस समय फॉर्म से जूझ रही हैं विश्व रैंकिंग में नीचे खिसक गई हैं।

पैन पैसिफिक ओपन टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर 21 साल की ओसाका ने घोषणा की कि वह अब कोच के साथ काम नहीं करेंगी। जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के बाद जेंकिंस उनकी टीम से जुड़े थे। ओसाका ने ट्वीट किया, 'आप सभी को यह बताने के लिए लिख रही हूं कि मैं और जे (जेंकिंस) अब एक साथ काम नहीं करेंगे। उनके (कोच) साथ जो समय बिताया, उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। मैंने उनसे कोर्ट के अंदर और बाहर काफी कुछ सीखा लेकिन अब मुझे कोच बदलने का सही समय लग रहा है। सब चीजों के लिए शुक्रिया।' इससे पहले ओसाका ने अपने पूर्व कोच सास्चा बाजिन के साथ नाता तोड़ लिया था जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने 2018 में यूएस ओपन और इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब जीते थे। हालांकि मेलबर्न में खेलने के बाद उनके नतीजे अच्छे नहीं रहे। फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में ओसाका को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्हें विंबलडन के पहले दौर में हैरान करने वाली हार झेलनी पड़ी।

बियांका ने लिया नाम वापस: यूएस ओपन चैंपियन बियांसा एंड्रीस्कू ने दायें पैर में चोट की वजह से अगले सप्ताह से शुरू हो रहे पैन पैसेफिक ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा फ्रेंच ओपन की उपविजेता मार्केटा वोंड्रोसोवा और बेलिंडा बेंसिक ने भी चोट की वजह से इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है।

विरोध प्रदर्शन के कारण हांगकांग ओपन स्थगित

हांगकांग : डब्ल्यूटीए हांगकांग महिला टेनिस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। इसके आयोजकों ने शुक्रवार को बताया कि पिछले कई महीने से हो रही लोकतंत्र समर्थक हिंसक प्रदर्शन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले महीने होने वाले टूर्नामेंट को स्थगित कर रहे हैं। हांगकांग टेनिस संघ ने कहा, 'अपने हितधारकों से लंबी चर्चा के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टूर्नामेंट को बाद में कराना ही सही रहेगा। हांगकांग ओपन का आयोजन पांच से 13 अक्टूबर तक होना था। इस टूर्नामेंट में पहले वीनस विलियम्स, एंजलिक कर्बर और कैरोलिन वोज्नियाकी सहित कई शीर्ष खिलाड़ी भाग ले चुकी हैं। इसका आयोजन विक्टोरिया पार्क में होता है जो विरोध प्रदर्शन के केंद्र के पास है। हांगकांग में पिछले 14 सप्ताह से लाखों लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन उस विवादास्पद विधेयक को लेकर हो रहा था जिसमें जरूरत पड़ने पर हांगकांग के किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण कर चीन भेजने का प्रावधान था।

क्लिस्टर्स ने तोड़ा संन्यास

नई दिल्ली : पूर्व नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी बेल्जियम की किम क्लिस्टर्स 36 साल की उम्र में अपना संन्यास तोड़कर एक बार फिर से कोर्ट पर लौटने के लिए तैयार हैं। किम 2020 में होने वाले डब्ल्यूटीए से टेनिस में वापसी करेंगी। किम का मानना है कि वह इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहती हैं और कुछ भी साबित नहीं करना चाहती हैं। किम ने साल 2007 में तब संन्यास ले लिया था जब वह पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं। इसके बाद उन्होंने दो साल बाद 2009 में वापसी की थी और यूएस ओपन तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया था। चोट के कारण हालांकि उन्होंने साल 2012 में फिर से संन्यास ले लिया था। किम ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि सही मायने में मैं जीवन में क्या चाहती हूं। पिछले सात वर्षों से मैं पूरी तरह से एक मां की भूमिका में रही हूं और मैंने इसका आनंद उठाया लेकिन मुझे एक टेनिस बनना भी बहुत भाया इसलिए मैंने एक बार फिर वापसी करने का फैसला किया।

फैसला लोकपाल डीके जैन ने कहा कि बीसीसीआइ सुनिश्चित करे गांगुली एक पद से ज्यादा पर न रहें

हितों के टकराव को लेकर गांगुली पर सख्त लोकपाल

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के लोकपाल डीके जैन ने बोर्ड से साफ कह दिया है कि सौरव गांगुली के हितों का टकराव का मुद्दा आसानी से प्रभावित होने वाला है और वह अपने पदों को चयन करने पर ध्यान दें। वह इस बात का ख्याल रखें कि एक से ज्यादा पद पर न रहें।

हालांकि जैन ने हितों के टकराव के मुद्दे पर गांगुली को संदेह का लाभ दिया है लेकिन साथ ही कहा है कि उन्हें एक पद से ज्यादा पर सवार नहीं रहना चाहिए। इसे लेकर जैन ने बीसीसीआइ को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हालिया मामले में, गांगुली को नोटिस दिया गया था। उसमें लिखा था कि अगर लोकपाल को लगा कि नियम 38 के तहत क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) में उनका रहना हितों के टकराव का मुद्दा है तो ऐसे में इन शिकायतों को लेकर उनका जवाब तुरंत प्रभाव से उनके इस्तीफे के तौर पर मान लिया जाएगा, दूसरा यह कि उनका आइपीएल फ्रेंचाइजी से करार तुरंत प्रभाव से खत्म होगा।

मैं यह साफ करता हूं कि इस मामले में हितों का टकराव आसानी से प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि कानून का ज्ञान न होना बहाना नहीं हो सकता। गांगुली को 38(2) के नियम के तहत जरूरी जानकारी देनी थी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नियम अगस्त 2018 से अस्तित्व में आया, मैं गांगुली को संदेह का लाभ दे रहा हूं कि शायद उन्होंने पद स्वीकार करते हुए यह पता न हो कि यहां हितों का टकराव है। मैं बीसीसीआइ को निर्देश देता हूं कि वह इस बात को सुनिश्चित करे कि गांगुली ऐसी स्थिति से बचें, जहां हितों का टकराव आड़े आए। बीसीसीआइ उन्हें नियम 38 (4) के मुताबिक एक पद पर ही बने रहने दें।

सौरव गांगुली ● फाइल फोटो, प्रेट्र

सौरव को लेकर ये है पूरा मामला

नई दिल्ली : सौरव गांगुली पर बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, सीएसी सदस्य और आइपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के सलाहकार के तौर पर तीन भूमिका निभाने के लिए हितों के टकराव का आरोप लगा था। नियम के मुताबिक कोई भी बीसीसीआइ में एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मामला सामने आने के बाद गांगुली सीएसी से अलग हो गए थे। बता दें कि इसी तरह के विवाद में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण पर भी फंस चुके हैं।

पर्यवेक्षक नियुक्त करने पर सीओए का यूटर्न

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई प्रशासकों की समिति (सीओए) ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में बैठक की और राज्य संघों द्वारा रखे गए मुद्दों पर चर्चा की। रोचक बात यह है कि सीओए के अध्यक्ष विनोद राय ने साफ किया है कि 10 राज्यों के कामकाज पर पर्यवेक्षक नजर नहीं रखेंगे न ही वह राज्य संघों के किसी भी फैसले में दखल देंगे। राय से जब 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, बिहार, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पुडुचेरी में पर्यवेक्षक नियुक्त करने और बीसीसीआइ के संविधान में इसकी इजाजत होने पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सिर्फ राज्य संघों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए की गई थी। यह फैसला इसलिए लिया गया था क्योंकि हमारे पास कई तरह के सवाल आ रहे थे। यह सिर्फ मदद करने के लिए लिया गया फैसला था। वह एक पर्यवेक्षक हैं, वह किसी तरह के फैसले लेने में हिस्सा नहीं लेंगे। यह साफ है कि वह फैसले नहीं लेंगे और न ही किसी तरह के निर्देश देंगे। वह बैठेंगे और सिर्फ चीजों को देखेंगे। यह जवाब देने वाला सवाल ही नहीं है। राज्य संघों को जो मेल किया गया है उसमें साफ लिखा है कि पर्यवेक्षक राज्य संघों को क्रिकेट संबंध मसलों में मार्गदर्शन देंगे।

30 राज्य संघ हुए बीसीसीआइ के संविधान से संबद्ध : विनोद राय

नई दिल्ली : करीब ढाई साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सीओए के प्रमुख विनोद राय ने कहा कि 22 अक्टूबर को बीसीसीआइ के प्रस्तावित चुनाव को लेकर प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है। चुनाव नियत समय पर हो जाएंगे। राय ने यह भी कहा कि लगभग 30 राज्य क्रिकेट संघ अब बीसीसीआइ के संविधान के अधीन आ चुके हैं। राज्य क्रिकेट संघों का बीसीसीआइ के संविधान के अधीन काम करना इस पूरी प्रक्रिया का अहम हिस्सा था। यह काफी अच्छी संख्या है। कुछ राज्यों जैसे कि मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के साथ कुछ समस्याएं थीं, लेकिन हमने वे मुद्दे सुलझा लिए हैं। यह पूछे जाने पर कि कौन से राज्य अभी बीसीसीआइ से संबद्ध नहीं हुए हैं। राय ने कहा कि हरियाणा और तमिलनाडु हमारे पास नहीं आए, इसलिए हम इस मामले में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से राज्य संघ हमसे जुड़े हैं, हमें उम्मीद है कि चुनाव नियत तिथि पर हो जाएंगे। राय ने बताया कि सीओए आगामी 16 सितंबर को एक बैठक आयोजित करेगी। सीओए ने राज्य संघों को संबद्धता संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आखिरी तारीख 28 सितंबर तक बढ़ा दी थी। राय ने कहा कि अब इस तारीख को आगे बढ़ाना मुमकिन और उचित नहीं है क्योंकि बीसीसीआइ चुनाव के लिए एजीएम (सालाना आम बैठक) के लिए 21 दिन पहले नोटिस जारी होना जरूरी है जो कि इस मामले में 30 सितंबर की तारीख है। बीसीसीआइ के चुनाव के लिए राज्य संघों को अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजने होंगे।

पाक ने दूसरे देशों का दौरा कर उनका समर्थन किया : सरफराज

लाहौर : श्रीलंका क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि उनका क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका की टीम से सिर्फ अपील कर सकता है कि वे पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलें। हमने दूसरे देशों का दौरा करके हमेशा उनका समर्थन किया है।

इंग्लैंड दौरे पर टीम के खिलाड़ियों का संतुलन और मिश्रण पिछली प्रतियोगिताओं जैसा ही रहेगा।
– शॉर्ड मारिन, महिला हॉकी टीम के कोच

फुटबॉल डायरी ▶ ईपीएल में आज न्यूकैसल से यूरोपियन चैंपियन की भिड़ंत

लिवरपूल ने बढ़ाई दूसरों की बेचैनी

दूसरे स्थान पर काबिज सिटी का नॉर्विक से सामना

लंदन, एएफपी : इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में अपनी दमदार शुरुआत से लिवरपूल ने खिताब के अन्य दावेदारों की बेचैनी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में लिवरपूल फुटबॉल क्लब शनिवार को न्यूकैसल युनाइटेड से भिड़ेगा।

मैनेजर जुर्जेन क्लोप की लिवरपूल टीम ने मौजूदा सत्र के चार मैचों में चार जीत के साथ शीर्ष स्थान पर कब्जा जमाया हुआ है और दूसरे स्थान पर काबिज मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी पर उसे दो अंकों की बढ़त हासिल है। इस दौरान यूरोपियन चैंपियन लिवरपूल ने नॉर्विक, साउथैंप्टन, आर्सेनल और बर्नले को शिकस्त दी है और विरोधियों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश भेजा है। पिछले सत्र में लिवरपूल मामूली अंतर से सिटी से खिताबी जंग में पिछड़ गया था।

ईपीएल में शनिवार को मैनचेस्टर सिटी का सामना नॉर्विक सिटी से होगा, लेकिन जब यह मुकाबला शुरू होगा तब तक संभवतः लिवरपूल उस पर पांच अंकों की बढ़त बना चुका होगा। मैनेजर पेप गॉर्डियोला की टीम सिटी भी मौजूदा सत्र में अजेय है और उसने वेस्टहम और ब्रिज्टन को हराया है, लेकिन टॉटनहम के खिलाफ ड्रॉ ने लिवरपूल को अंक तालिका में आगे बढ़ने का मौका दिया।

चोट ने बढ़ाई युनाइटेड की मुश्किलें

ओले गनर सोल्सकजेर की मैनचेस्टर युनाइटेड की टीम लीसेस्टर सिटी से शनिवार को भिड़ेगी। युनाइटेड की शुरुआत खराब रही है और उसने अपने चार मुकाबलों में से केवल एक में विजय प्राप्त की है। हालांकि, हाल ही में युनाइटेड से जुड़े हैरी मेग्यूरे से उम्मीद होगी कि वह अपने पुराने क्लब के खिलाफ अपने मौजूदा क्लब को जीत दिलाएं। युनाइटेड पॉल पोग्बा सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में इस मुकाबले में उतरेगा, जो चोटिल हैं। अन्य मुकाबलों में टॉटनहम का सामना क्रिस्टल पैलेस से, जबकि चेल्सी का सामना वोल्वरहैंप्टन से होगा। अगर चेल्सी के स्ट्राइकर टैमी अब्राहम दो गोल करने में सफल रहे तो वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डेले अली के बाद 21 साल से कम उम्र में लगातार तीन मुकाबलों में दो या उससे ज्यादा गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बनेंगे।

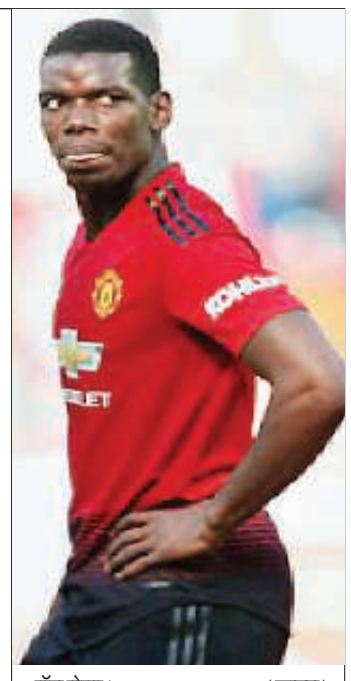

पॉल पोग्बा। (फाइल)

ला लीगा में पदार्पण के लिए हैजार्ड तैयार

मैड्रिड, एएफपी : स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड के मैनेजर जिनेदिन जिदान ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में एक मोटी रकम में क्लब से जुड़े ईडन हैजार्ड ने फिटनेस परीक्षण पास कर लिया है और वह शनिवार को लेवांते के खिलाफ ला लीगा में बहुप्रतीक्षित पदार्पण करेंगे। जिदान ने कहा कि सभी हैजार्ड को खेलते देखना चाहते हैं। उन पर बहुत दबाव है और उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे अहम चीज यह है कि वह तैयार हैं। हैजार्ड जून में चेल्सी को छोड़कर रीयल से जुड़े थे। उधर, ला लीगा में ही शनिवार को एक अन्य अहम मुकाबले में वेलेंसिया की टीम मौजूदा चैंपियन बार्सिलोना से भिड़ेगी, जिसे आने वाले दिनों में चैंपियंस लीग में चेल्सी से भी भिड़ना है। वहीं, अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज एटलेटिको मैड्रिड को रीयल सोसिएदाद से भिड़ना है।

जुवेंटस को मिलेगा सारी का साथ

मिलान, एएफपी : इटालियन लीग सीरी-ए में शनिवार को जुवेंटस की टीम फ्योरेंटिना से भिड़ेगी, जहां पुर्तगाली स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपना जलवा बिखरते नजर आएंगे। साथ ही बीमारी से उबर चुके जुवेंटस के मैनेजर मॉरिजियो सारी भी पहली बार इस सत्र में अपनी सीट पर बैठे नजर आएंगे। चेल्सी के पूर्व मैनेजर सारी जुवेंटस के पिछले दो मुकाबलों में क्लब के साथ नहीं थे। रोनाल्डो पर भी सबकी निगाहें होंगी, जिन्होंने यूरो कप क्वालीफायर में पुर्तगाल की ओर से चार गोल करके सुर्खियां बटोरी थीं।

तटस्थ स्थल पर नहीं खेली जाएगी पाकिस्तान–श्रीलंका सीरीज : पीसीबी

क्रिकेट डायरी

लाहौर, प्रेट्र : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साफ कर दिया है कि इस महीने के अंत में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज किसी तटस्थ स्थल पर नहीं खेली जाएगी। श्रीलंका का पाकिस्तान दौरा पूरी तरह से तय था, लेकिन फिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री कार्यालय को उनकी टीम पर संभावित आंतकी हमले की सूचना मिली। इसके बाद, श्रीलंका क्रिकेट ने कहा कि उसे पाकिस्तान दौर के अपनी योजना का पुनः मूल्यांकन करना होगा।

पाकिस्तान इस स्थिति पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है, लेकिन सीरीज को किसी तटस्थ स्थल पर ओयाजित कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पीसीबी का यह मानना है कि अगर सीरीज किसी तटस्थ स्थल पर खेली जाती है तो पाकिस्तान में दोबारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट शुरू करने की उनकी योजना खतरे में पड़ जाएगी। बोर्ड का यह भी मानना है कि ऐसा करने से पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के लिए विदेश खिलाड़ियों को पाकिस्तान में बुलाना भी मुश्किल होगा। श्रीलंका की टीम को पाकिस्तान में 27 सितंबर और नौ अक्टूबर के बीच तीन-तीन वनडे और टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

इससे पहले श्रीलंका के 10 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया था। लसित मलिंगा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चांदीमल, सुरंगा लकमल, दिमुथ करुणारत्ने, तिसारा परेरा, अकिला धनंजय, धनंजय डिसिल्वा, कुशल परेरा और निरोशन डिकवेला ने दौरे से खुद को अलग कर लिया है। लाहिरु थिरिमाने वनडे जबकि दासुन शनाका टी-20 में श्रीलंका की कप्तानी करेंगे।

स्ट्रॉस बने ईसीबी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन

लंदन : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में नाइटहुड सम्मान पाने वाले 42 वर्षीय स्ट्रॉस ने 2015 से 2018 तक इंग्लैंड क्रिकेट के निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह अपनी पत्नी रूथ की देखभाल के लिए पद से हट गए थे। रूथ का निधन कैंसर के कारण हुआ। बीबीसी से स्ट्रॉस ने कहा कि ईसीबी इस कठिन वर्ष में समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। इस नए पद पर वापसी करके मुझे वास्तव में बहुत खुशी हो रही है। ईसीबी की क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन के रूप में स्ट्रॉस इंग्लैंड और वेल्स में सभी स्तरों की निगरानी करेंगे ताकि खेल पेशेवर रूप से जारी रहे। स्ट्रॉस ने इंग्लैंड के लिए 100 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 40.91 की औसत से 7,037 रन बनाए। उन्होंने कप्तान के रूप में अपने 50 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड को दो एशेज जीत के साथ-साथ नंबर एक टेस्ट टीम भी बनाया।

रियाज ने लाल गेंद क्रिकेट से ब्रेक लिया

लाहौर : पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने सीमित ओवर के प्रारूप में अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए लाल गेंद क्रिकेट से ब्रेक लिया है। रियाज ने कहा कि लाल गेंद क्रिकेट में पिछले कुछ वर्षों के मेरे प्रदर्शन को देखते हुए और आगामी सीमित ओवरों के क्रिकेट की समीक्षा करने के बाद मैंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से ब्रेक लेने का फैसला किया है। रियाज अब पाकिस्तान की प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता कायदे-ए-आजम ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लेंगे। रियाज ने कहा कि वह लाल गेंद क्रिकेट में तभी वापसी करेंगे जब उन्हें यकीन हो जाएगा कि वह इस प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। रियाज ने कहा कि इस अवधि के दौरान मैं 50 ओवर एवं टी-20 क्रिकेट पर ध्यान देना चाहूंगा और खेल के लंबे संस्करण के लिए अपनी फिटनेस का आकलन करना जारी रखूंगा। एक स्तर पर जब मुझे लगेगा कि मैं न केवल वापसी कर सकता हूं बल्कि लाल गेंद से भी दमदार प्रदर्शन कर सकता हूं तब मैं खुद को उपलब्ध कराऊंगा। उन्होंने आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेला था।

रसेल को सीपीएल के दौरान सिर पर गेंद लगी

चोटिल होने के बाद बाहर जाते आंद्रे रसेल। ट्विटर

किंगस्टन (जमैका): वेस्टइंडीज के दमदार ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) में जमैका तालावास और सेंट लूसिया जुओक्स के बीच हुए मुकाबले में सिर पर गेंद लगी। बल्लेबाजी करते समय रसेल ने हेलमेट पहनी हुई थी, लेकिन गेंद लगने के बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। हालांकि रसेल का स्कैन हुआ है और उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी है। यह घटना गुरुवार को सबीना पार्क में 14वें ओवर में घटी जब रसेल शून्य पर खेल रहे थे। पुल शॉट खेलने के प्रयास में उनका सिर घूमा और उन्हें चोट लगी। वह उसी समय मैदान पर गिर गए और बाकी खिलाड़ियों ने रसेल का हेलमेट हटाकर उनकी चोट को देखा। रसेल को जल्द ही मैदान से बाहर ले जाया गया और उनका सिटी स्कैन किया गया।

इंग्लैंड दौरे पर महिला हॉकी टीम की कप्तान होंगी रानी

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल को शुक्रवार को 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया, जो मार्लो में हो रही पांच मैचों की सीरीज में इंग्लैंड से भिड़ेगी। सीरीज 27 सितंबर से चार अक्टूबर तक खेली जाएगी और गोलकीपर सविता उप कप्तान होंगी।

हाल में जापान में ओलंपिक टेस्ट इवेंट में टीम की जीत के बाद सविता और रजनी इतिमारपू ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है। डिफेंडर दीप ग्रेस एक्का, गुरजीत कौर, रीना खोखर और सलीमा टेटे को भी टीम में रखा गया है। मिडफील्ड में अनुभवी नमिता टोप्पो की वापसी हुई है, जो चोट के कारण बाहर थीं।

मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा, 'हमारी टीम में खिलाड़ियों का संतुलन पिछले टूर्नामेंट की तरह ही है क्योंकि हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई करने के अहम चरण में हैं।'

एआइटीए ने दी जानकारी, डेविस कप पर फैसला दोबारा सुरक्षा जायजा के बाद

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस्लामाबाद में 29 या 30 नंवबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान डेविस कप मुकाबले पर फैसला दोबारा सुरक्षा जायजा के बाद किया जाएगा। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआइटीए) ने शुक्रवार को दी।

इससे पहले इस्लामाबाद में होने वाला यह मुकाबला 14-15 सितंबर को होना था, लेकिन पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ (आइटीएफ) द्वारा गहन सुरक्षा जांच के बाद इसे नवंबर तक के लिए टाल दिया गया था। एआइटीए ने बताया कि चार नवंबर को सुरक्षा जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि इसका आयोजन इस्लामाबाद या फिर किसी तटस्थ स्थल पर होगा।

एआइटीए ने कहा, 'भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप मुकाबला 29 और 30 नवंबर या फिर 30 नवंबर/एक दिसंबर को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। वहां सुरक्षा हालात का चार नवंबर को फिर जायजा लिया जाएगा, ताकि यह तय हो सके कि मुकाबला इस्लामाबाद में होगा या किसी तटस्थ स्थल पर।' आइटीएफ की डेविस कप समिति ने 22 अगस्त को दोनों देशों के बीच मौजूदा राजनयिक तनाव को ध्यान रखकर मुकाबले कहीं और स्थानांतरित करने के भारत के अनुरोध के बाद इसे नवंबर तक स्थगित कर दिया था। जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लेने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए थे।

भारत ने मुकाबले के लिए मजबूत टीम का एलान किया था, लेकिन जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के राजदूत को देश छोड़ने को कहा था। इसके अलावा सद्भावना एक्सप्रेस रोक दी गई और पाकिस्तान बार-बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देकर इसे अंतरराष्ट्रीय विवाद बनाना चाहता है।

विविध

जलवायु परिवर्तन से बाघों ने बदला अपना ठिकाना

कॉप-14

- सुंदरवन में जल स्तर बढ़ने से बाघ बदल रहे हैं ठिकाना
- बाघ अभयारण्य में इंसानी दखल दूर करने के हो रहे प्रयास

अरविंद मिश्रा, ग्रेटर नोएडा

जलवायु परिवर्तन के असर से बंगाल टाइगर (बाघ) भी नहीं बचा है। सुंदरवन में जलस्तर बढ़ने से बाघ वहां से पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बक्सा बाघ अभयारण्य में बाघों की मौजूदगी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। सुरक्षित जगह और प्रचुर भोजन की तलाश में बाघों ने ठिकाना बदल दिया है। इसलिए देश में तीन नए बाघ अभयारण्य अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। बाघ संरक्षित क्षेत्र में इंसानी दखल को कम से कम करने का काम भी हो रहा है।

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, मरुस्थलीकरण बड़ी समस्या बन चुका है। इससे सिर्फ इंसान ही प्रभावित नहीं हैं, बल्कि बेजुबान जीव-जंतुओं पर भी जलवायु परिवर्तन का असर है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से सुंदरवन क्षेत्र में बाघों का प्राकृतिक आवास भी प्रभावित हुआ है। सुंदरवन क्षेत्र से बाघ पलायन कर रहे हैं। यही नहीं पश्चिम बंगाल के बक्सा बाघ अभयारण्य से बाघ पूरी तरह से पलायन कर चुके हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी) ने बक्सा बाघ अभयारण्य में बाघों की कोई गतिविधि दर्ज नहीं की है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि प्राकृतिक आवास प्रभावित होने के कारण बाघों ने ठिकाने बदल दिए हैं। नए क्षेत्रों में बाघों की गतिविधियां दर्ज हुई हैं। इसलिए देश में तीन नए बाघ अभयारण्य बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश के रातापानी, राजस्थान, और छत्तीसगढ़ में हैं।

प्राधिकरण के वैज्ञानिक वीबी झाला ने बताया कि तकनीक की मदद से भारत बाघों की संख्या बढ़ाने में कामयाब हुआ है। विशेष कार्रवाई बल (स्पेशल टास्क फोर्स) ने एप से निगरानी एवं बाघों का ब्योरा एकत्र किया है। इसके साथ ही बाघ अभयारण्य से इंसानी दखल को समाप्त करने के प्रयास चल रहे हैं। कान्हा और बांदीपुर बाघ अभयारण्य में रहने वाले लोगों को वहां से दूसरी जगह विस्थापित किया गया है।

भूक्षरण रोकने में आदिवासियों का अनुभव हो सकता है मददगार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

सदियों से आदिवासी जंगल के आस पास रहते आए हैं। उन्होंने जंगल को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपने जीवन यापन को पर्यावरण के अनुकूल रखा है। आदिवासियों के इस अनुभव का फायदा भूक्षरण रोकने एवं भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने में लिया जा सकता है। कॉप-14 में आयोजित सत्र को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह बात कही।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों का जीवन पूरी तरह जंगलों पर आधारित रहा है। अपने भरण पोषण के लिए उन्होंने जंगलों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। दुनिया में जिस तरह से जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ रही है, इससे निपटने के लिए आदिवासियों का ज्ञान फायदेमंद हो सकता है। जनजातीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भारत में किए जा रहे प्रयासों की जिक्र करते हुए आदिवासी सहकारिता विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के प्रबंध निदेशक प्रवीर कृष्ण ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल विकास व गरीबों की आय से समझौता किए बिना भूमि की गुणवत्ता में हुई कमी को दूर करने के लिए भारत आदिवासियों के अनुभव व विशेषज्ञता का सहारा लेगा।

अब किसानों की दोस्त बनेगी जलकुंभी

जागरण विशेष

रोहित कुमार, पाकुड़

- जलीय जीवों को नष्ट कर देने वाली जलकुंभी का बनेगा खाद
- भारतीय वन उत्पादक संस्थान ने लगाई खाद की गुणवत्ता पर मुहर

खेतों, तालाबों और नदियों की दुश्मन मानी जाने वाली जलकुंभी का स्वभाव अब बदलने वाला है। लंबे प्रयास के बाद यहां के एक वैज्ञानिक ने इससे हरी खाद बनाने की विधि ईजाद की है। बहुत ही आसान तरीके से बनी यह खाद खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर खुशहाली लाएगी।

जलीय जीवों को नष्ट कर देने वाली जलकुंभी को बंगाल की खुशहाली की राह में बड़ा रोड़ा माना जाता है। किसानों के लिए यह बड़ी समस्या रही है। इसे तालाब के पानी के साथ-साथ उसमें रहने वाली मछलियों और अन्य जलीय जीव के लिए काफी नुकसानदेह माना जाता है। यह ताल-तालाब और अन्य जल स्रोतों का पानी तो तेजी से सोखती ही है, उसमें मौजूद ऑक्सीजन व अन्य पौष्टिक तत्वों को भी सोख लेती है। शोध बताते हैं कि एक जोड़ी जलकुंभी एक सीजन में 48 हजार गुणा बढ़ जाती है।

80 दिन में तैयार होगी हरी खाद : पादप वैज्ञानिक डॉ. प्रसन्नजीत मुखर्जी ने इस समस्या की काट निकाल ली है। उन्होंने इससे हरी खाद बनाने की विधि ईजाद की है। डॉ. प्रसन्नजीत बताते हैं कि इस पर शोध के दौरान पाकुड़ कॉलेज में उन्होंने काफी काम किया। सबसे अहम यह है कि जलकुंभी से कोई भी किसान अपने खेतों में हरी खाद तैयार कर सकता है। इसमें 80 दिन का समय लगता है। उन्होंने बताया कि शोध के दौरान 272 तरह के जलीय पौधे मिले, जिनमें 56 जलीय पादपों में औषधीय गुण पाए गए हैं। शोध के दौरान इन पौधे के आर्थिक महत्व को रेखांकित किया गया।

तालाब में उगी जलकुंभी। एक वैज्ञानिक ने इससे हरी खाद बनाने की तारीका ढूंढ़ निकाला है। जागरण

भारतीय वन उत्पादक संस्थान ने जलकुंभी से तैयार होने वाली हरी खाद की गुणवत्ता पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार को किसानों के हित में इसका प्रयोग करना चाहिए।
–डॉ. प्रसन्नजीत मुखर्जी शोधकर्ता सह व्याख्याता, केके एम कॉलेज, पाकुड़

वैज्ञानिक डॉ. प्रसन्नजीत मुखर्जी। जागरण

उन्होंने झारखंड के 24 जिलों में जलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनस्पतियों का अध्ययन करने के बाद इसके सदुपयोग की योजना बनाई है।

ऐसे करते हैं तैयार : डॉ. प्रसन्नजीत ने बताया कि जमीन में एक निश्चित आकार का गड्ढा तैयार किया जाता है। उसमें जलकुंभी और गाय का गोबर परत दर परत डालकर छोड़ दिया जाता है। इसमें बहुत कम मात्रा में सुपर फॉस्फेट और यूरिया भी डाल सकते हैं। इससे बनी हरी खाद न केवल उपज बढ़ाने में मददगार होती है बल्कि खेतों की मिट्टी को नवजीवन प्रदान करती है।

दोहरा लाभ : उन्होंने बताया कि उनके शोध से दोहरा लाभ लिया जा सकता है। एक तो तालाबों के लिए नुकसानदेह जलकुंभी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरी ओर किसानों को सस्ते दर पर हरी खाद भी उपलब्ध होगी।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

नाम नानक का, श्रेय लेने की पार्टियों में छिड़ी जंग

इन्द्रप्रीत सिंह, सुल्तानपुर लोधी

- स्टेज एसजीपीसी संभालेगी या सरकार इसी को लेकर है मतभेद

श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाशोत्सव को 58 दिन से भी कम रह गए हैं, लेकिन इसे कैसे मनाया जाना है इसको लेकर न तो पंजाब सरकार में सहमति बनी है और न ही एसजीपीसी में। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस व शिरोमणि अकाली दल सुल्तानपुर लोधी के घरों, दफ्तरों और अन्य इमारतों की दीवारें अपने-अपने हिसाब के रंगों से पोतने में जरूर लगे हुए हैं। लेकिन गुरु नानक साहिब की शिक्षाओं का प्रसार करने के कार्यक्रम क्या होंगे, उन्हें आम जन तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। दरअसल, शिरोमणि अकाली दल अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए कार्यक्रम का सारा नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) को दिलाना चाहता है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दो दिन पहले सुल्तानपुर लोधी में एसजीपीसी और शिअद को हाशिए पर धकेलने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि उनके पास पूरा रिकार्ड है कि खालसा पंथ की स्थापना के 300 साला दिवस को मनाने में किस-किस की क्या भूमिका थी।

दिलचस्प बात यह है कि 1999 में अकाली दल-भाजपा की सरकार के दौरान श्री आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का 300 साला स्थापना दिवस मनाया गया था। उस समय भी सारा कार्यक्रम एसजीपीसी ने तय किया था। कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि 31 दिसंबर, 1998 को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार भाई रणजीत सिंह ने एक हुक्मनामा जारी किया था। इसमें प्रकाश सिंह बादल और गुरचरन सिंह टोहड़ा को हिदायत दी थी कि खालसा पंथ की स्थापना की तीसरी शताब्दी से पहले कोई भी पक्ष एक-दूसरे का किसी किस्म का नुकसान न करे। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने राज सता के बलबूते पर 16 मार्च, 1999 को एसजीपीसी के प्रधान जत्थेदार गुरचरन सिंह टोहड़ा को अध्यक्ष पद से उतार कर श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मनामे का सरेआम उल्लंघन करके इसकी सर्वोच्चता को चुनौती दी थी। बादल सरकार ने तब सारा कार्यक्रम चलाया था जिमसें मंच का संचालन एसजीपीसी की बजाए तब के वित्तमंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह ने किया था।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एसजीपीसी द्वारा तालमेल न करने को लेकर लगाए आरोपों पर भी कहा है कि सरकार ने मंत्रियों की समिति गठित की हुई है। उन्होंने कहा कि सारे धार्मिक काम एसजीपीसी ही कर रही है, हम उसमें कोई बाधा नहीं पैदा कर रहे, लेकिन राज्य स्तरीय समारोह तो सरकार करवा रही है।

एसजीपीसी के प्रधान जत्थेदार गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने एक बार फिर से सरकार पर समारोहों के लिए सहयोग न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वह एक और कोशिश कर रहे हैं। 17 सितंबर को एक और संयुक्त तालमेल कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने सरकार से इसमें अपना नुमाइंदा भेजने की अपील की।

पपला को छुड़ाने में शामिल दो और बदमाश गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बहरोड़ (अलवर)

पुलिस थाना बहरोड़ पर हमला और फायरिंग कर कुख्यात बदमाश महेंद्रगढ़ के गांव खैरोली निवासी विक्रम गुर्जर उर्फ पपला को फरार कराने व सहयोग करने के आरोप में स्पेशन आपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में महेंद्रगढ़ गांव खैरोली निवासी महेंद्र उर्फ पप्पू गुर्जर व अलवर के गांव गुजरीवास निवासी अजय कुमार उर्फ बिल्लू है। गिरफ्तार किया आरोपित अजय वर्तमान में दिल्ली के घीटोरनी में रह रहा है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि प्रकरण में फरार कराने वाले व षड्यंत्र में शामिल अभियुक्त विनोद स्वामी, कैलाश चंद, जगन खटाना, महिपाल गुर्जर, सुभाष गुर्जर, नरेंद्र सिंह, श्यामसुंदर उर्फ अशोक, जितेंद्र उर्फ जीतू, विक्रम सिंह व एक इनामी अपराधी दिनेश कुमार को एसओजी द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस प्रकार एसओजी द्वारा फरार कराने एवं फरारी में सहयोग करने के आरोप में 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से गहनता से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस कर्मियों से की पूछताछ : संस, भिवाड़ी: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने बहरोड़ थाने से इनामी हिस्ट्रीशीटर विक्रम उर्फ पपला की फरारी के दौरान मौजूद पुलिसकर्मियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच अधिकारी एसओजी के एएसपी करण शर्मा बहरोड़ थाने पहुंचे। वह घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर रहे हैं। एएसपी करण शर्मा ने सबसे पहले घटना के समय तैनात थाने के संतरी कृष्ण कुमार से पूछताछ की। हथियार सहित तैनात होने के बावजूद संतरी कृष्ण कुमार ने एक भी फायर नहीं किया और छुप गया था।

मौसम विशेष

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पंजाब तथा सटे हुए हरियाणा में हल्की वर्षा होगी। दिल्ली तथा पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।

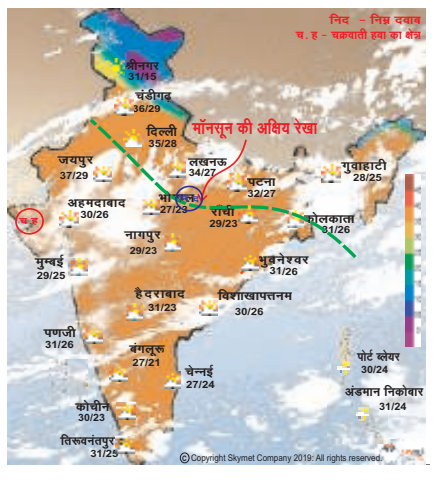

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	30/25/व	अहमदाबाद	34/24/व
कोलकाता	31/26/व	बड़ोदा	34/25/आंबा
चेन्नई	35/26/व	नागपुर	30/24/व
हैदराबाद	31/24/व	इन्दौर	32/23/सा
बंगलूरु	28/20/व	रांची	32/23/आंबा
त्रिवेन्द्रम	31/26/व	पटना	30/25/आंबा
गुवाहाटी	30/24/व	जमशेदपुर	33/25/आंबा
गंगटोक	17/08/व	पुणे	24/22/व

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
आजकल
शनिवार 14 सितंबर 2019
16
www.jagran.com

चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना-2

1959 में आज ही सोवियत संघ का लूना-2 चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। हालांकि लूना-2 चांद पर उतरते ही क्रैश हो गया था। लूना-2 से ही पता चला था कि चांद पर न तो चुंबकीय क्षेत्र है न ही किसी भी तरह का रेडिएशन।

दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी

1939 में आज ही अमेरिका में दुनिया के पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। इस हेलीकॉप्टर की यह उड़ान सिर्फ कुछ ही सेकंड की थी और इस दौरान यह हेलीकॉप्टर बंधा हुआ था। इसे अमेरिकी मूल के इगोर सिकोरस्की ने डिजायन किया था।

बहुमुखी प्रतिभा के धनी आयुष्मान को जन्मदिन मुबारक हो

हिंदी सिनेमा के हैंडसम एक्टर की लिस्ट में शुमार आयुष्मान खुराना का जन्म 1984 में आज ही चंडीगढ़ में हुआ था। रेडियो और टीवी रियलिटी शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाले आयुष्मान ने साल 2012 आई फिल्म विक्की डोनर से डेब्यू किया। उनकी इस फिल्म ने बड़े परदे पर धमाल मचा दिया था। अभिनेता होने के साथ-साथ वह बहुत अच्छे गायक और गीतकार भी हैं। उन्होंने आगाज और पंचतंत्र जैसे नाटकों में काम किया। 2018 में आई फिल्म अंधाधुन में बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आर्टिकल 15, बधाई हो, दम लगा के हईशा उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में हैं।

इधर-उधर की

कैलिफोर्निया में बोतल ने बचाई परिवार की जान

वाशिंगटन,एजेंसी : अमेरिका के कैलिफोर्निया में 40 फीट गहरी खाई में फंसे परिवार की जान एक बोतल की मदद से बच गई। दरअसल, कर्टिस विटसन, उनकी पत्नी और उनका 13 साल का बेटा कैलिफोर्निया घूमने गए थे। इस दौरान वे एक घाटी से होते हुए अरोयो सेको नदी और फिर वहां से झरने तक जाना चाहते थे, लेकिन तीसरे दिन वे घाटी के एक ऐसे तंग हिस्से में फंस गए, जहां दोनों तरफ 40 फीट ऊंची दीवारें थीं। कर्टिस को पहले तो कुछ दिमाग में नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने एक बोतल पर हेल्प लिखा। साथ ही एक स्लिप पर संदेश लिखा और बोतल में डालकर झरने के बहाव में फेंक दी। बोतल बहते हुए 400 मीटर दूर पहुंची, जहां हाइकर्स का एक ग्रुप मौजूद था। किस्मत से यह बोतल उनको मिल जाती है। वह फौरन मदद को वहां पहुंचते हैं और परिवार की जान बचा लेते हैं।

नए ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण का लगाया पता

खोज ▶ वैज्ञानिकों का दावा, गुरुत्वीय तरंगों से ब्लैक होल के द्रव्यमान का लग सकता है अनुमान

कहा- इससे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत को मिलता है और बल

- फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ ब्रिटेन के शोधकर्ताओं का अध्ययन
- ब्लैक होल के तीन गुणों का ही किया जा सकता है अवलोकन

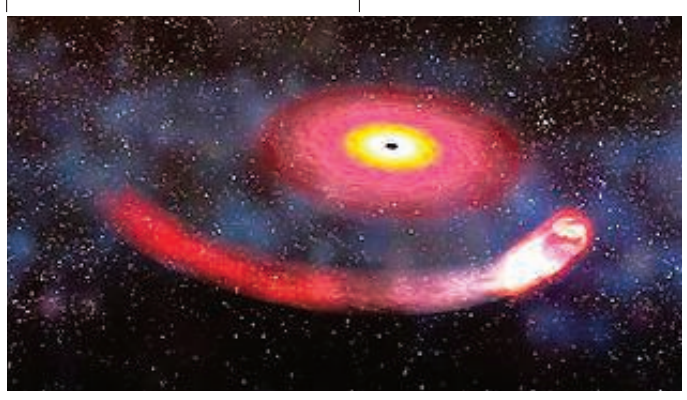

ब्लैक होल से प्रकाश की किरणें भी बाहर नहीं निकल पातीं। प्रतीकात्मक

बोस्टन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने पहली बार एक नवजात ब्लैकहोल में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही वैज्ञानिकों का दावा है कि इन तरंगों के घूमने के पैटर्न के आधार पर ब्लैक होल के द्रव्यमान और उसके घूमने की गति का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के साक्ष्यों को और बल मिलता है।

सामान्य सापेक्षता सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव देखा जाता है उसका वास्तविक कारण यह है कि हर वस्तु अपने मान और आकार के अनुसार अपने इर्द-गिर्द एक दिक्-काल (स्पेस-टाइम) में ऐंठन पैदा कर देती है। यह अध्ययन फिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस अध्ययन से इस बात की संभावना और बढ़ गई है कि ब्लैक होल केवल अपने तीन गुणों को प्रदर्शित करता है, जिसमें द्रव्यमान, घूर्णन (स्पिन) और इलेक्ट्रिक चार्ज शामिल हैं। इन तीनों में खास बात यह है कि इनका अवलोकन किया जा सकता है, जबकि अन्य गुणों का अवलोकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी ब्लैक होल में ही समा जाते हैं।

अमेरिका में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के शोधकर्ताओं की टीम ने गुरुत्वाकर्षण के घूर्णन की गणना कर कहा कि ब्लैक होल को भौतिकविद् अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए, जिसका घूमने का पैटर्न दिया गया है। अध्ययन के मुताबिक, शोधकर्ताओं की यह गणना ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूर्णन के पहले के माप से मेल खाती है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक मैक्सिमिलियानो इस्सी ने कहा कि पहले हम केवल सामान्य सापेक्षता के सही होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब हमने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आइंस्टीन के सिद्धांत का सीधे परीक्षण करने वाला यह पहला प्रायोगिक माप था।

पहले भी लगाया था पता : इससे पहले वैज्ञानिकों ने दो स्पायरलिंग ब्लैक होल में गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया था, जो बाद में टकराने के बाद एक ब्लैक होल में समा गया था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने पाया था कि जब दोनों ब्लैक होल एक-दूसरे से मिले तो उस समय गुरुत्वीय तरंगों की गति सबसे ज्यादा तीव्र हो गई थी।

ब्लैक होल क्या है : ब्लैक होल अंतरिक्ष का एक हिस्सा है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश की किरणें भी वहां से बाहर नहीं निकल पातीं, इसीलिए इसे ब्लैक होल कहा जाता है और इसे हम सीधी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिस जगह से प्रकाश भी नहीं बाहर आ पाता है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है।

फिल्म रिव्यू

ड्रीम गर्ल

निर्देशन : राज शांडिल्य
मुख्य कलाकार : आयुष्मान खुराना, नुसरत भरूचा, अन्नू कपूर, मनजोत सिंह, विजय राज, राजेश शर्मा, निधि बिष्ट
अवधि : 2 घंटे 12 मिनट

हंसाती-गुदगुदाती फिल्म

कॉमेडी शो 'कॉमेडी सर्कस' और 'जबरिया जोड़ी', 'फ्रीकी अली' व 'वेलकम बैक' जैसी फिल्मों के डायलॉग लिख चुके राज शांडिल्य की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है। अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने मनोरंजन के साथ संदेश देने का भी प्रयास किया है। भागमभाग भरी जिंदगी में भले ही सोशल मीडिया पर लोगों के फॉलोवर्स सैकड़ों की संख्या में हों, लेकिन मन की बात साझा करने वाला सच्चा दोस्त शायद ही हो। राज ने दिनोंदिन बढ़ती आबादी के साथ इंसान के बढ़ते अकेलेपन का मुद्दा उठाया है। हालांकि फिल्म विशुद्ध कॉमेडी है।

करम (आयुष्मान खुराना) बचपन से ही लड़कियों की आवाज में बात करने का महारथी होता है। वह नौकरी की तलाश में है। पिता जगजीत सिंह (अन्नू कपूर) कर्मकांड की दुकान चलाते हैं। वह बैंक के कर्ज तले दबे होते हैं। (हालांकि इसके कारणों के बारे में नहीं बताया गया है) करम रामलीला में सीता या कृष्णलीला में राधा बनकर थोड़ी-बहुत कमाई कर लेता है। पिता चाहते हैं कि वह कोई नियमित नौकरी करे। बहुरूपिया की भूमिका न करे। अचानक उसे कॉलसेंटर में लड़की की आवाज में लड़कों से बात करने की नौकरी मिल जाती है। शुरुआत में वह उसे मजाकिया अंदाज में लेता है। मुश्किल तब शुरू होती है, जब वे लड़के उससे प्यार करने लगते हैं और शादी के ख्वाब संजोने लगते हैं। उनमें उसके पिता भी शामिल होते हैं। करम की मंगनी माही (नुसरत भरूचा) से हो चुकी होती है। फोन पर बात करने वाले कई लोग उसके आसपास के होते हैं, जो पूजा समझकर उससे प्यार करते हैं। वह अपने जिगरी दोस्त (मनजोत सिंह) के साथ मिलकर सबसे पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालता है। सब चालें उल्टी पड़ती है। वह कैसे इनसे पार पाता है, यह देखना मनोरंजक है।

इंसान ने भले ही तमाम सुविधाएं जुटा ली हैं, लेकिन अकेलेपन की समस्या कायम है। फिल्म के एक दृश्य में आयुष्मान कहते हैं, 'पापा ने सारी जिंदगी बिना मां के अकेले काट दी। कभी अपनी कोई समस्या बयां नहीं की। एक हम है छोटी-सी समस्या पर दारू पीने लग जाते हैं।' बात छोटी, लेकिन बहुत कीमती है। राज शांडिल्य हंसाते-गुदगुदाते हुए कई मुद्दों को छूते हुए निकल जाते हैं। उन्होंने फिल्म पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। फरीदाबाद के परिवेश और लहजे का पूरा खयाल रखा है। फिल्म की तकनीकी टीम मुस्तैद रही है। किरदारों को सही सीन और प्रसंग दिए हैं। उन्हें विश्वसनीय बनाया है और उन्हें उपयुक्त संवाद दिए हैं। कॉमेडी किरदारों को गढ़ने में राज शांडिल्य पारंगत हैं। उन्होंने किरदारों की छोटी-छोटी हरकतों और बातों से इसे साबित किया है। उन्हें कलाकारों का भी भरपूर सहयोग मिला है।

सहयोगी कलाकारों में अन्नू कपूर उल्लेखनीय हैं। वह किरदारों में आसानी से ढल जाते हैं। माही के भाई के किरदार में अभिषेक बनर्जी, पुलिसकर्मी बने विजयराज समेत सहयोगी कलाकारों की भूमिकाओं में आए कलाकार फिल्म के माहौल और मजे को गाढ़ा करते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता आयुष्मान खुराना लगातार लीक से हटकर विषयों का सावधानीपूर्वक चयन कर रहे हैं। फिल्म में वह पूजा की आवाज निकालते हुए बॉडी लैंग्वेज का खास ध्यान रखते हैं। किरदार को सहज भाव-भंगिमा देते हैं। उनके किरदार को रोचक और मजेदार बनाने में संवादों का बड़ा हाथ रहा है। फिल्म हास्य की लय को बरकरार रखती है। नुसरत भरूचा खूबसूरत और मासूम दिखी हैं। आयुष्मान के साथ उनकी केमिस्ट्री जमती है। फिल्म 'फुकरे' से लोकप्रिय हुए मनजोत सिंह ने आयुष्मान के जिगरी दोस्त की भूमिका को सहजता से निभाया है। दोनों की कॉमिक टाइमिंग सटीक रही। निधि बिष्ट भी अपनी संक्षिप्त भूमिका में प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहती हैं। फिल्म का गाना राधे राधे... और दिल का टेलीफोन... लोकप्रिय हो चुका है। ढगाला लागली... गाने को प्रमोशन में इस्तेमाल किया गया था, पर वह गाना फिल्म से नदारद है।

- स्मिता श्रीवास्तव

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

शोध अनुसंधान

मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ा सकती है चाय

चाय पीने का एक नया फायदा सामने आया है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नियमित तौर पर चाय पीने वालों के मस्तिष्क की संरचना बेहतर होती है। इसका संबंध स्मृति संबंधी स्वस्थ कार्यक्षमता से पाया गया है। सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर फेंग लेई के अनुसार, 'हमारे नतीजों से चाय पीने का मस्तिष्क की संरचना पर सकारात्मक प्रभाव का पहला प्रमाण मिला है। यह भी जाहिर हुआ है कि नियमित चाय पीने का मस्तिष्क की संरचना में उम्र संबंधी गिरावट के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव भी पड़ता है।' यह निष्कर्ष 60 साल की उम्र के 36 लोगों की सेहत, जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। पूर्व के अध्ययनों में शोधकर्ता यह साबित कर चुके हैं कि लोगों की सेहत के लिए चाय फायदेमंद है। इसका मूड पर सकारात्मक असर पड़ता है और हृदय रोग से रोकथाम भी होती है। -आइएएनएस

ज्यादा फैट वाले भोजन की हर किसी में अलग प्रतिक्रिया

एक अध्ययन में पाया गया है कि ज्यादा फैट (वसा) वाले भोजन को पचाने में हर व्यक्ति में अलग प्रतिक्रिया होती है। इसे इंफ्लेमेटरी रिस्पांस कहा जाता है। खाने के संबंध में यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। अमेरिका के एआरएस वेस्टर्न ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता डेनियल जी लेमे ने कहा, 'हमने इंफ्लेमेटरी रिस्पांस को लेकर 20 वालंटियर पर गौर किया। भोजन के तुरंत बाद, तीन घंटे बाद और छह घंटे बाद इंफ्लेमेटरी रिस्पांस को परखा गया और सभी में प्रतिक्रियाएं पूरी तरह अनूठी पाई गईं। किन्हीं भी दो लोगों में पूरी तरह समान प्रतिक्रिया नहीं पाई गई। इन लोगों को मानक के अनुरूप ऐसा भोजन दिया गया था, जिसमें 38 फीसद फैट था।' उन्होंने कहा, 'हमें आहार में विभिन्न जरूरतों के बारे में विचार करने से पहले यह समझने की जरूरत है कि लोगों में भिन्नता का क्या कारण है?' -एएनआइ

न्यूयॉर्क फैशन वीक में नौ साल की दिव्यांग लड़की ने जीता सबका दिल

- फिबुलर हेमीमेलिया नामक बीमारी होने के बाद भी रैंप वॉक कर पेश की मिसाल
- बिग फैशन नाइट में वॉक करने वाली पहली दिव्यांग मॉडल बनीं दिमेत्रे

न्यूयॉर्क में रैंप पर वॉक करतीं दिव्यांग डेजी मे दिमेत्रे। एएनआइ

वाशिंगटन, एएनआइ : नौ साल की दिव्यांग डेजी मे दिमेत्रे ने ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में अपने रैंप वॉक से सबका दिल जीत लिया। ब्रिटेन के बर्मिंघम में रहने वाली डेजी फिबुलर हेमीमेलिया नामक गंभीर बीमारी के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी में व्यक्ति के पैर की फिबुलर हड्डियां छोटी होती हैं या बिल्कुल नहीं होतीं। इसकी वजह से 18 माह की उम्र में डेजी के दोनों पैर काटने पड़े थे। अब वह नकली पैरों के सहारे चलती हैं।

दुनिया के सबसे मशहूर फैशन शो में हिस्सा लेकर डेजी ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। अपने हौसले से डेजी ने साबित कर दिया कि दिव्यांगता किसी के सपनों में रुकावट नहीं बन सकती। शो में डेजी ने फ्रांस के लुलु एट गिगी काउचर के लिए रैंप वॉक किया। वह इस कंपनी की ब्रांड एंबेसडर बन चुकी हैं। अपनी इस उपलब्धि से खुश डेजी ने कहा कि उन्हें खुद पर गर्व है।

हर वक्त उनका साहस बढ़ाने वाले उनके पिता ने कहा, 'वह पेशेवर मॉडल की तरह चली। वह मुझे भी प्रेरित करती है।' डेजी नाइकी और रिवर आइलैंड समेत ब्रिटेन की कंपनियों के लिए मॉडलिंग कर चुकी हैं।

जापान में 70 हजार से ज्यादा लोग हैं शतायु

टोक्यो, आइएएनएस : घटती जन्मदर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी की समस्या से जूझ रहे जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र वालों की संख्या पहली बार 70 हजार के पार हो गई है। देश में लगातार 49वें साल बुजुर्गों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

जापान सरकार के स्वास्थ्य, श्रम व कल्याण मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश की आबादी 12.67 करोड़ है। इसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। सौ साल से ज्यादा उम्र वाले कुल 71 हजार 238 लोगों में 88 प्रतिशत महिलाएं हैं। जापान में पिछले 30 सालों में जिंदगी का शतक पूरा करने वालों की संख्या 23 गुना बढ़ चुकी है। फुकुओका निवासी 116 वर्षीय काने तनाका जापान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान हैं। उनका जन्म जनवरी 1903 में हुआ था।

जोइत्सु निगाता प्रांत के 112 वर्षीय चित्सु वतनबे जापान के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। राजधानी टोक्यो में सबसे ज्यादा 6059 शतायु रहते हैं, जबकि कनागावा प्रांत में 3933 और ओसाका प्रांत में 3648 लोग शतायु हैं।

आकर्षण का केंद्र बनी वैश्विक एकता को समर्पित प्रदर्शनी

चीन के वाणिज्यिक शहर शंघाई में प्रतिष्ठित समकालीन अफ्रीकी-अमेरिकी आर्टिस्ट मार्क ब्रैडफोर्ड की एकल प्रदर्शनी 'लास एंजिलिस' आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रैडफोर्ड की कलाकृतियां वैश्विक एकता और सामाजिक न्याय की अवधारता पर केंद्रित हैं। इस आर्ट इंस्टालेशन में उन्होंने छोटे-बड़े ग्लोब के माध्यम से दुनिया की स्थिति पर फोकस किया है। उनकी कई कलाकृतियों को वैश्विक स्तर पर काफी सराहा गया है। वह युवाओं को रचनात्मक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए लास एंजिलिस में गैरलाभकारी संगठन आर्ट प्रैक्टिस के सह-संस्थापक भी हैं। एएफपी

स्पेन में बाढ़ से भयावह हुए हालात

स्पेन में ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। इससे कई शहरों में हालात काफी गंभीर हो गए हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भर गया है। मोलिना डेल सेगुरा में पानी भर जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पिलर डी ला होराडाडा शहर में एक टनल में पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था चौपट हो गई है। राजधानी मैड्रिड में तो हालत यह हैं कि सड़कों पर वाहन पानी में बहते नजर आए। रायटर

स्क्रीन शॉट

हेयर ड्रेसर का हाथ, नीतू कपूर के साथ...

बॉलीवुड सितारों के जीवन का हिस्सा केवल फिल्में ही नहीं होती हैं, वे कई विज्ञापनों और फोटोशूट्स में भी व्यस्त रहते हैं। आजकल कलाकार जो फोटोशूट्स कराते हैं, उनमें मेकअप और तकनीक का खास ख्याल रखा जाता है। फोटो को ग्लैमरस और परफेक्ट बनाने की हर कोशिश की जाती है। पचास से लेकर सौ फोटो खींचे जाते हैं, जिनमें से एक फोटो चुनी जाती है मैगजीन के कवर पेज के लिए। अगर पिछली सदी के 70 और 80 के दशक की बात करें, तो उस वक्त नजारा थोड़ा अलग था। नीतू कपूर ने एक पुरानी तस्वीर साझा करते हुए इसका रहस्योद्घाटन किया है। नीतू ने इंस्टाग्राम पर वर्षों पुरानी एक मैगजीन का कवर पेज पोस्ट किया है। कवर पर नीतू कपूर (तब नीतू सिंह) हंसती हुई नजर आ रही हैं। उनके नाखूनों पर लाल रंग की नेलपॉलिश भी लगी है। इस तस्वीर के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि तस्वीर में जो हाथ है, वह उनका नहीं, बल्कि उनकी हेयरड्रेसर का है। मैगजीन के कवरपेज पर नीतू एक तरफ अपनी हेयरड्रेसर के बाल संवारती हुई भी नजर आ रही हैं। नीतू ने लिखा, 'रेड लिपस्टिक के साथ रेड नेल्स के कॉम्बिनेशन का यह कॉन्सेप्ट फोटोग्राफर राकेश श्रेष्ठ का था। चूंकि मेरे नाखून छोटे थे, इसलिए मेरी हेयर ड्रेसर का हाथ इस फोटो में इस्तेमाल किया गया है। हाथ का पॉश्चर अजीब लग रहा है।

महिला केंद्रित फिल्मों से अंगद बेदी को परहेज नहीं

बॉलीवुड में लगातार महिला सशक्तीकरण को दर्शाने वाली फिल्में बन रही हैं। मसलन गणितज्ञ शकुंतला देवी, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, कारगिल वॉर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना आदि महिलाओं पर फिल्में बन रही हैं। फिल्म 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' की बात की जाए तो इस फिल्म की शीर्षक भूमिका में जाह्नवी कपूर हैं, जबकि गुंजन के भाई अंशुमन सक्सेना का किरदार फिल्म में अंगद बेदी निभा रहे हैं। 'पिंक' के बाद अंगद 'द जोया फैक्टर' और अब 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' में काम कर रहे हैं। लगातार महिला केंद्रित फिल्मों का हिस्सा बनने को लेकर अंगद कहते हैं, 'मेरे ख्याल से किरदार अच्छा होना चाहिए। अगर किरदार को अच्छी तरह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वेब शो 'इनसाइड एज' में भी लड़कों की दुनिया थी, लेकिन उसमें अहम किरदार रिचा चड्ढा ने निभाया था। अब लोगों को भी समझ आ गया है कि सिनेमा में महिलाओं के लेकर उन्हें केवल कलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब उन्हें टक्कर के किरदार देने होंगे। उन्हें वे किरदार देने ही होंगे, जो कहानी की डिमांड हैं। यह महिलाओं का वक्त है और वे चमक रही हैं।' 'पिंक' में 21 साल की उम्र के लड़के का किरदार कर निभा चुके अंगद इस फिल्म में 19 साल से 21 साल की उम्र का किरदार निभाएंगे। अंगद का एक दिन का काम बचा है। उम्र को लेकर अंगद कहते हैं कि उनकी स्क्रीन पर उम्र 21 से 26 के बीच लगती है। यह अब तक की सबसे छोटी उम्र का किरदार होगा, जो वह पर्दे पर निभाएंगे। अंगद अभिनीत 'द जोया फैक्टर' 20 सितंबर को रिलीज होगी, जबकि 'गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल' अगले साल रिलीज होगी।

बेटे युग के जन्मदिन पर अजय ने गुरुद्वारे में टेका मत्था

शुक्रवार को अजय देवगन के बेटे युग देवगन का नौवां जन्मदिन था। इस खास मौके पर अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो साझा की है। फोटो में अजय और युग हाथ में प्रसाद लिए गुरुद्वारे में खड़े हैं। इस फोटो को साझा करते हुए अजय ने लिखा, 'तुमको बड़े होते हुए देखना आनंददायक है। काजोल ने भी युग के जन्मदिन पर एक डबस्मैश वीडियो (जिसमें आवाज किसी और की होती है) साझा करते हुए लिखा, 'तीन की उम्र में शानदार, 9 में उससे भी शानदार और ढीठ। जन्मदिन की शुभकामनाएं युग। मुझे लगता है कि वह मुझे नींद में भी चिल्लाते हुए सुनता है।' रकुलप्रीत और दिव्या दत्ता जैसे कई सितारों ने युग को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उधर, अनुष्का शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर अपने बचपन की तीन तस्वीरें साझा की।

ऋषि कपूर की वेलकम पार्टी में रणबीर संग पहुंचीं आलिया

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी इन दिनों बी-टाउन में चर्चा में है। दोनों अक्सर एक साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में रणबीर और आलिया को साथ में गणपति की पूजा करते हुए भी देखा गया था। अब रणबीर के पिता ऋषि कपूर के न्यूयॉर्क से 11 महीने बाद घर वापस लौटने पर आलिया उनसे मिलने पहुंचीं। हालांकि अभी दोनों ने सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन खबर है कि दोनों अगले साल तक शादी के बंधन में बंध सकते हैं। फिल्मों की बात करें तो अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहली बार साथ में स्क्रीन शेयर करते हुए दिखेंगे। उनके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन और मौनी रॉय की भी अहम भूमिकाएं होंगी। इसके अलावा रणबीर फिल्म 'शमशेरा' में दिखेंगे। इसमें उनके अपोजिट वाणी कपूर होंगी। वहीं, आलिया की झोली में 'सड़क 2' और 'आरआरआर' फिल्में हैं।

अध्ययन

कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन, चांद पर मौजूद पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चंद्रमा के गर्भ में छुपे आयरन सल्फेट से जोड़ा

चंद्रमा के गर्भ में छिपी हो सकती हैं मूल्यवान धातुएं

- नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ शोध
- चांद पर मिल सकती हैं प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी धातुएं

टोरंटो, प्रेट्र : पृथ्वी और चंद्रमा पर मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी के संबंध में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी के उपग्रह के गर्भ में कई मूल्यवान धातुओं का बड़ा भंडार छुपा हो सकता है।

कनाडा की डलहौजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स ब्रेनन ने दावा किया है कि वह चंद्रमा पर मौजूद च्वालामुखी पत्थरों में पाए जाने वाले सल्फर का संबंध चांद के गर्भ में छुपे आयरन सल्फेट से जोड़ने में सफल रहे हैं। ब्रेनन ने कहा कि धरती पर मौजूद धातु भंडारों के विश्लेषण से पता चलता है कि प्लैटिनम और पैलेडियम जैसी मूल्यवान धातुओं की मौजूदगी के लिए आयरन सल्फाइड बहुत महत्वपूर्ण है।

4.5 अरब साल पहले हुआ था निर्माण : वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा का निर्माण धरती से निकले एक बड़े ग्रह के आकार के गोले से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ है। दोनों के इतिहास में समानता की वजह के कारण माना जाता है कि दोनों की बनावट भी मिलती-जुलती है। नेचर जियोसाइंस पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में चंद्रमा पर मौजूद धातुओं की संभावनाओं को बारे में विस्तार से बताया गया है।

दब गई धातुएं : ब्रेनन ने कहा 'अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि चंद्रमा की चट्टानों में सल्फर की मौजूदगी, उसकी गहराई में आयरन सल्फाइड की उपस्थिति का अहम संकेत है। हमारे विचार से, जब लावा बना तब कई बहुमूल्य धातुएं नीचे दब गईं होंगी।'

सतह पर नहीं आ पाती धातु : पिछले अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया था कि चंद्रमा की ज्वालामुखी चट्टानों में कीमती धातुओं का मिश्रण आश्चर्यजनक रूप से कम था, जिसके बाद ब्रेनन ने कनाडा की कैरलटन यूनिवर्सिटी के सहयोगी जिम मुंगाल और भूभौतिकीय प्रयोगशाला के नील बेनेट के साथ आयरन सल्फाइड के निर्माण का निर्धारण करने के लिए प्रयोग किए। इस दौरान शोधकर्ताओं को ऐसे संकेत मिले जिसने आधार पर उन्होंने दावा किया कि आयरन सल्फेड से बनी चट्टानों में कीमती धातु मौजूद हैं पर ये आयरन सल्फेड से ही बंधी हुई हैं। जिसके कारण ये धातुएं लावा के साथ चंद्रमा की सतह पर नहीं आ पातीं।

अभी और अध्ययन की है जरूरत : ब्रेनन ने कहा कि हम काफी लंबे समय से पृथ्वी की सतह पर शोध कर रहे हैं, इसलिए हमें इसकी रचना के बारे में अच्छी जानकारी है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे पास कुल 400 किलोग्राम का चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी के नमूने हैं, जिसे अपोलो और चंद्र मिशनों द्वारा लाया गया था। यह सामग्री बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए चंद्रमा की सतह के बारे में अन्य जानकारियों के लिए अभी और अध्ययन की आवश्यकता है।